राष्ट्रीय संस्करण

दैनिक जागरण

वर्ष 3 अंक 222

मूल्य ₹6.00, नई दिल्ली, रविवार, 19 जनवरी 2020

www.jagran.com

पृष्ठ 16

स्मिथ और केन के वीडियो देख की तैयारी : राहुल

>> 14

सरोकार

मजाक उड़ाने वालों को आईना दिखातीं मीना और रीना

रोहतक : हरियाणा के रोहतक की इन दो बहनों के जज्बे की मिसाल आज हर कोई देता है। बस ड्राइवर बन ये बेटियां पुरुषों के एकाधिकार वाले इस पेशे में चुनौती पेश कर रही हैं। दोनों ने तंगहाली में गुजर कर रहे परिवार की गाड़ी को पटरी पर ला दिया है। (पेज-15)

रविवार विशेष

इस बार ग्लेशियरों से दिल्लगी का भी भरपूर मौका...

पिथौरागढ़ : मौसम की जोरदार बर्फबारी ने स्पष्ट संकेत दे दिए हैं कि आने वाले दिनों में उच्च हिमालयी क्षेत्र ग्लेशियरों से गुलजार रहेगा। नदी-नाले जमने लग गए हैं और सीजनल ग्लेशियरों का बनना शुरू हो गया है। (पेज-15)

निर्भया की मां बोलीं, भगवान भी कहें तो दोषियों को माफ नहीं करूंगी

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

पूरा देश दोषियों को जल्द से जल्द फंदे पर लटकता हुआ देखना चाहता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं, जो उन्हें बचाने में लगे हैं। दोषियों को माफ कर देने की सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह की सलाह पर भड़कते हुए निर्भया की मां ने शनिवार को यह बात कही। उन्होंने कहा कि ऐसे (इंदिरा जयसिंह) लोगों के कारण ही दोषियों की फांसी की सजा में देरी हो रही है। आखिर इंदिरा जयसिंह इस तरह की सलाह देने वाली कौन होती हैं? भगवान भी कहें तो दोषियों को माफ नहीं करूंगी।

▶ **सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह की सलाह पर जताई नाराजगी**

इससे पहले इंदिरा जयसिंह ने ट्वीट कर निर्भया की मां को सोनिया गांधी का अनुसरण करते हुए दोषियों को माफ करने की सलाह दी थी। सोनिया गांधी ने अपने पति व पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्या के मामले में दोषी पाई गई नलिनी श्रीहरन को माफ करते हुए कहा था कि वह उसके लिए मृत्युदंड नहीं चाहती हैं। अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह की इस सलाह पर निर्भया की मां का दर्द छलक उठा। उन्होंने कहा, 'वकील चाहते ही हैं कि मामला लंबा चलता रहे। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान कई बार मेरी मुलाकात इंदिरा जयसिंह से हो चुकी है। उन्होंने कभी मेरे बारे में नहीं सोचा, लेकिन आज वह दोषियों की ओर से बोल रही हैं।' दर्दनाक मंजर को याद करते हुए उन्होंने कहा, 'सात साल पहले खून से लथपथ बेटी को मैंने देखा था। सिर्फ सांसें चल रही थीं। आज भी वह मंजर जब आंखों के सामने आता है तो कांप उठती हूं। मैंने बेटी को खोया है और इंदिरा सलाह दे रही हैं कि हम दोषियों को माफ कर दें।' दिसंबर, 2012 में हुई दुष्कर्म व हत्या की इस वारदात के चारों दोषियों की फांसी के लिए पहली फरवरी की तारीख तय की गई है।

निर्भया के दोषी के दावे पर 20 को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट पेज>>5
विशेषज्ञ बोले-कानून के आधार पर तय होती है सजा पेज>>5

इंदिरा जयसिंह ने कहा था

मैं उनके (निर्भया की मां) दर्द को पूरी तरह समझ सकती हूं, फिर भी आग्रह करती हूं कि जैसे नलिनी को माफ कर सोनिया गांधी ने उदाहरण स्थापित किया था, उन्हें भी ऐसा ही करना चाहिए। हम आपके साथ हैं लेकिन मृत्युदंड के खिलाफ हैं।

छलका मां का दर्द

मुझे इंदिरा जयसिंह की सलाह नहीं चाहिए। वह मेरी लगती क्या हैं? दोषियों से उनकी रिश्तेदारी होगी, इसलिए उनके प्रति जयसिंह के मन में नरमी हो सकती है। वह महिला के नाम पर कलंक हैं। उन्हें पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए।

आहत पिता ने कहा

इंदिरा जयसिंह खुद महिला हैं। उन्हें ऐसी टिप्पणी पर शर्म आनी चाहिए। हम सात साल से यह केस लड़ रहे हैं। हम आम लोग हैं, कोई राजनेता नहीं हैं। हमारा दिल सोनिया गांधी जितना बड़ा नहीं है।

गुड़िया सामूहिक दुष्कर्म कांड में प्रदीप व मनोज दोषी करार

नई दिल्ली : गुड़िया से सामूहिक दुष्कर्म के बहुचर्चित मामले में शनिवार को कड़कड़डूमा स्थित पॉक्सो कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नरेश कुमार मल्होत्रा ने प्रदीप कुमार और मनोज शाह को दोषी करार दिया। 30 जनवरी को सजा सुनाई जाएगी। फैसले के बाद बच्ची के पिता और चाचा ने खुशी जाहिर की, लेकिन इसमें देरी पर दुख भी जताया। पिता ने कहा कि मैं चाहता हूं कि दोषियों को अदालत फांसी की सजा सुनाए। (पेज-5)

सीएए से बच नहीं सकते राज्य : सिब्बल

बेजा विरोध ▶ कहा, संसद से पास कानून को ना कहना असंवैधानिक, खड़ी हो सकती हैं मुश्किलें

केरल, बंगाल समेत कांग्रेस शासित राज्य कानून लागू करने से कर रहे इन्कार

कोझिकोड, प्रेट्र : नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) को लागू करने से इन्कार करने वाले राज्यों को कांग्रेस नेता और पूर्व कानून मंत्री कपिल सिब्बल ने आईना दिखाया है। सिब्बल ने कहा है कि संसद से पारित नागरिकता संशोधन कानून को कोई राज्य लागू करने से मना नहीं कर सकता है। ऐसा करना न सिर्फ असंवैधानिक होगा, बल्कि आगे मुश्किलें भी खड़ी हो सकती हैं। कांग्रेस नेता का यह बयान कांग्रेस शासित पंजाब के सीएए के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव पारित करने के एक दिन बाद आया है। केरल पहले ही इस कानून को लागू नहीं करने के संबंध में विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर चुका है। उसने सुप्रीम कोर्ट में भी इसे चुनौती दी है।

सिब्बल का यह बयान इसलिए भी अहम है क्योंकि खुद उनकी पार्टी सीएए का विरोध कर रही है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने इसे वापस लेने की मांग की है। जबकि, बंगाल, महाराष्ट्र समेत कांग्रेस शासित राज्यों-मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ ने भी कहा है कि वो अपने यहां सीएए के साथ ही राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) लागू नहीं करेंगे।

केरल लिटरेचर फेस्टिवल (केएलएफ) में तीसरे दिन शनिवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री सिब्बल ने कहा, 'यदि सीएए पास हो गया है तो कोई राज्य यह नहीं कह सकता है कि 'मैं इसे लागू नहीं करूंगा।' यह संभव नहीं है और यह असंवैधानिक भी है। आप इसका विरोध कर सकते हैं, आप विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर सकते हैं और केंद्र सरकार से इसे वापस लेने को कह सकते हैं।' सिब्बल ने आगे कहा, 'लेकिन संवैधानिक रूप से यह कहना कि मैं इसे लागू नहीं करूंगा, अधिक समस्याएं पैदा कर सकता है।' पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि एनआरसी एनपीआर पर आधारित है। एनपीआर स्थानीय रजिस्ट्रार द्वारा लागू किया जाएगा, जिसे राज्य सरकारें नियुक्त करती हैं। ऐसे में राज्य सरकारें ज्यादा से ज्यादा यह तो कह सकती हैं कि वो केंद्र सरकार की मदद के लिए अपने अधिकारी को नहीं लगाएंगी। लेकिन व्यवहारिक रूप में ऐसा संभव है या नहीं उसको लेकर वह कुछ निश्चित नहीं कह सकते।

सीएए को लेकर चल रहे विरोध पर कांग्रेस नेता ने कहा कि देश में लोग विकास चाहते हैं, लेकिन मोदी सरकार क्या कर रही है? वह देश का विकास करने की बजाय अपना विकास कर रही है।

सीएए रैली में सिब्बल ने पीएम मोदी पर किया हमला : केरल लिटरेचर फेस्टिवल में सीएए पर राज्यों को आईना दिखाने के बाद कपिल सिब्बल इस कानून के विरोध में आयोजित रैली में पहुंचे तो पूरी तरह से कांग्रेसी नजर आए। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार सीएए पर झूठ फैला रही है। प्रधानमंत्री मोदी देश की समस्याओं को सुलझाने की जगह पाकिस्तान को लेकर सपने देख रहे हैं। सिब्बल ने कहा कि प्रधानमंत्री सुबह उठते हैं तो पाकिस्तान की बात करते हैं। संसद में बोलते हैं तो पाकिस्तान को लेकर बात करते हैं। वह पूरी तरह से भारत को भूल गए हैं।

कपिल सिब्बल। फाइल

आरिफ ने कहा-राज्यों को लागू करना ही पड़ेगा सीएए

जयपुर : केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने शनिवार को कहा कि सीएए राज्य सूची का नहीं, बल्कि केंद्रीय सूची का विषय है। यही कारण है कि राज्यों को इसे लागू करना ही होगा। उनके पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। इसे अनुच्छेद-254 के तहत लागू करना जरूरी है। (पेज-3)

अमित शाह की राहुल को नसीहत, पूरा पढ़ें सीएए

बेंगलुरु : केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को सीएए का विरोध करने वालों को दलित विरोधी बताते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी को पूरा कानून पढ़ने की नसीहत दी। उन्होंने राहुल को चुनौती दी कि वह साबित करें कि सीएए भारतीय मुस्लिमों से नागरिकता छीन लेगा। (पेज-3)

नागरिकता सिर्फ हक नहीं, कर्तव्य से भी जुड़ा है : सीजेआइ बोबडे पेज>>3
सीएए पर सस्ती राजनीति (संपादकीय पेज पर आलेख) पेज>>8

यूनिटेक के अधूरे प्रोजेक्ट पूरे करेगी केंद्र सरकार

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

वित्तीय संकट में फंसी रियल एस्टेट कंपनी यूनिटेक की अधूरी परियोजनाओं के मामले में सरकार नजीर बनने वाला कदम उठाने की तैयारी में है। कंपनी का प्रबंधन हाथ में लेने के बाद सरकार की योजना अब जल्द से जल्द इस कंपनी की अधूरी आवासीय व कमर्शियल परियोजनाओं को पूरा करने की है। सोमवार को सरकार की तरफ से इस बारे में विस्तृत मसौदा सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट में सरकार की ओर से पेश किया जाने वाला मसौदा बेशक यूनिटेक से जुड़ा है, लेकिन इसके बड़े निहितार्थ हैं। प्रस्ताव पर कोर्ट की मुहर लगने के बाद रियल एस्टेट सेक्टर की अधूरी पड़ी 1,600 परियोजनाओं के लिए भी नया रास्ता खुल सकता है। सरकार की मंशा स्पष्ट है कि यूनिटेक के मामले को अन्य रियल एस्टेट कंपनियों के लिए एक नजीर के तौर पर पेश किया जाए। इस दिशा में यूनिटेक के बाद सरकार जेपी समूह की अटकी परियोजनाओं पर कदम उठा सकती है। कंपनी मामलों का मंत्रालय अभी जेपी समूह को लेकर नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) के फैसले का इंतजार कर रहा है। सब ठीक रहा तो जेपी समूह की परियोजनाओं में बुकिंग कराने वाले ग्राहकों को राहत देने का भी एलान जल्द किया जाएगा। सरकार के प्रस्ताव के मुताबिक यूनिटेक में सरकार अपनी ओर से कोई पैसा नहीं लगाएगी, बल्कि अधूरी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए बैंकों से ऋण लिया जाएगा।

होम बायर्स की उम्मीदें

- हाउसिंग सेक्टर के 1600 अटके प्रोजेक्ट के पूरा होने की बढ़ी आस
- सुप्रीम कोर्ट में 20 जनवरी को सरकार पेश करेगी मसौदा

नोएडा सेक्टर-117 स्थित यूनिटेक यूनिहोम्स सोसाइटी। जागरण आर्काइव

ग्राहकों से बकाया राशि की वसूली की जाएगी पेज>>5

न्यूज गैलरी

राज-नीति ▶ पृष्ठ 3

रेलमंत्री ने फिर कहा, नहीं होगा रेलवे का निजीकरण

नई दिल्ली : रेलमंत्री पीयूष गोयल ने एक बार फिर आश्वस्त किया है कि रेलवे का निजीकरण नहीं होगा। रेलवे यूनियनों के प्रतिनिधियों से बातचीत में गोयल ने कहा, मैं संसद से लेकर अलग-अलग मंचों पर यह स्पष्ट कर चुका हूं कि रेलवे का कभी निजीकरण नहीं किया जाएगा।

नेशनल न्यूज ▶ पृष्ठ 6

कार दुर्घटना में शबाना आजमी घायल, हालत स्थिर

मुंबई : फिल्म अभिनेत्री शबाना आजमी की टाटा सफारी कार शनिवार शाम मुंबई-पुणे एक्सप्रेस हाईवे पर खालापुर टोल नाके पास ट्रक से भिड़ गई। इस हादसे में शबाना को काफी चोटें आई हैं। बताते हैं कि वहां मौजूद स्थानीय लोगों ने उन्हें कार से निकालने में मदद की।

बिजनेस ▶ पृष्ठ 12

तेल आयात पर रूस से बड़े समझौते की तैयारी

नई दिल्ली : भारत अपनी जरूरत का तकरीबन 60 प्रतिशत तेल खाड़ी के देशों से आयात करता रहा है। लेकिन इस क्षेत्र के हालात रह-रह कर जिस तरह अनिश्चित हो जाते हैं, उसे देखते हुए भारत अब तेल के दूसरे विश्वसनीय स्रोतों की तलाश करने लगा है।

अंतरराष्ट्रीय ▶ पृष्ठ 13

अमेरिका-तालिबान में इसी माह हो सकता है समझौता

काबुल : अफगानिस्तान में 19 साल से जारी खूनी संघर्ष के खत्म होने के आसार बढ़ गए हैं। तालिबान ने कहा कि अमेरिका के साथ जनवरी के आखिर तक समझौते पर हस्ताक्षर करने का लक्ष्य है।

बराबरी का मुकाबला
तीसरा वनडे
भारत 28 ऑस्ट्रेलिया
दोपहर 1:30 बजे से
स्थान : बेंगलुरु
प्रसारण : स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क

ब्रिटेन से मंगलवार तड़के भारत लाया जा सकता है सट्टेबाज संजीव चावला

नई दिल्ली, आइएएनएस : क्रिकेट पर सट्टा लगाने वाले गिरोह के सरगना संजीव चावला को ब्रिटेन से मंगलवार तड़के भारत लाया जा सकता है। उम्मीद की जा रही है कि चावला को भारत प्रत्यर्पित करने पर ब्रिटेन का गृह मंत्रालय सोमवार को आखिरी फैसला ले लेगा। दिल्ली पुलिस के उच्चपदस्थ सूत्रों ने शनिवार को यह जानकारी दी।

ब्रिटिश हाई कोर्ट के दो जजों की पीठ ने प्रत्यर्पण के खिलाफ चावला की याचिका गुरुवार को खारिज कर दी थी। उसके बाद हाई कोर्ट ने अंतिम फैसला लेने के लिए गृह मंत्रालय के पास अपने फैसले की कॉपी भेज दी है। लंदन में रहने वाला व्यवसायी संजीव चावला 1990 के बाद के वर्षों में डी-कंपनी (दाऊद गिरोह) के लिए क्रिकेट मैचों पर सट्टा लगाने लगा था। चावला दक्षिण अफ्रीका, भारत, पाकिस्तान और अन्य देशों के खिलाड़ियों के साथ मिलकर क्रिकेट मैच फिक्स करता था, जबकि डी कंपनी का काम सट्टे के पैसे का बिना विवाद बंटवारा कराना था। भारत और ब्रिटेन के बीच 1992 में प्रत्यर्पण संधि हुई थी। उसके बाद से चावला दूसरा वांछित होगा, जिसे भारत लाया जाएगा। दिल्ली पुलिस के डीसीपी-क्राइम राम गोपाल नाइक अपनी टीम के साथ लंदन में हैं। गृह मंत्रालय से मंजूरी मिलते ही उनकी टीम चावला को अपनी हिरासत में ले लेगी।

दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच के अधिकारी ने कहा कि हाई कोर्ट ने पहले ही चावला के प्रत्यर्पण की मंजूरी दे दी है। अब कुछ औपचारिकताएं पूरी की जानी हैं। उम्मीद है कि सोमवार दोपहर तक प्रत्यर्पण आदेश दिल्ली पुलिस की टीम को मिल जाएगा। चावला को 19 साल बाद भारत लाया जा रहा है, लेकिन दिल्ली में उससे पूछताछ क्रिकेट की दुनिया के कई बड़े नामों को लेकर सनसनीखेज रहस्योद्घाटन कर सकती है।

खुलेंगी फिक्सिंग की परतें

- ब्रिटिश हाई कोर्ट प्रत्यर्पण के खिलाफ याचिका कर चुका है खारिज
- सोमवार को आखिरी फैसला ले सकता है ब्रिटेन का गृह मंत्रालय

टिकट बेचने का आरोप लगाकर योगानंद शास्त्री ने छोड़ी कांग्रेस

नई दिल्ली : शीला दीक्षित सरकार में मंत्री व विस अध्यक्ष रहे डॉ. योगानंद शास्त्री ने प्रदेश अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा के साथ मतभेदों का हवाला देते हुए कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। उनका कहना है कि उन्होंने कार्यकर्ताओं की उपेक्षा से व्यथित होकर कांग्रेस के प्रभारी पीसी चाको को इस्तीफा भेज दिया है। शास्त्री ने विस चुनाव के मद्देनजर प्रदेश कांग्रेस के कुछ नेताओं पर टिकट बेचने का आरोप भी लगाया है। (पेज-2)

वामदलों के पाखंड से हिंदुत्ववादी ताकतें मजबूत हुईं : गुहा

बेंगलुरु : भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कट्टर आलोचक और जाने-माने इतिहासकार रामचंद्र गुहा ने वामपंथी दलों को निशाने पर लिया है। गुहा का कहना है कि वामदलों के पाखंड के चलते ही देश में हिंदुत्ववादी ताकतों को मजबूती मिली है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी में नेतृत्व करने की क्षमता नहीं है। हालांकि, राहुल को लेकर दिए बयान पर विवाद होने पर शनिवार को उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि उनके बयान के कुछ हिस्से को ही उठाया गया। (पेज-4)

सावरकर पर शिवसेना-कांग्रेस में महाभारत

ओमप्रकाश तिवारी, मुंबई

वीर सावरकर को लेकर शिवसेना और कांग्रेस के बीच बयानबाजी का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। शनिवार को शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि जो लोग सावरकर को भारत रत्न देने का विरोध कर रहे हैं, उन्हें दो दिन के लिए अंडमान के सेल्युलर जेल भेज दिया जाना चाहिए। तभी उनको पता चलेगा कि सावरकर ने कितना बड़ा बलिदान किया है।

राउत के बयान पर तंज कसते हुए महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रवक्ता सचिन सावंत ने कहा कि वह सेल्युलर जेल में रह चुके ऐसे स्वतंत्रता सेनानी को भारतरत्न दिया जाना पसंद करेंगे, जिसने अंग्रेजों से माफी न मांगी हो। ऐसे स्वतंत्रता सेनानी के रूप में उन्होंने योगेश शुक्ल का नाम भी सुझाया है, जो सेल्युलर जेल में रहने के बाद महात्मा गांधी के साथ काम करते रहे। सावंत का कहना है कि 1911 से पहले के सावरकर अलग थे। लेकिन कांग्रेस 1923 के बाद वाले सावरकर का विरोध करती है, जब वह ब्रिटिश सरकार को माफीनामा देकर जेल से छूटे।

हालांकि, महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट मंत्री आदित्य ठाकरे इतिहास की छोड़ वर्तमान के मुद्दों पर बात करने की सलाह दे रहे हैं। शनिवार को वे यह कहते भी नजर आए कि उन्हें नहीं मालूम कि राउत ने किस हैसियत से यह बयान दिया है।

बताते चलें कि शिवसेना और भाजपा दोनों ही सावरकर को भारतरत्न देने की समर्थक रही हैं। लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव के बाद दोनों की राहें अलग हो चुकी हैं। अब शिवसेना अपने विचारों की धुर विरोधी कांग्रेस एवं राकांपा के साथ मिलकर महाराष्ट्र में सरकार बना चुकी है। लेकिन, कांग्रेस-शिवसेना में वैचारिक टकराव थमने का नाम नहीं ले रहा है। पार्टी के वरिष्ठ नेता वैचारिक मुद्दों पर पहले से चली आ रही नीति से अलग हटने को तैयार नहीं हैं। बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी कई बार सावरकर की देशभक्ति पर सवाल उठा चुके हैं। इससे पहले राहुल ने कहा था कि मेरा नाम राहुल गांधी है, राहुल सावरकर नहीं। इस पर इस पर राउत ने कहा था कि हिंदुत्व विचारक के प्रति श्रद्धा को लेकर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। हम महात्मा गांधी और पंडित नेहरू का सम्मान करते हैं। कृपया वीर सावरकर का अपमान न करें।

- संजय राउत ने किया हमला, कहा-दो दिन अंडमान जेल में रहें, तब सावरकर को समझेंगे
- कांग्रेस का पलटवार, उन स्वाधीनता सेनानियों के बलिदान को समझें जो अंग्रेजों के आगे नहीं झुके

महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने शनिवार को कोल्हापुर स्थित महालक्ष्मी मंदिर में पूजा-अर्चना की। प्रेट्र

फडनवीस बोले, सावरकर के विचार हमेशा प्रासंगिक रहेंगे पेज>>6

वापसी की उम्मीद

अनुच्छेद 370 समाप्त होने के बाद बदले हालात में मोदी सरकार से बढ़ीं कश्मीरी पंडितों की आशाएं, अगले वर्ष निर्वासन की बरसी नहीं, मनाना चाहते हैं घर वापसी का जश्न, वादी में अलग-अलग जगह नहीं एक जगह पर पुनर्वास की मांग

खौफनाक त्रासदी के 30 साल : गम, गुस्से और आस की कहानी

नवीन नवाज, जम्मू

कट्टरवाद की जड़ अनुच्छेद 370 समाप्त हो चुका है। नए जम्मू-कश्मीर के उदय के साथ विकास और खुशहाली की नई इबारत लिखने की कोशिश हो रही है। बदलते हालात के बीच बीते 30 साल में पहली बार विस्थापित कश्मीरी पंडितों को घाटी में अपनी सम्मानजनक वापसी की उम्मीद जगी है। यही कारण है कि शनिवार को सोशल मीडिया पर शिकारा फिल्म का डायलॉग 'हम वापस आएंगे' ट्रेंड करता रहा। अपने ही घर में शरणार्थी बने पंडितों का कहना है कि केंद्र की मोदी सरकार ने जो संकल्पशक्ति जम्मू-कश्मीर को लेकर दर्शायी है वैसी ही उनके मुद्दों को हल करने के लिए भी कायम रहती है तो शायद ही कोई कश्मीरी विस्थापित अगले साल इस निर्मम त्रासदी की बरसी मनाए। हम उम्मीद कर रहे हैं कि अगले साल इस दिन घर वापसी का जश्न मनाएं।

कश्मीर में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकी संगठन जम्मू-कश्मीर लिबरेशन फ्रंट (जेकेएलएफ) और हिजबुल मुजाहिदीन समेत विभिन्न संगठनों ने 1988 में धीरे-धीरे अपनी गतिविधियां बढ़ानी शुरू कीं और 1990 की शुरुआत में हालात इस कदर बिगड़ गए कि रातों-रात कश्मीरी पंडितों को अपने घर छोड़कर जम्मू समेत देश के विभिन्न हिस्सों में शरण लेनी पड़ी। इसके बाद से ही कश्मीरी पंडित हर साल 19 जनवरी को निर्वासन दिवस मनाते हुए अपने साथ हुए अत्याचार की ओर देश और दुनिया का ध्यान दिलाते हैं।

कश्मीरी पंडित तीन दशक से देश-विदेश में विभिन्न मंचों पर अपने लिए इंसाफ मांग रहे हैं। हालांकि केंद्र सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में कश्मीरी पंडितों की कश्मीर वापसी के लिए कई कॉलोनियां बनाने के साथ उनके लिए रोजगार पैकेज का भी एलान किया, इसके बावजूद साल 2015 तक सिर्फ एक ही परिवार कश्मीर वापसी पैकेज के तहत श्रीनगर लौटा था। प्रधानमंत्री पैकेज के तहत रोजगार पाने वाले भी ट्रांजिट कॉलोनियों में ही सिमट कर रह गए हैं। पांच अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 हटने के बाद विस्थापित कश्मीरी पंडितों में भी उम्मीद की एक नई किरण जगी है।

चुरुंगु बोले-अगर अब कुछ नहीं हुआ तो कभी नहीं होगा : पनुन कश्मीर के चेयरमैन डॉ. अजय चुरुंगु कहते हैं कि अनुच्छेद 370 और 35ए जम्मू-कश्मीर को पंथनिरपेक्ष भारत में एक लघु इस्लामिक राज्य का दर्जा देते थे। अब यह समाप्त हो चुका है। अब जम्मू-कश्मीर पंथनिरपेक्ष भारत का एक पूर्ण हिस्सा है। जेकेएलएफ और जमात-ए-इस्लामी पर भी पाबंदी लग चुकी है। इसलिए अब हमें अपनी वापसी की उम्मीद है। केंद्र सरकार को चाहिए वह रिवर्सल ऑफ जिनोसाइड करे, पंडितों की पूरे देश में निष्पक्ष जनगणना होनी चाहिए। कश्मीर में एक अलग शहर होना चाहिए, उन्हें होमलैंड चाहिए। अगर अब कुछ नहीं हुआ तो कभी नहीं होगा।

'हम वापस आएंगे' बना कैंपेन

'हम आएंगे अपने वतन और यहीं पर दिल लगाएंगे, यहीं मरेंगे और यहीं के पानी में हमारी राख बहाई जाएगी'। दरअसल, यह डायलॉग विधु विनोद चोपड़ा की आने वाली फिल्म शिकारा का है। इस फिल्म में बताया गया कि कश्मीरी पंडितों का कैसे पलायन हुआ और उन्हें कितनी पीड़ा सहनी पड़ी। 'हम वापस आएंगे' का डायलॉग अब सोशल मीडिया पर एक कैंपेन बन गया है, जो कि शनिवार को पूरे दिन देश में ही नहीं, विदेशों में भी ट्विटर पर ट्रेंड करता रहा।' युवा कश्मीरी पंडित तो भावुक पोस्ट भी कर रहे हैं।

सियासत भी कम होने के आसार पेज>>5
विस्थापन के तीस साल की दुखभरी दास्तां पेज>>6
कश्मीरी पंडितों की उम्मीद (विचार) पेज>>8

ईडी ने जब्त कीं भूषण स्टील के पूर्व सीएमडी की 204 करोड़ की संपत्तियां

नई दिल्ली, प्रेट्र : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड (बीपीएसएल) के पूर्व चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) संजय सिंघल की 204 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्तियां जब्त कर ली हैं। इनमें उनके दिल्ली और लंदन स्थित आवास भी शामिल हैं।

ईडी ने शनिवार को एक बयान जारी कर बताया कि यह जब्ती मनी लांड्रिंग रोधी कानून के तहत की गई। बयान के अनुसार, 'संजय सिंघल ने बीपीएसएल को मिले बैंक ऋण में से 204.31 करोड़ रुपये की राशि में हेरफेर किया और इसका उपयोग देश एवं विदेश में संपत्तियां खरीदने में किया।' ईडी ने शुक्रवार को मनी लांड्रिंग कानून से जुड़ी विशेष अदालत में यहां सिंघल एवं अन्य के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था। आरोप पत्र में 24 लोगों और कंपनी को आरोपित बनाया गया है। अदालत ने सिंघल के खिलाफ 21 जनवरी के लिए पेशी वारंट जारी किया है। ईडी ने पिछले साल नवंबर में सिंघल को गिरफ्तार किया था, तब से वह न्यायिक हिरासत में है। जांच एजेंसी का आरोप है कि कंपनी ने 2007 से 2014 के दौरान 33 बैंक और वित्तीय संस्थानों से लिए ऋण में से बड़े हिस्से का हेरफेर किया है। ईडी इस मामले में अब तक 4,229 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त कर चुका है। ईडी ने आरोपित के खिलाफ सीबीआइ की एफआइआर के आधार पर मनी लांड्रिंग कानून के तहत मामला दर्ज किया है।

संजय सिंघल। फाइल

26 जनवरी के बाद आएगा आम आदमी पार्टी (आप) का चुनावी घोषणा पत्र। इस बार प्रदूषण, यमुना सफाई, परिवहन आदि पर प्रमुख रूप से होगी बात।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
रविवार 19 जनवरी 2020

कांग्रेस की पहली सूची में 54 सीटों पर प्रत्याशी घोषित

रणनीति ▸ पार्टी ने पुराने के साथ ही नए चेहरों पर भी जताया विश्वास, 10 महिलाओं को भी चुनाव के मैदान में उतारा गया

चांदनी चौक से अलका लांबा को दिया मौका, सिसोदिया के खिलाफ लक्ष्मण सिंह रावत

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

आगामी आठ फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने शनिवार देर रात 54 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी। इस सूची में पार्टी ने पुराने चेहरों के साथ-साथ कुछ नए उम्मीदवारों को भी मौका दिया है। उम्मीदवारों के चयन को लेकर शनिवार सुबह पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति (सीईसी) की बैठक भी हुई। इससे पहले शुक्रवार को भी सीईसी की बैठक हुई थी। बैठक में 70 सीटों में से 54 उम्मीदवारों के नाम पर सहमति बनी। पहली सूची में 10 महिलाओं को भी चुनाव मैदान में उतारा गया है।

शुक्रवार रात जारी हुई सूची में कांग्रेस ने चांदनी चौक से अलका लांबा को मौका दिया है, जबकि इसी सीट से पूर्व सांसद जेपी अग्रवाल के चुनाव लड़ने की खबरें भी खूब चली थीं। वह कुछ माह पूर्व ही आप से कांग्रेस में शामिल हुई थीं। वहीं उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ पटपड़गंज से कांग्रेस ने लक्ष्मण सिंह रावत पर भरोसा जताया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की के खिलाफ नई दिल्ली सीट से अब तक किसी उम्मीदवार का चयन नहीं हो पाया। आप छोड़ शनिवार को ही कांग्रेस में शामिल हुए आदर्श शास्त्री को भी द्वारका से उम्मीदवार बनाया गया है। भाजपा छोड़ कर आए कीर्ति आजाद की पत्नी पूनम झा को संगम विहार से टिकट दिया गया है। प्रदेश अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा की बेटी शिवानी चोपड़ा कालकाजी से मैदान में हैं। यह सीट सुभाष चोपड़ा की ही मानी जाती रही है। अब 16 सीटों पर घोषणा होनी बाकी है। इनमें से चार सीटें गठबंधन के तहत राष्ट्रीय जनता दल (राजद) को दे दी गई हैं। बाकी 12 सीटों पर मंथन जारी है। प्रदेश अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा और दिल्ली प्रभारी पीसी चाको के मुताबिक, पार्टी ने उम्मीदवारों के चयन में हर वर्ग को महत्व दिया है।

कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में आदर्श शास्त्री (दाएं से दूसरे) प्रवक्ता मुकेश शर्मा (बाएं से), प्रदेश अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा और दिल्ली प्रभारी पीसी चोको (दाएं) की मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल हुए। जागरण

आप विधायक आदर्श शास्त्री ने थामा कांग्रेस का हाथ

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

टिकट कटने से नाराज आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक आदर्श शास्त्री ने शनिवार शाम समर्थकों के साथ कांग्रेस का हाथ थाम लिया। प्रदेश अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा व दिल्ली प्रभारी पीसी चाको ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस अवसर पर आदर्श ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर 10 से 20 करोड़ रुपये में विधानसभा की टिकटें बेचने का आरोप लगाया। उन्होंने यह भी कहा कि केजरीवाल तानाशाह हैं और उनका लोकतंत्र में कोई विश्वास नही है।

शास्त्री ने कहा कि केजरीवाल ने हमेशा विधायकों के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई है। उन्होंने अपना अनुभव बताते हुए कहा कि जब मैने एपल कंपनी से नौकरी छोड़ी तो सोचा था कि एक ईमानदार व्यक्ति दिल्ली की राजनीति को बदलेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि आप के राज्यसभा के दो सदस्य टिकटों की खरीद-फरोख्त को अंजाम दे रहे हैं। यही नहीं दिल्ली नगर निगम के टिकट वितरण के दौरान भी खरीद-फरोख्त हुई थी। शास्त्री ने केजरीवाल पर हमला जारी रखते हुए कहा कि उन्होंने नागरिकता संशोधन विधेयक, जामिया व जेएनयू में छात्रों की पिटाई के मामले में उनके आग्रह के बाद भी स्पष्ट रूप से मुखर होकर बोलने से इन्कार कर दिया था। इससे वह आहत हैं। उन्होंने कहा कि केजरीवाल वोट बैंक की राजनीति करने वाले गैर जिम्मेदार मुख्यमंत्री हैं, जो संवेदनशील मामलों में हमेशा चुप रहते हैं।

चोपड़ा ने आदर्श शास्त्री की घर वापसी का स्वागत करते हुए कहा कि आप पूरी तरह बेनकाब हो चुकी है और यह साबित हो गया है कि भ्रष्टाचार को मिटाने, स्वराज व लोकपाल के नाम पर दिल्ली की सत्ता में आए केजरीवाल खुद ही भ्रष्टाचार का प्रतीक बन गए हैं। इस पार्टी के पास आज कार्यकर्ता नाम की कोई चीज नहीं है। चाको ने कहा कि आदर्श शास्त्री के शमिल होने से पार्टी और मजबूत होगी। इस मौके पर मुख्य प्रवक्ता मुकेश शर्मा और पूर्व विधायक नसीब सिंह भी मौजूद थे।

पूर्व विधान सभा अध्यक्ष योगानंद शास्त्री ने छोड़ी कांग्रेस

▸ पार्टी के समर्पित कार्यकर्ताओं की उपेक्षा का लगाया आरोप

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

शीला दीक्षित सरकार में मंत्री और विधानसभा अध्यक्ष रहे डॉ. योगानंद शास्त्री ने प्रदेश अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा के साथ वैचारिक मतभेदों का हवाला देते हुए शनिवार को कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। उनका कहना है कि उन्होंने पार्टी के समर्पित कार्यकर्ताओं की उपेक्षा से व्यथित होकर कांग्रेस के प्रभारी पीसी चाको को इस्तीफा भेज दिया है। शास्त्री ने विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रदेश कांग्रेस के कुछ नेताओं पर टिकट बेचने का आरोप भी लगाया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश कांग्रेस की कमान ऐसे व्यक्ति के पास है जो किसी का सम्मान नहीं करता है। साथ ही ऐसे लोगों से घिरा है जो विधानसभा चुनाव के टिकट बेचने में लिप्त हैं।

वहीं, सुभाष चोपड़ा और चाको ने शास्त्री का इस्तीफा मिलने से इन्कार किया। चाको ने कहा कि उनके पास ऐसी कोई सूचना नहीं है और न ही उनका इस्तीफा मिला है। चोपड़ा ने कहा कि योगानंद शास्त्री हमारे वरिष्ठ नेता हैं। उन्हें नहीं पता है कि उन्होंने इस्तीफा दिया है। टिकट बेचने के आरोप पर सुभाष का कहना था कि पार्टी में टिकट पाने वालों की लंबी कतार है। छोटी-मोटी नाराजगी हो सकती है, लेकिन कांग्रेस ने जिस तरीके से पिछले महीनों में संघर्ष किया है, उससे दिल्ली की जनता प्रभावित है।

पार्टी सूत्रों का कहना है कि महरौली विधानसभा सीट से टिकट नहीं मिलने की आशंका से योगानंद शास्त्री नाराज चल रहे थे। वहीं पार्टी उनकी बेटी प्रियंका सिंह को आरके पुरम से उम्मीदवार बनाने को तैयार है और दोनों को टिकट देने के पक्ष में नहीं है।

भाजपा में टिकट बंटवारे के बाद शुरू हुआ विरोध

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : भाजपा प्रत्याशियों की पहली सूची आने के बाद विरोध भी शुरू हो गया है। गांधीनगर व मंगोलपुरी से कार्यकर्ताओं ने प्रदेश भाजपा कार्यालय पहुंचकर विरोध जताया। वहीं, पूर्व विधायक करण सिंह तंवर को दिल्ली कैंट से टिकट देने की मांग करते हुए उनके समर्थकों ने भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर के बाहर प्रदर्शन किया। आप से भाजपा में शामिल हुए पूर्व विधायक अनिल वाजपेयी को भाजपा ने गांधीनगर से टिकट दिया है। पार्टी के कई नेता उनकी उम्मीदवारी का विरोध कर रहे हैं। टिकट कटने से नाराज नेताओं के समर्थकों ने दिल्ली प्रदेश भाजपा कार्यालय पहुंचकर वाजपेयी को प्रत्याशी बनाए जाने का विरोध किया। उन्होंने पार्टी से इस्तीफे का भी एलान किया। उनका कहना था कि वर्षों से पार्टी के लिए काम करने वाले कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज कर दूसरी पार्टी से आने वाले को टिकट देना गलत है। मंगोलपुरी से पार्टी ने करम सिंह कर्मा को टिकट दिया है। इसके विरोध में कुछ लोगों ने पार्टी कार्यालय पहुंचकर रोष जताया।

13 सीटों पर अब तक पार्टी ने प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है, लेकिन इन सीटों को लेकर भी नेताओं के समर्थक व विरोधी प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली कैंट से पूर्व विधायक करण सिंह तंवर दावेदारी जता रहे हैं। उन्हें टिकट खतरे में दिख रहा है, इसलिए उनके समर्थकों ने नड्डा के निवास के बाहर प्रदर्शन किया। इसी तरह से नांगलोई जाट से पूर्व विधायक मनोज शौकीन टिकट की दौड़ में शामिल बताए जाते हैं। उनकी समर्थक कई दिनों से प्रदेश कार्यालय पहुंचकर विरोध जता रहे हैं।

चुनावी हलचल

आज नहीं होगा नामांकन, आखिरी दो दिन में रहेगी भीड़

नई दिल्ली : विधानसभा चुनाव के लिए रविवार को उम्मीदवारों का नामांकन नहीं हो पाएगा। इसके बाद नामांकन के लिए सिर्फ दो दिन शेष रह जाएंगे। इसलिए आखिरी के दो दिन में निर्वाचन अधिकारियों के कार्यालयों में नामांकन भरने के लिए उम्मीदवारों की भीड़ बढ़ेगी। 21 जनवरी नामांकन के लिए आखिरी तारीख है। इस तरह अब सोमवार व मंगलवार को उम्मीदवार अपना पर्चा भर सकेंगे। हालांकि रविवार को सभी निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय खुले रहेंगे, लेकिन अधिकारी चुनाव से जुड़ी दूसरी तैयारियों में व्यस्त रहेंगे। इसलिए साप्ताहिक अवकाश के दिन नामांकन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। (जासं)

आतिशी ने क्राउड फंडिंग से जुटाए 4.5 लाख रुपये

नई दिल्ली : आम आदमी पार्टी से कालका जी विस सीट की उम्मीदवार आतिशी ने चुनाव के लिए क्राउड फंडिंग की शुरुआत की। इसमें उन्हें देश के कई मशहूर लोगों का समर्थन मिला। आतिशी ने शुक्रवार को शाम 7.30 बजे दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए एक क्राउड फंडिंग अभियान शुरू किया। अभियान शुरू होने के 12 घंटे के भीतर आतिशी का क्राउड फंडिंग अभियान 4.5 लाख को पार कर गया। 100 से अधिक समर्थकों के दान में 100 से 50,000 रुपये तक की राशि शामिल है। (जासं)

बसपा ने उतारे 42 प्रत्याशी एनडी को बदरपुर से टिकट

नई दिल्ली : दिल्ली विस चुनाव के लिए बसपा ने 42 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। इसमें आप के बदरपुर से बागी विधायक नरायण दत्त शर्मा (एनडी) को बदरपुर से टिकट दिया गया। आप ने यहां कांग्रेस छोड़ कर आप में शामिल हुए पूर्व विधायक राम सिंह नेताजी को प्रत्याशी बनाया था। शर्मा ने निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा की थी। रामसिंह नेताजी बसपा के टिकट पर ही बदरपुर सीट से 2008 में विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं। बसपा के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह ने कहा कि अन्य सीटों पर भी प्रत्याशियों की जल्द घोषणा की जाएगी। (जासं)

'हमने स्कूलों को दुकान नहीं बनने दिया'

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि अरविंद केजरीवाल सरकार ने निजी स्कूलों को मुनाफे की दुकान बनने से रोका है। मनमानी फीस बढ़ाने से तो उन्हें रोका ही, साथ ही शिक्षा की बेहतरी के लिए भी कई कदम उठाए। उन्होंने कहा कि भाजपा और कांग्रेस शासित प्रदेशों में हर साल निजी स्कूलों ने मनमाने तरीके से फीस में वृद्धि की, इससे अभिभावकों पर अतिरिक्त बोझ पड़ा। सिसोदिया ने दिल्ली के शिक्षा मॉडल और अन्य प्रदेशों के शिक्षा मॉडल से जुड़े तथ्यों को भी रखा।

पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि जो आकलन किया गया है। उसके अनुसार 2015 से पहले हर साल लगभग 12 फीसद से लेकर 15 फीसद तक प्राइवेट स्कूलों की फीस बढ़ाई जाती थी। इस तरह 5 साल में करीब 75 फीसद फीस बढ़ जाती थी। 2015-16 में जब आप की सरकार बनी उस साल इन 350 प्राइवेट स्कूलों ने 8 फीसद से लेकर 15 फीसद तक फीस बढ़ाई थी।

आप कार्यालय में पत्रकारों से बात करते उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया। जागरण

क्योंकि सरकार के गठन के समय तक स्कूलों में एडमिशन प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी। 2016-17 में सभी स्कूलों को सरकार के साथ हुए करार का पालन करने को कहा गया। इसमें 334 स्कूलों में फीस नहीं बढ़ाने दी। कुछ स्कूलों को स्क्रूटनी के बाद 5 से 8 फीसद फीस वृद्धि की अनुमति दी गई। 2017-18 और 2018-19 में किसी भी स्कूल को फीस बढ़ाने की अनुमति नहीं दी गई। 2019-20 में 309 स्कूलों को फीस नही बढ़ाने दी गई। यही नहीं पिछले 4 साल में करीब 198 स्कूलों के द्वारा 32 करोड़ 10 लाख रुपये की अतिरिक्त बढ़ाई गई फीस 78 हजार विद्यार्थियों को वापस करवाई गई।

पिछले 5 सालों में दिल्ली सरकार ने स्कूलों को मुनाफे की दुकान बनने से रोका। वहीं उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में आज भी मुनाफे की दुकान चल रही हैं। दिल्ली में लगभग 1700 निजी स्कूल हैं। लगभग 350 बड़े प्राइवेट स्कूल हैं, जिनमें एडमिशन के लिए भी बहुत मारामारी रहती है। इसमें 364 प्राइवेट स्कूल हैं, जो सरकारी जमीन पर बने हैं। 1970 के बाद इन स्कूलों को 1 रुपये की लीज पर जमीन आवंटित की गई थी। इसमें यह करार हुआ था कि निजी स्कूल सरकार की अनुमति से ही फीस बढ़ाएंगे। लेकिन, जमीन लेने के बाद किसी भी स्कूल ने करार कार पालन नहीं किया था, लेकिन आप ने इसके लिए निजी स्कूलों को मजबूर किया।

भाजपा आयोजित करेगी पांच हजार चुनावी सभाएं

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : भाजपा ने विधानसभा चुनाव में बड़ी रैलियों की जगह छोटी चुनावी सभाएं करने का फैसला किया है। उम्मीदवारों के नामांकन पत्र भरने के साथ ही छोटी चुनावी सभाओं का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। चुनाव प्रचार खत्म होने तक पूरी दिल्ली में पांच हजार चुनावी सभाएं आयोजित होंगी, जिनमें केंद्रीय नेताओं से लेकर प्रदेश के बड़े नेता शामिल होंगे। प्रधानमंत्री की भी दो से तीन चुनावी सभाएं आयोजित करने की तैयारी है।

बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने बड़ी रैलियों की जगह छोटी-छोटी सभाएं करके मतदाताओं तक पार्टी की बात पहुंचाने की सलाह दी थी। इस पर अमल करते हुए पार्टी के रणनीतिकारों ने चुनाव प्रचार अभियान तैयार कर लिया है। पिछले दिनों उम्मीदवारों का नाम तय करने के लिए केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में भी इसे लेकर चर्चा की गई थी। भाजपा नेताओं ने बताया कि 50 से अधिक स्टार प्रचारकों सहित लगभग एक सौ नेता चुनाव प्रचार में उतरेंगे।

वॉर रूम से आप रखेगी प्रचार अभियान पर नजर

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

आप ने विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान तेज कर दिया है। पार्टी ऑफिस में एक कंट्रोल वॉर रूम बनाया गया है। वहां से पूरे चुनाव प्रचार पर नजर रखी जा रही है। पार्टी की ओर से सभी संसदीय क्षेत्र में एक-एक पर्यवेक्षक की तैनाती की गई है।

इस वॉर रूम में चार सेक्शन बनाए गए हैं। इनमें सोशल मीडिया सेल, लीगल सेल, ग्राउंड कैंपेन सेल के साथ-साथ प्रचार को किस तरह लुभावना बनाया जाए, इसके लिए अलग से सेल बनाया गया है, जो इस पूरी प्रक्रिया का संचालन कर रहा है। सबसे मजबूत सोशल मीडिया व लीगल सेल को बनाया गया है। इसमें पांच-पांच लोगों की टीम बनाई गई है। ग्राउंड कैंपेन सेल प्रचार रैलियों का निरीक्षण करेगी। प्रमुख नेताओं की रैलियों और कार्यक्रमों की पूरी जानकारी रखेगी। वॉर रूम सभी विधानसभा क्षेत्रों की निगरानी भी करेगा। वार रूम में एक समय में 20 लोग तैनात रहेंगे। जैसे-जैसे चुनाव करीब आएगा, इसे और प्रभावी बनाया जाएगा। सोशल मीडिया सेल में उन वालंटियर्स को भी जिम्मेदारी दी गई है, जिन्होंने 2015 के विधानसभा चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसी तरह लीगल सेल में निचली अदालतों के वकीलों से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक के वकील लगाए गए हैं, जो प्रत्याशियों के नामांकन की भी जांच करते हैं। वार रूम का नेतृत्व कर रहे डायलॉग एवं डेवलपमेंट कमीशन ऑफ दिल्ली के उपाध्यक्ष जस्मिन शाह कहते हैं कि यहां सब कुछ व्यवस्थित तरीके से चल रहा है। सभी की जिम्मेदारी बंटी हुई हैं। दूसरे राज्यों से आ रहे अपने-अपने क्षेत्र के तकनीकी विशेषज्ञ वालंटियर्स को जिम्मेदारी दी जा रही है। चुनाव प्रचार के दौरान विभिन्न इलाकों में छोटे छोटे नुक्कड़ नाटक आदि कार्यक्रम दिखाई देंगे।

घुसपैठ पर होगा भाजपा का जोरदार वार

संतोष कुमार सिंह, नई दिल्ली

भाजपा का आरोप है कि नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) को लेकर दिल्ली सहित देशभर में विरोध-प्रदर्शन हो रहा है। इससे दबाव में आने के बजाय भाजपा दिल्ली में अवैध घुसपैठिये का मुद्दा भी जोरशोर से उठाएगी। लोगों को बताया जाएगा कि किस तरह से राजधानी की कानून व्यवस्था को लेकर घुसपैठिये खतरा बने हुए हैं। लोकसभा चुनाव में भी अवैध घुसपैठ को मुद्दा बनाया गया था और अब विधानसभा चुनाव में भी इसे धार देने की तैयारी है। पार्टी इस मुद्दे को जोरशोर से उठाकर राष्ट्रीय राजधानी में रह रहे बांग्लादेशी व रोहिंग्या घुसपैठियों के खिलाफ माहौल बनाएगी। इसके साथ ही इस मुद्दे पर आप व कांग्रेस को कठघरे में खड़ा करने की तैयारी है। भाजपा नेताओं का आरोप है कि दोनों पार्टियां राजनीतिक लाभ के लिए देश व राजधानी की सुरक्षा को खतरे में डाल रही हैं। वोट बैंक के लिए सीएए के नाम पर लोगों को गुमराह किया जा रहा है।

भाजपा बांग्लादेशी व रोहिंग्या घुसपैठियों को देश की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बताती रही है। उसका मानना है कि घुसपैठिये देश के भविष्य को दीमक की तरह चाट रहे हैं। बावजूद इसके कांग्रेस व आप सहित अन्य पार्टियां इनके समर्थन में खड़ी हैं। लोकसभा में भी भाजपा नेता इस मुद्दे को लेकर लोगों के बीच गए थे।

उनका कहना है कि घुसपैठिये आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा होने के साथ-साथ यहां के नागरिकों के लिए उपलब्ध संसाधनों पर भी बोझ हैं। वे यहां के युवकों का रोजगार हथिया रहे हैं और गरीबों का राशन खा रहे हैं। वर्षों से लाखों लोग अवैध रूप से राजधानी में रह रहे हैं।

> घुसपैठ दिल्ली सहित पूरे देश की बड़ी समस्या है। घुसपैठिये आपराधिक व आतंकी गतिविधियों में शामिल हैं। आप व कांग्रेस इन घुसपैठियों का सहारा लेकर सरकार बनाना चाहती हैं। यहां के संसाधन व सरकारी सुविधाओं पर दिल्लीवासियों का हक होना चाहिए लेकिन घुसपैठिये इसका फायदा उठा रहे हैं। लोगों को इस बारे में जागरूक किया जाएगा।
>
> **-नवीन कुमार, दिल्ली प्रदेश भाजपा प्रवक्ता**

आप के 35 सहित 94 प्रत्याशियों ने भरे पर्चे

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू होने के पांचवें दिन विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों से 94 प्रत्याशियों ने 141 पर्चे भरे। इनमें विधानसभा अध्यक्ष राम निवास गोयल ने शाहदरा, श्रम मंत्री गोपाल राय ने बाबरपुर, सीमापुरी से समाज कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल गौतम, राजेंद्र नगर सीट से राघव चड्ढा व संगम विहार से दिनेश मोहनिया सहित आप के 35 उम्मीदवारों ने शनिवार को नामांकन किया। इसके अलावा बिजवासन से भाजपा के उम्मीदवार सतप्रकाश राणा ने भी पर्चा दाखिल किया।

कई उम्मीदवारों ने दो से तीन सेट पर्चा भरा। आप से नामांकन करने वालों में तिलक नगर से जरनैल सिंह, बवाना से जय भगवान, बुराड़ी से संजीव झा, जंगपुरा से प्रवीण कुमार, कोंडली से कुलदीप कुमार, देवली से प्रकाश, पटेल नगर से राज कुमार आनंद, मादीपुर से गिरीश सोनी, चांदनी चौक से प्रहलाद सिंह साहनी, किराड़ी से ऋतुराज, मालवीय नगर से सोमनाथ भारती, कृष्णा नगर से एसके बग्गा, विकासपुरी से महेंद्र यादव, जनकपुरी से राजेश ऋषि, बल्लीमारन से इमराज हुसैन, दिल्ली कैंट से वीरेंद्र सिंह कादियान, करोल बाग से विशेष रवि आदि प्रमुख हैं।

नेशनल कैपिटल

गणतंत्र दिवस की सुरक्षा तैयारी में जुटी पुलिस व सुरक्षा एजेंसियां

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

एक माह से दिल्ली पुलिस व सुरक्षा एजेंसियां इस कवायद में जुटी हैं कि गणतंत्र दिवस के मौके पर दहशतगर्द दिल्ली में किसी भी वारदात को अंजाम न दे सकें। दिल्ली के सभी प्रमुख बाजारों, रेलवे-मेट्रो स्टेशनों, एयरपोर्ट, बस अड्डों, ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों सहित भीड़भाड़ वाले इलाके में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त कर दिए गए हैं। राजपथ, लाल किला व परेड वाले कई महत्वपूर्ण स्थानों को सुरक्षाबलों ने कब्जे में ले लिया है। दिल्ली की सभी सीमाओं पर चौकसी बढ़ा दी गई है। गणतंत्र दिवस से एक दिन पहले राजधानी में 50 हजार पुलिस कर्मियों व अर्धसैनिक बलों के जवान तैनात कर दिए जाएंगे।

राजधानी को 28 सेक्टरों में बांटकर इसका जिम्मा पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को सौंपा गया है। परेड वाले मार्ग में विजय चौक से लाल किले तक 600 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। वीवीआइपी मूवमेंट के लिए व्यापक स्तर पर यातायात प्रबंधन किया जाएगा। लोगों को सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए आम लोगों के साथ बैठकें की जा रही हैं। पड़ोसी राज्यों की पुलिस के साथ दिल्ली पुलिस बैठक कर सूचनाओं का आदान-प्रदान कर रही है। सड़कों पर वाहनों की जांच की जा रही है।

26 जनवरी को परेड विजय चौक से शुरू होकर लाल किले तक जाएगी। इसके तहत मुख्य आयोजन स्थल इंडिया गेट व परेड गुजरने वाले मार्गों सहित नई दिल्ली क्षेत्र में सुरक्षा के खास बंदोबस्त किए जाएंगे। सभी भीड़भाड़ वाले स्थानों पर पुलिस व सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है। राजपथ-इंडिया गेट व आसपास के इलाके की सुरक्षा के लिए बहु स्तरीय सुरक्षा योजना तैयार की गई है। अंदर की सुरक्षा का जिम्मा जहां एसपीजी और एनएसजी पर होगा वहीं बाहर से दिल्ली पुलिस की सुरक्षा रहेगी। परेड के दौरान कोई गड़बड़ी ना हो इसके लिए परेड गुजरने वाले प्रमुख मार्ग व ऊंची बिल्डिगों पर शार्प शूटर तैनात किए जाएंगे।

हवाई हमले को नाकाम करने के लिए एंटी एयरक्राफ्ट गन तैनात की जा रही हैं। गणतंत्र दिवस के दौरान आतंकी संगठन दहशत फैलाने के लिए भीड़भाड़ वाले बाजार सहित मेट्रो स्टेशन, एयरपोर्ट अथवा धार्मिक व ऐतिहासिक स्थल को निशाना न बना सकें इसके लिए दिल्ली को अलर्ट पर दिया गया है।

इसके अलावा एयरपोर्ट पर भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ की सर्विलांस टीम लगातार चौकसी बरत रही है क्योंकि एयरपोर्ट बेहद संवेदनशील जगह है।

अतीत से

राजौरी गार्डन विस क्षेत्र से 2015 में जीत आप प्रत्याशी जरनैल सिंह को मिली थी, लेकिन इसके बाद हुए उपचुनाव में भाजपा-अकाली गठबंधन के प्रत्याशी मनजिंदर सिंह सिरसा जीत गए

दो वर्ष में ही बदल गया मतदाताओं का मिजाज

भगवान झा, नई दिल्ली

▸ राजौरी गार्डन विधानसभा क्षेत्र से तीन बार विधायक रहे अजय माकन

▸ 2017 में आप प्रत्याशी ने दर्ज की थी जीत

राजौरी गार्डन विधानसभा क्षेत्र पश्चिमी दिल्ली का सबसे हाईप्रोफाइल इलाका है। इस विधानसभा क्षेत्र में पॉश कालोनी के साथ-साथ अनियोजित कॉलोनियां भी हैं। ऐसे में इस इलाके का राजनीतिक मिजाज समय के साथ बदलता रहा है। वर्ष 2015 के विधानसभा चुनाव में जहां एकतरफा जीत आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी जरनैल सिंह को मिली थी। पंजाब में विधानसभा चुनाव के दौरान जरनैल सिंह ने यहां से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद हुए उपचुनाव में यहां के मतदाताओं का मिजाज बदला और उन्होंने भाजपा अकाली गठबंधन के प्रत्याशी मनजिंदर सिंह सिरसा को जीत दिलाई। इससे पहले यह विधानसभा क्षेत्र कांग्रेस का गढ़ रहा है। यहां से प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अजय माकन तीन बार विधायक रहे हैं।

वर्ष 1993 की बात करें तो कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी के रूप में अजय माकन को यहां से उतारा था। उस चुनाव में अजय माकन ने भाजपा प्रत्याशी मनोहर लाल कुमार को करीब 3551 वोट के अंतर से शिकस्त दी थी। वर्ष 1998 में कांग्रेस ने दोबारा अजय माकन को यहां से टिकट दिया। भाजपा ने शशि प्रभा आर्या को टिकट दिया। चेहरा बदलने का भी फायदा इस चुनाव में भाजपा को नहीं मिला और अजय माकन ने 19 हजार से ज्यादा वोटों के अंतर से जीत हासिल की। इसके बाद वर्ष 2003 के चुनाव में फिर से अजय माकन कांग्रेस प्रत्याशी थे। इस चुनाव में भाजपा ने सरबजीत सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया। लेकिन फिर भी कांग्रेस के गढ़ में भाजपा सेंध नहीं लगा पाई। अजय माकन ने 24 हजार से ज्यादा वोटों के अंतर से जीत हासिल की। हर चुनाव में अजय माकन के जीत का अंतर बढ़ता चला गया। इसके बाद वर्ष 2008 में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने इस सीट से प्रत्याशी बदला और दयानंद चंदेला को टिकट दिया। इस चुनाव में मुकाबला दिलचस्प रहा और शिरोमणि अकाली दल (एम) के प्रत्याशी अवतार सिंह हित चुनाव मैदान में थे। इस चुनाव में जीत-हार का अंतर सिर्फ 46 वोट का रहा। 46 वोट से दयानंद चंदेला ने जीत हासिल की थी। इसके बाद से यह सीट कांग्रेस के हाथ से फिसलती चली गई। वर्ष 2013 के चुनाव में शिअद प्रत्याशी मनजिंदर सिंह सिरसा ने कांग्रेस प्रत्याशी धनवंती चंदेला को हराया था।

मनजिंदर सिंह सिरसा

जरनैल सिंह

अजय माकन फाइल

55 हजार अमेरिकी डॉलर के साथ तीन चीनी नागरिक दबोचे

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआइएसएफ) के जवानों ने आइजीआइ एयरपोर्ट पर 55 हजार अमेरिकी डॉलर के साथ तीन चीनी यात्रियों को दबोचा है।

सीआइएसएफ के प्रवक्ता ने बताया कि घटना 17 जनवरी की है। आइजीआइ एयरपोर्ट पर बल के इंटेलिजेंस स्टाफ ने टर्मिनल-3 के चेक-इन में दो विदेशी यात्रियों को संदिग्ध अवस्था में देखा। शक के आधार पर उनकी जांच की गई तो उनके पास 35 हजार अमेरिकी डॉलर बरामद हुए। उनकी पहचान चीनी नागरिक फैन किंगलियन और गुआन जियानहोंग के रूप में हुई। पूछताछ में बताया कि उनका चाइना एयरलाइंस की उड़ान से ग्वांगझोउ का टिकट बना हुआ है। सीसीटीवी फुटेज में उनके साथ एक अन्य चीनी नागरिक भी दिखा। पी वेंग नाम के उस तीसरे शख्स के पास से 20 हजार अमेरिकी डालर मिले।

जेएनयू हिंसा : एसआइटी ने अक्षत अवस्थी से की तीन घंटे तक पूछताछ

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) हिंसा मामले में क्राइम ब्रांच की एसआइटी ने एक निजी चैनल के स्टिंग में फंसे अक्षत अवस्थी से करीब तीन घंटे तक पूछताछ की। अक्षत ने हिंसा और भीड़ को उकसाने की बात से इन्कार करते हुए स्टिंग को गलत ठहराया। सूत्रों के मुताबिक, अक्षत ने एसआइटी को बताया कि उसने स्टिंग को लेकर वसंतकुंज उत्तरी थाने में शिकायत भी दी है।

एसआइटी ने योगेंद्र भारद्वाज और विकास पटेल को भी नोटिस जारी कर पूछताछ में शामिल होने के लिए कहा था। हालांकि दोनों के दोपहर बाद पहुंचने से एसआइटी उनसे पूछताछ नहीं कर सकी। अब सोमवार को दोनों से पूछताछ की जाएगी। योगेंद्र और विकास उन नौ विद्यार्थियों में शामिल हैं जिनकी पहचान एसआइटी ने हिंसा में शामिल संदिग्धों के रूप में की है।

जेएनयू हिंसा मामले में जांच कर रही एसआइटी ने अब तक सबसे लंबी पूछताछ अक्षत अवस्थी से ही की है। अक्षत एक न्यूज चैनल पर स्टिंग में नजर आया था। जिसमें उसने हिंसा में अपना हाथ होने की बात कुबूली थी। स्टिंग के सामने आने के बाद वह भूमिगत हो गया था। एसआइटी ने उसे नोटिस जारी कर जांच में शामिल होने के लिए कहा था। अक्षत से गत 5 जनवरी को जेएनयू में हुई हिंसा के वक्त उसकी लोकेशन के बारे में भी पूछताछ की गई। जिस पर उसने कहा कि वह न तो साबरमती और न ही पेरियार हॉस्टल में गया था। बवाल के दौरान वह पेरियार के बाहर मौजूद था जहां से बाद में वह अपने हॉस्टल जाकर सो गया था।

102 मृत्युदंड के फैसले ट्रायल कोर्ट ने 2019 में दिए। यह आंकड़ा 2018 की तुलना में 60 फीसदी कम है। डेथ पेनल्टी इन इंडिया की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, 2018 में 162 आपराधिक मामलों में फांसी की सजा सुनाई गई थी।

सीजेआइ बोबडे बोले, नागरिकता सिर्फ हक नहीं, कर्तव्य से भी जुड़ा है

- नागपुर विवि में छात्रों से बोले, अच्छा नागरिक बनना सबकी जिम्मेदारी
- शिक्षा का असली उद्देश्य बुद्धि और चरित्र का विकास करना

नागपुर, प्रेट्र : देश भर में नागरिकता संशोधन कानून को लेकर छिड़ी बहस के बीच देश के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआइ) शरद अरविंद बोबडे का नागरिकता को लेकर अहम बयान आया है। जस्टिस बोबडे ने शनिवार को कहा कि नागरिकता सिर्फ लोगों के हक का मामला नहीं है, बल्कि यह समाज के प्रति उनके कर्तव्यों से भी जुड़ा है।

जस्टिस बोबडे यहां राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय (आरटीएमएनयू) के 107वें दीक्षा समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने इस बात पर दुख जताया कि कुछ शिक्षण संस्थान पूरी तरह से व्यावसायिक मानसिकता के हो गए हैं और कहा कि शिक्षा का असली उद्देश्य बुद्धि और चरित्र का विकास करना है। सीजेआइ ने कहा कि विश्वविद्यालय केवल ईंट और गारे से बनी इमारतें नहीं हैं। विश्वविद्यालयों को असेंबली लाइन प्रोडक्शन यूनिट की तरह काम नहीं करना चाहिए। विश्वविद्यालय का विचार इस रूप में नजर आना चाहिए कि हम एक समाज के रूप में क्या हासिल करना चाहते हैं? जस्टिस बोबडे ने कहा कि शोध और विचार अहम हैं और इस पर विश्लेषण किया जाना चाहिए। लेकिन इसके साथ ही छात्रों को यह अहसास दिलाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि समाज उनसे क्या उम्मीद करता है। यह हमेशा याद रखना चाहिए कि समाज में परस्पर निर्भरता उतना ही महत्वपूर्ण है जितनी स्वतंत्रता।

नागपुर में शानिवार को आरटीएमएनयू के 107वें दीक्षा समारोह को संबोधित करते देश के प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे। एएनआइ

उन्होंने कहा, 'आप सभी पर एक सक्रिय नागरिक बनने की भी जिम्मेदारी है और नागरिकता सिर्फ अधिकारों का मसला भर नहीं है, बल्कि इसके साथ समाज के प्रति आपके कर्तव्य भी जुड़े हैं।' उन्होंने आगे कहा, 'आप आज जो कुछ भी हैं निश्चित रूप से अपनी मेहनत के बल पर हैं, लेकिन यह जानना भी जरूरी है कि आप जिन सुविधाओं का लाभ उठाते हुए यहां तक पहुंचे हैं, वो दूसरों द्वारा तैयार की गई हैं। इसलिए, हम दूसरों की भलाई को लेकर बेखबर नहीं हो सकते हैं।' चीफ जस्टिस का बयान इसलिए भी अहम है, क्योंकि जामिया से लेकर जेएनयू तक नागरिकता संशोधन कानून से लेकर फीस वृद्धि के मसले पर आंदोलन देखने को मिले हैं।

धार में पूर्व केंद्रीय मंत्री वर्मा व भाजपा सांसद सहित 41 पर केस

नईदुनिया, भोपाल : मध्य प्रदेश के धार में पूर्व केंद्रीय मंत्री विक्रम वर्मा, भाजपा सांसद छतरसिंह दरबार और पूर्व सांसद सावित्री ठाकुर समेत 41 लोगों पर केस दर्ज किया गया है। उनपर बिना अनुमति सीएए के समर्थन में रैली निकालने का आरोप है। पुलिस ने सोशल मीडिया से फुटेज व जानकारी के आधार पर कार्रवाई की है। उधर, मप्र के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को सीएए के समर्थन में गुना में आयोजित आक्रोश सभा में जिला प्रशासन को आड़े हाथों लिया।

उन्होंने पिछले दिनों कलेक्टर भास्कर लाक्षाकार द्वारा भाजपा नेताओं पर की गई कार्रवाई को लेकर चेतावनी दी कि कलेक्टर संभल जाएं। सरकार हमारी भी आएगी। सीएए के विरोध में इंदौर में धरना दे रहे लोगों पर लाठीचार्ज को लेकर प्रदेश के मंत्री आरिफ अकील ने अधिकारियों को खुलकर चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि ऐसी घटना प्रदेश में अब नहीं होनी चाहिए। गौरतलब है कि इंदौर में सीएए का विरोध कर रहे लोगों पर शुक्रवार तड़के पुलिस ने लाठीचार्ज किया था, इसके बाद एएसपी जीपी पाराशर को हटा दिया गया।

केरल के राज्यपाल ने कहा-राज्यों को लागू करना ही पड़ेगा नागरिकता कानून

- जयपुर में आरिफ मोहम्मद खान ने दिया बड़ा बयान
- बोले-यह राज्य नहीं, बल्कि केंद्रीय सूची का विषय

राज्य ब्यूरो, जयपुर

केरल के राज्यपाल आरिफ मुहम्मद खान ने शनिवार को कहा कि नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) राज्य सूची का नहीं, बल्कि केंद्रीय सूची का विषय है। यही कारण है कि राज्यों को इसे लागू करना ही होगा। उनके पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। इसे अनुच्छेद- 254 के तहत लागू करना जरूरी है।

एक कार्यक्रम के चलते जयपुर आए खान ने मीडिया से बातचीत में कहा कि सभी को अपने क्षेत्राधिकार का ज्ञान होना चाहिए। आप अपना तर्क रख सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दे सकते हैं, लेकिन यह केंद्रीय सूची का विषय है, राज्य सूची का विषय नहीं है। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति अपनी बात पर अड़ सकता है, लेकिन कानून से ऊपर नहीं जा सकता है।

गौरतलब है कि केरल सरकार ने हाल ही में सीएए के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। इसमें कहा गया है कि यह कानून समानता के अधिकार और संविधान की धर्मनिरपेक्षता की भावना के खिलाफ है।

आरिफ मुहम्मद खान। फाइल

खान ने शुक्रवार को ही इस बात पर आपत्ति प्रकट की थी कि केरल सरकार ने उन्हें जानकारी में लाए बिना यह याचिका दायर कर दी। सीएए को लेकर देशभर में हो रहे विरोध प्रदर्शनों पर खान ने कहा कि देश में पहली बार विरोध प्रदर्शन नहीं हो रहे हैं। इससे भी बड़ा प्रदर्शन 1986 में हुआ था, जब सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय को लागू नहीं किया गया था। जयपुर में एक निजी विश्वविद्यालय में रामायण और महाभारत युग पर आधारित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारत की परंपरा ज्ञान और बुद्धिमता की परंपरा है और इसे फिर से जीवित करने की जरूरत है। भारतीय सभ्यता जीवित और लगातार चलने वाली सभ्यता है, जबकि अन्य सभ्यताओं का विकास रुक गया है। उन्होंने कहा कि धर्म शब्द बहुत गहरा है और इसका अर्थ सिर्फ रीति रिवाज और परंपराओं तक सीमित नहीं है।

उन्होंने भारतीय परंपरा को बताने के लिए रामायण और ऋग्वेद के उदाहरण भी दिए। ब्राह्मणत्व के बारे में उन्होंने कहा कि ब्राह्मण वह है, जो खुद ज्ञान प्राप्त करता है ताकि वह सभी को समानता से देख सके। यह बहुत गहरी परंपरा है। यह बांधती नहीं है बल्कि विस्तार का अवसर देती है। उन्होंने कहा कि भारतीय ज्ञान और बुद्धिमता को तो 10वीं शताब्दी में अरबी सभ्यता ने भी स्वीकार किया था।

उन्होंने कहा कि जन्म के आधार पर भेदभाव नहीं हो सकता। जन्म के आधार पर कोई किसी से कम नहीं है।

न्यूज गैलरी

नड्डा के पक्ष में पेश होंगे दो दर्जन सेट

नई दिल्ली : भाजपा के भावी अध्यक्ष जेपी नड्डा के पक्ष में लगभग दो दर्जन नामांकन सेट भरे जाएंगे। बताया जा रहा है कि उन सभी राज्यों से जहां संगठन के चुनाव हो चुके हैं, वहां से एक सेट आएगा। यह चुनाव निर्विरोध ही होने की संभावना है। यूं तो भाजपा में सर्वसम्मति से राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने की परंपरा रही है लेकिन एक बार जब नितिन गडकरी को दोबारा अध्यक्ष चुने जाने की तैयारी हो रही थी तब थोड़ा विवाद खड़ा हुआ था। यशवंत सिन्हा के लिए नामांकन का फार्म लेकर महेश जेटमलानी गए थे। हालांकि उस समय यशवंत सिन्हा की ओर से नामांकन पत्र दाखिल नहीं किया गया था। तब नाटकीय ढंग से गडकरी की जगह राजनाथ सिंह को अध्यक्ष बनाया गया था। (जाब्यू)

हवाला मामले में भाजपा नेता मुकुल रॉय से पूछताछ

कोलकाता : हवाला के एक मामले में कोलकाता पुलिस की विशेष टीम ने शनिवार को भाजपा नेता मुकुल रॉय से पूछताछ की। बीते वर्ष कालीघाट थाने में मुकुल के खिलाफ एफआइआर दर्ज की गई थी। इसके बाद पुलिस ने नोटिस भेजकर उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया था। शनिवार को थाने पहुंचे भाजपा नेता से कोलकाता पुलिस की विशेष टीम ने घंटेभर पूछताछ की। पुलिस ने उनसे हवाला मामले से जुड़े कई सवाल किए। पूछताछ के दौरान भाजपा समर्थकों ने थाने के बाहर विरोध-प्रदर्शन किया। एहतियातन थाने के बाहर सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए थे। बीते वर्ष रेलवे की स्थायी समिति में सदस्य बनाने के नाम पर धोखाधड़ी के मामले में भी मुकुल रॉय का नाम सामने आया था। (जासं)

एमबीए पाठ्यक्रमों के नाम की एआइसीटीई ने बनाई सूची

नई दिल्ली : प्रबंधन पाठ्यक्रमों के अलग-अलग नामों से लोगों को होने वाली परेशानियों को ध्यान में रखते हुए एआइसीटीई ने उससे जुड़े कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के लिए पीजी डिप्लोमा व एमबीए पाठ्यक्रमों की 73 नामों की सूची तैयार की है। एआइसीटीई ने तय किया है कि चार पाठ्यक्रमों आधुनिक कार्यालय प्रबंधन, आधुनिक कार्यालय प्रबंधन एवं सचिव कार्य, आधुनिक कार्यालयी कार्य और राष्ट्रीय प्रबंधन कार्यक्रम को वोकेशनल पाठ्यक्रम बनाया जाए। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, 'पीजी डिप्लोमा देने वाले एआइसीटीई से जुड़े कॉलेजों और एमबीए की डिग्री देने वाले विश्वविद्यालयों को निर्देश दिया गया है कि वे सूची के अनुरूप ही नाम रखें और 2020 के शैक्षणिक सत्र से अवधि विस्तार के लिए ऑनलाइन आवेदन करते हुए इसका ध्यान रखें।' (प्रेट्र)

शाह की राहुल को नसीहत, पूरा पढ़ें सीएए

चुनौती ▶ गृह मंत्री ने ममता और केजरीवाल पर भी साधा निशाना

कहा, साबित करें कि सीएए छीन लेगा भारतीय मुस्लिमों की नागरिकता

बेंगलुरु, प्रेट्र : केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) का विरोध करने वालों को दलित विरोधी बताते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी को पूरा कानून पढ़ने की नसीहत दी। उन्होंने राहुल को चुनौती दी कि वह साबित करें कि सीएए भारतीय मुस्लिमों से नागरिकता छीन लेगा।

भाजपा के देशव्यापी 'जन जागरण अभियान' के तहत हुबली में एक जनसभा को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि सीएए में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो मुस्लिमों से उनकी नागरिकता छीनता हो। उन्होंने राहुल गांधी पर भ्रम फैलाने की कोशिश का आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें कानून में अगर कुछ ऐसा मिलता है जो भारतीय मुस्लिमों की नागरिकता छीनता हो तो प्रहलाद जोशी (संसदीय कार्य मंत्री) उनसे बहस करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कांग्रेस के साथ-साथ वामपंथी दलों, बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जदएस, बसपा और सपा पर वोट बैंक के लिए सीएए पर राजनीति करने का आरोप भी लगाया।

बेंगलुरु में शनिवार को वेदांत भारती के विवेक दीपिनी महासमर्पणे कार्यक्रम के दौरान शंकर भारती महास्वामीजी से आशीर्वाद लेते केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। एएनआइ

वहीं, वेदांत भारती के विवेक दीपिनी महासमर्पणे कार्यक्रम में शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी दुनिया का भ्रमण कर रहे हैं क्योंकि वह भारतीय संस्कृति और परंपरा के ध्वजवाहक हैं। अपनी बात पुष्ट करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने शपथ ग्रहण करने से पहले वाराणसी में गंगा में डुबकी लगाई और गंगा आरती में हिस्सा लिया। भारत सरकार की ओर से विशेष पूजा के लिए पहली बार प्रधानमंत्री के रूप में मोदी ने नेपाल में पशुपतिनाथ मंदिर में लाल चंदन भेजा। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों ने पंथनिरपेक्षता की गलत व्याख्या की जिसकी वजह से वे देश की सर्वश्रेष्ठ चीजों का सम्मान नहीं कर सकीं। लेकिन लंबे अंतराल के बाद हमें ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जिसने संदेश दिया है कि हमारे पास दुनिया को देने के लिए काफी कुछ है। कार्यक्रम में अमित शाह ने बच्चों को वेदों और आदि शंकराचार्य के लेखन से रूबरू कराने की कोशिश के लिए वेदांत भारती को धन्यवाद दिया और छात्रों से जीवन में हमेशा सही रास्ते पर चलने का आह्वान किया।

धार्मिक उत्पीड़न के शिकार अल्पसंख्यकों की मदद के पक्ष में थे राष्ट्रपिता : नड्डा

नई दिल्ली, प्रेट्र : भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विपक्ष पर सीएए को लेकर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया है। नड्डा ने कहा कि महात्मा गांधी, जवाहर लाल नेहरू और मनमोहन सिंह भी पड़ोसी देशों में धार्मिक आधार पर उत्पीड़न के शिकार अल्पसंख्यकों की मदद के पक्ष में थे। भाजपा मुख्यालय में पाकिस्तान से आए अल्पसंख्यक शरणार्थियों के एक समूह को संबोधित करते हुए नड्डा ने आरोप लगाया कि विपक्षी दल यह गलत सूचना फैला रहे हैं कि इस कानून के बनने से भारत में करोड़ों शरणार्थी आ जाएंगे, जिन्हें संभालना मुश्किल होगा। नड्डा ने कहा कि यह कानून उन लोगों पर लागू होगा जो 31 दिसंबर, 2014 से पहले भारत आ चुके हैं। लोगों को यह गलत जानकारी दी जा रही है कि सीएए के लागू होने से उनकी नागरिकता खत्म हो जाएगी। जबकि, यह कानून नागरिकता देता है, छीनता नहीं। नड्डा ने कहा कि विपक्षी दल वोट बैंक की राजनीति में सीएए को लेकर गलत जानकारी फैला रहे हैं।

एनपीआर है एनआरसी का ही छद्म रूप : चिदंबरम

- कांग्रेस नेता ने कहा-सीएए-एनपीआर-एनआरसी का विरोध संविधान के लिए, विपक्ष आए साथ
- ममता को दी क्लीन चिट, कहा-बैठक में शामिल नहीं होने का मतलब सीएए का समर्थन नहीं

जागरण संवाददाता, कोलकाता

नागरिकता संशोधन कानून (सीएए), राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) को लेकर कांग्रेस का केंद्र सरकार पर हमला जारी है। शनिवार को बंगाल कांग्रेस मुख्यालय विधान भवन में पत्रकारों से मुखातिब वरिष्ठ कांग्रेस नेता व पूर्व केंद्रीय वित्तमंत्री पी. चिदंबरम ने कहा कि एनपीआर, एनआरसी का ही छद्म रूप है। असम में एनआरसी की विफलता के बाद नरेंद्र मोदी सरकार ने तुरंत गियर बदल दिया है और अब वह एनपीआर के बारे में बात कर रही है।

चिदंबरम ने सीएए-एनपीआर-एनआरसी का विरोध कर रहे सभी विपक्षी दलों से एक साथ आने की अपील की। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी की ओर से बुलाई गई बैठक से नदारद रहे छह विपक्षी दलों में से एक तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी को क्लीनचिट देते हुए उन्होंने कहा-'किसी के बैठक में शामिल नहीं होने का मतलब यह नहीं कि वह सीएए के पक्ष में है। संभव है कि राज्यों में राजनीतिक दलों के समक्ष कुछ घरेलू मामले हों व परिस्थितियां अलग हों, लेकिन हमें याद रखना होगा कि यह लड़ाई संविधान के लिए है।' विधान भवन में सीएए-एनआरसी-एनपीआर पर प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व का मार्गदर्शन करने चिदंबरम कोलकाता पहुंचे थे। हालांकि, इस दौरान लोकसभा में कांग्रेस के नेता व पार्टी सांसद अधीर रंजन चौधरी अनुपस्थित थे। वे यहां नहीं पहुंचकर पार्टी के एक अन्य कार्यक्रम में उपस्थित हुए। बैठक के अंत में चिदंबरम ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस राज्यभर में सीएए-एनआरसी-एनपीआर के खिलाफ आंदोलन करेगी।

प्रदर्शन में भी शामिल हुए चिदंबरम : महानगर के पार्क सर्कस इलाके में बीते 12 दिनों से सीएए के खिलाफ चल रहे प्रदर्शन में चिदंबरम शामिल हुए। उन्होंने प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए आश्वस्त किया कि कांग्रेस उनके साथ है। यहां प्रदर्शन कर रहीं महिलाओं का कहना है कि जब तक उनके पक्ष में फैसला नहीं आता, तब तक वे यहां से नहीं हटेंगी।

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का इंतजार : पार्क सर्कस मैदान में करीब 60 मुस्लिम महिलाएं धरना दे रही हैं। प्रदर्शन में पेशेवर महिलाओं से लेकर आम गृहिणी तक शामिल हैं। उन्हेसुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिकाओं पर फैसले का इंतजार है। 59 याचिकाओं पर सुनवाई 22 जनवरी को होनी है।

'पड़ोस में बढ़ते चीनी प्रभाव के बावजूद कर रहे अपने हितों की रक्षा'

नई दिल्ली, प्रेट्र : विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने शनिवार को संसद सदस्यों को आश्वस्त किया कि पड़ोस में बढ़ रहे चीनी प्रभाव के बावजूद देश अपने हितों की रक्षा कर रहा है। जयशंकर विदेशी मामलों की परामर्श समिति के सदस्यों को जानकारी दे रहे थे। इस समिति में कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी शामिल हैं। समिति के सदस्य बीजद सांसद सस्मित पात्रा ने ट्वीट कर कहा, 'विचार-विमर्श भारत के पड़ोस पर केंद्रित रहा। समिति में चर्चा का विवरण गोपनीय है इसलिए उजागर नहीं किया जा सकता।' उन्होंने कहा कि चर्चा अर्थपूर्ण और गंभीर रही। कांग्रेस नेता और पूर्व विदेश राज्यमंत्री शशि थरूर ने चर्चा को बेहद जीवंत बताते हुए इस बात का खासतौर पर उल्लेख किया कि राहुल गांधी ने कई गंभीर सवाल पूछे।

बैठक में मौजूद रहे भाजपा सांसद जीवीएल नरसिम्हा राव ने जयशंकर की सराहना करते हुए उन्हें सफल राजनयिक और बेहद सफल मंत्री बताया। उन्होंने कहा कि विदेश मंत्री ने सदस्यों के सभी सवालों के बेहद चतुराई, स्पष्टता और दूरदृष्टि के साथ जवाब दिए।

'कांग्रेस में हिंदू-सिख विरोधी आत्मा का वास'

- नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के समर्थन में वाराणसी में हुई रैली में उमड़ा जनसैलाब
- कांग्रेस में हिंदू-सिख विरोधी आत्मा का वास, अब ईसाइयों की भी विरोधी : स्मृति ईरानी

जागरण संवाददाता, वाराणसी

नागरिकता नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) पर विपक्षियों के विरोधी रवैये को लेकर केंद्रीय वस्त्र, महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी के तेवर बेहद तल्ख रहे। वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में शनिवार को इस कानून के समर्थन में सजे रैली के मंच से उन्होंने कांग्रेस को निशाने पर लिया।

उन्होंने कहा कि अंग्रेजों ने हिंदुस्तान का अस्तित्व मिटाने के उद्देश्य से 1947 में धर्म को देश विभाजन का आधार बनाया। गोरों की सीख को कांग्रेस ने अपना संस्कार बना लिया। सीएए की आड़ में संविधान की दुहाई देने वालों को 72 साल बाद भी जवाब देना भारी पड़ता है कि धर्म के नाम पर बंटवारा उनकी पार्टी ने क्यों स्वीकारा। कारण यह है कि कांग्रेस को राष्ट्रहित के बजाय परिवार हित प्यारा था। वास्तव में अपराधी तत्वों के साथ खड़े होना कांग्रेस का संस्कार बन गया है। इस रैली में लोगों की भारी उमड़ी।

स्मृति ने कहा कि वर्षों से जो विषय ऐतिहासिक-राजनीतिक दृष्टि से समाज व राष्ट्र के समक्ष प्रश्न चिह्न बनकर उभरे, उनका जवाब बनना काशी के सांसद के नसीब में था। विभाजन के समय गांधी जी ने कहा था कि जो हिंदू -सिख परिवार पाकिस्तान में टिके हैं, वहां उन्हें सम्मान न मिले तो उनका संरक्षण हिंदुस्तान का कर्तव्य होगा। बापू के कथन को पीएम मोदी ने स्वीकार और साकार भी किया। कांग्रेस में हिंदू-सिख विरोधी आत्मा का वास है, वह अब ईसाइयों की भी विरोधी हो गई है।

उत्तर प्रदेश के वाराणसी में शनिवार को संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में आयोजित रैली में उमड़े लोग। जागरण

बड़ी जनसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सीएए का विरोध देश के खिलाफ एक षड्यंत्र है। सीएए नागरिकता देने का कानून है नागरिकता लेने का नहीं। कांग्रेस भारत विरोधी नारे लगाने वालों का समर्थन कर रही है। सपा सहित सभी विपक्षी दलों का चरित्र सामने आ चुका है। विरोध की आड़ में अराजक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास कार्यों और बड़े फैसलों से घबराए विपक्षी दल सीएए के नाम पर लोगों को बरगलाने में जुट गए हैं। विरोध के नाम पर हिंसा करने और सरकारी संपत्तियों को क्षति पहुंचाने वालों से कड़ाई से पेश आया जाएगा। क्षतिपूर्ति उन्हीं से कराई जाएगी।

सीएए के समर्थन में गूंजा वंदेमातरम

जेएनएन, नई दिल्ली : सीएए के समर्थन में शनिवार को भी देशभर में आवाज बुलंद हुई। जगह-जगह तिरंगा यात्राएं निकाली गईं, रैलियां और गोष्ठियां हुईं।

उत्तर प्रदेश के गोंडा, अमेठी, सीतापुर, बाराबंकी व हरदोई में में सीएए के पक्ष में सभाएं, रैली व वंदेमातरम का गान किया गया। झांसी, मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत, मुरादाबाद, अलीगढ़, सहारनपुर व बुलंदशहर में भारतीय जनता युवा मोर्चा (भाजयुमो) की अगुवाई में मानव श्रृंखला बनाकर प्रदर्शन किया गया। पंजाब के अमृतसर में तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें विद्यार्थियों ने 170 फुट लंबे राष्ट्रीय ध्वज के साथ भाग लिया। पठानकोट में बाइक रैली निकाली गई। झारखंड के खूंटी में केंद्रीय इस्पात मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा कि सीएए को लेकर विपक्षी पार्टियां लोगों को गुमराह कर अराजकता का माहौल पैदा कर रही हैं, जबकि इससे किसी भारतीय नागरिक की नागरिकता नहीं जाएगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन (एनआरसी) को लेकर बेतुकी बातें कर रहे हैं, जबकि इसे लागू करने के बारे में सरकार ने सोचा भी नहीं है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही असम में एनआरसी को प्रायोगिक तौर पर लाया गया था। पद्मभूषण पूर्व केंद्रीय मंत्री कड़िया मुंडा ने कहा कि जो लोग सीएए का विरोध कर रहे हैं, उन्हें इस कानून के बारे में जानकारी ही नहीं है।

शादी के कार्ड पर लिखवाया 'आइ सपोर्ट सीएए' : मध्य प्रदेश में नरसिंहपुर जिले के करेली में एक युवक प्रभात ने अपनी शादी के कार्ड पर 'आइ सपोर्ट सीएए' लिखवाया है। शादी में उनको सीएए के नाम पर समर्थन भी खूब मिला। प्रभात का कहना है कि उनका मकसद संविधान के प्रति आस्था और निष्ठा रखने का संदेश देना है।

कह के रहेंगे

माधव जोशी

दिलाया भरोसा

परिवर्तन संगोष्ठी में यूनियनों को न बुलाने की गलती हुई, अब करते रहेंगे बात

रेलमंत्री फिर बोले, नहीं होगा रेलवे का निजीकरण

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

रेल मंत्री पीयूष गोयल ने एक बार फिर आश्वस्त किया है कि रेलवे का निजीकरण नहीं होगा। रेलवे यूनियनों के प्रतिनिधियों से बातचीत में गोयल ने कहा, मैं संसद से लेकर अलग-अलग मंचों पर यह स्पष्ट कर चुका हूं कि रेलवे का कभी निजीकरण नहीं किया जाएगा।

गोयल रेलवे की दो प्रमुख यूनियनों-ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन (एआइएफआर) तथा नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे मेन (एनएफआइआर) के साथ डिपार्टमेंटल काउंसिल की बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने स्वीकार किया कि परिवर्तन संगोष्ठी में यूनियनों को बुलाया जाता तो और बेहतर नतीजे सामने आते। यूनियनों के साथ संवाद की प्रक्रिया को दोबारा चालू किया जाएगा और हर तीन महीने में कर्मचारी यूनियनों व छह महीने में अफसरों की यूनियनों के साथ चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि परिवर्तन संगोष्ठी के सुझावों पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। बैठक में यूनियन नेताओं ने निजीकरण को लेकर अपनी आशंकाएं सामने रखीं। सबसे बड़ी यूनियन एआइएफआर के महासचिव शिवगोपाल मिश्रा ने कहा कि निजीकरण और निगमीकरण की चर्चाओं से रेलवे कर्मचारी भयभीत हैं।

पीयूष गोयल। फाइल

एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले से वंदे भारत की बात कर रेलकर्मियों की प्रशंसा करते हैं। दूसरी ओर कम कर्मचारियों के बावजूद उत्पादन दोगुना-तिगुना होने पर भी रेल कारखानों के निगमीकरण की बात हो रही है। तेजस जैसी ट्रेनों का निजीकरण कर उन्हें मनमाना किराया वसूलने की इजाजत दे दी गई है, जबकि वह शताब्दी से सिर्फ पांच मिनट पहले पहुंचाती है।

अब तेजस जैसी 150 निजी ट्रेनें चलाने की बात की जा रही है। इनसे 15 मिनट पहले कोई भी सामान्य ट्रेन नहीं चलने दी जाएगी।

सवाल यह है कि जिस समझौते में रेल, पटरी, बोगी, लोको, लोको पायलट, मेंटीनेंस, स्टेशन, स्टेशन मास्टर, केबिन सब हमारा हो और मुनाफा प्राइवेट ऑपरेटर का हो, वह कैसा समझौता है? अगर पैसा कमाना ही मकसद है तो रेलवे को भी मनमाफिक किराया वसूलने और स्टॉपेज तय करने का अधिकार दीजिए। फिर देखिए निजी क्षेत्र से भी बेहतर आमदनी करके दिखाएंगे। हम सुधारों के खिलाफ नहीं हैं। ट्रेनों की स्पीड, सुविधाएं बढ़नी चाहिए। वाई-फाई, सफाई, सुरक्षा हम भी चाहते हैं, लेकिन निजीकरण कतई बर्दाश्त नहीं है।

संगोष्ठी के दौरान कहा गया कि 50 हजार यूनियन पदाधिकारी कोई काम नहीं करते। स्टेशन मास्टर, गार्ड, लोको पायलट से लेकर ट्रैकमैन सब हमारे पदाधिकारी हैं। क्या इनके काम के बगैर ही ट्रेनें चल रही हैं। पदाधिकारी पहले अपना काम करते हैं, फिर यूनियन के लिए समय निकालते हैं।

REUNION IAS
IAS V.K.TRIPATHI PCS
NEW BATCHES
सामान्य अध्ययन-II (मुख्य परीक्षा)
राजव्यवस्था
POLITY (MAINS)
से कक्षा प्रारम्भ... 20 JAN 2020 11:30 AM 2:00 PM
GS (प्रारम्भिक परीक्षा)
राजव्यवस्था
POLITY (PT) 20 JAN 2020 6:15 PM 8:15 PM
OFFLINE / ONLINE CLASSES
B-11, 1st FLOOR, IN FRONT OF MEERUT SWEETS, MUKHERJEE NAGAR DELHI-9
9999421659-58

23 सितंबर 1980 को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून बना था। यह कानून केंद्र और राज्य सरकार को सुरक्षा की नजर से किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में लेने शक्ति देता है। इसके तहत बिना किसी आरोप के 12 महीने तक जेल में रखा जा सकता है।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
रविवार 19 जनवरी 2020

न्यूज गैलरी

पबजी पर पाबंदी लगाने का विचार कर रही केंद्र सरकार

चंडीगढ़ : ऑनलाइन मोबाइल गेम पबजी पर केंद्र सरकार रोक लगाने पर विचार कर रही है। केंद्रीय संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साइबर व ई-सिक्योरिटी के निदेशक एवं वरिष्ठ वैज्ञानिक वीके त्रिवेदी ने यह जानकारी दी है। वरिष्ठ अधिवक्ता एचसी अरोड़ा ने इस मामले को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। हाई कोर्ट के आदेश पर वीके त्रिवेदी ने अरोड़ा को बताया है कि पबजी पर रोक लगाना सरकार के समक्ष विचारणीय है। याचिका में अरोड़ा ने बताया था कि यह गेम बच्चों पर बुरा प्रभाव डाल रहा है। बच्चे कई-कई घंटे इसे खेलते रहते हैं, जिसकी वजह से उनका शारीरिक और मानसिक विकास धीमा हो जाता है। वे सामाजिक रूप से कम ही सक्रिय रह पाते हैं। इस गेम के कारण बच्चों में हिंसक प्रवृत्ति बढ़ती है और कई बच्चों की मौत भी हो चुकी है। इस पर हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को विचार करने का आदेश दिया था। (राब्यू)

गलत दवा लिखने पर अस्पताल पर पांच लाख का जुर्माना

कोलकाता : बंगाल के स्वास्थ्य आयोग ने एक निजी अस्पताल पर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना एक मरीज को अस्पताल में दी गई पर्ची में गलत दवा लिखने को लेकर लगाया गया है। यह राशि आयोग ने एनजीओ और वृद्धाश्रम में जमा देने का आदेश दिया है। यह मामला 2018 का है। विमन नंदी नामक एक व्यक्ति ने स्वास्थ्य आयोग में शिकायत की कि दक्षिण कोलकाता स्थित निजी अस्पताल सीएमआरआइ ने उनके बीमार रिश्तेदार को छुट्टी देते समय प्रिंट की हुई पर्ची दी थी, जिसमें जो दवा लिखी गई थी, वह किसी अन्य मरीज की थी। बाद में जब डॉक्टर को दिखाने के लिए वे लोग अस्पताल गए, तब इस भारी भूल के बारे में पता चला। अस्पताल प्रबंधन ने स्वीकार कर लिया कि उनसे गलती हुई है। इसके बाद रोगी के परिजनों ने स्वास्थ्य आयोग में अस्पताल के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी। इसके बाद आयोग ने जांच में आरोप को सही पाया और पांच लाख रुपये जुर्माना सुनाया। (राब्यू)

पूर्व सीएम के घर शव मिलने का मामला राज्यपाल तक पहुंचा

रायपुर : छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के प्रमुख अजीत जोगी ने कहा कि कर्मचारी को आत्महत्या के लिए प्रेरित करने का झूठा आरोप उन पर और पुत्र अमित जोगी पर लगाया गया है। उसके स्वजनों पर दबाव डालकर एफआइआर नामजद कराई गई। उन्होंने व उनकी पार्टी ने राज्यपाल अनुसुइया उइके को ज्ञापन सौंपकर मामले की जांच राज्य की पुलिस के बजाय न्यायिक मजिस्ट्रेट या सीबीआइ से कराने की मांग की है। गौरतलब है कि बिलासपुर स्थित जोगी के निवास मरवाही सदन में कर्मचारी मनवा उर्फ संतोष कौशिक (30) पुत्र पुसऊ का शव फंदे पर लटकता मिला था। पुलिस ने इस मामले में जोगी पिता-पुत्र के खिलाफ आत्महत्या के लिए प्रेरित करने का मुकदमा दर्ज किया है। सरकारी आवास सागौन बंगला में शनिवार को पत्रकारवार्ता में जोगी ने कहा कि पिछले 16 वर्षों से भाजपा और कांग्रेस ने एक ही परिवार को प्रताड़ित किया है, क्योंकि दोनों पार्टियां नहीं चाहती हैं कि छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़िया परिवार अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो। (नईदुनिया)

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन देने का निर्देश

प्रयागराज : इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बेसिक शिक्षा विभाग बिजनौर में नियुक्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन व अन्य परिलाभ देने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति एमसी त्रिपाठी ने प्रदीप कुमार व अन्य की याचिका पर दिया है। याची अधिवक्ता का कहना था कि सात याचियों की नियुक्ति बेसिक शिक्षा विभाग बिजनौर में अनुकंपा के आधार पर अलग-अलग तारीखों पर हुई थी। याची प्रदीप कुमार दिसंबर 2000, अश्विनी कुमार 2002 में नियुक्त हुआ था। इसी प्रकार से अन्य याची अलग-अलग तारीखों पर अनुकंपा के आधार पर नियुक्त किए गए। (जासं)

शिरडीवासियों को पाथरी के विकास की घोषणा से महत्व कम होने का डर

राज्य ब्यूरो, मुंबई

- आज से अनिश्चितकालीन बंद का आह्वान
- सीएम उद्धव ठाकरे विवाद के हल के लिए सभी पक्षों से करेंगे बात

शिरडी वाले साई बाबा के जन्मस्थान पाथरी के विकास के लिए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे द्वारा 100 करोड़ रुपये दिए जाने की घोषणा से शिरडीवासियों को डर सताने लगा है कि कहीं पाथरी का महत्व बढ़ने से शिरडी का महत्व कम न होने लग जाए। इसके विरोध में रविवार से शिरडी कस्बे में अनिश्चितकालीन बंद का आह्वान किया गया है, हालांकि मंदिर खुला रहेगा। वहीं, विवाद का समाधान करने के लिए उद्धव राज्य सचिवालय में सभी पक्षों के साथ बातचीत करेंगे।

परभणी जनपद के पाथरी गांव के लिए की गई उक्त घोषणा शिरडीवासियों को रास नहीं आ रही है। उनका तर्क है कि साई बाबा ने जब खुद कभी स्पष्ट नहीं किया कि उनका जन्मस्थान कहां है तो पाथरी को आस्था के दूसरे केंद्र के रूप में विकसित करने की जरूरत ही क्या है? शिरडी साई ट्रस्ट और साई बाबा में आस्था रखने वाले लोग साई बाबा के जीवन पर लिखी एकमात्र पुस्तक 'साई सच्चरित्र' का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि इस पुस्तक में भी साई जन्मस्थान का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता तो उनके जन्मस्थान के रूप में नया केंद्र स्थापित करने की जरूरत क्यों पड़ रही है।

बता दें कि पिछले वर्ष शिरडी के साई बाबा की समाधि के 100 वर्ष पूरे होने पर भव्य उत्सव मनाया गया था। इसमें राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भी शामिल हुए थे। कभी अहमदनगर में एक छोटा सा गांव रहा शिरडी आज साई मंदिर के कारण एक बड़ा तीर्थस्थल बन चुका है। यहां प्रतिदिन कम से कम 25,000 लोग और विशेष अवसरों पर ढाई से तीन लाख लोग साई बाबा के दर्शन करने पहुंचते हैं। मंदिर में तो लाखों का चढ़ावा चढ़ता ही है, भक्तों की बड़ी संख्या के कारण शिरडी का स्वरूप भी बदल चुका है। बड़े-बड़े होटल और दुकानें खुल गई हैं। रेलवे स्टेशन और विमानतल बन चुके हैं। प्रतिदिन आधा दर्जन से ज्यादा उड़ानें शिरडी से होती हैं। इससे क्षेत्रीय लोगों का आर्थिक विकास भी हुआ है। अब पाथरी को साई बाबा के जन्मस्थान के रूप में विकसित किए जाने की घोषणा से उन्हें लग रहा है कि इससे शिरडी का महत्व कम हो जाएगा।

संघ किसी का रिमोट कंट्रोल नहीं : मोहन भागवत

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद

- संघ प्रमुख बोले, कमजोर की कोई नहीं सुनता, इसलिए राष्ट्र को शक्तिशाली बनाने के लिए करें कार्य

'भारत को बड़ा बनाने के लिए हम काम करते हैं। संघ के विचारों और संस्कार के अनुसार हम हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं। संघ इतने काम करता है और उन कामों को देखकर लोग संघ को समझने का प्रयास करते हैं। कभी-कभी पत्रकार कहते हैं कि संघ रिमोट कंट्रोल है। संघ किसी का रिमोट कंट्रोल नहीं, हम तो अपने स्वयंसेवकों पर भी कंट्रोल नहीं करते। हम अच्छा काम करते हैं तो लोग साथ आते हैं। हम भी कहते हैं कि निर्भय बनो, शक्तिशाली बनो।' ये बातें सर संघ चालक मोहन भागवत ने मुरादाबाद स्थित एमआइटी में आयोजित मकर संक्रांति उत्सव में कहीं।

कार्यक्रम स्थल पर ध्वज प्रणाम के बाद उन्होंने साढ़े छह हजार से अधिक स्वयंसेवकों को संबोधित किया। उन्होंने संघ के कार्यों पर विस्तार से प्रकाश डाला, मजबूत भारत की बात कही। कहा कि रूस कभी महाशक्ति था, अमेरिका लगभग महाशक्ति है, चीन भी महाशक्ति बनने की ओर है। हमें भी महाशक्ति बनना चाहिए। कमजोर को कोई नहीं पूछता, इसलिए देश को शक्तिशाली बनाने के लिए कार्य करें। हमें भारत को फिर से विश्व गुरु बनाना है। चार दिवसीय प्रांतीय कार्यकारिणी के अंतिम दिन मकर संक्रांति उत्सव के बाद कार्यक्रम स्थल पर पालकों की बैठक में संघ के शाखाओं में लोगों को जोड़ने का मंत्र दिया। इसके बाद गांधी नगर स्थित संघ के कार्यालय का लोकार्पण किया।

दृढ़ संकल्प की जरूरत : सर संघचालक ने कहा कि देश को परम वैभव तक पहुंचाने के लिए हम सभी के मन में दृढ़ संकल्प होना चाहिए। इसके लिए हमें स्वतंत्रता के साथ समझौता नहीं करना है। हमें अपने देश की सर्वांगीण उन्नति करनी है। इजराइल का उदाहरण देते हुए बताया कि वहां के लोगों को स्वतंत्रता से पहले प्रस्ताव दिया गया कि वह अफ्रीका में कहीं भी चार गुना जगह ले लें और इजराइल छोड़ दें लेकिन, इजराइल के लोगों ने प्रस्ताव को ठुकरा दिया। इजरायल के लोगों ने कहा कि हमारी मिट्टी, हमारी संस्कृति इसी देश में बसी है, इसीलिए हम इसे नहीं छोड़ सकते है। संघ क्या कहता है, क्या बोलता है, संघ के स्वयंसेवक क्या-क्या करते हैं, इसकी समीक्षा करने से पहले इसको अनुभव से समझना पड़ेगा तभी संघ के बारे में जाना जा सकता है।

हिंदू से हो व्यक्ति की पहचान : सर संघचालक ने कहा कि किसी भी व्यक्ति की पहचान उसकी जाति से नहीं बल्कि हिंदू से होनी चाहिए। इसकी शुरुआत हमें अपने घर और कार्यक्षेत्र से करनी होगी। घर में काम करने वाली बाई हो या ड्राइवर, सफाई कर्मचारी या कपड़े धोने वाला, उसे सहजता से हिंदुत्व की विचारधारा से जोड़ें। मलिन बस्तियों में जाकर उनका दर्द समझें और घुल-मिल जाएं। उनके साथ भोजन करें। उन्हें हिंदू होने पर गर्व करवाएं। कहा कि देश में हजारों अरबपति लोग हैं लेकिन, यदि देश का एक व्यक्ति भी भूखा सोता है तो भूखों का देश कहलाएगा। हमें सजगता दिखानी होगी कि कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोए।

उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में शनिवार को एमआइटी परिसर में आयोजित मकर संक्रांति उत्सव को संबोधित करते आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। जागरण

अपनी संस्कृति के कारण भारत की अलग पहचान

संघ प्रमुख ने कहा कि संघ में जातिवाद और छुआछूत को नहीं माना जाता, सभी समान हैं। हमारा धर्म शाश्वत है। कहा कि भारत एक संस्कृति वाला देश है और उस संस्कृति को मानने वाला हर व्यक्ति भारतीय है। एक सौ तीस करोड़ की जनता पर इसी संस्कृति का प्रभाव है। इसीलिए दुनिया कहती है कि यह भारतीय संस्कृति है। इसी संस्कृति के कारण ही दुनिया में भारत की अलग पहचान बनी है।

भोक्ता को जल संसाधन, आलमगीर को मिल सकता है ग्रामीण विकास

टिकीं निगाहें ▸ 23 जनवरी के बाद हो सकता है झारखंड मंत्रिमंडल का विस्तार

मंत्रिमंडल के विस्तार से पहले सामने आ रहे हैं दलों के दावे

राज्य ब्यूरो, रांची

झारखंड में मंत्रिमंडल बंटवारा पर निर्णय में भले ही कुछ वक्त बाकी हो, दलों के दावे सामने आने लगे हैं। सबसे पहला दावा राजद ने किया है और यह दावा ग्रामीण विकास विभाग के अलावा जल संसाधन विभाग को लेकर था। ग्रामीण विकास विभाग बड़े बजट का है और इसे राजद को न देकर जल संसाधन विभाग के लिए लोग राजी हो गए हैं। राजद कोटे से मंत्री बने सत्यानंद भोक्ता को यह विभाग दिए जाने पर किसी को आपत्ति भी नहीं होगी।

इसके साथ ही, कांग्रेस नेता आलमगीर आलम को ग्रामीण विकास विभाग दिए जाने का रास्ता साफ हो गया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉ. रामेश्वर उरांव को वित्त एवं राजस्व विभाग अथवा स्वास्थ्य देने की बात की जा रही है। कांग्रेस के सूत्रों के अनुसार, मंत्रिमंडल का विस्तार 23 जनवरी के बाद हो सकता है।

सड़क निर्माण रह सकता है झामुमो के पास: निर्माण कार्यों से जुड़े दो बड़े विभाग कांग्रेस और झामुमो आपस में बांटकर सत्ता चलाएंगे। झामुमो के पास सड़क निर्माण रहने की बात कही जा रही है, तो कांग्रेस के पास भवन निर्माण एवं आवास विभाग। पिछली सरकार में यह विभाग मुख्यमंत्री के तौर पर हेमंत सोरेन के पास ही था। गृह, कार्मिक, ऊर्जा, उद्योग, वाणिज्यकर आदि विभाग झामुमो के पास होगा। झामुमो कोटे से मंत्रियों के बीच विभागों के अलावा अधिसंख्य महत्वपूर्ण विभाग मुख्यमंत्री के पास ही होंगे।

मंत्रियों की संख्या को लेकर कांग्रेस में किसी प्रकार का भ्रम नहीं : सूत्रों के अनुसार, मंत्रिमंडल को लेकर तमाम उलझनों को सुलझा लिया गया है और 23 जनवरी तक इसे मूर्त रूप दे दिया जाएगा। पिछली बार 14 विधायकों के साथ कांग्रेस के पांच मंत्रियों को कैबिनेट में जगह मिली थी और इस बार कांग्रेस के विधायक अधिक हैं, सो मंत्रियों की संख्या को लेकर कांग्रेस में किसी प्रकार का भ्रम नहीं है। पूर्व में कांग्रेस के पास रहे सभी विभाग भी एक बार कांग्रेस को मिल सकते हैं। कुछ विभागों को लेकर जिच बनी हुई है, लेकिन कांग्रेस इस बात पर झमेले की नौबत नहीं आने देना चाहती है। दूसरी ओर, झामुमो अपने हिस्से के मंत्रियों के बीच विभाग बंटवारे को फाइनल करने में जुटा है।

मरांडी के सुर हुए भाजपाई, फिर भी विलय पर नहीं खुले

जासं, गिरिडीह : झाविमो प्रमुख बाबूलाल मरांडी के सुर भाजपाई होते दिख रहे हैं। वह नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) पर केंद्र की वकालत करते नजर आ रहे हैं, लेकिन भाजपा में विलय की बातों को खुलकर स्वीकार नहीं कर रहे। विलय के सवाल पर गोलमोल जवाब ही दिया। मरांडी शनिवार को अपने पैतृक आवास कोदईबांक में पत्रकारों से मुखातिब थे। उन्होंने प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल गठन को लेकर हो रही देरी पर भी सवाल उठाया और कहा कि इसे शीघ्र पूरा कर लेना होगा। मरांडी ने कहा कि एनआरसी व सीएए से लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। अलबत्ता, मुस्लिम डरे हुए हैं। इस डर से लोगों को बाहर निकालने के लिए केंद्र सरकार को जनता के बीच जाकर सही चीजें बतानी चाहिए। हिंदू मुस्लिम आपस में उलझ रहे हैं, जो गलत है। उन्होंने कहा कि हेमंत नीत सरकार को उन्होंने बिना शर्त समर्थन दिया है, लेकिन दुख की बात है कि लंबे समय के बाद भी मंत्रिमंडल का गठन नहीं हो सका है। अगर आज यह स्थिति है तो राम जाने कल क्या होगा।

निकाय चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस-द्रमुक में तनातनी

चेन्नई, प्रेट्र : तमिलनाडु के स्थानीय निकाय चुनाव में सीटों के बंटवारे को लेकर कांग्रेस और द्रमुक के बीच तनातनी पैदा हो गई है। दरअसल, कांग्रेस नेता अलागिरी और द्रमुक नेता दुरईमुरुगन की टिप्पणियों ने इस तनातनी को हवा दी। इसके बाद शनिवार को विवाद को सुलझाने की कोशिशें तेज हुईं। द्रमुक सुप्रीमो एमके स्टालिन ने दोनों दलों के नेताओं को बयानबाजी से दूर रहने की सलाह दी है।

विवाद खत्म करने की पहल करते हुए तमिलनाडु कांग्रेस समिति अध्यक्ष केएस अलागिरी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ द्रमुक प्रमुख से मिलने उनके पार्टी मुख्यालय 'अन्ना अरविलयम' पहुंचे। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में अलागिरी ने कहा कि कांग्रेस और द्रमुक के बीच सीटों को लेकर किसी तरह का मतभेद नहीं है। उनका कहना था कि दोनों पार्टियां एकजुट हैं और आगे भी रहेंगी। उन्होंने द्रमुक नेता दुरईमुरुगन की इस टिप्पणी को अधिक तवज्जो नहीं दी कि कांग्रेस के पास वोट बैंक नहीं है।

कांग्रेस नेताओं से विचार-विमर्श के बाद स्टालिन ने दोनों पार्टियों के नेताओं से यह स्थिति दोबारा पैदा नहीं होने देने के लिए अपने विचार सार्वजनिक करने से बचने को कहा। स्टालिन ने कहा कि सीटों के बंटवारे जैसे मुद्दे बातचीत से हल होने चाहिए, लेकिन दोनों तरफ से अवांछित बयान दिए गए। उन्होंने कहा की जुबानी जंग से राजनीतिक विरोधियों और मीडिया को मौका मिलता है।

'वामदलों के पाखंड के चलते हिंदुत्ववादी ताकतें मजबूत हुईं'

बेंगलुरु, एजेंसियां : भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कट्टर आलोचक और जाने-माने इतिहासकार रामचंद्र गुहा ने वामपंथी दलों को निशाने पर लिया है। गुहा का कहना है कि वामदलों के पाखंड के चलते ही देश में हिंदुत्ववादी ताकतों को मजबूती मिली है। वामदलों को भारत से ज्यादा दूसरे देशों से लगाव है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी में नेतृत्व करने की क्षमता नहीं है। हालांकि, राहुल गांधी को लेकर दिए बयान पर विवाद होने पर शनिवार को उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि उनके बयान के कुछ हिस्से को ही उठाया गया, जबकि कई मुद्दों पर उन्होंने अपने विचार रखे थे।

कोझिकोड में शुक्रवार को केरल लिटरेचर फेस्टिवल (केएलएफ) के दूसरे दिन गुहा ने वामदलों पर जमकर प्रहार किया था। उनका कहना था कि वामदल पूरे देश में सिमटते जा रहे हैं। लेकिन वो मुगालते में हैं। यह वामदलों का पाखंड ही है, जिसके चलते हिंदुत्व आज इतना प्रभावी हो गया है। आज वामदल सिर्फ केरल में ही सत्ता में रह गए हैं। वामदल विश्वविद्यालयों, बुद्धिजीवियों, कलाकारों और फिल्म निर्माताओं के बीच ही प्रभावी हैं। वामदल वैचारिक रूप से पाखंडी हो गए हैं क्योंकि वो भारत से ज्यादा दूसरे देशों से प्यार करते हैं।

गुहा ने कहा कि हिंदुत्व का बढ़ना देश के लिए खतरा है। अगर हिंदुत्ववादी ताकतें इसी तरह मजबूत होती जाएंगी तो देश बर्बाद हो जाएगा। गौरतलब है कि केएलएफ में शुक्रवार को 'देशभक्ति बनाम अंधराष्ट्रीयता' विषय पर विचार रखते हुए गुहा ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी से मुकाबले के लिए एक विश्वसनीय और स्थिर विपक्ष की जरूरत है। राहुल गांधी में वो क्षमता नहीं है कि वो ऐसे विपक्ष को नेतृत्व दे सकें। 'पांचवीं पीढ़ी के राजवंशी' राहुल गांधी का कर्मठ नरेंद्र मोदी के सामने राजनीति में कोई भविष्य नहीं है। नरेंद्र मोदी सेल्फमेड हैं। उन्होंने 15 वर्षों तक एक राज्य को चलाया है। उनके पास प्रशासनिक अनुभव है। वह बेहिसाब मेहनती हैं और कभी छुट्टी पर यूरोप नहीं जाते। उन्होंने यह भी कहा था कि युवा भारत पांचवीं पीढ़ी का राजवंशी नहीं चाहता।

गुहा ने कहा था कि गांधी और नेहरू परिवार ने कांग्रेस के भीतर दूसरे नेतृत्व को पनपने नहीं दिया। भारत में तेजी से सामंतवाद खत्म हो रहा है और लोकतंत्र मजबूत हो रहा है, लेकिन कांग्रेस में ठीक इसके उलट हो रहा है। उन्होंने आगे कहा था, 'आप (सोनिया) दिल्ली में हैं, आपकी सल्तनत तेजी से सिमट रही है, लेकिन आपके चमचे आपको बता रहे हैं कि आप अभी भी बादशाह हैं।'

रामचंद्र गुहा फाइल

इतिहासकार रामचंद्र गुहा ने भाजपा से मुकाबले के लिए विश्वसनीय विपक्ष की जरूरत बताई

छत्तीसगढ़ में बजट बनाने के लिए सीएम ने जनता से मांगी राय

नईदुनिया, रायपुर

- भूपेश ने कहा- हम चाहते हैं कि आपकी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए बनाए जाने वाले बजट में हो आपकी भागीदारी

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नए वित्तीय वर्ष के बजट को लेकर एक अनूठी पहल की है। उन्होंने बजट के लिए जनता से सीधे सुझाव और राय मांगी है। सीएम ने ट्वीट और फेसबुक पर मैसेज पोस्ट किया है, जिसमें कहा है कि हम चाहते हैं कि आपकी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए बनाए जाने वाले बजट में आपकी भागीदारी हो। कृपया अपने सुझाव देकर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। इस अपील के साथ मुख्यमंत्री ने वाट्सएप नंबर और ई-मेल एड्रेस भी जारी किया है।

राज्य का इस बार का बजट एक लाख करोड़ के पार पहुंचने की उम्मीद की जा रही है। देश के अभी कुछ ही राज्य ऐसे हैं, जिनका बजट एक लाख करोड़ के पार जाता है। हालांकि, दो वित्तीय वर्षों से अनुपूरक बजट को शामिल करने के बाद राज्य का कुल बजट एक लाख करोड़ से अधिक का हो रहा है, लेकिन मुख्य बजट अब तक एक लाख करोड़ का नहीं आया है।

भूपेश बघेल फाइल

मंत्री स्तरीय चर्चा का दौर शुरू : इस बीच वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट को अंतिम रूप दिया जाने लगा है। इसके लिए मंत्री स्तरीय चर्चा का दौर शुरू हो गया है। शनिवार को मंत्री मोहम्मद अकबर ने मुख्यमंत्री और वित्त विभाग के अफसरों के साथ बैठकर अपने विभागों की नई योजनाओं के संबंध में चर्चा की। रविवार को ताम्रध्वज साहू के साथ बैठक होगी। यह सिलसिला 27 जनवरी तक चलेगा।

मध्य प्रदेश एटीएस करेगी सांसद प्रज्ञा ठाकुर को धमकी दिए जाने की जांच

राज्य ब्यूरो, भोपाल

- भोपाल पुलिस ने शनिवार शाम को सौंपी केस डायरी

भोपाल से भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को जान से मारने की धमकी भरा पत्र और संदिग्ध पाउडर भेजे जाने की जांच अब मध्य प्रदेश पुलिस की एटीएस (आतंकवाद निरोधक दस्ता) द्वारा की जाएगी। भोपाल पुलिस ने छह दिन बाद शनिवार को एटीएस को केस डायरी सौंप दी है। एटीएस ने तत्काल मामला दर्ज कर लिया। उधर, समाचार एजेंसी एएनआइ ने शनिवार को ट्वीट कर महाराष्ट्र के नांदेड़ से सैयद अब्दुल रहमान को हिरासत में लिए जाने की खबर दी, लेकिन एटीएस ने इसकी पुष्टि नहीं की।

सांसद प्रज्ञा ठाकुर को महाराष्ट्र के पुणे जिले के खड़की से स्वामी रामचंद्र अय्यर के नाम से भेजा किया गया एक पत्र मिला था। उर्दू में लिखे पत्र में धमकी दी गई थी तथा एक संदिग्ध पाउडर की पुड़िया भी मिली थी। इस मामले की छह दिन तक भोपाल पुलिस ने जांच की थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह व एनएसए अजीत डोभाल सहित सांसद प्रज्ञा ठाकुर को जान से मारने की धमकी से जुड़ा मामला होने से इसकी जांच एटीएस से कराए जाने का फैसला किया गया।

भोपाल पुलिस से केस डायरी मिलने के बाद एटीएस द्वारा जांच के लिए टीम बनाई जा रही है। हालांकि, प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार व सांसद का मामला होने की वजह से एटीएस द्वारा पहले दिन से ही केस पर नजर रखी जा रही थी। अब प्रकरण से जुड़े सूत्रों को जोड़कर तेजी से जांच शुरू की गई है।

नांदेड़ में संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में लेने की चर्चा : बताया जाता है कि इस मामले में महाराष्ट्र के नांदेड़ से एक संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है। इसका नाम सैयद अब्दुल रहमान बताया जा रहा है। इस बारे में जब एटीएस एडीजी राजेश गुप्ता से पूछा गया तो उन्होंने प्रकरण में फिलहाल किसी को हिरासत में लेने या गिरफ्तारी करने की बात से इन्कार किया है। सूत्र बताते हैं कि अभी तक की जांच में यह जरूर सामने आया है कि प्रकरण के तार महाराष्ट्र से जुड़े हो सकते हैं। इसके पीछे धमकी भरे पत्र पर पुणे का पता होना बताया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि इस पत्र में उर्दू भाषा में अंसार उल मुसलमिन संगठन के जिंदाबाद के नारे के साथ 26/11 मुंबई हमले और पुलवामा जैसे कई हमलों की धमकी भी दी गई थी।

साध्वी प्रज्ञा ठाकुर फाइल

राजपथ पर इस बार छग करेगा देशभर की झांकियों का नेतृत्व

नईदुनिया, रायपुर : गणतंत्र दिवस के मौके पर नई दिल्ली के राजपथ पर होने वाले मुख्य समारोह में देशभर की झांकियों का नेतृत्व इस बार छत्तीसगढ़ करेगा। राजपथ पर निकलने वाली विभिन्न राज्यों की झांकियों के क्रम में छत्तीसगढ़ राज्य की झांकी का क्रम सबसे पहले होगा। राज्य बनने के बाद संभवतः पहली बार राज्य को यह अवसर मिला है। राज्य की झांकी यहां के पारंपरिक शिल्प और आभूषणों पर आधारित है। झांकी के साथ बस्तर के 25 आदिवासी नर्तकों का दल भी शामिल होगा।

झांकी का निर्माण राष्ट्रीय रंगशाला कैंप नई दिल्ली में किया जा रहा है। राजपथ पर झांकी के साथ छत्तीसगढ़ के नर्तक दल ककसार नृत्य का प्रदर्शन करेंगे। जनसंपर्क विभाग के आयुक्त तारण प्रकाश सिन्हा ने शनिवार को नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय रंगशाला कैंप में जाकर राज्य की तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने सांस्कृतिक दलों से भी मुलाकात की और उनका उत्साहवर्धन किया। साथ ही छत्तीसगढ़ के दूरस्थ आदिवासी अंचल नारायणपुर से आए आदिवासी कलाकार रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति देकर रंग जमा रहे हैं। यही दल बाद में राष्ट्रपति व पीएम के समक्ष भी अपनी लोकनृत्य कला को प्रदर्शित करेगा।

पांच कठिन राउंड के बाद हुआ चयन : देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच पांच राउंड की कठिन चयन प्रक्रिया से गुजर कर छत्तीसगढ़ की झांकी का चयन हुआ है। महाराष्ट्र, दिल्ली, बिहार, उत्तराखंड, बंगाल, झारखंड जैसे कई राज्यों की झांकी का इस बार चयन नहीं हो पाया है। ऐसे में छत्तीसगढ़ की झांकी का चयन होना इस वजह से भी बड़ी बात है, क्योंकि पिछले वर्ष राज्य की झांकी का चयन नहीं हुआ था।

विरोध

विधानसभा परिसर में मुन्नालाल ने सरकार पर अफसरशाही हावी होने का लगाया आरोप, विधानसभा चुनाव के वचन-पत्र में गरीबों को पट्टे देने का वचन पूरा करने की मांग की

मप्र में अपनी ही सरकार के खिलाफ धरने पर बैठे कांग्रेस विधायक

नईदुनिया, भोपाल

मध्य प्रदेश में कांग्रेस विधायकों का पार्टी लाइन से हटकर विरोध जताने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। ताजा मामले में ग्वालियर (पूर्व) के विधायक मुन्नालाल गोयल ने अपनी ही सरकार के खिलाफ धरना दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार पर अफसरशाही हावी है, जो नेताओं को अपमानित कर रही है।

पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक माने जाने वाले गोयल अपने क्षेत्र के गरीबों की आड़ में सरकार के खिलाफ खड़े हो गए हैं। वे शनिवार सुबह अपनी मांगों के लिए गांधीवादी तरीके से विरोध जताने के लिए विधानसभा भवन पहुंचे। अवकाश होने के कारण प्रवेश द्वार पर बैरीकेड्स लगे थे, जिन्हें लांघते हुए वे परिसर में पहुंचे। गांधी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके बाद विधानसभा भवन के सामने मुख्य द्वार पर धरना दिया। धरने के दौरान मीडिया से चर्चा में गोयल ने आरोप लगाया कि प्रदेश में अफसरशाही हावी है। उन्होंने मुख्यमंत्री के सचिव अशोक वर्णवाल और ग्वालियर के एडीएम अनूपसिंह पर कांग्रेस नेताओं के अपमान का आरोप लगाया। साथ ही कहा कि वे अपनी कांग्रेस सरकार के खिलाफ धरना नहीं दे रहे हैं, बल्कि वे पार्टी द्वारा विधानसभा चुनाव में लोगों से वोट लेने के लिए जारी किए गए वचन-पत्र के वचनों को याद दिला रहे हैं। गोयल ने कहा कि वे अपने क्षेत्र के 1200 गरीबों को पट्टे दिलाने के लिए एक साल से प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि गरीबों को पट्टे देने का एक वचन विधानसभा चुनाव के वचन-पत्र में है। उन्हें पट्टे देने के बजाय उनके क्षेत्र के गरीबों के आशियाने उजाड़े जा रहे हैं।

यह पहला अवसर नहीं है, जब किसी कांग्रेस विधायक ने पार्टी गाइडलाइन से बाहर जाकर विरोध जताया हो। इससे पहले वरिष्ठ कांग्रेसी नेता दिग्विजय सिंह के छोटे भाई और विधायक लक्ष्मण सिंह के अलावा विधायक हरदीप सिंह डंग ने नागरिकता संशोधन कानून को लेकर पार्टी के तय मापदंडों से अलग बयान दिया था।

अपनी ही सरकार के खिलाफ धरने पर बैठे कांग्रेस विधायक मुन्नालाल गोयल (बाएं से तीसरे)। नईदुनिया

भाजपा ने किया जुबानी हमला

विधायक गोयल के धरना प्रदर्शन पर भाजपा को कांग्रेस पर जुबानी हमला करने का अवसर मिल गया है। मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने कहा कि प्रदेश में गूंगी-बहरी सरकार, विपक्ष और जनता तो दूर अब अपने ही विधायकों की नहीं रही। सुनीता पटेल और अब मुन्नालाल गोयल मुख्यमंत्री को वचन याद दिला रहे हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि सरकार की कार्यप्रणाली से उसके विधायक भी खुश नहीं हैं।

पार्टी के नेताओं को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा तय की गई रीति-नीति के अनुरूप व्यवहार करना चाहिए। उन्हें पार्टी की रीति-नीति के खिलाफ धरना-प्रदर्शन या बयान नहीं देना चाहिए।

- चंद्रप्रभाष शेखर, संगठन प्रभारी उपाध्यक्ष, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी

5 जिलों में हिमाचल में हिमस्खलन की चेतावनी जारी की गई है। ये जिले कुल्लू, लाहुल, चंबा, किन्नौर व शिमला हैं। प्रदेश में बर्फबारी और ओलावृष्टि के चलते 209 सड़कें बंद हो गई हैं।

न्यूज गैलरी

नक्सली संपर्क में उस्मानिया विवि के प्रोफेसर गिरफ्तार

हैदराबाद : उस्मानिया तेलंगाना पुलिस ने उस्मानिया विश्वविद्यालय में तेलुगु विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर सी. कासिम को नक्सलियों से संपर्क के शक में गिरफ्तार किया है। पुलिस ने शनिवार सुबह प्रोफेसर के आवास की तलाशी भी ली। इस दौरान कुछ दस्तावेज और इलेक्ट्रानिक सुबूत मिले हैं। सिद्दिपेट पुलिस आयुक्त डी जोएल डेविस ने कहा कि कुछ सुबूत मिले हैं। कासिम ने हाल में 'वीरसम' (क्रांतिकारी लेखक संघ) के महासचिव पद की जिम्मेदारी संभाली थी। उनकी पत्नी स्नेहलता ने आरोप लगाया कि उस्मानिया विवि के शिक्षक पर दर्ज मामला आधारहीन है। उन्होंने आरोप लगाया कि करीब 50 पुलिसकर्मी विवि परिसर स्थित उनके आवास पर सुबह आए और दरवाजा नहीं खोलने पर उसे तोड़ दिया। स्नेहलता ने कहा कि मुलुगु थाने में 2016 में दर्ज मामला कार हादसे से जुड़ा था और पुलिस ने उस समय दो किताबें बरामद की थीं जिसके लेखक कासिम थे और उस किताब के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज किया। भाकपा नेता नारायण ने सरकार पर जानबूझकर बुद्धिजीवियों को नक्सलियों से संबंध रखने का आरोप लगाकर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। (एएनआइ)

मोदी वाले बयान पर राहुल गांधी को समन

रांची : रांची सिविल कोर्ट ने शनिवार को मानहानि के एक मामले में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ समन जारी 22 फरवरी को पक्ष रखने का आदेश दिया है। न्यायिक दंडाधिकारी कुमार विपुल की अदालत में अधिवक्ता प्रदीप मोदी द्वारा दर्ज कराए गए 20 करोड़ रुपये की मानहानि के मामले में शनिवार को सुनवाई हुई। सिविल कोर्ट में दर्ज कराई गई इस शिकायत में कहा गया है कि राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान रांची के मोरहाबादी मैदान में कांग्रेस की सभा में नरेंद्र मोदी, नीरव मोदी, ललित मोदी का नाम लेने के साथ कहा कि जिनके नाम के आगे मोदी है, वे सभी चोर हैं। (राब्यू)

कोर्ट में हाजिर नहीं होने से हार्दिक पटेल गिरफ्तार

अहमदाबाद : राजद्रोह के मामले में अदालत में हाजिर नहीं होने के चलते सत्र न्यायालय की ओर से गैरजमानती वारंट जारी होने के बाद पुलिस ने पाटीदार नेता हार्दिक पटेल को गिरफ्तार कर लिया है। आरक्षण आंदोलन से चर्चित होने के बाद कांग्रेस में शामिल होने वाले हार्दिक एक बार फिर कानून के चंगुल में फंस गए हैं। अहमदाबाद में राजद्रोह के तहत दर्ज मुकदमे की पेशी पर हाजिर नहीं होने के चलते सत्र न्यायालय ने उनके खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी किया था। इसी के आधार पर पुलिस ने उन्हें गांव विरमगाम से गिरफ्तार कर लिया। (जासं)

प्रदीप और मनोज शाह दोषी करार

गुड़िया दुष्कर्म मामला ▸ 30 जनवरी को सुनाई जाएगी सजा, पिता ने कहा– मिले फांसी

जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली

बहुचर्चित गुड़िया सामूहिक दुष्कर्म मामले में शनिवार को कड़कड़डूमा स्थित पॉक्सो कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नरेश कुमार मल्होत्रा ने प्रदीप कुमार और मनोज शाह को दोषी करार दिया। 30 जनवरी को सजा सुनाई जाएगी। बच्ची के पिता और चाचा ने फैसले पर खुशी जाहिर की, लेकिन इसमें देरी पर दुख जताया। पिता ने कहा कि मैं चाहता हूं कि दोषियों को फांसी की सजा मिले।

न्यायाधीश ने अपने 100 पेज के फैसले में बहुत सख्त टिप्पणी की। इस मामले में 59 लोगों की गवाही हुई थी। अभियोग के मुताबिक 5 अप्रैल 2013 की शाम को बच्ची घर के बाहर गली में खेल रही थी। मनोज शाह वहां पहुंचा और उसे बहला-फुसलाकर अपने कमरे पर ले गया। यहां बच्ची को बंधक बनाया और जान से मारने की धमकी देकर अपने साथी प्रदीप के साथ मिलकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। दो दिन तक पीड़िता को बंधक बनाकर रखा और कई बार सामूहिक दुष्कर्म किया। दोषियों ने बच्ची के गुप्तांग में बोतल, मोमबत्ती और कई चीजें डाल दीं। इसके बाद उसको कमरे में बंद कर बाहर से ताला लगाकर फरार हो गए। दो दिन तक पीड़िता के परिवार वाले उसे ढूंढते रहे। पीड़िता ने हिम्मत करके अंदर से गेट खटखटाया। एक पड़ोसी ने आवाज सुनी। शक होने पर कमरे का दरवाजा तोड़ा तो बच्ची खून से लथपथ थी। गंभीर हालत में उसे एम्स में भर्ती कराया गया, जहां पांच सर्जरी हुईं।

इन धाराओं में ठहराया दोषी: कोर्ट ने प्रदीप कुमार और मनोज शाह को अपहरण, सामूहिक दुष्कर्म, हत्या की कोशिश, सुबूत मिटाने और पॉक्सो के तहत आइपीसी की धाराओं 342 (गलत बयान), 363(अपहरण), 376 (2)(गैंगरेप), 201(सबूतों से छेड़छाड़), 304 (हत्या की कोशिश), 377(अप्राकृतिक कृत्य)के तहत दोषी ठहराया।

मनोज ने मीडियाकर्मी पर बोला हमला: दोषी ठहराए जाने के बाद प्रदीप और मनोज के चेहरे पर कोई डर नहीं दिख रहा था। कोर्ट परिसर से बाहर निकलने के दौरान मनोज ने वीडियो बना रहीं एक महिला पत्रकार को थप्पड़ मार दिया। पत्रकार ने इसकी शिकायत सुनवाई कर रहे जज नरेश कुमार मल्होत्रा से की। उन्होंने पुलिस को पीड़िता की रिपोर्ट दर्ज करने का निर्देश दिया।

निर्भया के दोषी के दावे पर सुप्रीम कोर्ट 20 को करेगा सुनवाई

नई दिल्ली, प्रेट्र: उच्चतम न्यायालय निर्भया बलात्कार एवं हत्या मामले में मौत की सजा पाए पवन गुप्ता की याचिका पर 20 जनवरी को सुनवाई करेगा। उसका दावा है कि अपराध के समय वह नाबालिग था। दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा उसका दावा खारिज कर दिया गया है। इसे उसने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। जस्टिस आर भानुमति, अशोक भूषण और एएस बोपन्ना की पीठ उसकी याचिका पर सुनवाई करेगी। इसके साथ ही पवन ने अधिकारियों को फांसी की सजा पर अमल रोकने का निर्देश देने की भी अपील है। दोषियों को फांसी देने के लिए एक फरवरी की तारीख तय की गई है। उसने हाई कोर्ट के 19 दिसंबर के आदेश को चुनौती दी है, जिसमें उसके वकील को फर्जी दस्तावेज पेश करने और अदालत में हाजिर नहीं होने के लिए फटकार लगाई गई थी।

कानून के आधार पर तय होती है सजा

▸ प्रथम पृष्ठ से आगे

इस बीच, विशेषज्ञों का कहना है कि सजा या माफी को लेकर पीड़ित के परिजनों की राय का कानूनी आधार नहीं होता है। फैसला कानून के अनुसार ही होता है। हालांकि दया याचिका के समय दोषी इस तरह के बयानों को अपने पक्ष में इस्तेमाल जरूर कर सकते हैं। राज्यसभा सदस्य केटीएस तुलसी ने भी इंदिरा जयसिंह के बयान से असहमति जताई है। उन्होंने कहा कि भारत में मृत्युदंड को लेकर संतुलन बना हुआ है। पिछले 17 साल में सिर्फ चार लोगों को फांसी हुई है। निर्भया के मामले में बहुत बर्बरता हुई थी।

जल्लाद के लिए फिर पत्र लिखेगा जेल प्रशासन : डेथ वारंट आगे बढ़ने के बाद तिहाड़ जेल प्रशासन उत्तर प्रदेश के जेल विभाग को सोमवार को पत्र लिखकर जल्लाद को फांसी की तिथि से दो दिन पहले तिहाड़ जेल भेजने का आग्रह करेगा। फांसी के लिए पहले 22 जनवरी की तिथि निर्धारित की गई थी, जिसे अब पहली फरवरी कर दिया गया है। जल्लाद 30 जनवरी तक पहुंचेगा।

दोषियों के वकील को बार काउंसिल का नोटिस : दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर दिल्ली बार काउंसिल ने निर्भया के दोषी पवन कुमार गुप्ता के वकील एपी सिंह को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में जवाब मांगा है। पवन ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर घटना के समय नाबालिग होने का दावा किया था। पिछले साल 19 दिसंबर को हाई कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी थी।

ग्राहकों से बकाया राशि की वसूली की जाएगी

▸ प्रथम पृष्ठ से आगे

साथ ही बुकिंग कराने वाले ग्राहकों से बकाया राशि की वसूली की जाएगी। बैंकों से आसान दरों पर ऋण के लिए सरकार ने पहले ही 25 हजार करोड़ रुपये का एक कोष गठित कर दिया है, जिसका उपयोग पहले से फंसी आवासीय परियोजनाओं को पूरा करने में किया जाएगा। सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में जो प्रस्ताव पेश किया जाने वाला है उसमें बताया जाएगा कि रिटायर्ड आइएएस अधिकारी युद्धवीर मलिक को यूनिटेक का चेयरमैन व प्रबंधन निदेशक बनाने का फैसला किया गया है। इस बारे में सुप्रीम कोर्ट में काफी समय से मामला चल रहा है।

फॉरेंसिक ऑडिट में सामने आई थी धांधली: सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश पर यूनिटेक की फॉरेंसिक ऑडिट कराई गई थी। इसकी रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी की 74 परियोजनाएं ठप पड़ी हुई हैं, जिसमें 30 हजार से अधिक होम बायर्स ने मकान खरीदने के लिए 14270 करोड़ रुपये जमा कराया है। मकान की बुकिंग भी 10 से 12 साल पुरानी हो चुकी हैं। ऑडिट रिपोर्ट में हैरान करने वाले तथ्य सामने आए हैं। इसमें पाया गया है कि 5063 करोड़ रुपये का उपयोग इन आवासीय परियोजनाओं के बजाय कहीं और कर दिया गया है। ऑडिट में 2393 करोड़ रुपये का कुछ पता नहीं चला।

कोर्ट के निर्देश पर बढ़ा कदम: एक सुनवाई के दौरान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और एमआर शाह की खंडपीठ ने सरकार को निर्देश दिया था कि यूनिटेक के सभी निदेशकों को बर्खास्त कर उनकी जगह स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किए जाएं। सरकार का यह फैसला उसी निर्देश के अनुरूप है। सरकार के इस फैसले के साथ ही यह भी तय हो गया कि यूनिटेक कंपनी अब दिवालिया प्रक्रिया में नहीं जाएगी। सरकार के इस फैसले के अमल के साथ ही रियल एस्टेट सेक्टर में होम बायर्स का विश्वास लौटेगा और इस क्षेत्र के अटके बाकी प्रोजेक्ट को पूरा करने का विकल्प मिल जाएगा। सरकार को भी इस तरह के रास्ते की तलाश पहले से ही थी। हालांकि आठ दिसंबर, 2017 को एनसीएलटी ने अपने एक फैसले में कंपनी प्रबंधन को निरस्त करने इसका दायित्व स्वतंत्र निदेशकों को सौंपने को कहा था। रियल एस्टेट सेक्टर के लिए बनाए गए रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट (रेरा) में इस तरह का प्रावधान है कि अगर कंपनी परियोजनाओं को पूरा नहीं कर पाती है तो सरकार उसका प्रबंधन अपने हाथ में ले सकती है।

कश्मीरियों के नाम पर सियासत भी होगी कम

प्रथम पृष्ठ से आगे

कश्मीरी हिंदू वेलफेयर सोसाइटी के सदस्य चुन्नी लाल के मुताबिक उनके समुदाय के अधिकांश लोग कश्मीर से चले गए, लेकिन उनके जैसे करीब तीन हजार लोग वहां रहे। वह कहते हैं, हम लोगों की हालत आप देख सकते हैं। कुपवाड़ा, बारामुला समेत वादी के दूरदराज इलाकों में आतंकी हमलों से डरकर लोग श्रीनगर आ गए। हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं देता। जितनी सियासत कश्मीरियों के नाम पर हुई है, अब उसके समाप्त होने की उम्मीद की जा सकती है। रविवार को पूरी दुनिया में हम निर्वासन दिवस मनाएंगे।

सीबीआइ अधिकारी बनकर रिश्वत मांगने वाले दो गिरफ्तार

नई दिल्ली, प्रेट्र : सीबीआइ ने दो ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया है, जो सीबीआइ अधिकारी होने का दावा कर बैंक धोखाधड़ी मामले के एक आरोपित से रिश्वत मांग रहे थे और उसे धमकी दे रहे थे। हाल के समय में इस तरह का यह तीसरा मामला है। लोगों ने एजेंसी के लैंडलाइन नंबर से चकमा देकर उन मामलों के संदिग्धों से रिश्वत की मांग की, जिसकी जांच केंद्रीय एजेंसी कर रही है।

हैदराबाद के रहने वाले वाई मणिवर्द्धन रेड्डी एवं तमिलनाडु के मदुरै निवासी सेल्वम रामराज को गुरुवार को दर्ज किए गए मामले में एजेंसी ने गिरफ्तार किया।

उनके खिलाफ आरोप लगाया गया है कि केंद्रीय एजेंसी की जांच का सामना कर रहे विभिन्न लोगों से इन्होंने बड़े पैमाने पर न केवल रिश्वत की मांग की बल्कि उन्हें धमकाया भी। सीबीआइ के प्रवक्ता नितिन वकानकर ने बताया, 'उन्होंने बैंक धोखाधड़ी से संबंधित मामले के एक आरोपित से संपर्क किया और दिल्ली में तैनात जांच एजेंसी के एक वरिष्ठ अधिकारी के नाम पर उससे बड़े पैमाने पर रिश्वत की मांग की।' इसी मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया।

विशाल ने मुझे हाथ उठाने पर मजबूर किया : मधुरिमा तुली

एंटरटेनमेंट ब्यूरो, मुंबई

रियलिटी शो 'बिग बॉस' सीजन 13 के प्रतिभागी विशाल आदित्य सिंह और उनकी पूर्व प्रेमिका मधुरिमा तुली के बीच बढ़ते घमासान का आखिरकार पटापेक्ष हो गया। मधुरिमा को घर से बाहर निकाल दिया गया है। दोनों के बर्ताव से शो के मेजबान सलमान खान भी तंग आ गए थे। गुरुवार को प्रसारित एपिसोड में मधुरिमा ने विशाल को फ्राई पैन से मारा था। शनिवार को बिग बॉस के नियमों का उल्लंघन करने के कारण आखिरकार मधुरिमा को घर से बाहर निकाल दिया गया।

शो से बाहर आने के बाद मधुरिमा ने खास बातचीत में बताया कि वह काफी समय से विशाल के साथ रिश्ते को दोबारा पटरी पर लाने का प्रयास कर रही थीं, लेकिन उनका प्यार झूठा था। विशाल हमेशा उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते थे। हालात इतने बुरे हो गए थे कि उन्हें हाथ उठाना पड़ा। मधुरिमा कहती हैं, 'मुझे अफसोस है कि विशाल ने मुझे नकारात्मक इंसान बना दिया। मैं यह बर्दाश्त नहीं कर सकती कि

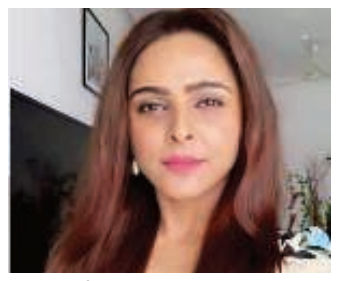

मधुरिमा तुली। फाइल

कोई लगातार मेरी बेइज्जती करे। उस वक्त मुझे जो सही लगा मैंने वह किया। इस घटना को लेकर मुझे सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह की प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं। कुछ लोग मेरे इस कदम की सराहना भी कर रहे हैं। आने वाले दिनों में देखना होगा कि मेरे इस घटना का मेरे करियर पर क्या प्रभाव पड़ता है।' विशाल को किसी भी हालत में दोबारा अपनाने से मधुरिमा ने इन्कार किया है। दोनों इससे पहले डांस रियलिटी शो 'नच बलिए' का भी हिस्सा रह चुके हैं। तब भी दोनों के बीच झगड़े, बहसबाजी और मारपीट की नौबत आई थी।

बेटी से दुष्कर्म के प्रयास मामले में गवाह रही मां की हत्या

जागरण संवाददाता, कानपुर : कानपुर के चकेरी क्षेत्र के जाजमऊ में नाबालिग संग दुष्कर्म के प्रयास के मामले में गवाह रही पीड़िता की मां की घर में घुसकर हत्या कर दी गई जबकि उसकी बहन जख्मी है। जाजमऊ स्थित शहीद का भट्टा निवासी परिवार वालों ने बताया कि 2018 में जाजमऊ निवासी बाबू भाई की टेनरी में नाबालिग से दुष्कर्म का प्रयास हुआ था। जिसमें पीड़िता की मां गवाह थी।

मामले में आरोपित बाबू भाई समेत जमील, फिरोज, महफूज, महबूब, पिंटू व वकील उसे गवाही न देने के लिए धमकाने के साथ मुकदमा वापस लेने का दबाव बना रहे थे। नौ जनवरी को आरोपितों ने घर में घुसकर चापड़ से जानलेवा हमला किया था। पुलिस ने दोनों को एलएलआर अस्पताल में भर्ती कराया था। शुक्रवार रात पीड़िता की घायल मां की मौत हो गई।

मुठभेड़ में दो और आरोपित पकड़े : पीड़िता के परिवार पर दबाव बनाने के लिए हमला कर किशोरी की मां की जान लेने वाले दो और आरोपित परवेज आलम उर्फ मिंटू और मो. आबिद को चकेरी पुलिस ने शनिवार तड़के मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया।

जब संसद खराब कानून बनाती है तो जज करते हैं सांसदों का काम : अंसारी

नई दिल्ली, प्रेट्र : पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने शनिवार को कहा कि जब संसद खराब कानून बनाती है तो उसका अंत किसी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में होता है और जजों को वह काम करना पड़ता है जो सांसदों को करना चाहिए।

▸ उपराष्ट्रपति ने कहा कि लोकतंत्र में लोगों की सहमति और लोगों की आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति महत्वपूर्ण है

'संसद-2020' नामक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए हामिद अंसारी ने कहा कि अच्छे कानून तब बनते हैं जब संसद और विधानसभाएं वर्तमान शासक के विचारों का अनुमोदन नहीं करतीं। लोकतंत्र में लोगों की सहमति और लोगों की आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति महत्वपूर्ण है। राज्यसभा के पूर्व सभापति ने कहा कि पहले संसद 10 दिनों के लिए बैठती थी, अब साल में 60 दिन के लिए बैठती है जबकि अन्य देशों में विधायिका की बैठकें 120 से 150 दिनों के लिए होती हैं। उन्होंने कहा कि कोई भी कानून या नियम बनाने के लिए उस पर चर्चा के लिए काफी समय की जरूरत होती है, लेकिन संसद और विधानसभाओं के सत्र आज रस्म अदायगी भर रह गए हैं जहां आप मिलते हैं, कुछ चीजें कहते हैं, कुछ दिन साथ रहते हैं और चले जाते हैं। अंसारी ने कहा कि लोकतांत्रिक प्रणाली में सलाह-मशविरे की प्रक्रिया निष्पक्ष और खुली होनी चाहिए।

एनआइए ने संभाला देविंदर से पूछताछ और जांच का जिम्मा

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर : राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) ने आतंकियों संग पकड़े गए जम्मू-कश्मीर पुलिस के निलंबित डीएसपी देविंदर सिंह के मामले की जांच का जिम्मा शनिवार को औपचारिक रूप से संभाल लिया। एनआइए ने एक एफआइआर दर्ज करने के साथ ही पुलिस से जरूरी दस्तावेज भी हासिल किए हैं। एनआइए उसे रविवार या सोमवार को आगे की पूछताछ के लिए दिल्ली ले जाएगी।

डीएसपी देविंदर सिंह को गत शनिवार को दक्षिण कश्मीर में श्रीनगर-जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर पुलिस के एक दस्ते ने हिजबुल मुजाहिदीन के दो नामी आतंकियों नवीद और आतिफ उर्फ आसिफ व लश्कर के ओवरग्राउंड वर्कर इरफान शफी मीर के साथ पकड़ा था। डीएसपी देविंदर सिंह की निशानदेही पर पुलिस ने उसके घर से हथियारों का एक जखीरा और बड़ी मात्रा में नकदी भी बरामद की। हालांकि, एनआइए के अधिकारियों का एक दल पहले ही दिन से राज्य पुलिस के साथ मिलकर देविंदर सिंह और उसके साथ पकड़े गए आतंकियों से पूछताछ में जुटा है।

केस डायरी न होने से बेहमई नरसंहार पर फिर टला फैसला

जागरण संवाददाता, कानपुर

▸ सत्र लिपिक को नोटिस देकर मूल केस डायरी पेश करने का आदेश

39 साल पहले बेहमई गांव में हुए नरसंहार में शनिवार को भी फैसला नहीं आ सका। इसका कारण निर्णय के लिए पेश की गई पत्रावली का अधूरा होना रहा। न्यायालय ने सत्र लिपिक को नोटिस देकर मूल केस डायरी पेश करने का आदेश दिया और अगली तारीख 24 जनवरी तय कर दी।

14 फरवरी-1981 को कानपुर देहात के सिकंदरा थाना क्षेत्र स्थित बेहमई गांव में फूलन देवी, मुस्तकीम, रामऔतार व लल्लू गैंग में शामिल 35-36 डकैतों ने धावा बोला था। उन्होंने घरों में लूटपाट के साथ ही 26 पुरुषों को गांव के बाहर ले जाकर अंधाधुंध फायरिंग की। इसमें 20 लोगों की मौत हो गई थी जबकि छह लोग घायल हो गए थे। मुकदमा दर्ज कराने के बाद 24 अगस्त-2012 को पांच अभियुक्तों भीखा, पोसे उर्फ पोसा, विश्वनाथ उर्फ पुतानी उर्फ कृष्ण स्वरूप, श्याम बाबू व राम सिंह के खिलाफ आरोप तय होने पर कोर्ट में ट्रायल शुरू हो सका। पांचों आरोपितों में से भीखा, विश्वनाथ उर्फ पुतानी व श्याम बाबू जमानत पर हैं जबकि पोसा व राम सिंह जेल में बंद थे। 13 फरवरी 2019 को जेल में राम सिंह की मौत हो गई। मामले की सुनवाई विशेष न्यायालय दस्यु प्रभावित कोर्ट में चल रही है। न्यायालय ने सुनवाई पूरी होने के बाद छह जनवरी फैसले की तिथि तय की थी लेकिन बचाव पक्ष ने कुछ रूलिंग पेश करने का समय मांगा तो न्यायालय ने 18 जनवरी की तारीख तय की। अब न्यायालय में पत्रावली पेश की गई तो मूल केस डायरी गायब थी। इससे फैसला फिर टल गया। न्यायालय ने सत्र लिपिक को नोटिस देकर मूल केस डायरी प्रस्तुत करने के आदेश दिए हैं। जिला शासकीय अधिवक्ता राजू पोरवाल ने बताया कि मूल केस डायरी पत्रावली में होनी चाहिए लेकिन उसकी जगह फोटोकापी है। न्यायालय ने मूल केस डायरी तलाश कर पेश करने के आदेश दिए हैं। अब 24 जनवरी को फैसला आने की उम्मीद है।

मुजफ्फरपुर बालिका गृह मामले में ब्रजेश की याचिका खारिज

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली: मुजफ्फरपुर बालिका गृह में बच्चियों के साथ हुए दुष्कर्म मामले में कोर्ट के निर्णय से पहले दाखिल की गई ब्रजेश ठाकुर की याचिका साकेत कोर्ट ने खारिज कर दी।

ब्रजेश ठाकुर की याचिका में कहा गया था कि सीबीआइ ने आठ जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में मामले में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की है, जिसमें साफ कहा गया कि जिन बच्चियों की हत्या के आरोप लगाए गए हैं उनमें से कई बच्चियां जिंदा हैं। ऐसे में बच्चियों के बयान को गंभीरतापूर्वक नहीं लिया जा सकता। अपील में सीबीआइ की रिपोर्ट के आधार पर निर्णय सुनाने से पहले ब्रजेश ठाकुर के पक्ष को दोबारा सुनने की बात कही गई थी। लेकिन, एडिशनल सेशन जज सौरभ कुलश्रेष्ठ ने साफ किया कि दोनों अलग तरह के मामले हैं। वह 20 जनवरी को अपना फैसला सुनाएंगे। जज सौरभ कुलश्रेष्ठ ने कहा कि बिहार में चल रहा मामला हत्या का है, जबकि उनके सामने बच्चियों के यौन उत्पीड़न का मामला है। ऐसे में ब्रजेश ठाकुर की याचिका को खारिज किया जाता है।

नृपेंद्र एनएमएमएल कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष बने

नई दिल्ली, प्रेट्र: प्रधानमंत्री के पूर्व प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्रा को नेहरू मेमोरियल संग्रहालय एवं पुस्तकालय (एनएमएमएल) की कार्यकारी परिषद का अध्यक्ष बनाया गया है। इस नियुक्ति के साथ ही एनएमएमएल सोसायटी और एनएमएमएल कार्यकारी परिषद का पुनर्गठन पूरा हो गया।

सरकार ने कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे, जयराम रमेश और कर्ण सिंह को परिषद के सदस्य पद से हटाते हुए पिछले साल नवंबर में एनएमएमएल सोसायटी का पुनर्गठन किया था। उसमें रजत शर्मा और प्रसून जोशी सहित अन्य को शामिल किया गया था।

संस्कृति मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक 74 वर्षीय मिश्रा को 14 जनवरी को एक आदेश जारी कर नियुक्त किया गया। उन्होंने अगस्त, 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव का पद छोड़ा था। आदेश में कहा गया है कि प्रसार भारती बोर्ड के अध्यक्ष ए. सूर्य प्रकाश परिषद उपाध्यक्ष होंगे।

एनएमएमएल सोसायटी के अध्यक्ष स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उपाध्यक्ष रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं। केंद्रीय मंत्री

नृपेंद्र मिश्रा। फाइल

अमित शाह, निर्मला सीतारमण, रमेश पोखरियाल निशंक, प्रकाश जावडेकर, वी. मुरलीधरन और प्रह्लाद सिंह पटेल, आइसीसीआर के अध्यक्ष विनय सहस्रबुद्धे, प्रसार भारती के अध्यक्ष ए. सूर्य प्रकाश को बतौर सदस्य शामिल किया गया है। इनके अलावा यूजीसी के अध्यक्ष, जवाहर लाल नेहरू मेमोरियल फंड के प्रतिनिधि राघवेंद्र सिंह इसके नए सदस्य हैं। अन्य सदस्यों में अनिर्बान गांगुली, सचिदानंद जोशी, कपिल कपूर, लोकेश चंद्रा, मकरंद परांजपे, किशोर मकवाना, कमलेश जोशीपुरा, रिजवान कादरी और आइजीएनसीए अध्यक्ष राम बहादुर राय शामिल हैं।

नक्सली हमले में एसपी समेत 29 की शहादत की होगी न्यायिक जांच

नईदुनिया, रायपुर: छत्तीसगढ़ सरकार ने करीब 11 वर्ष पहले 12 जुलाई 2009 में राजनांदगांव जिले के मदनवाड़ा में हुए नक्सली मुठभेड़ की न्यायिक जांच कराने का फैसला किया है। इस वारदात में राजनांदगांव के तत्कालीन एसपी (आइपीएस) विनोद कुमार चौबे समेत 25 जवान शहीद हो गए थे। सरकार ने इसके लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति शंभूनाथ श्रीवास्तव की अध्यक्षता में एक सदस्यीय आयोग का गठन किया है। जांच के लिए 11 बिंदु तय किए गए हैं। आयोग छह महीने में अपनी रिपोर्ट देगा।

12 जुलाई 2009 को राजनांदगांव के मदनवाड़ा कैंप से बाहर निकले जवानों पर नक्सलियों ने हमला कर दिया था। इसमें दो पुलिस कर्मी शहीद हो गए थे। वएसपी चौबे सुरक्षाबलों के साथ घटनास्थल के लिए रवाना हुए। रास्ते में ग्राम कोरकोट्टी के पास नक्सलियों ने घेर कर गोलीबारी शुरू कर दी। इसमें एसपी समेत 25 जवान शहीद हो गए थे। सरकार ने जांच आयोग के गठन की वजह भी बताई है। इसमें कहा गया है कि जांच में भ्रमों को दूर किया जाएगा।

उम्मीद

विहिप के संत सम्मेलन में होगी घोषणा, कई केंद्रीय पदाधिकारी पहुंचे, मंदिर निर्माण के दौरान शिला पूजन वाले गांवों में मनाया जाएगा रामोत्सव

रामनवमी से मंदिर निर्माण का श्रीगणेश संभव

ज्ञानेन्द्र सिंह, प्रयागराज

अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के श्रीगणेश की तिथि राम नवमी घोषित हो सकती है। विश्व हिंदू परिषद ने यह एलान किया है कि माघ मेला में 21 जनवरी को होने वाले संत सम्मेलन में अयोध्या में राम मंदिर निर्माण शुरू करने की तिथि घोषित की जाएगी। मंदिर निर्माण के शुभारंभ के दौरान देशभर के उन गांवों में रामोत्सव भी मनाया जाएगा, जहां 1989 में शिलापूजन कार्यक्रम हुए थे। आधारशिला समारोह में देश और विदेश से भी संत शिरकत करेंगे।

विश्व हिंदू परिषद ने यह भी कहा है कि संत सम्मेलन में ही मंदिर निर्माण के लिए गठित होने वाले ट्रस्ट को लेकर भी रणनीति बनेगी। सम्मेलन के एक दिन पहले 20 जनवरी को माघ मेला स्थित विहिप के शिविर में केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की महत्वपूर्ण बैठक होगी, जिसमें लगभग तीन सौ संत तथा पदाधिकारी शिरकत करेंगे। इस बैठक के लिए केंद्रीय पदाधिकारी पहुंचने लगे हैं। विहिप के संरक्षक दिनेश कुमार, केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल के संयोजक जीवेश्वर मिश्र,

राम मंदिर का मॉडल। फाइल फोटो

▸ आधारशिला समारोह में देश और विदेश से भी संत शिरकत करेंगे

▸ संत सम्मेलन में गठित होने वाले ट्रस्ट को लेकर भी रणनीति बनेगी

उपाध्यक्ष चंपत राय, विहिप की केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी पिसवे, केंद्रीय मंत्री राजेंद्र सिंह पंकज पहुंच चुके हैं। विहिप के अध्यक्ष वीएस कोगजे, कार्याध्यक्ष आलोक कुमार, महामंत्री मिलिंद परांडे, संगठन महामंत्री विनायक रविवार तक आ जाएंगे।

केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल के संयोजक जीवेश्वर मिश्र ने दैनिक जागरण को बताया कि मंदिर निर्माण की तिथि की घोषणा संत सम्मेलन में की जाएगी। तिथि मार्गदर्शक मंडल की बैठक में ही तय की जाएगी। कहा कि इसके लिए राम नवमी तिथि सबसे उपयुक्त है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि इस तिथि की घोषणा की जा सकती है। केंद्रीय मंत्री राजेंद्र सिंह पंकज ने भी कहा कि नवरात्र में यह दिन सबसे ज्यादा खास होता है, इसलिए इस दिन पर सहमति बन सकती है।

फिलहाल, यह केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल में ही तय होगा। विहिप के उपाध्यक्ष जीवेश्वर मिश्र ने यह भी बताया कि मंदिर निर्माण के लिए जिस दिन आधारशिला रखी जाएगी, उस समय शिलापूजन वाले गांवों व मोहल्लों में रामोत्सव मनाया जाएगा।

राम सुतार करेंगे श्रीराम की प्रतिमा का निर्माण

कुंदन तिवारी, नोएडा

अयोध्या में भगवान श्रीराम की 215 मीटर ऊंची विशालकाय मूर्ति स्थापित करने की कवायद प्रदेश सरकार ने शुरू कर दी है। उम्मीद है कि नौ फरवरी तक ट्रस्ट के गठन के साथ ही मूर्ति का निर्माण भी शुरू हो जाएगा। गुजरात में सरदार पटेल की 183 मीटर ऊंची प्रतिमा तैयार करने वाले नोएडा के मूर्तिकार राम सुतार को ही भगवान श्रीराम की मूर्ति के निर्माण का जिम्मा प्रदेश सरकार ने सौंपा है।

पिछले दिनों ही प्रदेश सरकार ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए 447 करोड़ रुपये का बजट भी आवंटित किया है। इस राशि से 61 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा। यह राशि निर्माण के लिए तकनीकी अध्ययन करने के लिए स्वीकृत 200 करोड़ रुपये के अलावा है। अयोध्या के मीरपुर गांव में 61 हेक्टेयर भूमि के अधिग्रहण के लिए 447.46 करोड़ रुपये की मंजूरी कैबिनेट की ओर से दी जा चुकी है। इससे भगवान राम की प्रतिमा,

भगवान राम की मूर्ति के दो प्रारूप सरकार को सौंपे गए थे। इसमें से पहले प्रारूप को संस्तुति प्रदान कर दी गई है। भगवान श्रीराम की मूर्ति के निर्माण का जैसे ही आदेश मिलेगा, कार्यशाला में काम शुरू कर दिया जाएगा।

–राम सुतार, मूर्तिकार

एक डिजिटल संग्रहालय, एक व्याख्यान केंद्र, एक पुस्तकालय, एक फूड प्लाजा, पार्किंग और पर्यटकों की जरूरत से जुड़ीं अन्य सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। मूर्ति के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए पिछले दिनों राज्य सरकार ने 200 करोड़ रुपये की मंजूरी दी थी।

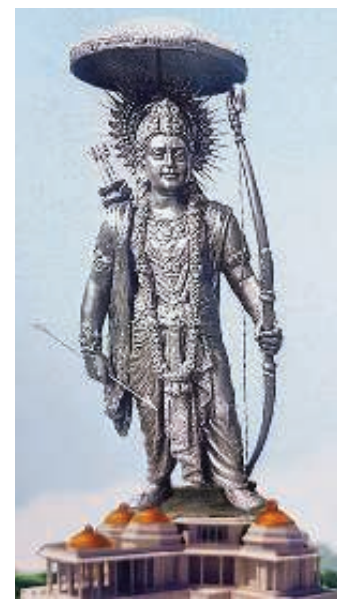

अयोध्या में स्थापित होने वाली भगवान श्रीराम की विशालकाय प्रतिमा का प्रारूप।

सौजन्य : राम व

70 वर्षों से उत्तर प्रदेश पुलिस 303 राइफल का इस्तेमाल कर रही है। अब 26 जनवरी के बाद इस राइफल का प्रयोग बंद कर दिया जाएगा यानी उत्तर प्रदेश पुलिस इसकी जगह दूसरे हथियारों का इस्तेमाल करेगी।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
रविवार 19 जनवरी 2020

विस्थापन के तीस साल की दुखभरी दास्तां

आज ही के दिन कश्मीरी पंडितों की काली यादों के तीस साल पूरे हो रहे हैं। सामने 19 जनवरी, 1990 का वो दिन है और इतिहास फिर कटघरे में है। इसी दिन कश्मीरी पंडितों को कश्मीर छोड़ने का फरमान सुनाया गया था। जिन घरों में उन लोगों की किलकारियां गूंजी, जिनमें उन्होंने लोरियां सुनी, पुरखों की निशानियां, यार-दोस्तों से जुड़ी यादें सब एक एक झटके में बहुत पीछे छूट गए। पुनर्वास योजना के तहत पिछले तीस सालों में सिर्फ एक परिवार कश्मीर लौटा है तो किसी में अनुच्छेद 370 के खात्मे के बाद वापस लौटने की आस जगी।

खाली होते गए घर

कश्मीर में आतंकवाद का दौर शुरू होने से पहले वादी में 1242 शहरों, कस्बों और गांवों में करीब तीन लाख कश्मीरी पंडित परिवार रहते थे। फिर 242 जगहों पर सिर्फ 808 परिवार रह गए। आतंकवादियों के फरमान के बाद कश्मीर से बेघर हुए कश्मीरी पंडितों में से सिर्फ 65 हजार कश्मीरी पंडित परिवार जम्मू में पुनर्वास एवं राहत विभाग के पास दर्ज हुए।

तीस साल में लौटा सिर्फ एक परिवार

प्रधानमंत्री पैकेज के तहत कश्मीरी पंडितों की घर वापसी के लिए करीब छह हजार नौकरियां देने की घोषणा हुई थी। तत्कालीन राज्य सरकार की ढुलमुल नीति के कारण लगभग 2200 पदों पर ही नियुक्तियां हुई हैं। जिन पदों पर नियुक्तियां हुई है वो लोग भी अपने परिवारों को कश्मीर नहीं ले जा पाए हैं। या तो उनकी संपत्ति और बगीचों पर कब्जा हो चुका है या फिर उन्हें जला दिया गया है। पैकेजों के तहत साल 2015 में सिर्फ एक ही कश्मीरी पंडित परिवार बीते 30 सालों के दौरान कश्मीर लौटा है।

श्रीनगर के पास खीर भवानी मंदिर, यहां कश्मीरी पंडित पूजा करने आते हैं।

दिल्ली में कश्मीरी पंडित पुनर्वास के लिए प्रदर्शन करते हुए। ● फाइल फोटो

- भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर को लेकर माहौल 1980 के बाद बदल चुका था। रूस अफगानिस्तान पर चढ़ाई कर चुका था और अमेरिका उसे वहां से निकालने की फिराक में था। इसके लिए अफगानिस्तान के लोगों को मुजाहिदीन बनाया जाने लगा।
- जब पुलिस ने कार्रवाई की तो कुछ मुसलमानों के मारे जाने पर कहा जाने लगा कि कश्मीरी काफिर दुश्मन हैं।
- कश्मीर में करीब 5 प्रतिशत पंडित थे। हालांकि कई जगह 15-20 प्रतिशत तक भी कहा जाता है।

महत्वपूर्ण तिथियां

- 1986 में गुलाम मोहम्मद शाह ने अपने बहनोई फारुख अब्दुल्ला से सत्ता छीन ली और मुख्यमंत्री बन गये। एलान हुआ कि जम्मू के न्यू सिविल सेक्रेटेरिएट एरिया में एक पुराने मंदिर को गिराकर मस्जिद बनवाई जाएगी तो लोगों ने प्रदर्शन किया। जवाब में कट्टरपंथियों ने नारा दे दिया कि इस्लाम खतरे में है। इसके बाद कश्मीरी पंडितों पर धावा बोल दिया गया।
- 4 जनवरी 1990 को उर्दू अखबार आफताब में हिजबुल मुजाहिदीन ने छपवाया कि सारे पंडित कश्मीर छोड़ दें। चौराहों और मस्जिदों में लाउडस्पीकर लगाकर कहा जाने लगा कि पंडित यहां से चले जाएं। अपनी औरतों को यहीं छोड़ जाएं। इसके बाद हत्याएं और दुष्कर्म की घटनाएं सामने आने लगीं।

इन्हें चाहिए

कश्मीरी पंडित चाहते हैं कि उनके लिए कश्मीर में एक अलग होमलैंड बने जिसे केंद्र शासित राज्य का दर्जा मिले। राज्य के सभी सियासी दल इसका विरोध करते हैं। कांग्रेस व भाजपा भी प्रत्यक्ष रूप से इसकी समर्थक नजर नहीं आती। अगर यह संभव न हो तो राज्य में उनको एकसाथ बसाया जाए ताकि वह अपनी संस्कृति और धार्मिक मान्यताओं को जीवित रख सकें। इसके अलावा वे चाहते हैं कि पिछली सदी के आखिरी दशक में उनके मकानों व जमीन जायदाद पर हुए कब्जों को केंद्र व राज्य सरकार छुड़ाए या फिर जिन लोगों को अपनी सपंत्ति बेचनी पड़ी थी, उसे वह वापस दिलाई जाए।

भाषणों तक सीमित रहा भाईचारा

राज्य की सत्ता चंद लोगों के हाथ में रही और उन्होंने कभी पंडितों की घर वापसी के लिए कोई प्रयास नहीं किए। कश्मीरी पंडितों से भाईचारा केवल भाषणों तक ही रहा और लाखों परिवार तीन दशक तक वही दर्द झेलते रहे।

आपबीती : बहन-बेटियों के बारे में अपशब्द लिखे जाते थे

मैं 18 साल का था जब कश्मीर छोड़ने का एलान हुआ और हम घर के साथ पुरानी यादों को छोड़कर चल दिए। करते भी क्या..हमारी बहन-बेटियों के बारे में दीवारों पर अपशब्द लिखे जाते थे। घरों पर पत्थर फेंके जाते थे। जान बचाते या घर। सब कुछ याद करके आज भी रूह कांप जाती है।

सुनील पंडिता, कश्मीरी पंडित

अब जगी उम्मीद

अनुच्छेद 370 के कारण एक सेक्यूलर भारत में कश्मीर इस्लामिक राज्य की तरह बन गया था। अब देश का संविधान लागू होने के कारण हमें उम्मीद जगी है कि हमारे भी अच्छे दिन लौट सकते हैं। केंद्र से अपेक्षा है कि हमें अपनी धरती पर बसाने के लिए ठोस निर्णय लेगी और कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी।

अजय चुरंगु, पनून कश्मीर के चेयरमैन

न्यूज गैलरी

पाक सेना ने लाम व मेंढर सेक्टर में की भारी गोलाबारी

जम्मू : पाकिस्तानी सेना ने शनिवार को एलओसी पर राजौरी के उप जिला नौशहरा के लाम सेक्टर और पुंछ जिले के मेंढर सेक्टर में भारी गोलाबारी की। भारत ने भी इसका करार जवाब दिया। देर शाम तक रुक-रुक कर गोलाबारी जारी रही। इसमें फिलहाल किसी नुकसान की सूचना नहीं है। जानकारी के अनुसार, शनिवार देर शाम पाक सेना ने लाम सेक्टर में सैन्य चौकियों के साथ-साथ रिहायशी क्षेत्रों को निशाना बनाकर गोलाबारी शुरू कर दी। इस दौरान पाक सेना ने कई मोर्टार दागे। भारतीय सेना ने भी जवाबी कार्रवाई की। इससे पहले दोपहर करीब साढ़े बारह बजे पाक ने मेंढर में पहले भारतीय सेना की अग्रिम चौकियों पर छोटे हथियारों से गोलाबारी की। भारतीय सेना ने जवाबी कारवाई की तो पाकिस्तान ने भारत के रिहायशी इलाकों में मोर्टार दागने शुरू कर दिए, जो दोपहर डेढ़ बजे तक जारी रही। (जेएनएन)

सावरकर के विचार हमेशा प्रासंगिक रहेंगे : फडनवीस

प्रथम पृष्ठ के आगे

मुंबई, प्रेट्र: महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता देवेंद्र फडनवीस ने कहा है कि सावरकर सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, बल्कि विचार का नाम है, जिसकी प्रासंगिकता हमेशा बनी रहेगी। आदित्य ठाकरे द्वारा अतीत को छोड़ वर्तमान के मुद्दों पर बात करने की नसीहत देने पर उन्होंने यह टिप्पणी की है। फडनवीस ने कहा कि विचार कभी भी इतिहास नहीं हो सकता। यह हमारे वर्तमान के साथ भविष्य में भी बना रहता है।

'केंद्र शासित प्रदेश बनने से लोगों को अधिक फायदे मिले'

आउटरीच कार्यक्रम ▶ जम्मू के कन्वेंशन सेंटर में बोले केंद्रीय राज्यमंत्री

राज्य ब्यूरो, जम्मू

पीएमओ में राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि जम्मू-कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बनने से राज्य के लोगों को कल्पना से ज्यादा फायदे मिले हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का पुण्य काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों हुआ है। इसके लिए शायद हमें इसलिए इतना इंतजार करना पड़ा कि परमात्मा को भी यही मंजूर था कि कोई मोदी जी जैसा महापुरुष धरती पर उतरे और यह पुण्य काम उनके हाथों से हो।

पब्लिक आउटरीच कार्यक्रम के तहत जम्मू पहुंचे डॉ. जितेंद्र सिंह ने कन्वेंशन सेंटर में संबोधित करते हुए कहा कि 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद लोगों को कल्पना के परे फायदे मिले हैं। लखनपुर टोल पोस्ट को हटाया गया। केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद जम्मू-कश्मीर में सारे केंद्रीय कानून लागू हो रहे हैं। गैर कानूनी गतिविधियां का कानून लागू हुआ, जिसमें संलिप्त लोग पकड़े गए। कर्मचारियों के वेतन में फायदा हुआ। सूचना अधिकार कानून, बाल शोषण रोकथाम कानून, भ्रष्टाचार रोकथाम कानून समेत सभी केंद्रीय कानून लागू हो रहे हैं।

परिसीमन के साथ विस क्षेत्र आरक्षित भी होंगे: जितेंद्र सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों को भूमि अधिकार और डोमिसाइल पर केंद्र सरकार काम कर रही है। परिसीमन आयोग गठित करने की मांग करने वालों पर कटाक्ष करते हुए कहा कि परिसीमन भी होगा, लेकिन यह भी समझ लेना चाहिए इसमें विधानसभा क्षेत्र आरक्षित भी होंगे। अनुच्छेद हटने से पश्चिमी पाकिस्तान और गुलाम कश्मीर के रिफ्यूजियों के साथ इंसाफ हुआ है। सेल्फ रूल और स्वायत्तता का जिक्र करते हुए जितेंद्र सिंह ने कहा कि आज वो कहां पर हैं। जमीनी स्तर पर लोगों को अधिकार मिलना क्या सेल्फ रूल नहीं है। उद्योगों को बढ़ावा दिया जा रहा है और जम्मू कश्मीर में निवेश के लिए अप्रैल में निवेशक सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है।

जुगल बोले, विकास का नया अध्याय शुरू हुआ: सांसद जुगल किशोर ने कहा कि मोदी सरकार के समय में यह पहली बार है जब केंद्रीय मंत्री लोगों तक पहुंच बनाकर उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं। अनुच्छेद 370 हटने के बाद केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में विकास का नया अध्याय शुरू हुआ है। लोगों की समस्याओं का समाधान किया जा रहा है।

जितेंद्र सिंह। फाइल

मौसम ने रोकी केंद्रीय मंत्रियों की राह, श्रीनगर से होकर पहुंचे जम्मू

राज्य ब्यूरो, जम्मू : केंद्र शासित जम्मू-कश्मीर में लोगों को अनुच्छेद 370 की समाप्ति के बाद शुरू हुए विकास के दौर के बारे में समझाने के लिए शनिवार को आए तीन मंत्रियों की राह मौसम ने रोक ली। उन्हें जम्मू लेकर आ रहे विमान को खराब मौसम के चलते श्रीनगर जाना पड़ा। दोपहर बाद विमान से जम्मू पहुंचे। पीएमओ में राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री अश्विनी चौबे और संसदीय राज्यमंत्री अर्जुन मेघवाल का शनिवार को जम्मू-कश्मीर के दो दिवसीय दौरे का पहला दिन था। आज इन्हें जम्मू में विभिन्न जनसभाओं को संबोधित करना था। लेकिन देरी से जम्मू पहुंचने के चलते मंत्रियों के निर्धारित कार्यक्रमों को भी नए सिरे से शेड्यूल करना पड़ा।

गौरतलब है कि केंद्र सरकार के 36 मंत्री 18 से 25 जनवरी तक जम्मू-कश्मीर के विभिन्न इलाकों में क्रमानुसार दौरे कर स्थानीय लोगों को बीते पांच माह के बाद जम्मू-कश्मीर में हुए विकास, केंद्र सरकार द्वारा स्थानीय लोगों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए किए जा रहे कार्यों से अवगत कराएंगे।

जम्मू में बहाल की गई पोस्टपेड पर टू-जी मोबाइल इंटरनेट सेवा

राज्य ब्यूरो, जम्मू : जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने राज्य में प्री-पेड मोबाइल सेवा को बहाल कर दिया है। अब सभी प्री-पेड मोबाइल सेवा पर वायस कॉल हो पाएगी और लोग एसएमएस सेवा का लाभ भी उठा पाएंगे। वहीं, जम्मू संभाग के सभी 10 जिलों में पोस्ट पेड पर टू-जी स्पीड मोबाइल इंटरनेट सेवा को भी बहाल कर दिया गया है। यह जानकारी शनिवार को राज्य प्रशासन के प्रवक्ता रोहित कंसल ने पत्रकार वार्ता में दी।

कश्मीर संभाग के दो जिलों कुपवाड़ा और बांडीपोरा में टू-जी मोबाइल इंटरनेट सेवा बहाल करने के आदेश दिए गए हैं। कश्मीर के शेष बचे आठ जिलों में गांदरबल, श्रीनगर, शोपियां, पुलवामा, कुलगाम, अनंतनाग, बारामुला, बड़गाम में फिलहाल मोबाइल इंटरनेट सेवा पर रोक रहेगी। कंसल ने कहा कि टू-जी मोबाइल सेवा पर उपभोक्ता 153 व्हाइट लिस्ट वेबसाइटों का इस्तेमाल कर सकते हैं। व्हाइट लिस्ट वेब साइटों में मेल भेजने, बैंकिंग सेक्टर, शिक्षा, मनोरंजन, पर्यटन, ऑटोमोबाइल, सुविधाओं वाली आदि साइट भी शामिल हैं।

लोगों को संचार सेवाओं का फायदा देने के लिए जो कंपनियां साफ्टवेयर या आइटी में काम करती हैं, उन्हें फिक्सड लाइन इंटरनेट सेवा उपलब्ध करवाई जाएगी, ताकि उपभोक्ता फायदा उठा सकें। कंपनियों को गृह विभाग के आदेश का पालन करना होगा। प्री-पेड मोबाइल सिम पर इंटरनेट का फायदा लेने के लिए कंपनियों को पोस्ट पेड सेवाओं की तर्ज पर वेरीफिकेशन करनी होगी। हालांकि, मोबाइल कंपनियों को यह सख्त हिदायत दी गई है कि सेवा शुरू होने पर जम्मू-कश्मीर के उपभोक्ता मोबाइल पर किसी भी तरह की सोशल मीडिया साइट्स न खोल पाएं।

जिलेटिन छड़ व डेटोनेटर का इस्तेमाल करने लगे आतंकी

नवीन नवाज, जम्मू

कश्मीर में अमन बहाली से हताश आतंकी संगठन बड़ी साजिश रच रहे हैं। इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइसेस (आइईडी) तैयार करने में आतंकियों ने आरडीएक्स के बजाय अब जिलेटिन की छड़ों और डेटोनेटर का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। दरअसल दोनों कश्मीर में आसानी से मिल जाती हैं। आतंकी निर्माण कार्यों व उत्खनन में लिप्त ठेकेदारों से छड़ें और डेटोनेटर चोरी छिपे ले रहे हैं।

सुरक्षाबलों ने कश्मीर में आतंकियों द्वारा आइईडी तैयार करने में जिलेटिन और डेटोनेटर इस्तेमाल किए जाने की नई रणनीति का पर्दाफाश गत दिनों श्रीनगर में पकड़े गए जैश के पांच आतंकियों से पूछताछ के आधार पर किया है। पांचों आतंकी गणतंत्र दिवस पर श्रीनगर में बड़ी वारदात को अंजाम देने वाले थे। इनके कब्जे से मानव बम वाली जैकेट के अलावा 200 जिलेटिन की छड़ें और बड़ी मात्रा में डेटोनेटर भी बरामद हुए हैं। ये आतंकी गत दिनों श्रीनगर के हबक और कश्मीरी विश्वविद्यालय के पास हुए बम धमाकों में भी शामिल रहे हैं। पूछताछ में आतंकियों ने बताया कि एलओसी पर लगातार बढ़ती चौकसी और घुसपैठ की कोशिशों के नाकाम होने के कारण कश्मीर में जिहादी संगठनों के पास हथियार-विस्फोटकों की भारी कमी हो चुकी है। सरहद पार से कश्मीर में आरडीएक्स, ब्लैक एक्सप्लोसिव, प्लास्टिक एक्सप्लोसिव, ग्रेनेड की सप्लाई न्यूनतम स्तर पर पहुंच चुकी है। इसलिए अब जिहादी संगठन वादी में आसानी से उपलब्ध रसायनों और विस्फोटकों को इस्तेमाल कर रहे हैं।

गत वर्ष भी पकड़ी गई थीं विस्फोटक छड़ें

राज्य पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि गत वर्ष जुलाई में पुलवामा में हुए आइईडी विस्फोट में जिलेटिन और डेटोनेटर के इस्तेमाल होने की बात सामने आई थी। गत दिनों सोपोर के पास पकड़ी आइईडी में आरडीएक्स के अलावा जिलेटिन विस्फोटक छड़ें भी थी। उन्होंने बताया कि कश्मीर में विभिन्न इलाकों में बड़ी परियोजनाओं के निर्माण और पत्थर खदानों व पहाड़ों को काटने में जिलेटिन की छड़ों का इस्तेमाल हो रहा है। ऐसे में यह संबंधित निर्माण एजेंसियों और ठेकेदारों को उनके कोटे व लाइसेंस पर सरकारी काउंटरों से उपलब्ध कराया जाता है। जिन ठेकेदारों को यह उपलब्ध होती हैं उनका पूरा हिसाब भी लिखा जाता है। इसलिए यह पता लगाया जा रहा है कि आतंकियों तक यह कैसे पहुंच रही हैं। जैश आतंकियों ने विस्फोटक को जिस व्यक्ति से प्राप्त किया है उसकी भी तलाश की जा रही है। यह भी पता लगाया जा रहा है कि क्या किसी ठेकेदार ने जिलेटिन छड़ें और डेटोनेटर चोरी होनी की कोई रिपोर्ट लिखाई है। उन्होंने कहा कि आतंकवादियों तक जिलेटिन पहुंचाने में खदान मालिक-कर्मचारी या फिर सरकारी काउंटर पर तैनात कर्मचारी मदद कर रहें हैं। इसकी जांच की जा रही है।

आम्रपाली ग्रुप के निदेशक ईडी की रिमांड पर

जागरण संवाददाता, लखनऊ

▶ **आरोपितों पर छह सौ करोड़ रुपये से अधिक के घोटाले का है आरोप**

करोड़ों रुपये के घोटाले के आरोपित आम्रपाली ग्रुप के निदेशक अनिल कुमार शर्मा एवं शिव प्रिया को ईडी अदालत के विशेष न्यायाधीश एवं जिला जज अनिल कुमार ओझा ने सात दिन के लिए ईडी को रिमांड पर देने का आदेश दिया है।

दोनों आरोपितों को ईडी द्वारा सुबह करीब 12 बजे अदालत के समक्ष पेश किया गया। इन आरोपितों पर छह सौ करोड़ रुपये से अधिक के घोटाले का आरोप है। इसके पूर्व ईडी की ओर से विशेष अदालत के समक्ष अर्जी प्रस्तुत कर कहा गया था कि दोनों आरोपित मंडोली जेल में दिल्ली में निरुद्ध हैं, जिनसे ईडी पूछताछ करना चाहती है। लिहाजा उन्हें मंडोली जेल से तलब किया जाए। अदालत के आदेश के बावजूद उन्हें पेश न करने पर ईडी की ओर से सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष आग्रह किया गया था। जिस पर सर्वोच्च न्यायालय ने 2017 में विक्रम चटर्जी एवं अन्य की ओर से दाखिल याचिका पर निर्देश दिया था कि निदेशक अनिल कुमार शर्मा एवं शिव सुप्रिया को पूछताछ के लिए ईडी को सात दिन के लिए अभिरक्षा में दिया जाए तथा अभिरक्षा अवधि समाप्त होने के बाद फिर उन्हें मंडोली जेल दिल्ली भेज दिया जाए।

सर्वोच्च न्यायालय के इस आदेश के परिप्रेक्ष्य में ईडी ने शनिवार को दोनों आरोपितों को कस्टडी रिमांड पर लिए जाने के लिए अलग- अलग आवेदन प्रस्तुत किया। इन अर्जियों पर बचाव पक्ष के वकीलों का तर्क था कि आरोपित को समय-समय पर डॉक्टरों द्वारा बताई दवाएं एवं रिमांड अवधि के दौरान अधिवक्ता को रहने की अनुमति दी जाए। इसके अलावा रिमांड अवधि में उन्हें पूर्ण सुरक्षा मुहैया कराई जाए। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का हवाला देते हुए कहा गया है कि आरोपितों का नियमानुसार डाक्टरी परीक्षण कराया जाए तथा हर 24 घंटे के अंदर मेडिकल चेकअप कराया जाए। कोर्ट ने कहा है कि अनिल कुमार को विशेष चिकित्सा दी जा रही है लिहाजा, उसे समय-समय पर दवा दी जाए।

कार दुर्घटना में शबाना आजमी घायल, हालत स्थिर

एंटरटेनमेंट ब्यूरो, मुंबई

दुर्घटना में शबाना आजमी जी के चोटिल होने की खबर चिंताजनक है। मैं उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं।
– **नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री**

फिल्म अभिनेत्री शबाना आजमी की टाटा सफारी कार शनिवार शाम मुंबई-पुणे एक्सप्रेस हाईवे पर खालापुर टोल नाके पास ट्रक से भिड़ गई। इस हादसे में शबाना को काफी चोटें आई हैं। बताते हैं कि वहां मौजूद स्थानीय लोगों ने उन्हें कार से निकालने में मदद की। पैसेंजर सीट की तरफ का पूरा हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त था। उन्हें पनवेल के पास स्थित एमजीएम अस्पताल में भर्ती करवाया गया। शुक्रवार को ही उन्होंने अपने पति जावेद अख्तर का 75वां जन्मदिन काफी धूमधाम से मनाया था।

स्थानीय पुलिस ने बताया कि कार ड्राइवर दूसरे वाहन को ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा था और ट्रक से जा भिड़ा। एमजीएम अस्पताल से मिली जानकारी के मुताबिक, शबाना को शाम तकरीबन साढ़े चार बजे अस्पताल लाया गया। कैजुअल्टी में उन्हें डॉक्टरों ने फर्स्ट एड दिया। न्यूरो और ऑर्थो डिपार्टमेंट के डॉक्टरों ने उनकी जांच की। सीटीस्कैन भी किया गया। कैजुअल्टी में मौजूद डॉक्टरों ने बताया कि शबाना आजमी के सिर और चेहरे के अलावा रीढ़ की हड्डी में भी चोट लगी है। हालांकि उनकी हालत स्थिर है, वह बातचीत कर रही हैं और उनका रक्तचाप भी सामान्य था। अस्पताल में उनके साथ जावेद अख्तर भी मौजूद थे। अस्पताल के लोगों का कहना है कि जावेद इस एक्सीडेंट में सुरक्षित बच गए क्योंकि वह अलग कार में थे, जिसमें उनके साथ कुछ और लोग भी थे। शबाना आजमी अपनी कार में अकेली थीं। बाद में शबाना आजमी को कोकिलाबेन अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया।

शबाना के दुघर्टना में घायल होने की खबर फैलते ही सोशल मीडिया पर उनके स्वस्थ होने को लेकर राजनेताओं और फिल्म बिरादरी से जुड़े लोगों ने ट्वीट करना शुरू कर दिया। उनके चोटिल होने की फोटो भी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हुई। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक चव्हाण ने ट्वीट किया कि एमजीएम अस्पताल के डॉक्टरों से बात हुई है। मैं उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। कांग्रेस नेता संजय निरूपम ने भी उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हुए ट्वीट किया। फिल्ममेकर हंसल मेहता ने लिखा, 'मुंबई-पुणे हाईवे काफी खतरनाक है। वहां पर रैश ड्राइविंग को रोकने के लिए कोई मॉनीटरिंग नहीं हैं। उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के ऑफिस को टैग करते हुए इस मार्ग की सुरक्षा को लेकर तत्काल सुधार करने का आग्रह किया।

मुंबई के समीप मुंबई-पुणे एक्सप्रेस-वे पर शनिवार को वाहन दुर्घटना में घायल अभिनेत्री शबाना आजमी। उनकी टाटा सफारी कार ट्रक से भिड़ गई थी। प्रेट्र

बीएसएफ भर्ती परीक्षा में धांधली पर सीबीआइ के दिल्ली-एनसीआर में छापे

नई दिल्ली, प्रेट्र : सीबीआइ ने बीएसएफ कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में कथित धांधली को लेकर दिल्ली-एनसीआर में शनिवार को छापे मारे। ये छापे दिल्ली, गाजियाबाद और गुरुग्राम में मारे गए हैं। आरोप है कि उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में गड़बड़ी की गई है। अधिकारियों ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज करने के बाद जांच एजेंसी ने छापेमारी की। सीबीआइ ने गाजियाबाद के सुराना निवासी रवि कुमार और नई दिल्ली के पटपड़गंज औद्योगिक क्षेत्र के सीएस डाटामेशन रिसर्च सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के अलावा कई अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। जांच एजेंसी ने कहा है कि भर्ती परीक्षा के ओएमआर शीट के मूल्यांकन के दौरान गड़बड़ी की गई है। सीबीआइ इस मामले में बीएसएफ अधिकारियों के साथ ही पटपड़गंज इंडस्ट्रीयल एरिया में स्थित प्राइवेट फर्म की भूमिका का पता लगाने में जुटी है। इस प्राइवेट फर्म को मूल्यांकन प्रक्रिया का काम आउटसोर्स किया गया है। अधिकारियों ने कहा कि परीक्षा में कथित अनियमितता के चलते अयोग्य उम्मीदवारों को बीएसएफ ने मेडिकल जांच के लिए बुलाया गया।

पहल

मध्य प्रदेश की आलीराजपुर पुलिस का 'एक दिन के सीएम' की तर्ज पर अनूठा प्रयोग

नियम तोड़ने वालों को बनाया 'एक दिन का पुलिसकर्मी'

नईदुनिया, आलीराजपुर

मध्य प्रदेश के आलीराजपुर जिले की पुलिस ने अनोखा प्रयोग किया है। यातायात विभाग ने चेकिंग के दौरान ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों को बतौर 'सजा' एक दिन का यातायात पुलिसकर्मी बनाया। उन्हें वाहन चेकिंग की ड्यूटी भी सौंपी गई। जिले में सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत यातायात विभाग के प्रभारी शिवम गोस्वामी ने 'एक दिन का सीएम' की तर्ज पर यह पहल की। विभाग ने नियमों का उल्लंघन करने वालों को एक दिन का पुलिसकर्मी इसलिए बनाया ताकि उन्हें नियमों की जानकारी मिल सके और वे स्वयं के साथ ही लोगों को भी जागरूक करें। पिछड़ा क्षेत्र होने के कारण आदिवासी अंचल में अक्सर लोगों को यातायात नियमों की जानकारी नहीं होती है, जिससे वे नियमों का जाने-अनजाने में उल्लंघन कर देते हैं।

बाकायदा जैकेट पहनाई, कुछ: को अधिकारी बनाया गया: ट्रैफिक पुलिस को आलीराजपुर में जो भी नियमों का उल्लघंन करते हुए दिखा उसे पकड़कर यातायात पुलिस की ड्रेस के जैकेट पहनवाए गए। उनसे ड्यूटी करवाई गई। वहीं कुछ लोगों को अधिकारी भी बनाया गया। उन्हें टेबल-कुर्सी पर बैठाकर चालानी कार्रवाई भी करवाई गई।

एक दिन का पुलिस वाला बनने वालों में बालू तोमर, अली आदि शामिल हैं। नियम तोड़ने वाले पहले तो नियमों का उल्लंघन करने को लेकर बात करने से मना करने लगे फिर भी उन्होंने बताया कि उन्होंने हेलमेट नहीं पहना था। इस दौरान उन्होंने बताया कि एक दिन का पुलिस वाला बनने पर जिम्मेदारी का अहसास हुआ।

मध्य प्रदेश के आलीराजपुर में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों को एक दिन का पुलिसकर्मी बनाकर दिनभर ड्यूटी कराई गई। नईदुनिया

नवजात नहीं रोया तो नर्स ने आग में सेंका, पड़े फफोले

नईदुनिया, शहडोल: मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में आठ घंटे में छह बच्चों की मौत का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि एक नवजात को सरकारी अस्पताल में कंडे (उपले) की आग में सेंक दिया गया। इससे उसके दोनों गाल, माथा, हाथ की अंगुली और पीठ झुलस गई और फफोले पड़ गए। बच्चे की हालत गंभीर है। सीएमएचओ ने घटना की जांच के निर्देश दिए हैं।

शहडोल जिले के खन्नौधी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 16 जनवरी को पार्वती बैगा पत्नी गंगा बैगा ने बच्चे को जन्म दिया। स्वास्थ्य केंद्र में एएनएम (नर्स) की देखरेख में प्रसूता की सामान्य डिलीवरी हुई। जन्म लेते ही नवजात रोया नहीं तो इस पर गंगा बैगा ने बताया कि एएनएम ममता गोस्वामी ने बच्चे को सेंकने की सलाह दी। स्वास्थ्य केंद्र में उस समय बिजली नहीं थी। इस कारण अस्पताल परिसर में ही कंडे की आग जलाकर नवजात को सेंकने का इंतजाम किया गया।

2018 में बेरोजगारों और स्वरोजगार वाले लोगों ने अधिक आत्महत्या की

▶ **एनसीआरबी के मुताबिक, इन श्रेणियों में 26,085 लोगों ने आत्महत्या की**

▶ **हर दिन औसतन 35 बेरोजगार और 36 स्वरोजगार करने वालों ने दी जान**

नई दिल्ली, प्रेट्र: 2018 में हर दिन औसतन 35 बेरोजगार और 36 स्वरोजगार करने वाले लोगों ने अपना जीवन खत्म कर लिया। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के मुताबिक, इन दोनों श्रेणियों में 26,085 लोगों ने आत्महत्या की। आत्महत्या करने वालों में बेरोजगार व्यक्ति (12,936) स्वरोजगार करने वाले लोगों (13,149) से थोड़ा पीछे थे। जबकि कृषि क्षेत्र से जुड़े 10,349 ने उस साल आत्महत्या की।

एनसीआरबी ने हाल में जारी एक रिपोर्ट में कहा है कि 2018 में कुल मिलाकर देश में 1,34,516 लोगों ने आत्महत्या की। यह 2017 की तुलना में 3.6 फीसद ज्यादा है। 2018 में 2017 की तुलना में प्रति लाख आत्महत्या की दर भी 0.3 फीसद ज्यादा रही।

आत्महत्या करने वाली महिलाओं में गृहिणियों की दर 54.1 फीसद (42,391 में से 22,937) रही। ऐसा कदम उठाने वाले कुल लोगों की तुलना में यह आंकड़ा करीब 17.1 फीसद है।

रिपोर्ट के मुताबिक, 1,707 सरकारी कर्मचारियों ने खुदकशी की, जो आत्महत्या करने वाले कुल लोगों में 1.3 फीसद हैं। निजी क्षेत्रों में नौकरी करने वाले 8,246 लोगों ने आत्महत्या की जो कुल संख्या का 6.1 फीसद है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के 2,022 कर्मचारियों ने खुदकशी कर ली, जो कुल संख्या का 1.5 फीसद है। ऐसा कदम उठाने वाले विद्यार्थियों एवं बेरोजगारों की संख्या क्रमशः 1,0159 और 1,2936 है, जो कुल संख्या का क्रमशः 7.6 और 9.6 फीसद है।

13 साल 2019-20 के दौरान मैन्युफैक्चरिंग वृद्धि दर दो फीसद के साथ 13 साल के ढलान पर

11 साल पांच फीसद की जीडीपी वृद्धि दर 2008-09 के बाद सबसे खराब दौर में

हमारी विविधता की दुनिया कायल है। यही हमारी पूंजी है। यही हमारा संबल है। दुनिया के 2208 अरबपतियों में भारत से 131 शामिल हैं। यानी यहां हमारी हिस्सेदारी करीब छह फीसद है। दुनिया के कुल गरीबों में भारत की हिस्सेदारी 24 फीसद यानी करीब एक चौथाई है। ऐसे में किसी एक योजना या नीति से सबके हितों को साधना मुमकिन नहीं है। भारत की सतरंगी समस्याओं का समाधान एक व्यापक और सुस्पष्ट दृष्टिकोण से ही किया जा सकता है। लोगों की गरीबी भी खत्म हो और अमीरों के कारोबार में भी तेजी आए। किसानों का जीवन खुशहाल हो तो उद्यमियों का मुनाफा छलांग लगाए। नौकरीपेशा और आम आदमी सहित समाज-राष्ट्र के हर तबके के लिए नीतियां और योजनाएं बनाने का आधार आम बजट तैयार करता है। मौजूदा हालात बेहद प्रतिकूल हैं। जीडीपी वृद्धि दर 11 साल के सबसे निचले पायदान पर है। प्रति व्यक्ति आय खस्ताहाल है। मैन्युफैक्चरिंग का पहिया 13 साल की सबसे धीमी रफ्तार से घूम रहा है। नॉमिनल जीडीपी 42 साल की तलहटी पर है। ऐसे में लोगों को उस आम बजट की आस है जिससे दुनिया के कुल अमीरों और गरीबों में भारत की हिस्सेदारी का अनुपात आपस में वर्तमान स्थिति में बदल जाए। ऐसे अहा बजट, वाह बजट के मनोभाव लाने वाले क्रांतिकारी कदमों की पड़ताल आज बड़ा मुद्दा है।

42 साल की तलहटी पर नॉमिनल जीडीपी

देश की आर्थिक हालात की वास्तविक तस्वीर पेश करने वाली नॉमिनल जीडीपी की वृद्धि दर 42 साल की सबसे खराब स्थिति में है। बिना महंगाई को समायोजित किए देश की समस्त चीजों और सेवाओं का बाजार मूल्य बताने वाला यह आंकड़ा 2019-20 के लिए 7.5 फीसद रहा। इससे पहले ऐसी स्थिति 1978 में बनी थी।

खपत वृद्धि हो एकमात्र लक्ष्य

गुंजा कपूर
आर्थिक नीति विश्लेषक

डिस्पोजेबल आय वृद्धि, श्रम प्रधान उद्योगों को पुनर्जीवन, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में निजी निवेश को प्रोत्साहन जैसे तमाम अल्पावधि और दीर्घावधि के कदम हैं जो मांग और खपत बढ़ाने वाले हैं।

मोदी सरकार को मई 2019 में एक निर्णायक जनादेश मिला। इसके बाद जब वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना पहला बजट पेश किया, तो उसमें एक सतर्क नीति का प्रवाह देखने को मिला। हालांकि, जब उस बजट पर जनता और उद्योगपतियों से प्रतिक्रिया आयी, तो फौरन उद्योगों के कर दरों को घटाया गया और साथ ही कुछ और बदलाव भी शामिल किये गए। जहां तक बजट 2020 का सवाल है, अगर इस बजट का कोई एक मात्र ध्येय होना चाहिए, तो वो है खपत में वृद्धि करना।

डिस्पोजेबल आय बढ़ाने के लिए आयकर दर स्लैब में बदलाव स्पष्ट है कि भारत का प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय कम हो गया है। इसके कारण उपभोक्ताओं के हाथों में डिस्पोजेबल आय बढ़ाने की अत्यंत आवश्यकता है। 10 लाख रुपये से अधिक आय वालों के लिए आयकर दर में बदलाव करने की व्यापक संभावनाएं हैं। मैं डायरेक्ट टैक्स टास्क फोर्स कमेटी के प्रस्ताव से सहमत हूं कि मौजूदा 3 स्लैब के बजाय 4 टैक्स स्लैब लागू किए जाने चाहिए। जहां यह निश्चित रूप से मध्यम वर्ग में डिस्पोजेबल आय में वृद्धि करेगा, इससे भारत सरकार के राजकोष पर 30,000 करोड़ रुपये का भार भी बढ़ जायेगा। राजकोषीय विवेक और विकास के बीच, अब विकास को प्राथमिकता देकर रोजगार पैदा करना ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। भले ही यह एक दीर्घकालिक उपाय है, हम इस दायित्व से स्वयं को अलग नहीं कर सकते।

वर्तमान कर दरें

2.5 लाख तक	कुछ नहीं
2.5-5.0 लाख	5 फीसद
5-10 लाख	20 फीसद
10 लाख से ऊपर	30 फीसद

टैक्स टास्क फोर्स का प्रस्ताव

2.5 लाख तक	कुछ नहीं
2.5-10 लाख	10 फीसद
10-20 लाख	20 फीसद
20 लाख-2 करोड़	30 फीसद
2 करोड़ से अधिक	35 फीसद

श्रम प्रधान उद्योग हो पुनर्जीवित: भारत में आय व आयकर की चर्चा का आधार इस तथ्य से आरंभ होता है कि हमारे देश में 8 फीसद से कम नागरिक आयकर देते हैं। इसलिए, व्यापक पैमाने पर जीवन को प्रभावित करने के लिए, मात्र आयकर दरों में बदलाव पर्याप्त नहीं होगा। रियल एस्टेट, बुनियादी ढांचे और विनिर्माण सहित श्रम गहन क्षेत्रों को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है। दिसंबर 2019 में 102 करोड़ की नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन की घोषणा की गयी थी, जो बुनियादी ढांचे के लिए एक विस्तृत रोडमैप की योजना है। परंतु इसके प्रभाव के लिए, वैल्यू चेन में सम्मिलित सहायक उद्योगों का भी ध्यान रखना होगा; उदाहरण के लिए, सीमेंट उद्योग में इनपुट सामग्री पर आयात शुल्क में कमी; स्टील की खपत को बढ़ाने के लिए ऑटो सेक्टर में उत्पादन क्षमता को बढ़ने की आवश्यकता है। रियल एस्टेट क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए, सरकार को अनुबंध प्रवर्तन और समयबद्ध स्वीकृतियों को बढ़ाने के उपायों की घोषणा करने की आवश्यकता होगी। इसी तरह, अनुसंधान और विकास क्षेत्र में आर्थिक सहयोग, असंतुलित मूल्य निर्धारण पर रोक, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए अनुकूल नीतियों की भी घोषणा करनी होगी। अगर रोजगार ही सतत विकास का उपाय है, तो रोजगार देने वाले उद्योगों की रक्षा और उनके व्यापार की सहूलियत का ध्यान रखना भी हमारी नीतियों का अभिन्न अंग है।

ग्रामीण मांग में वृद्धि: इस बजट में निश्चित रूप से ग्रामीण क्षेत्र में निजी निवेश को प्रोत्साहन देने पर जोर दिया जाना चाहिए। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के संबंध में आगामी बजट में मनरेगा द्वारा जल संचयन निकाय के निर्माण तथा किसानों के लिए परिवहन सुविधाओं और कोल्ड स्टोरेज चेन को सब्सिडी देने के लिए कुछ बजट आवंटित करना होगा। पिछले बजट में जीरो बजट फार्मिंग की बात की गई थी। इसे सिरे चढ़ाने और खेती को लाभदायक व्यवसाय बनाना ही नीति निर्धारण का केंद्र बिंदु होना चाहिए। नए दशक में प्रवेश करते हुए हमें यह भी स्वीकार करना होगा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था का रूप बदल गया है। यह कृषि प्रधान से उत्पादन को आधार बना रही है। हमें कृषि क्षेत्र में जनशक्ति को बनाए रखने के लिए खाद्य प्रसंस्करण को एक आकर्षक विकल्प का रूप देने की आवश्यकता है। किसानों को अपनी उपज का प्रसंस्करण करने के लिए व सूक्ष्म और लघु उद्योगों की स्थापना के लिए कम ब्याज दर पर कर्ज मिलने का प्रयोजन हो, खेत में अप्रयुक्त सामग्री का उपयुक्त उपयोग करने को भी आर्थिक प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है।

राजकोषीय अनुशासन में सीमित होकर हम विकास की संभावनाओं को अनदेखा नहीं कर सकते। इस सरकार ने राजकोषीय विवेक को निभाने में अपनी क्षमता का बखूबी प्रदर्शन किया है, अब इस बार वृद्धि को चुनने और खपत को पुनर्जीवित करने में कोई कोताही नहीं करनी चाहिए। देशव्यापी जनादेश इस समय सरकार की ओर बड़ी उम्मीद से देख रहा है, प्रधानमंत्री मोदी अपने समर्थकों को निराश नहीं कर सकते।

हो जा सतरंगी रे...

देश प्रतिकूल आर्थिक हालातों से गुजर रहा है। वजहें तमाम हैं। इन तमाम दिक्कतों को दूर करने का मौका आ गया है। वित्तमंत्री अपना दूसरा आम बजट पेश करने जा रही हैं। इस बजट से आम आदमी के साथ कारोबारियों को भी काफी उम्मीदें हैं। लिहाजा वित्तमंत्री को ऐसा सतरंगी बजट पेश करना होगा जिससे देश में खुशियों का इंद्रधनुष खिल जाए।

विवेक कौल
अर्थशास्त्री और ईजी मनी ट्राइलॉजी के लेखक

1 जानकारों का मानना है कि सरकार को 2020-21 में पहले के वर्षों से कहीं ज्यादा पैसा खर्च करने की जरूरत है। इसके पीछे की वजह निजी खपत है। अर्थव्यवस्था में 60 फीसद हिस्सा रखने वाली खपत ठप पड़ गई है। अनुमान लगाया जा रहा है कि 2019-20 में निजी खपत में केवल 5.8 फीसद की बढ़त होगी। ये 2009-10 से लेकर अब तक की सबसे धीमी बढ़त है। लोग पहले की तरह चीजों पर पैसा खर्च नहीं कर रहे हैं। ऐसे माहौल में जरूरी है कि सरकार पहले से ज्यादा पैसा खर्च कर अर्थव्यवस्था की मदद करे।

2 खपत बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा ज्यादा रकम खर्च करने के कई नकारात्मक असर हो सकते हैं। अगर सरकार ज्यादा पैसा खर्च करेगी तो राजकोषीय घाटा बढ़ेगा। लगभग सभी सरकारें जितना पैसा कमाती हैं, उससे कहीं ज्यादा पैसा खर्च करती है। कमाने और खर्च के बीच के इस अंतर को राजकोषीय घाटा कहा जाता है। जब राजकोषीय घाटा बढ़ता है तो इस घाटे को भरने के लिए सरकार को ज्यादा पैसा उधार लेना पड़ता है। जब सरकार ज्यादा उधार लेती है तो बाकी वित्त संस्थानों के उधार लेने के लिए पहले से कम पैसा बचता है। ऐसी परिस्थिति में ब्याज दरों के बढ़ने का डर रहता है।

3 मार्च 2019 और नवंबर 2019 के बीच बैंकों के द्वारा दिया गया गैर खाद्य कर्ज केवल 0.5 फीसद बढ़ा है। उद्योग और सेवाओं को दिया गया कर्ज 3.9 फीसद और 2. फीसद घटा। ऐसे माहौल में सरकार ये कतई नहीं चाहेगी कि ब्याज दरें राजकोषीय घाटा बढ़ने की वजह से बढ़ जाए। इसलिए, सरकार का पहले से ज़्यादा खर्च करना जरूरी है पर ये भी ज़रूरी है कि सरकार पहले से कही ज़्यादा पैसा कमाए और राजकोषीय घाटे को ज्यादा बढ़ने ना दे। इसके लिए सरकार को अन्य विकल्पों पर ध्यान देने की जरूरत होगी। 2019-20 में सरकार ने विनिवेश से करीब एक लाख पांच हजार करोड़ कमाने की आशा की थी। नवंबर तक सरकार केवल 18,099 करोड़ रुपये ही कमा पाई थी। 2020-21 में जरूरी है कि सरकार विनिवेश का एक कैलेंडर बनाए और साल के शुरुआत से सरकारी कंपनियों का विनिवेश करती रहे। अभी तक का तजुर्बा ये रहा है कि सरकारें साल के आखिरी छह महीनों में जागती है और फिर विनिवेश का लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाती हैं।

4 बहुत सारी सरकारी कंपनियां, जो केवल चलाये जाने के लिए चलायी जा रही हैं, उन्हें बंद करने का समय आ गया है। इन कंपनियों की संपत्ति (ज्यादातर जमीन) को बेच कर 102 लाख करोड़ के नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में लगाया जाना चाहिए। इस देश को बेहतर सड़कों, ज्यादा बंदरगाहों, बेहतर रेलवे, बेहतर सिंचाई, इत्यादि की जरूरत है। अगर इसकी वजह से कुछ ख़राब प्रदर्शन करने वाली सरकारी कंपनियों और बैंकों को बंद करना पड़े तो घबराने की कोई बात नहीं है। इससे देश का भला होगा।

5 कृषि का देश की अर्थव्यवस्था में योगदान दिन ब दिन कम होता जा रहा है, लेकिन कृषि पर निर्भर लोगों की संख्या उस हिसाब से कम नहीं हो रही है। इसलिए कृषि क्षेत्र में सुधार लाने की बहुत जरूरत है। कृषि क्षेत्र को एपीएमसी से आगे देखने का समय आ गया है। ये जरूरी हो गया है कि किसान जो पैदा कर रहा है वो उसे खुद भी किसी को भी बेच सके, ना कि केवल एपीएमसी के एजेंटों को।

6 माल और सेवा कर में सुधार लाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अभी कुछ दिनों पहले भूटान माल और सेवा कर लागू करने की तरफ बढ़ा। भारत के विपरीत, भूटान में माल और सेवा कर की केवल एक ही दर होगी। समय आ गया है कि भारत भी इस तरफ बढ़े। हालांकि इसका आम बजट से कोई सीधा संबंध नहीं है पर वित्तमंत्री अपने बजट भाषण में इस तरफ बढ़ने की बात कर सकती है। जिन निर्यातकों का माल और सेवा कर की अदायगी फंसी हुई है, उसे सरकार को जल्द से जल्द अदा करने की जरूरत है।

7 व्यक्तिगत आयकर की दरों को घटाने की जरूरत है। इससे लोगों के हाथों में ज्यादा पैसा आएगा और वो इस पैसे को खर्च कर सकते हैं। इस खर्च से व्यापार को फायदा होगा और आर्थिक विकास की दर पहले से तेज़ी से बढ़ेगी। आयकर की दरों को घटाने के अलावा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में पहले से ज्यादा आवंटन करने की भी जरूरत है।

मैं बजट पेश करता तो...

भरत झुनझुनवाला
वरिष्ठ अर्थशास्त्री

मैं छह ऐसे कदम उठाने पर जोर देता जिससे युवाओं को रोजगार भी मिलेगा और तीन माह के भीतर ही देश की आर्थिक विकास की दर दस प्रतिशत या उससे अधिक हो जायेगी।

यदि बजट मैं बनाता, तो ये छह बिंदु होते। पहला बिंदु जीएसटी का है। मैं जीएसटी में छोटे उद्योगों द्वारा कच्चे माल की खरीद पर अदा किये गये जीएसटी के नकद रिफंड की व्यवस्था करता जिससे छोटे उद्योगों को बड़े उद्योगों के सामने खड़ा होने में सुविधा हो। साथ ही जीएसटी में श्रम सघन उत्पादन जैसे कपड़े और अगरबत्ती पर जीएसटी की दर को मैं कम करता और श्रम का हनन करने वाले पूंजी-सघन उत्पादों जैसे जेसीबी, एक्स्कावेटर और हार्वेस्टर पर जीएसटी की दर को बढ़ाता। राज्यों को जीएसटी की दर में परिवर्तन करने का मैं अवसर देता जिससे कि वे अपने विवेकानुसार जीएसटी के दायरे के अंदर रहते हुए अपनी जीएसटी की दरों में परिवर्तन कर सकें। जीएसटी के अंतर्गत माल के एक श्रेणीकरण को बनाये रखते हुए राज्यों द्वारा जीएसटी की दर में परिवर्तन करने का रास्ता खोजता। इन कार्यों से छोटे उद्योग और रोजगार को बढ़ावा मिलता, बाजार में मांग उत्पन्न होती और अर्थव्यवस्था चल निकलती।

दूसरा, विश्व व्यापार संगठन से मैं बाहर आने की पहल करता। विश्व व्यापार संगठन का आधार था कि हमारे कृषि उत्पादों के निर्यात के अवसर बढ़ेंगे। ऐसा नहीं हुआ है। अतः विश्व व्यापार संगठन में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है। पेटेंट्स कानून का संशोधन कर मैं यह व्यवस्था करता कि विदेश में विकसित नई तकनीकों को अपनाकर हम उत्पादन कर सकें जैसा कि हम 1995 के पहले करते आ रहे थे। इससे तकनीकी खरीद के नाम पर देश से जो भारी रकम बाहर जा रही है, उसमें कुछ ठहराव आता। हमारे उद्यमियों को प्रॉफिट कमाने के नए रास्ते मिलते और निवेश बढ़ता। तीसरा कार्य मैं यह करता कि सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों और लाभ अथवा हानि में चल रही तमाम सार्वजनिक इकाइयों का पूर्ण निजीकरण कर देता। मेरा अनुमान है कि इस कदम से हम लगभग बीस लाख करोड़ की विशाल राशि अर्जित कर सकते हैं। यह रकम केंद्र सरकार के पूरे साल के खर्च के बराबर होगी।

चौथा कार्य मैं यह करता कि सरकारी कर्मियों के वेतन और डीए को फ्रीज कर देता। सरकारी कर्मियों की नियुक्ति आम आदमी की सेवा करने के लिए की जाती है। अतः सेवक को सेवित की आय से अधिक वेतन देने का कोई औचित्य नहीं है। वर्तमान में सरकारी कर्मियों के वेतन, देश की आम आदमी की आय से कई गुना अधिक हैं। इसलिए इनके वेतन को फ्रीज कर बची हुई रकम को आम आदमी के खाते में सीधे डाल देता। मैं तमाम सरकारी कल्याणकारी योजनाओं को समाप्त कर उस रकम को भी देश की जनता के बैंक खातों में सीधे हस्तांतरित कर देता।

पांचवां, मैं ऋण लेकर आम आदमी परक बुनियादी संरचना में निवेश बढ़ाता जैसे कस्बों में मुफ्त वाई-फाई अथवा गांवों में सड़क में निवेश बढाता। इस निवेश से सीमेंट और स्टील की मांग तो बढती ही साथ में आम आदमी को अपना धंधा करने में सहूलियत होती और उसकी क्रय शक्ति में वृद्धि होती। कस्बों के युवा इंटरनेट से अपनी सेवाओं की बिक्री कर सकेंगे। हाईवे में निवेश करने से परेशानी बढ़ती ही है। टोल देना होता है। हाईवे पार करने में परेशानी होती है। ट्रकों के रुकने के ढाबों का धंधा चौपट हो जाता है।

जनमत

हां 95% नहीं 05%

क्या विकास की रफ्तार बढ़ाने के लिए सरकार को वित्तीय घाटे का लक्ष्य लचीला रखना चाहिए?

हां 10% नहीं 90%

क्या सभी आर्थिक-सामाजिक हैसियत वाले लोगों को खुश करने वाला बजट पेश करना संभव है?

आपकी आवाज

कितना ही बढ़िया बजट पेश किया जाए आलोचना करने वाले तो आलोचना करेंगे ही। विविध प्रकार के हैसियत वाले सभी लोगों को खुश करने वाला तो नहीं लेकिन विलक्षण अर्थशास्त्रीय बुद्धिमत्ता से देश व देशवासियों का हित करने वाला बजट पेश करना संभव है। **गौरीशंकर अंतज**

मंदी की मार से लड़ने के लिए दुनिया भर में सरकारों के पास सीमित ही उपाय है। फिर भी निचले तबके और मध्यम वर्ग की जेब मे पैसा आये तो मांग बढ़े, उद्योग में भी जान पड़े, बेरोजगारी कम हो और अर्थ चक्र गति पकड़े। **अमन**

वित्त मंत्री को चाहिए कि वे वित्तीय सुधारों के साथ ऐसा बजट पेश करे जो आम आदमी की जेब पर भार न बढ़ाए। **प्रकाश**

अर्थव्यवस्था में गिरावट को लेकर राजनीतिक दल बयानबाजी में जुटे हैं, लेकिन इस पर उन्हें विचार करना चाहिए और मिलजुलकर देश हित में कदम उठाने चाहिए। **प्रियशरण**

बजट में ऐसे प्रावधान किए जाने चाहिए जो भारत की विकास दर को बेहतर करे। हालांकि गरीब, किसान के बारे में भी ध्यान रखना चाहिए। साथ ही महंगाई को कम करने के लिए भी कोशिश की जानी चाहिए। **मनीषा**

8 फीसद की वृद्धि चाहिए तो...

इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च की हालिया रिपोर्ट के अनुसार अगर 8 फीसद की वृद्धि दर के लिए देश में श्रम उत्पादकता दर को 6.3 फीसद तक बढ़ाना होगा।

श्रम उत्पादकता में अगड़े क्षेत्र

वित्तीय वर्षों 2000 से 2016 के दौरान श्रम उत्पादकता दर में कई क्षेत्रों की रफ्तार तेज रही।

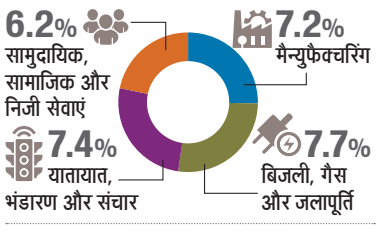

पिछड़े क्षेत्र

मौजूदा स्थिति

चालू वित्तीय साल के दौरान श्रम उत्पादकता वृद्धि 5.2 फीसद रही है। जबकि 2004-05 से 2007-08 के दौरान यह दर 8.5 थी।

चीन का मॉडल

वित्तीय वर्ष 2000 से लेकर 2016 के दौरान सभी क्षेत्रों में चीन की श्रम उत्पादकता दर 6.5 से ऊपर बनी रही।

घाटे की चिंता से मुक्त हों

डॉ. विकास सिंह
मैनेजमेंट गुरु, वित्तीय एवं समग्र विकास विशेषज्ञ

3.3 फीसद राजकोषीय घाटे की सीमा कोई पत्थर की लकीर नहीं है। इसे 3.8 फीसद तक ले जाने से सरकार को एक लाख करोड़ रुपये हासिल होंगे। कर्ज लेना टिकाऊ सौदा तब होता है जब उसका ग्रामीण संरचना में निवेश हो। इससे संपत्ति, रोजगार व मांग बढ़ेगी।

एक अध्ययन के मुताबिक मैक्रो उपभोक्ता से जुड़े 10 सेक्टरों में से आठ अपने सात साल के औसत से नीचे हैं। ये सेक्टर औद्योगिक क्षेत्र पर सीधे प्रतिकूल असर डाल रहे हैं। इससे कुल मिलाकर बाजार में मांग बहुत सुस्त हो चुकी है। ये चिंता की बात है। इसी के सामांतर अन्य बातें भी प्रतिकूल हैं। मूलभूत संकेतक जैसे कीमत सिग्नल (मांग बनाम आपूर्ति) गिर रही है। आर्थिक वृद्धि के चार प्रमुख सहभागी कारक, निजी निवेश, सरकारी खर्च, घरेलू खपत और निर्यात में गिरावट है। भारत को नए सुधारों की जरूरत है और इसे प्राथमिकता में रखना होगा।

इस चुनौती को सामना करना आसान नहीं है। खासतौर पर सार्वजनिक वित्त पर दबाव और बड़े प्रोत्साहन पैकेज के लिए सीमित राजकोषीय स्थिति को देखते हुए। बजट से भी आगे ट्रिलियन डॉलर का सवाल है कि अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए राजकोषीय धन की गठरी के तार किस हद तक ढीले होंगे। अधिकांश इस विडंबना से नहीं भाग सकते हैं कि राजकोषीय घाटे पर स्वयं द्वारा लगाई सीमा के जरिए वित्त मंत्री ने अर्थव्यवस्था के आपूर्ति पक्ष को पुनर्जीवित करने के लक्ष्य के साथ कर राजस्व को 1.5 लाख करोड़ रुपये से अधिक करने का फैसला किया है।

कॉरपोरेट टैक्स में कमी लाना एक गेम चेंजिंग रिफॉर्म है। हालांकि कर कटौती की आपूर्ति पक्ष से संबंधित अपनी अनिश्चितताएं हैं। मुनाफा उतना हो नहीं रहा है लिहाजा निवेश की भी सूरत नहीं नजर आती। अगर इसमें थोड़ा बहुत कुछ ग्रोथ को पुनर्जीवित करने की गुंजायश बनती है तो चुनौतियां और गहराती जाती हैं।नीति निर्माताओं के लिए यह ध्यान रखना अच्छा होगा कि जब कोई किसान या मजदूर किसी दुकान में जाता है और खरीदारी करता है तो वह बिक्री और खरीद की एक श्रृंखला शुरू करता है। इसमें कई मंच शामिल होते हैं, जो अपने साथ कई वित्तीय संस्थानों को शामिल करते हुए निर्माताओं से विनम्र खरीदार तक हर स्तर पर मूल्य जोड़ते हैं। धन का आदान-प्रदान और वस्तुओं का प्रवाह और इससे जुड़े लाभ जीडीपी में जुड़ते हैं। यह चेन कमजोर हो रही है। हमारी अर्थव्यवस्था में अवरोध आ गया है। इस गतिरोध को दूर करने के लिए सरकार खुले हाथ से पैसे खर्च करे और उपभोक्ताओं की जेब में उसे डाले। जीएसटी कर की दर मांग पक्ष को पूरी करेगी। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जनता के हाथ में अधिक धन रहे। आर्थिक विकास को शुरू करने का एकमात्र तरीका मांग पक्ष को मजबूत करना है। बजट आवंटन के लिए शोर ज्यादा है। वित्त मंत्री को आवंटन से आगे बढ़ना चाहिए। ज्यादातर बजट बड़ी सरकारों के पास जाते हैं। अब फोकस परिव्यय से परिणाम तक और आगत से अदायगी तक किए जाने की जरूरत है।

ऐसे बढ़ेगी मांग

- ग्रामीण भारत का मतलब सिर्फ कृषि ही नहीं है। इस क्षेत्र का खर्च समावेश के लिए महत्वपूर्ण है। ग्रामीण विकास गरीबी को तीन गुना तेजी से कम करता है।
- कृषि चुनौती का समाधान आसान है। किसानों की दुर्दशा घटती आय के कारण है और वास्तविक मजदूरी 5 साल के निचले स्तर पर है।
- असंतुष्ट उद्यमी सूक्ष्म उद्योग शुरू करता है और छोटा रहता है। अनुकूल माहौल में कई उद्यमी फल-फूल सकते हैं। सरकार को उद्यमशीलता को पोषित करने और पारिस्थितिकी तंत्र को सक्षम करने वाले उद्यमी बनाने के लिए नीतिगत उपायों को स्थापित करने की आवश्यकता है।
- नौकरियां विकास और मांग में वृद्धि करती हैं और मांग तब तक नहीं उठती है जब तक कि नौकरियां न हों। हम अगले दशक के करीब पहुंच गए हैं, जहां हमारी जनसांख्यिकी स्थिति जनसांख्यिकी आपदा में बदल रही है। हमारे श्रम बाजारों में बहुत अवरोध है और इस पर तेजी से ध्यान देने की आवश्यकता है।

Download UPSC IAS Material: www.iascgl.com

दैनिक जागरण
शांति समृद्धि की पहली शर्त है

कश्मीरी पंडितों की उम्मीद

इससे इन्कार नहीं कि जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35-ए हटने के बाद वहां के हालात बदले हैं, लेकिन अभी और भी बदलाव लाने और साथ ही एक ऐसा माहौल कायम करने की जरूरत है जिससे कश्मीरी पंडितों की वापसी का मार्ग प्रशस्त हो सके। किसी को भी इसकी अनदेखी नहीं करनी चाहिए कि कश्मीरी पंडित अपने घरों को वापस लौटने की बाट जोह रहे हैं। उनके निष्कासन के 30 साल बाद यह जो उम्मीद जगी है कि वे अपने घर-बार लौट सकते हैं उसे पूरा करने की जरूरत है। इस जरूरत को पूरा करने के लिए कश्मीर के लोगों को भी आगे आना चाहिए। कश्मीरी पंडितों का कश्मीर से बाहर निर्वासित जीवन जीना कश्मीरियत के लिए कलंक है। उस कश्मीरियत का कोई मतलब नहीं जिसमें कश्मीरी पंडितों के लिए कोई स्थान न हो। इस बात को कश्मीर के साथ शेष देश के लोगों को भी समझना होगा। यह अच्छा नहीं हुआ कि बीते 30 सालों में अपने ही देश में निवार्सित जीवन जी रहे कश्मीरी पंडितों की वापसी के पक्ष में वैसी आवाज नहीं उठी जैसी उठनी चाहिए थी। इससे बड़ी त्रासदी और कोई नहीं हो सकती कि कोई समुदाय अपने ही देश में शरणार्थी बनने को मजबूर हो जाए।

यह देखना दुखद है कि आज जब कश्मीरी पंडित घाटी से अपने निष्कासन के खौफनाक मंजर को बयान करने के साथ ही अपने घरों को लौटने की उम्मीद रेखांकित कर रहे हैं तब देश का राजनीतिक नेतृत्व एक स्वर से यह कहने के लिए तैयार नहीं दिखता कि उनकी इस स्वाभाविक अपेक्षा को पूरा करने के लिए हर संभव कदम उठाए जाने चाहिए। आखिर कश्मीरी पंडितों की वापसी का अधूरा काम देश का साझा संकल्प क्यों नहीं बन सकता? जो भी हो, केंद्र सरकार को तो यह स्मरण रखना ही चाहिए कि कश्मीरी पंडितों की वापसी का उसका संकल्प अभी शेष है। इस अधूरे संकल्प का संज्ञान उन केंद्रीय मंत्रियों को भी लेना चाहिए जो जम्मू-कश्मीर के लोगों को भरोसा दिलाने और वहां की समस्याओं को जानने-समझने एवं उनका निस्तारण करने के लिए वहां जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्रियों का जम्मू-कश्मीर दौरा एक ऐसे समय हो रहा है जब वहां संचार सुविधाओं पर लगी पाबंदी में ढील देने का काम भी शुरू हो गया है। संचार सुविधाओं की पूरी तौर पर बहाली बहुत कुछ सुरक्षा के हालात पर निर्भर करेगी। जम्मू-कश्मीर और खासकर घाटी के सुरक्षा माहौल को बेहतर बनाने में एक बड़ी भूमिका वहां के आम लोगों की भी है। उन्हें इस मामले में सक्रियता दिखानी चाहिए ताकि पहले से हतोत्साहित अलगाव एवं आतंक के समर्थकों को यह समझ आए कि अब उनकी दाल गलने वाली नहीं है।

अस्पतालों की सेहत सुधारें

बिहार के सरकारी अस्पतालों की हालत पर पटना हाईकोर्ट की चिंता को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। कोर्ट ने यदि कहा है कि बिहार में कोई भी अस्पताल उच्चस्तरीय नहीं है तो उम्मीद है कि सरकार निश्चय ही इस पहलू पर गौर करेगी। कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि प्रदेश में करीब 13 करोड़ लोग हैं, जिनके स्वास्थ्य के प्रति राज्य सरकार लापरवाह नहीं हो सकती। सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों एवं पारा मेडिकल कर्मियों की भारी कमी है। कोर्ट ने इसमें तत्काल सुधार का निर्देश दिया है। यह भी कहा है कि यदि अस्पतालों की हालात में सुधार नहीं होता है तो सरकार के अधिकारियों को बाहर जाकर इलाज कराने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। कोर्ट की चेतावनी भरी इस टिप्पणी को हल्के में नहीं लिया जा सकता। सरकार को चाहिए कि वह सरकारी चिकित्सा व्यवस्था को बेहतर और सुदृढ़ बनाने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को और भी तेज करे। आंकड़ों के हिसाब से देखें तो राज्य में अभी पांच हजार से अधिक डॉक्टरों और दस हजार से अधिक पारा मेडिकल कर्मियों की कमी है। सबसे पहले इस कमी को दूर करने की कोशिश होनी चाहिए। साथ ही अस्पतालों में जीवन रक्षक दवाओं, चिकित्सकीय उपकरणों सहित अन्य संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित कराना आवश्यक है। सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों और चिकित्सा कर्मियों की कमी के साथ ही अन्य कई कारणों के चलते चिकित्सा व्यवस्था की हालत चिंताजनक बनी हुई है। हालांकि इसे दुरुस्त करने की दिशा में राज्य सरकार लगातार सक्रिय है और भविष्य में बेहतर व्यवस्था की उम्मीद कर सकते हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से लेकर मेडिकल कॉलेजों तक की चिकित्सा व्यवस्था में सुधार सतत प्रयास से ही संभव है। इसके लिए दीर्घकालिक कार्ययोजना बनानी होगी। गरीब मरीजों के पास कोई चारा नहीं। उनके लिए सरकारी अस्पताल का ही आसरा है। वहां समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण दूसरे राज्यों की तुलना में बिहार में बीमारियों से मौत का आंकड़ा कुछ अधिक है। जाहिर है कि सरकारी अस्पतालों की सेहत में सुधार किए बिना स्वस्थ बिहार के सपने को साकार नहीं किया जा सकता। इस दिशा में अविलंब प्रयास अपरिहार्य हो गए हैं।

अस्पतालों की हालत पर हाईकोर्ट की चिंता जायज है। सरकार से उम्मीद है कि वह सरकारी चिकित्सा व्यवस्था को बेहतर और सुदृढ़ बनाने के प्रयासों को और तेज करेगी।

सीएए पर सस्ती राजनीति

संजय गुप्त

आखिर यह कितना उचित है कि जिस मसले पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाए उसी को लेकर सड़कों पर भी उतर आया जाए?

नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए को लेकर विपक्षी दल दिल्ली के साथ देश के विभिन्न हिस्सों में आम लोगों और खासकर मुस्लिम समुदाय को जिस तरह छल-कपट के सहारे उकसाकर सड़कों पर उतारने में लगे हुए हैं वह भारतीय राजनीति के विकृत होते जाने का ही प्रमाण है। विपक्षी दलों के इस शरारत भरे हथकंडे के बीच सरकार ने इस कानून को अधिसूचित कर अपने अडिग इरादे का परिचय दिया है। जहां सरकार अडिग है वहीं विपक्षी दल भी टकराव की राह पर बढ़ते दिख रहे हैं। केरल सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है और पंजाब सरकार ने विधानसभा में सीएए के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया है। विपक्षी दलों के इस अड़ियल रवैये के बीच सरकार राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर तैयार करने की दिशा में बढ़ रही है। यह जनगणना के तहत एक संवैधानिक दायित्व है, फिर भी बंगाल सरकार इस प्रक्रिया में शामिल होने से इन्कार कर रही है। यह तब है जब एनपीआर तैयार करने का काम 2010 में भी हो चुका है। यह देखना दुर्भाग्यपूर्ण है कि विपक्षी दलों ने एनपीआर को लेकर भी जनमानस में भ्रम फैलाना शुरू कर दिया है। वे इस तरह की अफवाहों को हवा दे रहे हैं कि एनपीआर के बाद एनआरसी की तैयारी की जाएगी। इस तरह की झूठी अफवाहें किस सुनियोजित तरीके से फैलाई जा रही हैं, इसका उदाहरण है दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में एक माह से जारी धरना। नोएडा को दिल्ली से जोड़ने वाली इस सड़क पर काबिज होकर दिए जा रहे धरने के कारण हर दिन लाखों लोग परेशान हो रहे हैं, लेकिन इस परेशानी को दरकिनार करके भीड़ को बरगलाया जा रहा है। इस काम में विपक्षी नेताओं के साथ कुछ वामपंथी एक्टिविस्ट, फिल्मकार और मीडिया के लोग भी शामिल हैं। यह देखना दुखद है कि स्वार्थी तत्वों की ओर से प्रायोजित इस धरने को जारी रखने के लिए छल-छद्म के साथ प्रलोभन का भी सहारा लिया जा रहा है। विपक्षी दल इस तरह के धरने देश के अन्य हिस्सों में भी शुरू करते दिख रहे हैं। वे ऐसा तब कर रहे जब खुद उन्होंने सीएए को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी हुई है। आखिर यह कितना उचित है कि जिस मसले पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाए उसी को लेकर सड़कों पर उतरा जाए?

सीएए के साथ ही एनपीआर का विरोध असंवैधानिक कृत्य ही है। संसद से पारित कानून का इस तरह का विरोध संवैधानिक अराजकता को ही जन्म देगा। इस अराजकता का परिचय तब दिया जा रहा है जब नागरिकता पूरी तौर पर केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र का विषय है। ऐसे विषय पर भी केंद्र सरकार को सीधी चुनौती देना सस्ती राजनीति के अलावा और कुछ नहीं। आखिर भारतीय लोकतंत्र की दुहाई देने वाले दुनिया भर के तमाम देश क्या सोच रहे होंगे? यह ठीक है कि अतीत में संवैधानिक ढांचे से छेड़छाड़ हुई है और कोई भी नहीं भूल सकता कि 1975 में देश में किस तरह आपातकाल थोप दिया गया था, लेकिन इसके बाद भी भारतीय लोकतंत्र की मिसाल दी जाती है। अब इस मिसाल को छिन्न-भिन्न करने का काम किया जा रहा है। शर्मनाक यह है कि इसमें बंगाल, केरल के अलावा कांग्रेस शासित राज्य सरकारें भी शामिल हैं। आखिर कांग्रेस किस मुंह से संविधान और लोकतंत्र की दुहाई दे रही है? कांग्रेस शासित राज्य सरकारें केरल और बंगाल की तरह संविधान की शपथ का उल्लंघन ही कर रही हैं। इस मामले में ममता बनर्जी सारी हदें लांघ रही हैं।

केंद्र सरकार की ओर से जनसंख्या रजिस्टर और जनगणना की प्रारंभिक तैयारियों को लेकर बुलाई गई बैठक का बहिष्कार करके ममता ने अपनी क्षुद्रता भरी राजनीति पर नए सिरे से मुहर लगाई है। राष्ट्रीय महत्व के जरूरी कामों में इस तरह की अड़ंगेबाजी संवैधानिक तौर-तरीकों का अनादर ही नहीं, संघीय ढांचे को सीधे तौर पर दी जाने वाली चुनौती है। ममता केंद्र सरकार के प्रति अंध विरोध से इतनी अधिक ग्रस्त हैं कि कई जनकल्याणकारी योजनाओं से भी बंगाल को बाहर किए हुए हैं। वह अंध विरोध की राजनीति इसीलिए कर रही हैं, क्योंकि बंगाल में भाजपा एक बड़ी राजनीतिक ताकत के रूप में उभर रही है। चूंकि विधानसभा चुनाव करीब आ रहे हैं इसलिए वह वोट बैंक की राजनीति को मजबूत करने में जुट गई हैं। वह बीते कुछ समय से बांग्लादेशी घुसपैठियों को निकालने की मांग का भी विरोध करने लगी हैं। एक समय वह इससे कुपित थीं कि इन घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें बंगाल से निकाला क्यों नहीं जा रहा है? वह शायद इस नतीजे पर पहुंच गई हैं कि सीएए और एनपीआर के विरोध में आगे दिखकर वह अपने मुस्लिम वोट बैंक को आसानी से सुरक्षित रख सकेंगी। कुछ ऐसे ही नतीजे पर अन्य विपक्षी दल भी पहुंच गए लगते हैं और यही कारण है कि सीएए के विरोध में मुस्लिम समुदाय को आगे किया जा रहा है।

चूंकि हर दल मुसलमानों का अपने पक्ष में ध्रुवीकरण करना चाह रहा है इसलिए उनकी ओर से सीएए को मुस्लिम विरोधी बताने की होड़ मची है। मुस्लिम समाज को भ्रमित और भयभीत करने के फेर में ही एनपीआर का विरोध किया जा रहा है। विपक्षी दलों को मुसलमानों को बरगलाने में आसानी इसलिए हो रही है, क्योंकि वे पहले से ही मुसलमानों को भाजपा का भय दिखाते चले आ रहे हैं। इस भय का कोई आधार नहीं, क्योंकि बीते पांच सालों में अल्पसंख्यक कल्याण की योजनाओं को जितनी सफलता से मोदी सरकार ने लागू किया है उतना शायद ही किसी सरकार ने किया हो। यह एक दुष्प्रचार ही है कि अनुच्छेद 370 हटाकर मुस्लिम हितों के खिलाफ काम किया गया? क्या भारत के मुसलमानों का हित देश हित से अलग है? इस अनुच्छेद को हटाकर तो कश्मीर के मुसलमानों को देश की मुख्यधारा में लाने की ठोस पहल की गई है। साफ है कि विपक्षी दल अपने संकीर्ण राजनीतिक हितों के लिए मुसलमानों से छल कर रहे हैं। अच्छा होगा कि खुद मुस्लिम समाज इस छल को समझे और यह देखे कि उसे किस तरह इस्तेमाल किया जा रहा है? आखिर जब सुप्रीम कोर्ट सीएए के खिलाफ दायर याचिकाओं को सुनने के लिए तैयार है और 22 जनवरी से सुनवाई तय भी हो गई है तब फिर उचित यही होगा कि उसके फैसले की प्रतीक्षा की जाए। जो ऐसा नहीं कर रहे वे एक तरह से सुप्रीम कोर्ट की अनदेखी ही कर रहे हैं।

response@jagran.com

अवधेश राजपूत

इतिहास बताने की कलाकारी

हास्य-व्यंग्य

ज्ञान चतुर्वेदी

इतिहास में जो भी लिखा है, लिखा रहे पर हम तुमसे कह रहे हैं न? बस, वही सुनो और समझो

कुछ लोग इतिहास बनाते हैं। ऐसे बड़े काम कर जाते हैं कि इतिहास आगे बढ़कर उनको और उनके काम को दर्ज करता है। वैसे यह इतिहास बनाना बड़े झंझट का काम है। उम्र लग जाती है, इतिहास बनाने में। फिर भी सभी नहीं बना पाते। यह तो हुई इतिहास बनाने वालों की बात। इनसे इतर एक तबका है इतिहास लिखने वालों यानी इतिहासकारों का। इनका काम भी छोटा नहीं होता, बल्कि बड़ा काम है यह भी। बड़ी समझ और तटस्थता चाहिए इस काम में। अक्सर ऐसा होता नहीं। हर इतिहासकार और कथित इतिहासकार की अपनी दृष्टि होती है। दृष्टि-दोष होते हैं। अलग-अलग चश्मे होते हैं। खेमे होते हैं, दरबार होते हैं, मालिक होते हैं, लगामें होती हैं, पहिये होते हैं, गड्ढे होते हैं, अपने चुने और बुने रास्ते होते हैं और स्वार्थ तो होते ही हैं। ये कलमें चुन-चुनकर इतिहास के अपने ही पन्ने तैयार करती हैं। इस तरह, इतिहास की अधिकांश पुस्तकें बस चुनी और गढ़ी हुई स्मृतियों तथा चुनी हुई विस्मृतियों का चालाक पोथा बनकर रह जाती हैं। इतिहास अक्सर भ्रम पैदा करता है। वही घटना कई पोशाकों में मिलती है। इतिहास में सब होता है। थोपी हुई कथाएं, रचे गए प्रसंग, सुनी-सुनाई बातें, कहां इतिहास है और कहां मात्र एक विशुद्ध किस्सा, पता ही नहीं चलता। सो इतिहासकार का काम इतिहास बनाने वालों जैसा कठिन न भी हो, पर है कठिन भी और बड़ी जिम्मेदारी का भी। फिसलन भरा रास्ता है इतिहास लेखन। इतिहास में गलत के दर्ज हो जाने और सही के छूट जाने के खतरे बहुत बड़े हैं। बार-बार यह हुआ भी है। होता ही है। गलत इतिहास पढ़ाकर और पढ़कर पीढियों को बरगलाया जा सकता है। इतिहासकार यदि दरबारी किस्म का हो तो वह इतिहास की कलाई को इतना मरोड़ सकता है कि पढ़ने वाले की समझ पर नील पड़ जाएं। बहस के लिए बड़ा मुफीद है ऐसा इतिहास लेखन। अब जाकर हमें पता चला कि इतिहास का एक और कोण भी हो सकता है। हाल के वर्षों में इतिहास में लिखे को लेकर देश में इतनी खींचतान मची है कि पुस्तक पुर्जे-पुर्जे हो गई है। सही पन्ने हवा में उड़ा दिए गए हैं। चुनाव सभाओं में, मीडिया की बहसों में, तू-तू मैं-मैं में, वॉट्सएप और फेसबुक आदि के अहातों में जारी प्रवचनों तथा गाली-गलौज में। इधर हमने इतिहास को एक साथ ही बहस, लात-घूंसे, मुंहजोरी और बरगलाने के काम पर लगा दिया है।

हमें यह भी पता चला है कि यदि इतिहास को तिरछा करके, उल्टा करके, सही स्थानों पर उसे ढांक कर, गलत जगहों पर उसे मनचाहा उजागर करके और उसमें अपने कारिंदों से लिखवाए गए जाली पन्ने जोड़कर, सही मजमें में, पूरी बाजीगरी और हाथ तथा गले की सफाई के साथ यदि तमाशे की तरह पेश किया जाए तो सारे तमाशे के बाद लोगों के बीच झोली घुमाकर वोट मांगे जा सकते हैं। वैसे इतिहास के गड़े मुर्दों में जान फूंककर उन्हें खड़ा कर देना इतना आसान होता भी नहीं है। तमाशा खड़ा करने की अपनी शर्तें होती हैं। सामान लगता है, कलाकारी लगती है, बेशर्मी लगती है और एक किस्म की हठधर्मी भी चाहिए यह सब करने के लिए। बहुत सा झूठ लगता है। सिखाए-पढ़ाए बंदर-बंदरिया लगते हैं। इतिहास से वर्तमान को बरगलाया जा सकता है। इतिहास को लेकर ठीक सा खेल पेश करें तो भीड़ आती तो है। इतिहास का यह इस्तेमाल नया है भी, नहीं भी है। सदियों से सत्ता ने अपनी सुविधानुसार इतिहास बनवाए हैं, पर अब तो उसकी भी जरूरत महसूस नहीं की जा रही। इतिहास में जो भी लिखा है, लिखा रहे पर हम तुमसे कह रहे हैं न? बस, वह सुनो। इतिहास के पन्ने चबाने और गुटकने के पश्चात उन्हीं की अपनी लड़ी बनाकर मुंह से निकालने वाले बाजीगरों का मजमा है अब राजनीति। इतिहास के पन्नों में बांधकर जहर की पुड़िया को भी अमृत बताकर बेचा जा सकता है। यह कला भी अब राजनीतिशास्त्र का अहम हिस्सा बन गई है। भगवान हमारे इतिहास की रक्षा करे और भविष्य की भी।

response@jagran.com

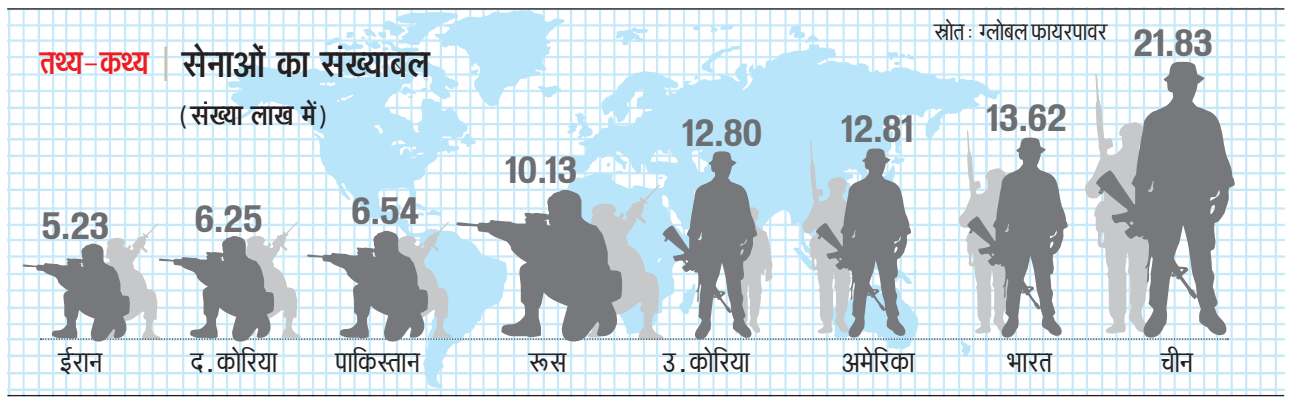

ऊर्जा

कर्मक्षेत्र

यह समूचा संसार एक अभयारण्य में उगी अनाप-शनाप झाड़ियों के सदृश है तथा जीव अथवा मनुष्य इसमें विचरण या निवास करने के लिए विवश एक प्रशिक्षित माली की तरह। अभयारण्य की जटिलताओं एवं विषमताओं से खीझकर वह माली अपने दुर्लभ जीवन को रुग्ण बनाकर, स्वयं के जीवन को औरों की दृष्टि में घृणास्पद बनाकर इस जन्म को कलंकित भी कर सकता है एवं भाग्यफल से मिले इस प्रारब्धरूपी अभयारण्य के कर्मक्षेत्र को अपने कर्म-कौशल से सजा संवारकर एक दुर्लभतम पुष्प और जड़ीबूटी के विशिष्ट उद्यान में भी परिणत कर उसको सभी की जिज्ञासा, अनुसंधान, ज्ञान, रोग हरण औषधियों के अनुपम केंद्र के रूप में भी विकसित कर सकता है। साधना एवं संघर्ष काल के व्यतीत होने पर वही उद्यान कालांतर में विशिष्ट तपोभूमि बन जगत के कल्याण एवं ऋषि-मुनियों की साधना भूमि बन जीव के मोक्ष की आधारभूमि भी सिद्ध हो सकती है।

हमें जो इस जन्म में उपहारस्वरूप मिला है, वह अतीत के कर्मों का फल है। आज के कर्म की कृषिभूमि रूपी जीवन में बोया गया कर्म का सुविकसित अथवा रुग्ण बीज भविष्य का प्रारब्धरूपी विटप बन महकेगा। सुख अथवा दुख हमारे कर्मों के संचित मूलधन रूपी वृक्ष पर फल रूप में ही लगते हैं। बोए गए बीज पर इस जन्म में अथवा जब भी, फल लगेगा तो तो उसी बीज का लगेगा। हर जन्म में जीव अत्यधिक चतुर बन विधाता की कर्म सारणी के बंधनों में चालाकीवश हेरफेर कर खुद को कर्मों की दौड़ में आगे निकाल देना चाहता है, लेकिन नहीं जानता कि उसका रिमोट उस ईश्वर रूपी मालिक के हाथ में है, जिसके पास उसकी हर चालाकी का लेखाजोखा बिना भेजे स्वतः ही उसके पास आ जाता है। कर्म भी वह अकेले ही करता है एवं कर्म के फल भी उसे अकेले भोगना है तो फिर क्यों नहीं वह केवल सत्कर्म करता? सत्कर्म के मनोहारी विटप पर सभी के लिए कल्याणकारी फल ही लगता है।

प्रो. दिनेश चमोला 'शैलेश'

मिला पृथ्वी का सबसे प्राचीन तत्व

मुकुल व्यास

जब तारे का जन्म होता है तब वह धूल का उत्पादन नहीं करता। तारे अपने जीवन के अंत में ही धूल उत्पन्न करते हैं

वैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर सबसे प्राचीन पदार्थ की पहचान की है। यह तारे की धूल है जो सात अरब वर्ष पुरानी है। यह धूल करीब पचास वर्ष पहले एक विशाल चट्टानी उल्कापिंड के जरिये पृथ्वी पर पहुंची थी। यह धूल जिन कणों से बनी है वे हमारे सूरज से भी पुराने हैं। मरणासन्न तारों ने अपने जीवन के अंतिम चरणों में इन धूल कणों को हमारे ब्रह्मांड में बिखेर दिया था। इनमें से कुछ धूल कण एक क्षुद्रग्रह पर जम गए जिसने मर्चिसन उल्कापिंड उत्पन्न किया। यह चट्टान 28 सितंबर, 1969 को ऑस्ट्रेलिया में मर्चिसन के निकट गिरी थी। इसका वजन 100 किलो था। मर्चिसन उल्कापिंड से निकाले गए दर्जनों सूर्य-पूर्व कणों के नए विश्लेषण से पता चला कि ये कण हमारे सूरज से करीब 40 लाख से लेकर 3 अरब वर्ष पुराने हैं। हमारे सूरज का निर्माण करीब 4.6 अरब वर्ष पहले हुआ था।

हमारे ब्रह्मांड में धूल कणों की भरमार है, लेकिन अभी तक पृथ्वी की चट्टानों में कोई सूर्य-पूर्व कण नहीं मिले हैं। इस अध्ययन के प्रमुख लेखक फिलिप हैक के अनुसार इसका कारण यह है कि प्लेट टेक्टोनिक्स (धरती के नीचे चट्टानों की हलचल), ज्वालामुखीय गतिविधियों और अन्य भौगोलिक प्रक्रियाओं ने उन सभी सूर्य-पूर्व धूल कणों को गर्म करके परिवर्तित कर दिया होगा जो पृथ्वी के निर्माण के दौरान जमा हुए होंगे। क्षुद्रग्रहों से निकलने वाली बड़ी चट्टानें भी प्राचीन अंतर-नक्षत्रीय धूल कणों को ग्रहण कर सकती हैं।

मर्चिसन उल्कापिंड का मूल क्षुद्रग्रह गैसों के बादल (सोलर नेब्यूला) से उत्पन्न हुआ था। यह एक स्थिर चट्टान है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अतः सूर्य-पूर्व कण भी किसी और पदार्थ में तब्दील नहीं हुए हैं। अधिकांश सूर्य-पूर्व कणों की लंबाई एक माइक्रोन या उससे कम होती है, लेकिन वैज्ञानिकों ने अध्ययन के लिए जिन कणों को चुना उनकी लंबाई 2 से 30 माइक्रोन के बीच थी। इन कणों को ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। शोध में एक डेटिंग तकनीक का इस्तेमाल किया जिसने अंतरिक्ष में कणों की अरबों वर्षों की अंतर-नक्षत्रीय यात्रा के दौरान उन पर ब्रह्मांडीय किरणों के प्रभावों की नाप जोख की। अत्यधिक ऊर्जा वाले कण विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न होते हैं और ये ठोस पदार्थों पर प्रहार करते हैं और उनमें प्रविष्ट हो जाते हैं। ये किरणें खगोलीय चट्टान के साथ क्रिया करके नए तत्व बनाती हैं। सूर्य-पूर्व कणों में विभिन्न तत्वों की मात्रा नाप कर यह अनुमान लग सकता है कि यह धूल कबसे ब्रह्मांडीय किरणों में नहा रही है।

करीब 60 प्रतिशत कण करीब 4.6 अरब से लेकर 4.9 अरब वर्ष पुराने हैं। इस उम्र के अधिकांश कणों की मौजूदगी का एक बड़ा कारण यह हो सकता है कि करीब 7 अरब वर्ष पहले हमारी आकाशगंगा में तारों का जन्म हुआ था। ये तारे करीब दो से ढाई अरब वर्ष बाद धूल उत्पन्न करने लायक हुए। जब तारे का जन्म होता है तब वह धूल का उत्पादन नहीं करता। तारे अपने जीवनकाल के अंत में ही धूल उत्पन्न करते हैं।

(लेखक विज्ञान के जानकार हैं)

राजरंग

पद की लालसा

भाजपा में नए अध्यक्ष का चुनाव अगले सप्ताह होने वाला है, लेकिन चर्चा नए अध्यक्ष को लेकर नहीं, बल्कि संगठन पदाधिकारियों को लेकर शुरू हो गई है। दरअसल यह पहले से ही तय है कि अध्यक्ष कौन बनेगा। नए अध्यक्ष के साथ ही संगठन में फेरबदल और विस्तार को लेकर संभावनाएं हैं। दरअसल अमित शाह ने अपने लंबे कार्यकाल में बहुत ज्यादा विस्तार नहीं किया था। महासचिव पद समेत कई पदों पर रिक्तियां थीं। पिछले दिनों में संसदीय बोर्ड में भी कई रिक्तियां हो गई हैं। जाहिर है कि जो पहले ही मंत्री या दूसरे महत्वपूर्ण पदों पर हैं उनके अंदर संसदीय बोर्ड में स्थान पाने की लालसा है जो पार्टी की शीर्ष निर्णायक कमेटी है। तो ऐसे कई लोग हैं जो दूसरे पद या फिर संगठन में प्रवेश को लेकर लालायित हैं। यह आशा संजोए बैठे हैं कि जेपी नड्डा के अध्यक्ष बनने के बाद सभी पदों पर रिक्तियां भरी जाएंगी और ऐसे में उनकी लाटरी निकल सकती है।

करामाती नेम-प्लेट

मंत्री जी के दफ्तर का रिनोवेशन हुआ और क्या रिनोवेशन हुआ। जिसने भी देखा तारीफ की। एक-एक आइटम मंत्री जी की पसंद का। उद्घाटन का दिन आया। मंत्री जी बेहद उत्साहित। दल-बल के साथ पहुंचे, लेकिन ये क्या। सब कुछ नया, लेकिन नेम प्लेट गायब। यह कैसे हो गया? तुरंत पूछताछ हुई तो पता लगा कि आसपास के लोगों को कुछ मालूम नहीं। खास किस्म का नेम प्लेट बनवाया गया था जो गायब हो गया। कुछ ही देर में एक दूसरे सहयोगी ने जांच पड़ताल के आधार पर बताया, नेम प्लेट जिस दरवाजे पर लगी थी वह दरवाजा ही रिनोवेशन करने वाली कंपनी ले गई है। सबने राहत की सांस ली। कंपनी ने सोचा जब सब बदला जा रहा है तो नेम प्लेट भी बदली जाएगी। उसे बताया गया जल्द से जल्द नेम प्लेट वापस करो, वह कोई ऐसी वैसी नेम प्लेट नहीं है। कुछ दिनों बाद नेम प्लेट वापस आ गई।

रेलवे में बेचैनी

रोज नए-नए आदेशों और निर्देशों से हलकान रेलवे के कर्मचारी इन दिनों एक नई मुसीबत को लेकर बेचैन हैं। ये बेचैनी रेलवे बोर्ड के उस आदेश से पैदा हुई है जिसमें सभी जोन, मंडल और उत्पादन इकाइयों से जुड़े तमाम दफ्तरों में सीसीटीवी कैमरे लगाने को कहा गया है। ये कैमरे आइपी बेस्ड होंगे, जिनमें चेहरे के भाव और हरकतों से व्यक्ति के इरादों की पहचान हो सकती है। आगामी 31 सितंबर तक पूरा होने वाले इस प्रोजेक्ट के तहत लाखों की संख्या में आइपी बेस्ड सीसीटीवी कैमरों की खरीद की जानी है। रेलवे कर्मचारियों को डर है कि इन कैमरों से उनकी आजादी छिन जाएगी और कार्यालयों का माहौल रोबोटिक हो जाएगा। अभी कार्यालयों में कर्मचारी हल्की-फुल्की गपशप के साथ मस्ती में काम करते हैं। कैमरे लगने के बाद अफसर उन्हें छोटी-छोटी बातों के लिए प्रताड़ित कर सकते हैं। दूसरी ओर रेलवे बोर्ड के अफसरों का कहना है कि कैमरे लगने से कार्यालयों में अवांछित लोगों की घुसपैठ रुकने के साथ भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा, लेकिन ये बात कर्मचारियों को हजम नहीं हो रही है।

साहब की हसरत

कृषि मंत्रालय के आला अफसर की हसरत पूरी हो या न हो, लेकिन इसे लेकर मंत्रालय के बाकी अफसरों में अटकलबाजियां खूब लगाई जा रही हैं। साहब की नजर अपने राज्य के चीफ सेक्रेटरी पद पर थी, लेकिन उसे ऐसी नजर लगी कि साहब की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वैसे तो साहब बेहद शरीफ और सज्जन श्रेणी वाले अफसरों में गिने जाते हैं, लेकिन जिस राज्य से वह आते हैं वहां के लोगों की क्या कहें? उन्हें शक और संदेह के घेरे में खड़ा कर दिया। बस फिर क्या था, उनके प्रतिद्वंद्वियों को मौका लग गया और साहब को दौड़ से बाहर करा दिया। राजनीतिक लोगों के आसपास रहने वाले अफसर राजनीति के पक्के खिलाड़ी हो जाते हैं, लेकिन बड़े साहब इसमें मात खा गए। इसीलिए उनके पीछे खड़े अफसर अब उन्हें ही चिढ़ाने से बाज नहीं आ रहे हैं। रेस में पिछड़े साहब अब मन मसोस कर रबी, खरीफ और जायद की तैयारी में लग गए हैं।

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. संपादकीय निदेशक-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई शुल्क अतिरिक्त।

1969 में महात्मा गांधी के 100वें जन्मदिन पर पहली बार देश के करेंसी नोट पर महात्मा गांधी की तस्वीर छापी गई। इसमें गांधीजी को बैठे हुए दिखाया गया था और इसकी पृष्ठभूमि में सेवाग्राम आश्रम था।

आजकल

रणनीतिक चूक से असफल हुई फिल्म

अनंत विजय
anant@nda.jagran.com

सिनेमा के प्रति दर्शकों का मूड हर दौर में तात्कालिक सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार रहा है और इसमें निरंतर बदलाव भी आता रहा है। लेकिन इस बदलाव को समझ पाना सभी के बूते की बात नहीं। आज के दौर में अधिकांश लोग राष्ट्रवाद से जुड़ी फिल्मों को देखना पसंद करते हैं और वे कलाकारों से भी ऐसी ही उम्मीद करते हैं। ऐसे में इसके विपरीत कृत्य से फिल्म को नुकसान ही होगा जो आज दिख भी रहा है

बीते दिनों जेएनयू में छात्र आंदोलन को समर्थन देने पहुंचीं दीपिका पादुकोण। फाइल फोटो।

अजय देवगन की फिल्म 'तान्हाजी' ने एक बार फिर से यह साबित किया कि दर्शकों की अपने ऐतिहासिक चरित्रों में खासी रुचि है। यह फिल्म रिलीज के पहले ही सप्ताह में सौ करोड़ के कारोबारी आंकड़े को पार कर अपनी सफलता का परचम लहरा चुकी है। जबकि इसके साथ ही दीपिका पादुकोण की फिल्म 'छपाक' भी रिलीज हुई थी जिसे मेघना गुलजार जैसी मशहूर शख्सियत ने निर्देशित किया था। अपनी फिल्म की रिलीज के पहले दीपिका ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के आंदोलनकारी छात्रों को मूक समर्थन देकर मीडिया में सुर्खियां बटोरने का उपक्रम भी किया था। बावजूद इसके फिल्म छपाक को अपेक्षित सफलता नहीं मिल सकी। छपाक एक सप्ताह में लागत भी नहीं निकाल सकी और सप्ताह का कलेक्शन 26 करोड़ से नीचे रहा। बॉक्स ऑफिस की रिपोर्ट के मुताबिक दीपिका की फिल्प 'छपाक' फ्लॉप हो गई है। सोशल मीडिया पर तमाम क्रांतिकारी शूरवीरों ने भी दीपिका की इस फिल्म को सफल बनाने की मुहिम चलाई थी, लेकिन उस फिल्म को लेकर जो एक अवधारणा लोगों तक पहुंचनी चाहिए थी वह बन नहीं पाई। रिपोर्ट के मुताबिक 'छपाक' ने बड़े शहरों में भी अच्छा बिजनेस नहीं किया और रिलीज होने के अगले गुरुवार को उसकी कमाई सिर्फ एक करोड़ रुपये ही रह गई। फिल्म 'छपाक' का विषय अच्छा है, लेकिन उसका ट्रीटमेंट और निर्देशन उस स्तर का नहीं है कि वो फिल्म से कोई छाप छोड़ सके। एसिड पीड़िता के दर्द को समाज में प्रत्येक संवेदनशील व्यक्ति महसूस करता है, इस हमले के खिलाफ उसके मन से प्रतिरोध की आवाज भी उठती रहती है, लेकिन फिर भी लोग इस फिल्म को अपेक्षित संख्या में देखने नहीं गए। इसकी वजह यही रही कि यह फिल्म लोगों के बीच आपसी बातचीत का हिस्सा नहीं बन पाई। 'छपाक' जैसी फिल्मों को कभी भी बंपर ओपनिंग नहीं मिली है और इस तरह की फिल्में धीरे-धीरे ही बेहतर कारोबार करती हैं। हाल ही में रिलीज हुई निर्देशक अनुभव सिन्हा की फिल्म 'आर्टिकल 15' भी इसी रास्ते पर चलकर सफल हुई। 'आर्टिकल 15' के विषय के बारे में, आयुष्मान खुराना के अभिनय के बारे में लोगों के बीच चर्चा शुरू हो गई और फिर धीरे-धीरे दर्शक इस फिल्म को देखने के लिए सिनेमा हॉल जाने लगे और फिल्म सफल हो गई। लोगों में चर्चा से फिल्म हिट होने का एक सटीक उदाहरण है फिल्म- शोले। वर्ष 1975 में जब यह फिल्म रिलीज हुई थी तब ना तो चौबीस घंटे के न्यूज चैनल थे, ना ही वेबसाइट्स और ना सोशल मीडिया। तब अखबारों में विज्ञापन आया करते थे। फिल्म समीक्षा छपा करती थी। पोस्टरों से लोगों को फिल्मों की जानकारी मिलती थी या कई शहरों में तो रिक्शे पर लाउडस्पीकर लगाकर फिल्म का प्रचार किया जाता था। जब अगस्त 1975 में 'शोले' रिलीज हुई थी तो लगभग सभी अखबारों ने इसको फ्लॉप करार दे दिया था। समीक्षकों को यह फिल्म अच्छी नहीं लगी थी। एक अखबार में तो फिल्म समीक्षा का शीर्षक था- 'शोले' जो भड़क न सका। लेकिन फिल्म को लेकर जब लोगों के बीच बातचीत शुरू हुई तो फिर माउथ पब्लिसिटी ने वो असर दिखाया जिसके आगे प्रचार के सारे माध्यम पिछड़ गए। 'शोले' की सफलता की कहानी लिखने की आवश्यकता नहीं है। 'शोले' की सफलता के पीछे भी दर्शकों में आपस में हुई बातचीत के फैलने का असर ही माना जाता है। ये एक कारक था, लेकिन इसके अलावा इसका निर्देशन और सभी कलाकारों का अभिनय भी कमाल का था।

दीपिका की फिल्म 'छपाक' को अपेक्षित सफलता नहीं मिलने की एक वजह उनका जेएनयू जाना भी रहा। वो छात्रों के बीच गईं, मौन रहीं, लेकिन उनके आसपास जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार की उपस्थिति और वामपंथी विचारधारा के लोगों के दीपिका के पक्ष में आने से फिल्म के खिलाफ माहौल बन गया। इस स्तंभ में विस्तार से इस बात की चर्चा की जा चुकी है कि दीपिका जेएनयू इस वजह से गईं कि उनकी प्रचार टीम को दीपिका के इर्द-गिर्द चर्चा चाहिए थी। प्रचार टीम यह आकलन करने में चूक गई कि बाजार के औजार तभी सफल हो सकते हैं जब उसके साथ व्यापक जन समुदाय हो। बाजार उस विचारधारा के कंधे पर नहीं चल सकता है जिस विचारधारा को पूरे देश ने लगभग नकार दिया। प्रचार टीम की इस रणनीतिक चूक का खामियाजा फिल्म को भुगतना पड़ा।

बाजार के स्वभाव को नजदीक से जानने वालों का मानना है कि आमिर और शाहरुख खान की फिल्मों के फ्लॉप होने या उनकी चमक फीकी पड़ने के पीछे उनका 2014 के बाद दिया गया बयान रहा है। जन के मानस पर जो बात एक बार अंकित हो जाती है उसको कुछ लोग आक्रामक तरीके से प्रकट कर देते हैं जबकि ज्यादातर लोग खामोशी से उसका प्रतिरोध करते हैं। फिल्मों के वितरण के कारोबार से जुड़े लोगों का मानना है कि जनता के मन को समझते हुए ही शाहरुख और आमिर दोनों ने अपना रास्ता बदला और वो दोनों नरेंद्र मोदी से मिलने का कोई मौका नहीं छोड़ते और प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात की तस्वीरों को प्रचारित भी करते हैं ताकि यह संदेश जा सके कि वे मोदी के विरोध में नहीं हैं। दूसरी बात यह कि देश की जनता खासकर हिंदी फिल्मों के दर्शक इस बात को पसंद नहीं करते हैं कि राजनीति को फिल्मों के सफल होने का उपयोग किया जाए। दर्जनों उदाहरण हैं कि जब फिल्म के कलाकारों ने फिल्म रिलीज के पहले राजनीति का दांव चला है, लेकिन उससे नुकसान ही हुआ है।

दीपिका के जेएनयू जाने से जो प्रतिरोध हुआ उसका फायदा अजय देवगन की फिल्म को मिला। आज देश भर में राष्ट्रवाद को लोग पसंद कर रहे हैं और उसके खिलाफ सुनने को तैयार नहीं है। कोई भी देश अपने स्वर्णिम इतिहास और उस इतिहास के उन चरित्रों को बेहद पसंद करता है जिन्होंने देश की गौरव गाथा लिखी और अपनी वीरता, शौर्य और अपने कृत्यों से देश का नाम रौशन किया। अपने अतीत को लेकर गौरव का उभार इस वक्त पूरी दुनिया में है। इस वैश्विक परिघटना से भारत भी अछूता नहीं है। अब भारत औपनिवेशिक गुलामी से मानसिक रूप से भी लगभग मुक्त हो चुका है। आजादी के बाद की फिल्मों को देखें तो उस दौर में फिल्मकार अंग्रेजों के जुल्म को दिखाते थे और फिर नायक उस जुल्म के खिलाफ खड़ा होता था। उसको देखने के लिए जनता की भारी भीड़ उमड़ती थी। यह क्रम काफी लंबे समय तक चलता रहा। क्रांति और लगान भी इसी थीम पर बनी और उसको दर्शकों का जबरदस्त प्यार मिला। इसके बाद भारत पाकिस्तान युद्ध पर आधारित फिल्में बनीं। पाकिस्तानियों को हारते हुए देखकर लोग खूब ताली बजाते थे और टिकट खिड़की पर दर्शक टूट पड़ते थे।

हिंदी फिल्मों में अब वह दौर बदल गया है। लोग भारत की गौरव गाथा को देखना चाहते हैं। चाहे वो खेल के मैदान में लिखी गई गौरव गाथा हो, विज्ञान की दुनिया की खास उपलब्धि हो या फिर आजाद भारत की सैन्य उपलब्धियां हों। चाहे वो अक्षय कुमार की फिल्म 'गोल्ड' हो, उनकी ही फिल्म 'मिशन मंगल' हो या फिर फिल्म 'उरी' हो। यह बदलाव इस बात को रेखांकित करता है कि भारत में सिनेमा के दर्शकों का मन और मिजाज दोनों बदल रहा है। सिर्फ फिल्म ही क्यों, अगर हम वेब सीरीज पर भी देखें तो ऐतिहासिक चरित्रों के इर्द गिर्द बनी सीरीज सफल हो रही हैं। नेटफ्लिक्स से लेकर अमेजन और जी फाइव से लेकर एमएक्स तक के प्लेटफॉर्म पर गौरव गाथाओं को प्राथमिकता दी जा रही है। बाजार का अच्छा जानकार वही माना जाता है जो देश के मूड को भांपते हुए जनता के मन मुताबिक चीज उसके सामने रखे। सफलता मिलती ही है नहीं तो फिर उसका 'छपाक' हो जाता है।

फिर से

भारतीय रुपये पर लक्ष्मी!

भाजपा नेता और राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी की भारतीय रुपये की सेहत सुधारने के लिए दी गई एक सलाह चर्चा में है। मध्य प्रदेश के खंडवा में बीते दिनों स्वामी विवेकानंद व्याख्यानमाला के बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि वह नोट में धन की देवी लक्ष्मी की तस्वीर छापने के पक्ष में हैं। पत्रकारों ने उनसे डॉलर के मुकाबले गिरते रुपये की हालत को लेकर सवाल किया था। स्वामी ने इंडोनेशिया के करेंसी नोट पर गणेशजी की फोटो होने का भी जिक्र किया और कहा, 'इस सवाल का जवाब तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे सकते हैं, लेकिन मैं इसके पक्ष में हूं। भगवान गणेश विघ्न दूर करते हैं। मैं तो कहूंगा कि देश की करेंसी को सुधारने के लिए लक्ष्मीजी की फोटो लगाई जा सकती है, इस पर किसी को आपत्ति भी नहीं होगी।'

सवाल यह है कि आखिर भारतीय करेंसी नोट पर किसकी तस्वीर होगी, इसे तय करने का अधिकार किसको है? क्या करेंसी नोट पर महात्मा गांधी की तस्वीर को हटाया जा सकता है? दुनिया के दूसरे केंद्रीय बैंकों की तरह भारत में भी करेंसी नोट जारी करने का अधिकार केवल आरबीआइ को है (एक रुपये का नोट भारत सरकार जारी करती है)।

भारतीय रिजर्व बैंक की वेबसाइट के मुताबिक भारत सरकार ने पहली बार 1949 में एक रुपये के नोट का नया डिजाइन तैयार किया। आजादी के बाद माना जा रहा था कि ब्रितानी महाराजा की जगह नोट पर महात्मा गांधी की तस्वीर लगेगी, लेकिन आखिर में सहमति इस बात पर बनी कि महात्मा गांधी की तस्वीर के बजाय करेंसी नोट पर अशोक स्तंभ छापा जाना चाहिए। इसके अलावा करेंसी नोट के डिजाइन में बहुत अधिक बदलाव नहीं किए गए थे। वर्ष 1950 में भारतीय गणराज्य में पहली बार दो, पांच, 10 और 100 रुपये के नोट जारी किए गए। दो, पांच और 100 रुपये के नोट के डिजाइन में तो बहुत अधिक अंतर नहीं था, पर रंग बहुत अलग थे। 10 रुपये के नोट के पीछे पाल नौका की तस्वीर ज्यों की त्यों रखी गई थी। वर्ष 1953 में नए करेंसी नोटों पर हिंदी को प्रमुखता से छापा गया।

वर्ष 1954 में एक हजार, दो हजार और 10 हजार रुपये के नोट फिर से जारी किए गए। वर्ष 1978 में इन्हें फिर व्यवस्था से बाहर कर दिया गया यानी 1978 में एक हजार, पांच हजार और 10 हजार रुपये की नोटबंदी हुई।

दो और पांच रुपये के छोटे करेंसी नोटों पर शेर, हिरण आदि की तस्वीरें छपी थीं, लेकिन 1975 में 100 रुपये के नोट पर कृषि आत्मनिर्भरता और चाय बागानों से पत्ती चुनने की तस्वीर नजर आने लगी।

वर्ष 1969 में महात्मा गांधी के 100वें जन्मदिन पर पहली बार करेंसी नोट पर महात्मा गांधी की तस्वीर छापी गई।

इंडोनेशिया का एक नोट। फाइल फोटो।

इसमें महात्मा गांधी को बैठे हुए दिखाया गया था और पृष्ठभूमि में था सेवाग्राम आश्रम। वर्ष 1972 में रिजर्व बैंक ने पहली बार 20 रुपये का नोट जारी किया और इसके तीन साल बाद 1975 में 50 रुपये का नोट जारी किया गया।

नए सुरक्षा फीचर्स के साथ महात्मा गांधी सीरीज के करेंसी नोट वर्ष 1996 में छापे गए। नौ अक्टूबर 2000 को एक हजार रुपये का नोट जारी किया गया। भारतीय मुद्रा का दूसरा सबसे बड़ा सुधार नवंबर 2016 में किया गया। दरअसल आठ नवंबर 2016 को महात्मा गांधी सीरीज के सभी 500 और 1,000 रुपये के नोट अवैध घोषित कर दिए गए जिसे 'नोटबंदी' के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद 2,000 रुपये का नया नोट जारी किया गया। इसमें भी महात्मा गांधी की तस्वीर छपी है।

(बीबीसी से संपादित अंश, साभार)

ट्वीट-ट्वीट

हम हिंदुओं को अपने अतीत जैसे मानवतावाद, ज्ञान प्रणाली, सांस्कृतिक-आध्यात्मिक विरासत सरीखे सकारात्मक पहलुओं पर गर्व करने में संकोच नहीं करना चाहिए, पर हमें दूसरी मान्यताओं को भी बराबर सम्मान देना चाहिए। देश को महान बनाने का यही एक रास्ता है।
सुधींद्र कुलकर्णी@SudheenKulkarni

सावरकर, करीम लाला या शिवाजी की विरासत, संजय राउत रोज नया विवाद खड़ा करते हैं। इससे भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र सरकार को निशाना बनाने में मदद मिल रही है। लगता है कि वह अपनी सरकार से खुश नहीं और उसे अस्थिर करना चाहते हैं।
निखिल वागले@waglenikhil

मोदी सरकार ने एक और ऐतिहासिक समस्या को दूर कर लिया। उसने ब्रू जनजातियों के संकट का समाधान करते हुए उन्हें त्रिपुरा में बसाने के लिए एक समझौते को अंतिम रूप दे दिया है।
प्रदीप भंडारी@pradip103

जीवन में पहली बार देखूंगा कश्मीरी पंडितों के दर्द को बयां करने वाली फिल्म शिकारा। महसूस करूंगा उन आवाजों को जो रात के अंधेरों में दबा दी गईं। जानूंगा अपने ही देश में कश्मीरी पंडित शरणार्थी कैसे? क्या उस समय मानव अधिकार, बुद्धिजीवी और कैंडल मार्च करने वाले लोग भारत में नहीं थे?
स्वामी दीपांकर@swamidipankar

ऑस्ट्रेलिया ने अरबों की संख्या में जीवजंतुओं को खो दिया है, क्योंकि उसने जलवायु परिवर्तन की समस्या पर समय रहते ध्यान नहीं दिया। हमें इस बात की अनदेखी नहीं करनी चाहिए कि भारत को भी जलवायु परिवर्तन की गंभीर कीमत चुकानी पड़ रही है। इसलिए समय रहते चेत जाना ही बेहतर होगा।
प्रीतीश नंदी@PritishNandy

जागरण जनमत

कल का परिणाम

क्या महेंद्र सिंह धौनी को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लेना चाहिए?

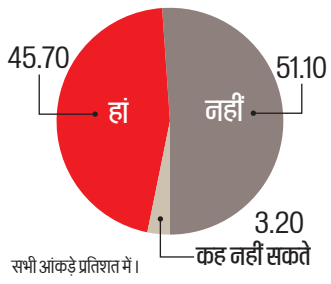

सभी आंकड़े प्रतिशत में।

आज का सवाल

क्या ग्राहकों को क्रेडिट, डेबिट कार्ड स्विच ऑफ करने की सुविधा मिलने से डिजिटल फ्रॉड के मामले रुकेंगे?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।

जनपथ

साथी अंडरवर्ल्ड के नेता रहे महान,
पर सावरकर से बड़ा दल में उनका मान।
दल में उनका मान उन्हें जाता है पूजा,
नेहरू-गांधी छोड़ नहीं दिखता है दूजा।
सुनकर जिनका नाम गर्व से फूले छाती,
जलते उनसे लोग रहे 'लाला' के साथी।
– ओमप्रकाश तिवारी

रचनाकर्म

जाकिर हुसैन की जिंदगी के अनछुए पहलू

अमित तिवारी

मशहूर तबलावादक उस्ताद जाकिर हुसैन के साक्षात्कार पर आधारित यह पुस्तक उन्हें और संगीत की इस विधा के परिदृश्य को समझने का अवसर देती है...

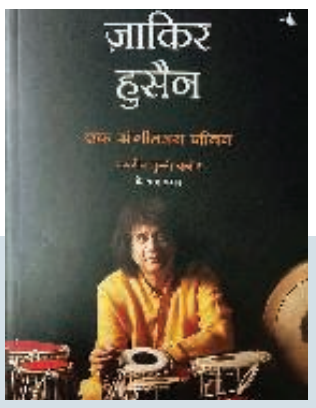

पुस्तक का नाम : जाकिर हुसैन : एक संगीतमय जीवन
लेखिका : नसरीन मुन्नी कबीर
प्रकाशक : मंजुल पब्लिशिंग हाउस
मूल्य : 350 रुपये

कुछ नाम ऐसे होते हैं, जिनका जिक्र होते ही मन में धुन-सी गूंज उठती है। उत्कृष्ट तबलावादक, संगीतकार और तालवाद्य के जानकार जाकिर हुसैन भी ऐसा ही नाम हैं। संगीत की दुनिया में जरा-सी रुचि रखने वाला भी उस्ताद जाकिर हुसैन के नाम से जरूर परिचित होगा। इस अंतरराष्ट्रीय संगीत हस्ती के बारे में खुद उन्हीं के शब्दों में पढ़ना किसी शानदार कंसर्ट में कर्णप्रिय संगीत सुनने जैसा ही अनुभव देता है।

यह किताब नसरीन मुन्नी कबीर और जाकिर हुसैन के बीच हुई बातचीत के आधार पर लिखी गई है। प्रश्नोत्तर शैली में लिखी किताब को पढ़कर ऐसा लगता है, मानो बस यही सवाल कहीं हमारे मन में भी रहा होगा। नसरीन मुन्नी कबीर ने जिस खूबसूरती से सवालों का चयन किया है, वह लेखन की उनकी खूबी दिखाता है। उन्हें बखूबी पता है कि कोई पाठक जाकिर हुसैन जैसी हस्ती से क्या सवाल पूछना चाहेगा। उस्ताद जाकिर हुसैन के जवाब उन सवालों को पूरा करने का काम करते हैं। सवाल-जवाब का यह क्रम बरबस ही कोई धुन तैयार करने जैसा अनुभव देता है।

यह किताब उस्ताद अल्लारक्खा के पुत्र जाकिर हुसैन के जीवन के कुछ ऐसे पहलुओं को जानने का मौका देती हैं, जो अब तक अनछुए हैं। किताब की शुरुआत ही एक ऐसे घटनाक्रम से होती है, जो शायद ही कभी किसी मंच पर सुनने को मिली हो। जाकिर हुसैन बताते हैं कि उनके जन्म के तुरंत बाद ही उनके पिता की तबीयत खराब हो गई थी। घर के लोग उन्हें मनहूस बच्चा मानने लगे थे। यहां तक कि मां ने भी उन्हें मनहूस मानते हुए अपना दूध नहीं पिलाया। परिवार की एक नजदीकी मित्र ने उनकी शुरुआती देखभाल की। हालांकि यह स्थिति बहुत ज्यादा समय तक नहीं रही। कुछ साल बाद उस्ताद अल्लारक्खा की तबीयत ठीक हो गई और धीरे-धीरे बेटे जाकिर हुसैन का रुतबा भी घर में बढ़ता गया। किताब में उस्ताद जाकिर हुसैन अपना नाम रखे जाने से जुड़ी दिलचस्प कहानी भी बताते हैं।

जाकिर हुसैन से हुई इस गुफ्तगू में ऐसी ही बहुत सी दिलचस्प बातें जानने को मिलती हैं। दुनिया भर के कई संगीतकारों के साथ संगत कर चुके उस्ताद जाकिर हुसैन इस बारे में भी अपना अनुभव साझा करते हैं। इसे इस तरह भी कहा जा सकता है कि किताब भले ही एक जीवन पर केंद्रित दिखती है, लेकिन सवाल-जवाब के समुद्र मंथन से कई ऐसे रत्न बरबस ही ऊपर आ जाते हैं, जिनके बारे में सोचा नहीं हो। दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में प्रस्तुति दे चुके उस्ताद जाकिर हुसैन की जुबानी संगीत को लेकर अलग-अलग देशों और वहां के लोगों की दिलचस्पी का भी अंदाजा लगता है। 68 वर्ष के जाकिर हुसैन ने सात साल की उम्र में ही लोगों को अपनी प्रतिभा का लोहा मानने पर मजबूर कर दिया था। आज वह अपने आप में संगीत का एक विश्वविद्यालय बन चुके हैं। वह जीवन जीने की प्रेरणा भी देते हैं और सफलता का सूत्र भी रचते हैं। वह संगीत साधना और ध्यान पर भी चर्चा करते हैं। किताब में कुछ तस्वीरों का भी संग्रह है, जिससे इसकी खूबसूरती में चार चांद लग जाते हैं।

नसरीन मुन्नी कबीर अब तक हिंदी सिनेमा पर 16 पुस्तकें लिख चुकी हैं। उन्होंने सिनेजगत की कुछ बड़ी हस्तियों से गूफ्तगू के आधार पर किताबें लिखी हैं। हालांकि संगीत जगत की किसी हस्ती से बातचीत का उनका यह पहला अनुभव है। उस्ताद जाकिर हुसैन से करीब डेढ़ दर्जन मुलाकातों में सवाल-जवाब के जरिये इस किताब को मूर्तरूप दिया गया। अंग्रेजी में लिखी इस किताब का अनुवाद महेंद्र नारायण सिंह यादव ने किया है। अनुवाद के समय शब्दों का चयन और भावों को बिखरने नहीं देने की कला इस किताब में झलकती है। अगर आप संगीत की दुनिया के इस बेताज बादशाह के जीवन को करीब से समझना चाहते हैं, तो निस्संदेह यह किताब इसका शानदार माध्यम बन सकती है।

विसंगतियों पर व्यंग्य की पैनी धार

कन्हैया झा

पुस्तक : नामुमकिन नेता
लेखक : यश गोयल
प्रकाशक : विवेक पब्लिशिंग हाऊस, जयपुर
मूल्य : 200 रुपये

कहा जाता है कि व्यंग्यकार के पास एक ऐसी दृष्टि होना आवश्यक है जिसमें वह समाज की विद्रूपताओं को देख-समझ सके और उन पर अपना वार कर सके। व्यंग्य संग्रह 'नामुमकिन नेता' में लेखक यश गोयल अपने लेखन से इस विचार की पुष्टि करते हैं और उसे विस्तार प्रदान करते हुए असंगत मूल्यों में सुधार का मार्ग भी सुझाते हैं। प्लांट बायोटेक्नोलॉजी से पीएचडी की उपाधि प्राप्त कर चुके यश गोयल पत्रकारिता से भी लंबे अरसे तक जुड़े रहे, लिहाजा उन्हें देश-दुनिया की अनेक विधाओं-क्षेत्रों का व्यापक ज्ञान है। इस व्यंग्य संग्रह के अलावा वह 'मंत्री का चश्मा', 'कुर्सी का देवदास', 'भ्रष्टाचार डॉट कॉम' जैसी अनेक पुस्तकें भी लिख चुके हैं। कई पुरस्कारों से सम्मानित लेखक यश गोयल की व्यंग्य विधा पर यह छठी पुस्तक है। प्रस्तुत व्यंग्य संग्रह 'नामुमकिन नेता' की एक बड़ी खासियत यह है कि इसमें लेखक ने 55 अलग-अलग विषयों पर व्यंग्य लिखे हैं और प्रत्येक को डेढ़ से दो पृष्ठों में ही समेटा है। इससे पाठकों में रोचकता बनी रहती है।

इस संग्रह के कुछ प्रमुख शीर्षक इस प्रकार हैं- बेचारी डेमोक्रेसी, अनहोनी को 'मुमकिन' कर दे, चौकीदार, एग्जिट पोल की 'फिरकी', विकास का मोतियाबिंद, चुनावी एजेंडा, आ गया 'आधार कार्ड' का 'पैडमैन' से लिंक, गब्बर अभी जिंदा है, नाचीज की इच्छाएं, क्लीन चिट का माहात्म्य, दिव्यस्वप्न, किट्टी में 'मीटू', बेचारा किसान किसका है?, पत्थरबाजी इन पॉलिटिक्स, डिजिटल दर्द, ब्रेकिंग सेल्फी, जुबान पर शब्दों का फिसलना, अच्छे दिनों का आखिरी दिन।

इस व्यंग्य संग्रह के रोचक शीर्षक व्यंग्य पढ़ने की उत्सुकता जगाते हैं। इनके विषय सामयिक हैं और अपना नयापन नहीं खोते हैं। कहा जा सकता है कि लेखक की इन रचनाओं में व्यंग्य की धार के साथ-साथ करुणा का भी मिश्रण है, जो इन्हें सार्थक व्यंग्य की श्रेणी में ले जाता है। पुस्तक की भाषा बहुत सरल है और अपनी धारदार विषयवस्तु की बेहतर जुगलबंदी के साथ यह पठनीय बन पड़ी है।

मध्य प्रदेश डायरी

बच्चों की दशा में सुधार के लिए भी हो राजनीति

आशीष व्यास
संपादक, नई दुनिया, मध्य प्रदेश

राजस्थान के कोटा में नवजात बच्चों की मौत के बाद देश भर में शिशु स्वास्थ्य जब मुद्दा बन रहा था, मध्य प्रदेश में भी छोटे बच्चों की सांसों पर संकट गहराने लग गया। शहडोल जिला अस्पताल में आठ घंटे में छह बच्चों ने जैसे ही दम तोड़ा, स्वास्थ्य नीति और प्रबंधन की समीक्षा शुरू हो गई। लेकिन अभी एक सप्ताह भी नहीं बीता है और इस पूरे मामले को फिर पुरानी सुस्ती ने अपने साथ शामिल कर लिया है। दरअसल शहडोल में दम तोड़ने वाले बच्चों में से दो वार्ड में और चार एसएनसीयू में भर्ती थे। एसएनसीयू में भर्ती बच्चों की उम्र एक महीने से भी कम थी, वहीं बच्चा वार्ड में भर्ती बच्चों की उम्र दो-तीन महीने ही थी। इन बच्चों को निमोनिया हुआ था।

लोक कल्याणकारी राज्य की कल्पना में शिक्षा-स्वास्थ्य वैसे भी सरकारों के बुनियादी दायित्व में शामिल हैं। लेकिन मध्य प्रदेश के साथ यह दुर्भाग्य है कि सरकारें जरूर बदलती रहीं, लेकिन स्वास्थ्य का बुनियादी ढांचा परंपराओं को ढोता रहा। तात्कालिक आवश्यकता इस बात की है कि मध्य प्रदेश परिणामदायक उदाहरण सामने रख अपनी लड़ाई शुरू करे, क्योंकि यहां बच्चों को बीमारी से लड़ने का अवसर ही नहीं मिल रहा है। बात कुपोषण से शुरू होती है, वहीं खत्म भी हो जाती है।

वर्ष 1990 से 2016 के बीच 'डिजीज बर्डेन प्रोफाइल' पर हुए एक अध्ययन के अनुसार मध्य प्रदेश में होने वाली मौतों में 13.7 फीसद 14 साल तक के बच्चे हैं। इसमें से करीब 36 प्रतिशत मौत डायरिया, रेस्पायरेटरी इंफेक्शन (श्वसन पथ संक्रमण) से होती है। इसका सीधा संबंध कहीं न कहीं कुपोषण, साफ-सफाई के अभाव और गरीबी से है। जन्मजात परेशानियों के कारण 37 फीसद नवजात की मौत हो जाती है। इसके अलावा तीन से सात प्रतिशत बच्चे मलेरिया व अन्य रोग, दिल की बीमारी सहित अन्य विकृतियों की वजह से असमय आंखें मूंद लेते हैं। आंकड़े गवाही देते हैं कि कुल मौतों में करीब 75 फीसद मौतें कुपोषण या इससे जुड़े हुए कारणों से हो रही हैं।

हाल ही में इंदौर में जुटे देश भर के शिशु रोग विशेषज्ञों का भी यही मानना है कि मध्य प्रदेश के लिए कुपोषण ही बीमारियों का गढ़ है। इंडियन पीडियाट्रिक्स एसोसिएशन की मध्य प्रदेश इकाई के पूर्व अध्यक्ष डॉ. वीपी गोस्वामी मानते हैं, 'हम कुछ ऐसी बीमारियों पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, जो प्रदेश में भौगोलिक परिस्थितियों के कारण मौजूद हैं। जैसे, पहाड़ी इलाकों पचमढ़ी, बैतूल सहित कई आदिवासी बहुल जिलों के बच्चों में आज भी आयोडीन की कमी पाई जाती है। प्रदेश के लगभग 18 जिलों के पानी में फ्लोराइड की समस्या है। पीथमपुर सहित आदिवासी इलाकों में तिवड़ा (अरहर दाल के विकल्प के रूप में इस्तेमाल होने वाला दलहन) के ज्यादा इस्तेमाल से बच्चों में अपंगता भी देखी गई।' इंडियन पीडियाट्रिक्स एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. बकुल पारिख सुझाव देते हैं, 'हमें बहुत ज्यादा खर्च करने की जरूरत नहीं है। सरकार उपकरण खरीदने में जितना खर्च कर रही है, उतना समाज-अभिभावकों को जागरूक करने, बच्चों के स्वास्थ्य से जुड़े डॉक्टरों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने और टीकाकरण में खर्च करे, तो बहुत हद तक हालात पर नियंत्रण पाया जा सकता है। 20 फीसद बच्चे मोटापा, उच्च रक्तचाप के शिकार हो रहे हैं। अभी से नियंत्रण नहीं किया गया, तो ये बीमारियां 2050 तक महामारी का रूप ले लेंगी।'

बच्चों की मौत के बाद शुरू हुई राजनीति फिलहाल अनिर्णय की शिकार है। शायद इसीलिए भी राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप का दौर थमने लगा है। बेहतर यही होगा कि प्रदेश के भविष्य को बचाने-बढ़ाने के लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति के साथ मिलकर प्रयास किए जाएं।

सीएए पर कांग्रेस विधायकों का उल्टा राग : मध्य प्रदेश में नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के समर्थन-विरोध के बीच धरना-प्रदर्शन और रैलियां लगातार निकाली जा रही हैं। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर के साथ प्रदेश के कई बड़े जिलों से लेकर गांव-कस्बों में हुए जमावड़े ने राजनीतिक दलों को भी चौकन्ना कर दिया है। कांग्रेस जहां देश भर में सीएए का विरोध कर रही है, वहीं मध्य प्रदेश के दो कांग्रेस विधायकों की धारणाओं ने इस मुद्दे पर पार्टी के लिए संकट खड़ा कर दिया है। दोनों कांग्रेस विधायकों ने अपने-अपने तर्क के साथ सीएए का समर्थन किया है। मंदसौर जिले के सुवासरा से विधायक हरदीप सिंह डंग का स्पष्ट रूप से मानना है, 'पाकिस्तान, बांग्लादेश आदि देशों के दुखी लोगों को भारत में सुविधा मिलती है तो उसमें बुराई क्या है।' डंग की वैचारिक डगर पर चलते हुए पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के भाई और विधायक लक्ष्मण सिंह ने भी सीएए पर राजनीति बंद करने की सलाह दे डाली। उन्होंने ट्वीट किया, 'नागरिकता कानून की राजनीति बंद करो। अब तो मुसलमान भी कह रहे हैं कि बंद करो। वे कह रहे हैं कि हमारे रोजगार की व्यवस्था करो। रस्सी को ज्यादा खींचने से वह टूट जाती है।' लक्ष्मण सिंह ने इसके पहले भी सीएए के समर्थन में अपनी राय सार्वजनिक की थी। बीते दिसंबर में उनका यह ट्वीट भी काफी सुर्खियां बटोर चुका है, 'राष्ट्रीय नागरिकता कानून संसद में पारित हो चुका है। सभी दलों ने अपने विचार व्यक्त कर दिए हैं। इस विषय पर ज्यादा टिप्पणी, बयान व्यर्थ हैं। इसे स्वीकार करो और आगे बढ़ो।' कांग्रेस के लिए चिंता और चुनौती का विषय यह है कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से लेकर प्रदेश में मुख्यमंत्री तक, जिस सीएए का विरोध कर रहे हैं, उसके पक्ष की पंक्ति में सामने आए दो विधायक अब राजनीतिक बहस के नए केंद्र बन गए हैं।

शिक्षा पर भारी 'सरकारी' राजनीति : स्वास्थ्य के साथ शिक्षा से जुड़ा एक मुद्दा भी देश-प्रदेश में बहस का विषय बन गया है। वीर सावरकर एनजीओ ने बीते वर्ष नवंबर में रतलाम जिले के शासकीय हाईस्कूल मलवासा में बच्चों को निशुल्क रजिस्टर बांटे थे, ताकि वे परीक्षा की तैयारी कर सकें। रजिस्टर के मुख्य पृष्ठ पर विनायक दामोदर सावरकर की फोटो थी। कमलनाथ सरकार ने इसे कर्तव्यों के निर्वहन में घोर लापरवाही व गंभीर अनियमितता माना और प्राचार्य आरएन केरावत को निलंबित कर दिया। प्राचार्य को निलंबित करने से स्कूली बच्चों के साथ-साथ कर्मचारी संगठन भी नाराज हैं। उनका तर्क है कि केरावत राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त शिक्षक हैं और इनके स्कूल में 10वीं का परिणाम हर व

01 लाख 34 हजार 516 मामले आत्महत्या के 2018 में दर्ज किए गए। राष्ट्रीय क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के अनुसार, 2017 की तुलना में यह संख्या 3.6 फीसदी अधिक है। सबसे अधिक मामले महाराष्ट्र (17,972) में दर्ज हुए।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
रविवार 19 जनवरी 2020

हिमाचल प्रदेश

वनों के संरक्षण पर दिया जाए ध्यान

जीवन के लिए जल, जंगल और जमीन अहम हैं। किसी एक के भी प्रभावित होने से जीवन प्रभावित हो जाता है। कहा भी जाता है कि वनों से वायु और वायु से आयु। इसके बावजूद वन में अवैध कटान और आग की घटनाएं निरंतर सामने आती रहती हैं। यह सुखद है कि हिमाचल प्रदेश में हरित पट्टी का विस्तार हुआ है, लेकिन जिस गति से पौधरोपण होता है, उसके अनुपात में वनों के अधीन क्षेत्र नहीं बढ़ पाया है। हरित पट्टी का बढ़ना ही जरूरी नहीं, बल्कि हरित पट्टी का घनत्व भी बढ़ना बहुत आवश्यक है। पहाड़ी राज्य होने के कारण पहाड़ों में चौड़ी पत्ती वाले पौधे कम और नुकीले पत्तों वाले पौधे बहुतायत में हैं। इनमें चीड़ के पौधे प्रमुख हैं। चीड़ की लकड़ी और इसके पत्ते अधिक ज्वलनशील हैं। इनमें आग बड़ी तेजी से फैलती है। गर्मियों में लगभग सभी जंगलों में आग लगती है। सरकार और वन विभाग इसके प्रति गंभीर हैं, इसके बावजूद आग की घटनाओं पर पूरी तरह अंकुश नहीं लग पाया है। हर साल जंगलों में आग लगती है। इससे बेशकीमती जड़ी बूटियां नष्ट हो जाती हैं, वहीं कई वन्य प्राणी भी मारे जाते हैं। प्रदेश मंत्रिमंडल ने चीड़ की पत्तियों को ईंधन के रूप में प्रयोग करने की नीति में संशोधन किया है। चीड़ की पत्तियों से उद्योगों को सस्ता ईंधन मिलेगा, साथ ही लोगों को स्वरोजगार भी मिल सकेगा। राज्य में हर साल जंगल में आग की सैकड़ों घटनाएं होती हैं। कई बार जंगल की आग बस्तियों तक भी पहुंच जाती है। जंगल में आग लगने के कारण ही जंगली जानवर बस्तियों तक पहुंच जाते हैं। कई बार लोग भी अपने लाभ के लिए जंगलों में आग लगा देते हैं। उनका मानना है कि आग लगाने से पत्तियां व घास फूस जल जाता है। इससे वहां अच्छी घास पैदा होती है। वे इससे अनभिज्ञ हैं कि जंगल में आग लगाने से प्रकृति को कितना नुकसान पहुंचता है। सरकार की इस नई नीति से निसंदेह आग लगने लगने की घटनाओं में कमी आएगी। इसके अलावा जंगलों के निकट रहने वाले लोगों की आर्थिकी में भी सुधार के साथ नई वनस्पति को पनपने का अवसर भी मिलेगा। आवश्यकता यह भी है कि जंगलों के निकट रहने वाले लोगों को सरकार की इस नीति से अवगत करवाया जाए व जागरूक किया जाए कि जंगलों में आग लगाने से उनका ही नुकसान है।

चीड़ की पत्तियों को रोजगार का साधन बनाने की नीति से न केवल जंगल बचेंगे, बल्कि कई लोगों को आजीविका का साधन मिलेगा

पिछले लगभग एक माह से अधिक समय से ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में बड़े इलाके में आग लगी हुई है जिससे व्यापक मात्रा में ना केवल धन की हानि हुई है, बल्कि इससे बड़ी संख्या में जंगली पशुओं समेत कई इंसानों के मारे जाने की खबरें भी आई हैं। हालांकि भारी बारिश के बाद से इस आग पर काफी हद तक काबू पाया जा चुका है, फिर भी इससे बहुत नुकसान हुआ है। इससे कुछ माह पहले ही ब्राजील में 'धरती का फेफड़ा' कहे जाने वाले अमेजन के जंगलों में लगी भयावह आग से ना केवल ब्राजील को, बल्कि पूरी दुनिया के पर्यावरण का नुकसान हुआ। समय रहते इस तरह की समस्याओं पर काबू नहीं पाया गया तो इससे वनों को बचाना मुश्किल होगा।

झारखंड

पानी बचाने की चिंता

राज्य सरकार भू-गर्भ जल के संरक्षण को लेकर पहली बार प्राधिकार का गठन करने जा रही है। यह प्राधिकार भू-गर्भ जल के अतिदोहन को रोकने तथा जल स्तर के लगातार नीचे जाने जैसे हालात पर प्रभावी नियंत्रण का काम करेगा। इसके लिए झारखंड स्टेट ग्राउंड वाटर डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट (कंट्रोल एंड रेगुलेशन) बिल, 2019 लाया जा रहा है जिसका ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। इस विधेयक में ही झारखंड राज्य भू-गर्भ जल प्राधिकार के गठन का प्राविधान किया गया है। फिलहाल विधेयक के ड्राफ्ट पर राज्य के नागरिकों से सुझाव मांगे हैं। इस पर सकारात्मक सुझाव भी आने चाहिए ताकि इसे लागू करने के बाद कोई विवाद न हो। यह प्राधिकार भू-गर्भ जल के अति दोहन पर नियंत्रण के साथ-साथ जल स्तर को बढ़ाने में भी अपनी भूमिका निभाएगा। साथ ही शिकायत मिलने पर प्राधिकार के पास छापामारी कर उचित कार्रवाई करने का भी अधिकार होगा। इस प्राधिकार का कार्य क्षेत्र शहरी क्षेत्रों में होगा, जहां सबसे अधिक जल का दोहन हो रहा है। इसके तहत कुछ मामले में व्यक्तिगत के अलावा कॉमर्शियल, इंडस्ट्रियल और अन्य संस्थागत उपयोग के लिए भू-गर्भ जल के दोहन के लिए प्राधिकार से अनुमति लेनी होगी। साथ ही जल के दोहन का हिसाब भी देना होगा।

देर से ही सही, राज्य सरकार की यह पहल सराहनीय कही जा सकती है। इस प्राधिकार के गठन को लेकर

प्रतीकात्मक फोटो।

बार-बार केंद्र सरकार निर्देश दे रही थी, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ रही थी। उम्मीद की जा सकती है कि संबंधित कानून लागू होने से राज्य में भू-गर्भ जल के अति दोहन पर रोक लगेगी। राज्य में बन रहे बड़े-बड़े भवनों में अभी तक वाटर हार्वेस्टिंग की अनिवार्यता को पूरी तरह लागू नहीं किया जा सका है। वाटर प्लांट कुकुरमुत्ते की तरह गली-मोहल्ले में लग रहे हैं, जो सबसे अधिक ऐसे जल का दोहन कर अपनी मोटी कमाई कर रहे हैं। इससे वहां के आसपास के क्षेत्र का जल स्तर काफी नीचे चला जाता है। बड़े-बड़े अपार्टमेंट बनने से भी यह परेशानी बढ़ रही है, जिसका खामियाजा आसपास के लोग गर्मियों में उठाते हैं। अभी तक कोई कानून नहीं बनने से इन पर अंकुश नहीं लग पा रहा था। कानून लागू होने से निश्चित रूप से इस पर शिकंजा कसेगा।

वास्तव में कल के सुनहरे भविष्य के लिए आज हमारे लिए पानी को बचाना अत्यंत ही आवश्यक है। जल का संचय करना वर्तमान समय की सर्वोपरि प्राथमिकता होनी चाहिए। परंपरागत जल संचयन संरचनाओं का जीर्णोद्धार करना भी अत्यंत आवश्यक है। मानव शरीर में भी लगभग 66 प्रतिशत जल विद्यमान होता है। पेड़-पौधों, मनुष्यों और जानवरों के अस्तित्व के लिए जल परम आवश्यक है। हमारे चारों ओर देखें तो बिना जल के जीवन की परिकल्पना करना संभव नहीं है। बिना जल के जीवन का अस्तित्व नजर नहीं आता है। हमारे देश में पानी की उपलब्धता की इतनी समस्या नहीं है, परंतु हमारे यहां पर पानी के समुचित प्रबंधन की समस्या प्रमुख है। पानी का उचित प्रबंधन हमें स्वयं के स्तर से करना चाहिए। हम बदलेंगे तो जग बदलेगा इस विश्वास के साथ कार्य करते हुए हम जमाने को मोड़ सकते हैं। भविष्य में इस धरा पर जीवन की कल्पना करना हो तो कल के लिए जल को बचा के रखना अत्यंत ही आवश्यक है।

पंजाब

सवालों में घिरी सरकार

विगत कुछ दिनों से पंजाब सरकार तमाम मुद्दों पर घिरी हुई नजर आ रही है और विधानसभा सत्र में तो यह शिकंजा और कसता हुआ दिखा। विपक्ष तो सरकार को सवालों में खड़ा करता ही रहा और यह उसका काम भी है, लेकिन सरकार के लिए सर्वाधिक चिंता की बात यह है कि उसके अपने भी पूरी तरह से मोर्चा खोले हुए दिखाई दे रहे हैं। चाहे कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रताप सिंह बाजवा हों, वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ हों या कुछ अन्य कांग्रेसी विधायक, ये कई मुद्दों पर अत्यंत मुखर दिखाई दे रहे हैं। इससे यही स्पष्ट हो रहा है कि सरकार के अंदर तालमेल का अभाव है। उसमें गुटबाजी का आलम है। इसके अतिरिक्त प्रशासन और सत्ताधारी दल के बीच भी सबकुछ सामान्य नहीं दिखाई दे रहा है। विगत दिवस जहां सुनील जाखड़ एडवोकेट जनरल को मुख्यमंत्री के सामने ही खरी-खोटी सुना चुके हैं, वहीं गत दिवस प्रताप सिंह बाजवा और मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच भी बयानबाजी हुई। इन सबका असर सरकार के कामकाज पर पड़ रहा है।

कैप्टन अमरिंदर सिंह। फाइल फोटो।

किसी सरकार के खिलाफ यदि विपक्ष हमलावर रुख अपनाता है और जनहित के मुद्दों को लेकर सरकार को घेरता है तो यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया कही जाएगी। यह किसी भी लोकतंत्र में होना आम बात है। इससे वह जनतंत्र मजबूत होता है, लेकिन जब सरकार को अपने ही घेरने लगें तो यह स्पष्ट है कि कहीं न कहीं कुछ तो गड़बड़ी जरूर है। यह गड़बड़ी दिख भी रही है। बिजली के मुद्दे पर खासतौर पर सभी हमलावर हैं। पंजाब में पड़ोसी राज्यों के मुकाबले बिजली पहले ही बहुत महंगी है और सरकार ने इसकी दरें और बढ़ा दी हैं। पेट्रोल-डीजल पर सर्वाधिक वैट वसूलने वाले राज्यों में भी पंजाब शामिल है। कदाचित इसी कारण प्रदेश में महंगाई भी अन्य राज्यों के मुकाबले अधिक है। इसका असर प्रदेश की जनता के चेहरे पर काफी हद तक पड़ता नजर भी आ रहा है। सरकार आर्थिक मोर्चे पर भी बुरी तरह संकटग्रस्त दिखाई दे रही है, जिसका असर प्रदेश के विकास कार्यों पर भी पड़ रहा है। ऐसे में सत्ताधारी दल के प्रदेश अध्यक्ष और कई अन्य नेताओं का चिंतित होना स्वाभाविक है।

सरकार को नींद से जागना होगा, क्योंकि उसके पास जनता और अपने नेताओं को संतुष्ट करने के लिए बहुत कम समय बचा है। यदि शीघ्र कदम न उठाए गए तो जो सवाल सरकार और प्रशासन पर उठ रहे हैं उनका स्वर और तेज होने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता।

बंगाल

आगामी चुनावों में भाजपा का दांव

आगामी वर्ष 2021 में बंगाल में विधानसभा चुनाव होना है। इस वर्ष के मध्य में सूबे के 100 से अधिक नगर निकायों का भी चुनाव होना है, जिसे विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है। बंगाल में पिछले कुछ वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का जनाधार व्यापक स्तर पर बढ़ा है। इसके लिए राज्य के भाजपा नेता समेत तमाम कार्यकर्ताओं की मेहनत और लगन को निश्चित रूप से श्रेय देना चाहिए। इस संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने एक बार फिर बंगाल में दिलीप घोष पर ही दांव लगाया है। दिलीप घोष के वर्ष 2015 में बंगाल की भारतीय जनता पार्टी इकाई के अध्यक्ष बनने के बाद वर्ष 2016 के विधानसभा चुनाव में पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने तीन सीटें जीती थी। दिलीप घोष खुद भी जीते थे। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के गठन के बाद वह पहला मौका था, जब विधानसभा चुनाव में पार्टी का खाता खुला था। वैसे पार्टी उपचुनाव में एक-दो सीटें जीती थी। लोकसभा चुनाव में भी खाता खुल चुका था। इसके बाद वर्ष 2018 में हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में हिंसा और आतंक के बीच भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन जबर्दस्त रहा और बंगाल में दूसरे स्थान वाली पार्टी बनकर उभरी और पिछले वर्ष हुए लोकसभा चुनाव में तो कमाल ही हो गया। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में तो पहली बार भारतीय जनता पार्टी 18 सीटें जीत गई। ऐसे जिताने वाले नेता से भला भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व क्यों अध्यक्ष पद छीने। यही वजह है कि एक बार फिर नरेंद्र मोदी- अमित शाह की जोड़ी ने बंगाल में दिलीप घोष के प्रति भरोसा जताया है। दिलीप घोष का कार्यकाल दिसंबर 2018 में ही खत्म हो गया था। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर उनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया था और तीन दिन पहले हुए चुनाव में दिलीप घोष निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित हो गए। अब घोष वर्ष 2023 तक बंगाल भारतीय जनता पार्टी की कमान संभालेंगे। दूसरी बार अध्यक्ष बनते ही घोष ने कहा कि अगले वर्ष होने जा रहे विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को ही जीत मिलेगी। उन्होंने कहा, 'हम अब वर्ष 2021 का विधानसभा चुनाव जीतने के लिए लड़ेंगे।'

वर्ष 2018 में हुए पंचायत चुनाव में भाजपा दूसरे स्थान वाली पार्टी बनकर उभरी। पिछले वर्ष लोकसभा चुनाव में तो कमाल ही हो गया

घोष के पुनः प्रदेश अध्यक्ष निर्वाचित होने से पार्टी कार्यकर्ताओं में खुशी है। घोष अक्सर अपने विवादित बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। अध्यक्ष निर्वाचित होने से तीन दिन पहले भी अपने एक विवादास्पद बयान को लेकर वे चर्चा में थे। उनके उस बयान की निंदा प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने भी की थी। इसके बावजूद पार्टी ने उन पर भरोसा बरकरार रखते हुए उन्हें फिर से बंगाल भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित किया है। कुछ दिन पहले घोष ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों को कुत्ते की तरह गोली मारी गई। इस बयान को लेकर दिलीप घोष के खिलाफ अब तक चार एफआइआर दर्ज हो चुके हैं, बावजूद इसके वे अब तक अपने बयान पर अडिग हैं।

देशभर में असलहा लाइसेंस को अब ऑनलाइन आवदेन

वसीम अख्तर, बरेली

केंद्र सरकार ने पहली बार देशभर में पासपोर्ट की तर्ज पर असलहा लाइसेंस के लिए भी ऑनलाइन आवेदन की सुविधा दी है। इसकी बदौलत करोड़ों लोग लाइसेंस नवीनीकरण की थकाऊ और जटिल प्रक्रिया भी घर बैठे पूरा करा सकेंगे। फीस जमा करने के लिए बैंकों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। सबसे खास यह कि भ्रष्टाचार पर भी काफी हद तक अंकुश लग जाएगा। बस एक ध्यान रखना होगा, वह यह कि अपना यूनीक आइडेंटिफिकेशन नंबर किसी को नहीं बताना है, वरना आपकी अहम जानकारियां दूसरों तक पहुंच जाएंगी।

इस वेबसाइट पर होगा आवेदन : एनडीएएल-एएलआइएस.जीओवी.इन (ndal-alis.gov.in) वेबसाइट पर लाइसेंस का साफ्टवेयर अपलोड कर दिया गया है। यह शनिवार से खुलने भी लगा है। उपरोक्त वेबसाइट खुलने के बाद अप्लाई ऑनलाइन बटन पर क्लिक करना होगा। एक पेज खुलेगा, जिसमें अप्लाई हेयर पर क्लिक कर सर्वप्रथम अपनी कैटेगरी, फिर राज्य सेलेक्ट करना होगा। उदाहरण के तौर पर उत्तर प्रदेश के बाद जिला बरेली सेलेक्ट कर सकते हैं। ऐसे ही अपनी लाइसेंसी अथॉरिटी को सेलेक्ट कर सकते हैं। कौन सी सुविधा चाहिए, नया लाइसेंस, नवीनीकरण, निरस्तीकरण, लाइसेंस पर शस्त्र चढ़ाना या उसे डिलीट कराना, सीमा विस्तार, शस्त्र बेचने की अनुमति चाहिए, ये तमाम सुविधाएं घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं। फोटो के बाद हस्ताक्षर भी स्कैन करके डालने होंगे।

नवीनीकरण के लिए ऐसे करें आवेदन : शस्त्र लाइसेंस नवीनीकरण को अप्लाई करते हैं तो सर्वप्रथम अपना 18 डिजिट का यूनीक आईडेंटिफिकेशन नंबर (यूआइएन) डालना होगा। ऐसा करते ही लाइसेंस का विवरण सामने आ जाएगा। एक फाइल नंबर जेनरेट होगा। उसके बाद कोई एक पहचान-पत्र नंबर डालना होगा। एड्रेस प्रूफ के लिए आधार कार्ड, पासपोर्ट, मतदाता पहचान-पत्र, बिजली बिल आदि दे सकते हैं। फोटो और उसके बाद हस्ताक्षर भी स्कैन करके डालेंगे।

ऑनलाइन ही जमा होगी फीस : एप्लीकेशन नंबर से ही ऑनलाइन फीस जमा होगी। जैसे ही फीस के लिए अप्लाई करेंगे, लाइसेंसिंग अथॉरिटी की तरफ से ऑटोमेटिक मेल जेनरेट हो जाएगा। बताया जाएगा कि अमुक आवेदक के लाइसेंस नवीनीकरण की तिथि देय है। तभी फीस जमा होगी, वरना नहीं।

- वेबसाइट पर डाउनलोड किया गया नया सॉफ्टवेयर
- घर बैठे पूरी करा सकेंगे नवीनीकरण की जटिल प्रक्रिया

असलहा लाइसेंस के लिए तैयार की गई वेबसाइट। सौ.- एनआइसी

एक बार होगा जाना

ऑनलाइन सुविधा हो जाने से बार-बार कलक्ट्रेट के चक्कर लगाने से छुटकारा मिल जाएगा। प्रक्रिया पूरी होने के बाद महज एकबार लाइसेंस पुस्तिका लेकर जाना होगा। उस पर नवीनीकरण की पर्ची चस्पा हो जाएगी।

नए सॉफ्टवेयर ने शनिवार से काम शुरू कर दिया है। प्रक्रिया बहुत ही आसान और सुविधाजनक है। इससे देश के करोड़ों लोगों को लाभ होगा। अनावश्यक लगने वाले समय की बचत होगी।

-मनोज शर्मा, तकनीकी निदेशक, एनआइसी, बरेली

एआइ से कानूनी फैसलों को समझना होगा आसान

जागरण संवाददाता, कोलकाता

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आइआइटी) खड़गपुर के शोधकर्ताओं की टीम ने कानूनी फैसलों को आसानी से समझने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (एआइ) पर आधारित एक प्रणाली विकसित की है। आइआइटी खड़गपुर की ओर से शनिवार को जारी बयान में कहा गया कि संस्थान के कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग विभाग की शोध टीम ने दो गहरे तंत्रिका मॉडल्स विकसित किए हैं, जिनकी मदद से जटिल वाक्यों के कारण कठिन माने जाने वाले कानूनी फैसलों को पढ़ने व समझने में काफी सहूलियत होगी। शोध टीम के एक सदस्य ने कहा कि ये मॉडल्स भारत में अद्वितीय हो सकते हैं, जहां कानूनी दस्तावेज को अक्सर असंरचित तरीके से लिखा जाता है।

शोध टीम का नेतृत्व करने वाले कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर सप्तर्षि घोष ने कहा कि संस्थान के राजीव गांधी स्कूल ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ के तीन सीनियर लॉ छात्रों की मदद से हमने सुप्रीम कोर्ट के 50 निर्णयों को लेते हुए इन्हें पहले लेबलिंग वाक्यों के साथ खंडित किया है। हमने व्यापक विश्लेषण के बाद उच्च गुणवत्ता वाली इस एआइ प्रणाली को विकसित किया है। इस प्रणाली का इस्तेमाल कानून से जुड़े विभिन्न मामलों में किया जा सकता है, मसलन कानूनी निर्णय, कानूनी खोज, केस लॉ विश्लेषण व अन्य।

- आइआइटी खड़गपुर के शोधकर्ताओं ने विकसित की आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस आधारित प्रणाली
- फैसलों को आसानी से समझ पाने में मदद करेगी तकनीक

कई देशों में प्रयोग की जा रही प्रणाली: घोष ने कहा कि अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में एआइ प्रणाली का उपयोग कानूनी अनुसंधान करने, मुकदमों के दौरान दस्तावेज की समीक्षा करने आदि में पहले से किया जा रहा है।

माइनस 50 डिग्री में भी काम करेंगे रोहतांग टनल में आधुनिक उपकरण

जसवंत ठाकुर, मनाली

पीर पंजाल की पहाड़ियों में 10 हजार फीट से अधिक की ऊंचाई पर निर्माणाधीन रोहतांग टनल पर देश व दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। यह टनल हिमाचल प्रदेश में लाहुल स्पीति की हर साल पांच से छह माह घरों कैद में रहने वाली 30 हजार से ज्यादा आबादी को राहत का सूरज दिखाएगी। संभावना है कि रोहतांग टनल सितंबर 2020 में खुल जाएगी।

इन दिनों माइनस 23 डिग्री सेल्सियस वाली भीषण ठंड में सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) के इंजीनियर की देखरेख में स्ट्रॉबेग एफकॉन और समेक कंपनी के अधिकारी व कर्मचारी काम कर रहे हैं। इस टनल का इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वर्क शुरू हो चुका है। 2017 में रोहतांग टनल के दोनों छोर मिल चुके हैं। बीआरओ की मानें तो टनल में हाईटेक तकनीक से लैस उपकरणों का इस्तेमाल किया जा रहा है। यह उपकरण माइनस 50 डिग्री सेल्सियस में भी खराब नहीं होंगे। इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वर्क देख रहे लेफ्टिनेंट कर्नल परमजीत ने बताया कि टनल में हाईटेक तकनीक से लैस उपकरणों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे टनल के अंदर होने वाली छोटी से छोटी हरकत भी कंट्रोल रूम में दर्ज होगी। 8.8 किलोमीटर लंबी रोहतांग सुरंग 3500 करोड़ लागत से तैयार हो रही है। इसके बनने के बाद मनाली से लेह की दूरी 46 किलोमीटर कम हो जाएगी।

टनल की ये खूबियां

- **80** किलामीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ सकेंगे वाहन।
- **3000** तक वाहन प्रतिदिन इस टनल को पार कर सकेंगे।
- **500** मीटर की दूरी पर इमरजेंसी एक्सीट होंगे।

सोलंगनाला से धुंधी तक 13 ऐसे क्षेत्र हैं, जहां हिमखंड गिरने का खतरा बना रहता है। इसके लिए जगह-जगह साइन बोर्ड लगाए गए हैं, ताकि बर्फबारी के बीच सड़क में सफर सुरक्षित रह सके। मनाली लेह मार्ग पर अभी बरालाचा, नकीला पास, लाचुंगला व तंगलांगला में टनल बनाने पर भारत सरकार विचार कर रही है। अटल टनल के बनने से बाद इन प्रस्तावित टनल के निर्माण में सहायता मिलेगी।

-केपी पुरुसोथमन, चीफ इंजीनियर बीआरओ, रोहतांग सुरंग परियोजना

कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट : निरंतर विकास, सुधार और उपलब्धियों की गाथा

इंद्रजीत सिंह, कोलकाता

कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट (केपीटी) देश के प्रमुख बंदरगाहों में एक है। इसका इतिहास संघर्ष और सफलता की सतत कहानी है। यह सिर्फ एक पोर्ट ही नहीं है, बल्कि अखंड भारत की 150 वर्षों की यात्रा का गवाह है। इसने अखंड और विभाजित भारत के हर घटनाक्रम को देखा है। मुगल बादशाह औरंगजेब द्वारा ब्रिटिश उपनिवेशकों को पूर्वी भारत में व्यापार करने का अधिकार दिए जाने के समय से यह भारत का प्रमुख बंदरगाह रहा है। इस बंदरगाह के साथ कोलकाता शहर का पुराना संबंध है। शुरू में कोलकाता बंदरगाह की स्थापना ब्रिटिश उपनिवेशों की रक्षा और हितों को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। इस बंदरगाह ने देश के विभाजन के बाद अपनी राष्ट्रीय जिम्मेदारी संभाली। समय के साथ इस विशाल देश पर शासन करने का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकलकर ब्रिटिश शासकों के पास चला गया। 1870 में बंदरगाह आयोग की नियुक्ति के साथ कोलकाता बंदरगाह को सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत लाया गया। कोलकाता बंदरगाह किसी समय देश में सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह माना जाता था, वह पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार कहलाया। बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश सहित यह विशाल पूर्वी भारत में और हिमालय की सीमा पर स्थित नेपाल और भूटान में व्यापार-वाणिज्य के क्षेत्र में मार्गदर्शक बना रहा।

सबसे लंबा नौपरिवहन मार्ग: मेजर पोर्ट ट्रस्ट अधिनियम-1963 के लागू होने के साथ कोलकाता बंदरगाह के आयुक्तों ने जनवरी 1975 तक बंदरगाह का कार्यभार संभाला। कोलकाता बंदरगाह भारत का प्रमुख नदी बंदरगाह है। यह नदी के रेतीले तट से 232 किमी दूरी पर धारा की प्रतिकूल दिशा में स्थित है। भारत के प्रमुख बंदरगाहों के बीच यह निस्संदेह सबसे लंबा नौपरिवहन मार्ग है।

हर लक्ष्य पार करने में सक्षम रहा: 1877 में बंगाल के उपराज्यपाल ने इसे यूरोप के बाहर का सबसे अच्छा और सुविधाजनक बंदरगाहों में एक करार दिया था। यह हर निर्धारित लक्ष्य को पार करने में सक्षम रहा है और बंदरगाह संबंधी हर गतिविधि में रिकॉर्ड स्थापित करने में सफल रहा है। समुद्र से 126 मील दूर होने के बावजूद कोलकाता बंदरगाह को इस महाद्वीपीय देश में प्रवेश के पूर्वी द्वार के रूप में उत्तम विकल्प माना गया है। इसकी विशाल तटक्षेत्रीय सीमा में भारतीय राज्यों, संपूर्ण पूर्वी और उत्तर पूर्वी क्षेत्र का लगभग आधा भाग और हिमालय की सीमा से लगे दो पड़ोसी देशों नेपाल और भूटान समाहित हैं। इसके दो डॉक सिस्टम हैं-कोलकाता में तेल घाट के साथ बजबज पर कोलकाता डॉक सिस्टम और हल्दिया डॉक कांप्लेक्स।

विशेषताएं और क्षमता: केपीटी की विशेषताओं में कुशल और आर्थिक सेवा, प्रयोक्ता के अनुकूल दृष्टिकोण, सरलीकृत और एकीकृत प्रक्रियाएं, स्वचालित ऑपरेशन, न्यूनतम निरोध, तीव्र टर्न राउंड, निरंतर उत्पादकता में सुधार, पर्याप्त और सुरक्षित भंडारण, अनुकूल औद्योगिक संबंध, सामुदायिक विकास, वनरोपण, पर्यावरण उन्नयन, निरंतर विस्तार और उन्नयन, पोर्ट आधारित और पोर्ट उन्मुख उद्योगों का समर्थन, प्रोत्साहन और विकास की सुविधाएं शामिल हैं। यह सड़क, रेल और जल मार्ग से दूरदराज के इलाकों के साथ अच्छी तरह से जुड़ा है। इसके पास भावी बंदरगाह आधारित उद्योगों और बंदरगाह उपयोगकर्ताओं के लिए पर्याप्त भूमि की उपलब्धता है। जहाजों के लिए प्रभावी और सुरक्षित मार्गदर्शन के लिए वीटीएमएस के माध्यम से रडार निगरानी की स्थिति है।

बीते दिनों ऐतिहासिक कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट ने अपनी स्थापना के 150 वर्ष पूरे किए और इस अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोर्ट का नाम बदलकर डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी पर किए जाने की घोषणा की। यह सिर्फ एक पोर्ट ही नहीं है, बल्कि अखंड भारत की 150 वर्षों की यात्रा का गवाह है...

कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट पर खड़ा शिप। फाइल

हुगली नदी के बाएं किनारे पर स्थित है कोलकाता डॉक सिस्टम

कोलकाता डॉक सिस्टम हुगली नदी के बाएं किनारे पर स्थित है, जबकि हल्दिया डॉक कांप्लेक्स हुगली नदी के दाएं किनारे पर स्थित है। कोलकाता पोर्ट की संरक्षण सीमा जंगीपुर में फीडर नहर के मुहाने पर फैली है। इसमें मुहाने के दूसरी तरफ पानी के उच्च स्तर 45.7 मीटर तक हुगली नदी के किनारे भी शामिल हैं। कोलकाता पोर्ट की समुद्र से दो पहुंच हैं, एक पूर्वी मार्ग के माध्यम से और अन्य पश्चिमी मार्ग के माध्यम से। वर्तमान में पूर्वी मार्ग नेविगेशन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि कोलकाता से मार्गदर्शन दूरी 223 किमी है, जिसमें नदी की 148 किमी और समुद्र मार्गदर्शन 75 किमी है। हल्दिया से मार्गदर्शन दूरी 121 किमी है, जिसमें नदी की 46 किमी और समुद्र मार्गदर्शन की 75 किलोमीटर है। सागर में पायलट बोर्डिंग बिंदु से सैंडहेड्स तक अपनी यात्रा के लिए, सभी जहाजों को पोत यातायात प्रबंधन प्रणाली (वीटीएमएस) मार्गदर्शन के माध्यम से दूरदराज का मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है। कोलकाता पोर्ट में बंगाल, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, असम, पूर्वोत्तर राज्यों और दो घिरे पड़ोसी देशों यानी नेपाल तथा भूटान सहित पूरा पूर्वी भारत शामिल है।

3.5 अरब परमाणु बम से उत्पन्न ऊर्जा के बराबर ऊष्मा पिछले 25 वर्षों में महासागरों में मिली। यह बात एडवांसेज इन एटमॉस्फेरिक साइंसेज नामक जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन से सामने आई है। अध्ययन के मुताबिक, पानी में हर सेकंड पांच हिरोशिमा परमाणु बम गिराए जाने पर निकलने वाली ऊष्मा की समान दर से समुद्र गर्म हो रहे हैं।

चर्चित चेहरा

धौनी की धुन

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धौनी को जब बीसीसीआइ ने सालाना केंद्रीय अनुबंध से बाहर किया तो यह खबर उनके प्रशंसकों के लिए किसी झटके से कम नहीं थी। अब सबकी निगाहें इस दिग्गज खिलाड़ी के भविष्य पर हैं...

अभिषेक त्रिपाठी, नई दिल्ली

जिस दिन बीसीसीआइ नियमों की दुहाई देकर भारत को तीनों आइसीसी ट्रॉफी दिलाने (चैंपियंस ट्रॉफी, विश्व कप, टी-20 विश्व कप) वाले अपने पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धौनी को सालाना केंद्रीय अनुबंध से बाहर कर रहा था उसी दिन दुनियाभर में अपनी धाक जमा चुका रांची का राजकुमार अपने गृहनगर में छह महीने के अंतराल के बाद फिर अपने बल्ले की धार तेज कर रहा था। यह सिर्फ संयोग था या सोची-समझी रणनीति ये तो बीसीसीआइ के हुक्मरान और पूर्व भारतीय कप्तान ही बता सकते हैं, लेकिन इन दोनों के ही कदमों ने दुनियाभर के क्रिकेट प्रशंसकों के दिमाग को स्विंग कर दिया। बीसीसीआइ और धौनी के बीच चल रही रस्साकशी में कौन जीतेगा ये तो मई के दूसरे हफ्ते में पता चल जाएगा।

आप सोच रहे होंगे कि मई का दूसरा हफ्ता क्यों? क्योंकि इसी समय आइपीएल का फाइनल होगा और इसी के साथ अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया में शुरू होने वाले टी-20 विश्व कप का बिगुल बज जाएगा। आइपीएल का अंत होते-होते विश्व कप जाने वाली टी-20 टीम का अंतिम रूप तय हो जाएगा। भारतीय टीम के मुख्य कोच रवि शास्त्री कह चुके हैं कि आइपीएल के प्रदर्शन के बाद भारत की टी-20 टीम तय हो जाएगी। शायद चेन्नई सुपर किंग्स को तीन आइपीएल खिताब दिलाने वाले धौनी ने भी शास्त्री की बात को दिल से लगा लिया है और वह भी दुनिया की सबसे महंगी क्रिकेट लीग में एक बार फिर खुद को साबित करना चाहेंगे। यही कारण है कि उन्होंने पिछले साल इंग्लैंड में न्यूजीलैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में हारने के बाद तीन दिन पहले फिर से अभ्यास करना शुरू कर दिया है। अब देखना है कि भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है?

किसी को कुछ नहीं बताते धौनी: धौनी ने दिसंबर 2014 में कप्तान रहते हुए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बीच सीरीज में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया था और इस कारण विराट कोहली को कप्तान बनने का मौका मिला। 33 साल की उम्र में उन्होंने अचानक ही टेस्ट क्रिकेट छोड़ दिया था और इसके बाद से उनकी छवि यह बन गई कि वह शीर्ष पर रहते हुए ही क्रिकेट छोड़ेंगे। 2016 में उन्होंने खुद ही वनडे और टी-20 की कप्तानी छोड़ दी। पिछले साल तक उनके करीबी कहते थे कि इंग्लैंड में 2019 विश्व कप के बाद वह सीमित ओवरों के क्रिकेट से संन्यास ले लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और अब किसी को नहीं पता कि उनके दिल में क्या चल रहा है? सीएसके में उनके साथी हरभजन सिंह को भले ही यह लगता हो कि धौनी अब दोबारा नीली जर्सी नहीं पहनेंगे, लेकिन उन्हीं की टीम के अन्य साथियों को लगता है कि किसी को भी इस बात का अनुमान नहीं है कि उनके दिल में क्या चल रहा है और वह आगे क्या करेंगे? अगर उन्हें वनडे और टी-20 से संन्यास ही लेना होता तो वह विश्व कप के बाद ही कर देते, लेकिन उनके दिमाग में कुछ और चल रहा है। जब किसी ने सोचा नहीं था तब उन्होंने टेस्ट से संन्यास लिया और सीमित ओवरों के क्रिकेट की कप्तानी छोड़ी। पिछले साल विश्व कप के बाद जब सबने सोचा कि वह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लेंगे तो उन्होंने ऐसा नहीं किया। जब नियमों के कारण बीसीसीआइ को उन्हें केंद्रीय अनुबंध से बाहर करने को मजबूर होना पड़ा तो वह रांची में बल्ला थामे नजर आए। धौनी ऐसे ही हैं। अभी सिर्फ इतना कहा जा सकता है कि वह अगले सत्र में आइपीएल में खेलेंगे।

धौनी ने कहा था कि जनवरी का करें इंतजार: पिछले साल नवंबर में जब धौनी से एक कार्यक्रम के दौरान उनके भविष्य पर सवाल किया गया था तो उन्होंने कहा था कि जनवरी तक इंतजार कीजिए। 16 जनवरी को वह अभ्यास में उतरे यानी धौनी ने अपनी कैलकुलेशन पहले से ही कर रखी है कि उन्हें कब खेलना है और कब नहीं खेलना है? अब सवाल यह है कि धौनी ने अपने दिमाग में टी-20 विश्व कप में खेलने के बारे में कोई योजना बना रखी है और अगर बना रखी है तो उस योजना के बारे में किस-किस को पता है। फिलहाल उन्होंने अपने भविष्य के बारे में अभी किसी से बात नहीं की है और वह टीम इंडिया में अपने स्थान के लिए किसी के सामने सिफारिश भी नहीं करने जा रहे हैं। इस बारे में उनके एक नजदीकी का कहना है कि धौनी आइपीएल के सहारे टीम इंडिया में वापसी करना चाहते हैं और अपने प्रदर्शन से राष्ट्रीय चयनकर्ताओं को मजबूर करना चाहते हैं। अब देखते हैं कि माही ऐसा करने में सफल हो पाते हैं या नहीं?

धौनी की कप्तानी में टेस्ट में नंबर वन बना भारत

माही ने 2008 में जब भारतीय टीम की कप्तानी संभाली थी तब उनके पास कई चुनौतियां थी। भारत ने धौनी की कप्तानी में पहली बार टेस्ट में नंबर एक बनने का स्वाद चखा। दिसंबर 2014 में धौनी ने टेस्ट क्रिकेट से अचानक संन्यास की घोषणा कर दी थी। उन्होंने 2016 के आखिर में वनडे और टी-20 की कप्तानी को भी उसी अंदाज में अलविदा कहा, जिसके लिए वह जाने जाते हैं। पिछले साल विश्व कप के दौरान वह अपनी धीमी बल्लेबाजी की वजह से आलोचकों के निशाने पर रहे। वह न्यूजीलैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में रन आउट हो गए थे, जिसके बाद ही भारत की उम्मीदों पर पानी फिर गया था। इसके बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से ब्रेक लिया और टेरिटोरियल आर्मी यूनिट के साथ कश्मीर में 15 दिन बिताए। तब से वह भारतीय टीम का हिस्सा नहीं हैं।

अब तक का सफर

धौनी का जूनियर क्रिकेट से झारखंड क्रिकेट टीम और वहां से इंडिया-ए व भारतीय टीम का सफर महज पांच-छह साल में पूरा हो गया। उन्होंने 1998 में जूनियर क्रिकेट खेलना शुरू किया था और 23 दिसंबर, 2004 को उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ वनडे मैच के जरिये अंतरराष्ट्रीय करियर का आगाज किया। वह बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज में कुछ खास नहीं कर पाए, लेकिन अगली सीरीज में पाकिस्तान के खिलाफ अपने पांचवें वनडे मैच में विशाखापत्तनम में 123 गेंदों पर 148 रनों की पारी खेलकर इस खिलाड़ी ने बता दिया था कि लंबे बालों वाला लड़का बहुत लंबी दूरी तय करेगा।

उपलब्धियां

- क्रिकेट विश्व कप (2011)
- टी-20 विश्व कप (2007)
- चैंपियंस ट्रॉफी (2013)
- तीन आइपीएल (2010, 2011, 2018)
- दो चैंपियंस लीग टी-20 (2010, 2014)

वनडे में प्रदर्शन

धौनी ने भारत के लिए अब तक 350 वनडे मैचों में 50.57 की औसत से 10773 रन बनाए हैं, जिसमें 10 शतक और 73 अर्धशतक शामिल हैं। इस दौरान उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर नाबाद 183 रन रहा। वनडे में धौनी के नाम एक विकेट है और उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 14 रन देकर एक विकेट रहा है।

टेस्ट में 38.09 की औसत

धौनी ने भारत के लिए अब तक 90 टेस्ट मैचों में 38.09 की औसत से 4876 रन बनाए हैं, जिसमें छह शतक और 33 अर्धशतक शामिल हैं। इस दौरान उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 224 रन रहा है।

टी-20 में 1617 रन

धौनी ने अब तक 98 टी-20 मैचों में 37.60 की औसत से 1617 रन बनाए हैं, जिसमें दो अर्धशतक शामिल हैं। इस दौरान उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 56 रन रहा है।

पिता का सपना पूरा कर रहीं ऋचा

उभरता सितारा

अगर कुछ कर गुजरने का जुनून हो तो उम्र मायने नहीं रखती। इस बात को चरितार्थ किया है बंगाल की ऋचा घोष ने, जो महज 16 साल की उम्र में आइसीसी टी-20 विश्व कप के लिए भारत की महिला टीम में शामिल की गई हैं। जानते हैं उनके अब तक के सफर के बारे में...

गौरव मिश्र, सिलीगुड़ी

पिछले हफ्ते जब आइसीसी टी-20 विश्व कप के लिए भारत की महिला टीम की घोषणा की गई तो उसमें 16 साल की ऋचा घोष का भी नाम शामिल था, जिससे क्रिकेट जगत के लोग आश्चर्यचकित रह गए। अब यह साफ हो चुका है कि ऋचा की हम उम्र ज्यादातर लड़कियां जब फरवरी में बोर्ड परीक्षाएं दे रही होंगी तब ऋचा ऑस्ट्रेलिया में टी-20 की 'परीक्षाओं' से दो-चार हो रही होंगी।

यूं शुरू हुआ सफर: ऋचा के पिता मानवेंद्र घोष का कहना है कि बेटी में क्रिकेट का जुनून पैदा करने के लिए वह उन्हें महज तीन साल की उम्र से ही क्रिकेट मैदान ले जाने लगे थे। दरअसल, मानवेंद्र खुद क्लब स्तर तक क्रिकेट खेल चुके हैं और जब उन्हें लगा कि आगे अवसर मिलना मुमकिन नहीं है तो वह अंपायरिंग करने लगे। उसके बाद से वह अपनी बेटी को एक सफल क्रिकेटर बनाने का सपना देखने लगे। मानवेंद्र बताते हैं कि जब उन्हें लगा कि ऋचा उनके सपनों को साकार कर सकती हैं तो उन्होंने उसे कोलकाता के एक कोचिंग कैंप में दाखिल करा दिया।

पिता ने हर वक्त दिया साथ: बंगाल के सिलीगुड़ी शहर के सुभाषपल्ली निवासी मानवेंद्र घोष ने बेटी ऋचा को इस मुकाम तक पहुंचाने में काफी अहम भूमिका निभाई है। ऋचा की बड़ी बहन मीडिया साइंसेज की पढ़ाई कर रही हैं, जबकि मां का अधिकतर वक्त बीमारी की वजह से बिस्तर पर ही गुजरता है। ऐसे में पिता के लिए ऋचा के करियर को बनाने के लिए अपना वर्षों पुराना घर भी छोड़ना पड़ा। मानवेंद्र ने बताया कि अपने कारोबार को बंद कर 2016 में उन्होंने कोलकाता में ही रहने का निर्णय लिया। उन्होंने बताया कि मैं ज्यादा से ज्यादा वक्त ऋचा को देना चाहता था। ऐसे में कुछ समय तक कोई कारोबार शुरू करना ठीक नहीं रहता। दरअसल, सिलीगुड़ी से कोलकाता जाने में 12 से 14 घंटे का वक्त लगता है। ऐसे में अगर ऋचा को कोलकाता में कोई टूर्नामेंट खेलने जाना होता था तो इतनी छोटी सी बच्ची को अकेले भेजना ठीक नहीं लगता था। इसलिए मुझे तुरंत सामान पैक कर घर से निकलना पड़ता था।

11 वर्ष की उम्र में अंडर 19 बंगाल टीम में मिला मौका: ऋचा जब 11 वर्ष की थीं तभी उनका चयन अंडर 19 बंगाल टीम के लिए हुआ। उनके प्रदर्शन को देखते हुए साढ़े बारह साल की उम्र में उनका चयन अंडर 23 टीम और सीनियर टीम में हुआ। 2018 में उन्हें बंगाल की क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार भी मिला।

शुरुआत में की विकेटकीपिंग: ऋचा को शुरुआती समय से करीब 10 साल तक प्रैक्टिस कराने वाले कोच गोपाल साहा ने कहा कि उनकी शुरू से ही खेल में रुचि रही है। उन्हें बल्लेबाजी का जो भी गुर सिखाया वह उसे आत्मसात कर अमल में लाती गईं। शुरुआती दौर में वह विकेटकीपिंग करती थीं, लेकिन धीरे-धीरे वह बल्लेबाजी पर ही ध्यान केंद्रित करने लगीं। अब वह एक बेहतरीन बल्लेबाज बन चुकी हैं। बचपन के कोच प्रणव दास ने बताया कि ऋचा प्रतिदिन दो घंटे से अधिक प्रैक्टिस करती थीं। सीनियर खिलाड़ियों के खेल को बड़े ध्यान से देखती थीं।

सचिन आदर्श तो धौनी के छक्कों की प्रशंसक: ऋचा का कहना है कि उनके पहले आदर्श हमेशा उनके पिता रहे हैं, जिनसे उन्होंने क्रिकेट सीखा। इसके बाद सचिन तेंदुलकर उनके आदर्श हैं और हमेशा रहेंगे। वह उनकी तरह खेलना चाहती हैं। हालांकि, छक्के जड़ने के मामले में वह भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धौनी की प्रशंसक हैं। उनका कहना है कि धौनी जिस तरह छक्के मारते हैं वह उन्हें पसंद है और वह भी ऐसा ही करने की कोशिश करती हैं।

झूलन और ऋद्धिमान से मिलता है हौसला: ऋचा के क्रिकेट सफर में बंगाल की महिला क्रिकेट खिलाड़ी झूलन गोस्वामी और भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के खिलाड़ी ऋद्धिमान साहा का भी योगदान है। झूलन ने हमेशा उनका समर्थन किया है और जब कभी मदद की दरकार हुई ऋद्धिमान ने साथ दिया। साहा ऋचा के ही जिले के रहने वाले हैं।

ऋचा घोष फाइल फोटो

ये रहेगी प्राथमिकता

टी-20 वर्ल्ड कप में चयनित होने पर ऋचा ने कहा कि मुझे जो अवसर मिला है इसमें मैं पूरी तरह से खरी उतरने का प्रयास करूंगी। मेरी पहली प्राथमिकता बेहतर खेल का प्रदर्शन व टीम को वर्ल्ड कप दिलाना है।

शिखर पर अकेले बिहार की मिताली

इनसे मिलिए

जयशंकर बिहारी, पटना

मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं, जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। ये पंक्तियां पटना विश्वविद्यालय के राजनीतिशास्त्र विभाग की छात्रा मिताली प्रसाद पर सटीक बैठती हैं, जिन्होंने बीते दिनों एशिया के बाहर सबसे ऊंची चोटी माउंट अकोंकागुआ (6962 मीटर) को फतह किया। शिखर तक पहुंचने के सफर में सबसे अहम बात यह रही कि उन्होंने बगैर किसी गाइड और पोर्टर के माउंट अकोंकागुआ को फतह किया और एशिया के बाहर की इस सबसे ऊंची चोटी पर अकेले पहुंचने वाली वह पहली भारतीय महिला बनीं। उनका यहां तक का सफर बिल्कुल भी आसान नहीं रहा। कमजोर आर्थिक स्थिति से गुजर रहे परिवार में जन्मी मिताली के लिए संसाधनों को जुटाना शिखर फतह करने से भी ज्यादा कठिन रहा। हालांकि, इन संघर्षों ने उनके इरादों को और मजबूत किया।

गत 13 जनवरी की रात 12:45 बजे दक्षिण अमेरिका की माउंट अकोंकागुआ की चोटी पर तिरंगा फहराने वाली मिताली पिछले साल अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो (तंजानिया) को भी फतह कर चुकी हैं। उनका लक्ष्य सातों महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों को फतह करना है, जिसके सफर पर वह निकली हैं।

मिताली ने चार जनवरी को माउंट अकोंकागुआ की चढ़ाई प्रारंभ की थी। मौसम खराब होने के कारण अतिरिक्त पांच दिन लगे। इस वजह से राशन की कमी भी आड़े आई। 90 से 100 किलोमीटर की रफ्तार वाली हवा और मानइस 30 डिग्री सेल्सियस के बीच चढ़ाई बिल्कुल भी आसान नहीं थी, लेकिन मिताली शिखर को फतह कर के ही मानीं। मिताली ने बगैर गाइड और पोर्टर चढ़ाई की। राशन भी खुद ही उठाया। रास्ते में खाना भी बनाया। रोडमैप और प्लानिंग भी खुद ही की। सामान्य तौर पर पर्वतारोही ग्रुप में चढ़ाई करते हैं। गाइड और पोर्टर के बिना चढ़ाई काफी जोखिम भरी होती है।

खुशी से ज्यादा कर्ज उतारने की चिंता: इस मिशन के लिए मिताली गत 17 दिसंबर को पटना से रवाना हुई थीं। उन्होंने बताया कि राज्य के खेलकूद में पर्वतारोहण शामिल नहीं होने के कारण सहायता नहीं मिल पाती। कुछ मददगार हैं, जो हौसला टूटने नहीं देते हैं। कराटे में ब्लैक बेल्ट मिताली नालंदा जिले के कतरीसराय प्रखंड के मायापुर गांव की हैं। वह पटना के बहादुरपुर में परिवार के साथ रहती हैं। मां चंचला देवी सर्जिकल बेल्ट बनाती हैं। पिता मणीन्द्र प्रसाद किसान हैं। परिजनों का कहना है कि चोटी फतह करने की अपार खुशी है, लेकिन बेटी कर्ज के पैसे से दक्षिण अमेरिका गई है। अब उसे उतारने की चिंता है।

चंदे में कोई 10 रुपये देता तो भर आतीं आंखें: मिताली कहती हैं, 'किलिमंजारो और अकोंकागुआ फतह करने से ज्यादा समय विभाग में प्रोत्साहन राशि के लिए दौड़ने में लगा। पैसा तो नहीं मिल सका, लेकिन तिरस्कार ने सपने को जिद में बदलने का हौसला पैदा कर दिया। साथियों की सलाह पर सर्टिफिकेट दिखाकर चंदा मांगती थी। लाखों रुपये सैलरी पाने वाले जब 10 रुपये चंदा देते थे तो घर पर आकर खूब रोती थी। हालांकि, कुछ सपोर्ट करने वालों ने हौसला टूटने नहीं दिया। किलिमंजारो फतह करने के बाद सपोर्ट करने वालों की संख्या बढ़ी है। अब माउंट एवरेस्ट की बारी है।'

मां का संघर्ष चोटी फतह करने से भी बड़ा: आर्थिक तंगी से निकलने के लिए मिताली की मां चंचला देवी ने खादी ग्रामोद्योग से ट्रेनिंग ली और 2008 में परिवार के सभी सदस्यों को लेकर पटना आ गईं। तीन बेटियों की पढ़ाई और सभी खर्चे उन्होंने ही 12 से 18 घंटे काम कर पूरे किए। चंचला देवी बताती हैं कि बड़ी बेटी ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन (अहमदाबाद) से टेक्सटाइल डिजाइनिंग में कोर्स किया है। अभी सिलवासा में नौकरी करती है। छोटी बेटी मीनल 12वीं में पढ़ती है।

पर्वतारोहण के सभी कोर्स में उत्तीर्ण: मिताली ने बताया कि उनके गांव से राजगीर के पहाड़ नजदीक हैं। पहाड़ पर चढ़ाई बचपन का सपना है, लेकिन घर की आर्थिक स्थिति इतना ज्यादा सोचने की इजाजत नहीं देती थी। पटना आने पर एनसीसी से जुड़ीं। 'सी' सर्टिफिकेट प्राप्त किया। पर्वतारोहण की परीक्षा में बेहतर करने पर एनसीसी की ओर से पैरा जंपिंग टीम में चयन हुआ। पर्वतारोहण के बेसिक, एडवांस, मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन के साथ-साथ अल्पाइन कोर्स भी किया। अल्पाइन कोर्स में तंबू के साथ विद्यार्थी किसी चोटी पर कई दिनों के लिए अकेले छोड़ दिया जाता है।

गत 13 जनवरी को माउंट अकोंकागुआ पर तिरंगा फहरातीं मिताली प्रसाद। फाइल

परिस्थितियां भले ही विपरीत हों, लेकिन मजबूत हौसलों से बड़े से बड़ा पहाड़ फतह किया जा सकता है। कुछ ऐसा ही कर दिखाया है बिहार की मिताली प्रसाद ने, जिन्होंने बगैर किसी गाइड और पोर्टर के माउंट अकोंकागुआ को फतह किया और एशिया के बाहर की इस सबसे ऊंची चोटी पर अकेले पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनीं...

नौकरियों में आ रहा बदलाव

फ्रीलांस लेंगे पूर्णकालिक कर्मियों का स्थान

हम नए साल के बाद नए दशक में प्रवेश करने जा रहे हैं। ऐसा महसूस होता है कि हमारे चारों ओर सबकुछ बदल रहा है। काम की दुनिया भी इसका अपवाद नहीं है। भविष्य की नौकरियों में आमूलचूल बदलाव आने वाला है। नए साल में बहुत कुछ बदला है, लेकिन अगले दशक में नौकरियों में आने वाला बदलाव सदियों तक याद किया जाएगा। वैश्विक स्तर पर रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस जैसे क्षेत्र प्रवाह को बदलने की क्षमता रखते हैं। जर्मनी में 18 फीसद नौकरियां स्वचालन के अंतिम जोखिम पर काम कर रही हैं। भविष्य में होने वाले हमारे कार्यस्थल फिलहाल बदलाव के दौर से गुजर रहे हैं। हाल ही में स्टेटिस्टा ट्रेंड कंपास ने पाया है कि 79 फीसद अधिकारी मानते हैं कि फ्रीलांस कर्मचारी अगले कुछ सालों में पूर्णकालिक कर्मचारियों का स्थान ले लेंगे।

फ्रीलांस वर्क के फायदे

- **84 %** योजना में लचीलापन
- **39 %** स्व विकास
- **60 %** रूपांतरित नहीं होना
- **66 %** कार्य-जीवन संतुलन
- **61 %** कहीं से भी काम करने की स्वतंत्रता
- **39 %** स्व विकास

सहकर्मी रोबोट

स्वचालन और ऐसे ही बड़े ट्रेंड जैसे रोबोट्स और आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस कार्य की दुनिया में नई उन्नति और नई उपलब्धियां हैं।

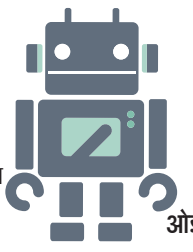

लचीलापन

- नौकरी का तरीका बदला
- पार्ट टाइम कहीं से भी काम का विकल्प
- निश्चित समय कार्य
- पूर्ण कालिक कहीं से भी काम का विकल्प

2016 से 78 फीसद पदों में बढोतरी जिनमें कार्यस्थल में लचीलापन था।

37% कर्मचारी ऐसी नौकरी करना चाहते हैं जहां पर उन्हें अपनी नौकरी में अन्य जगह से काम की अनुमति दी जाए।

2019 में वैश्विक स्तर पर 75 फीसद लोगों का विश्वास है कि नए नियमों में लचीलापन आएगा। यह जापान में 80 फीसद और जर्मनी में 68 फीसद है।

नौकरियों की तुलना जहां स्वचालन में है उच्च जोखिम

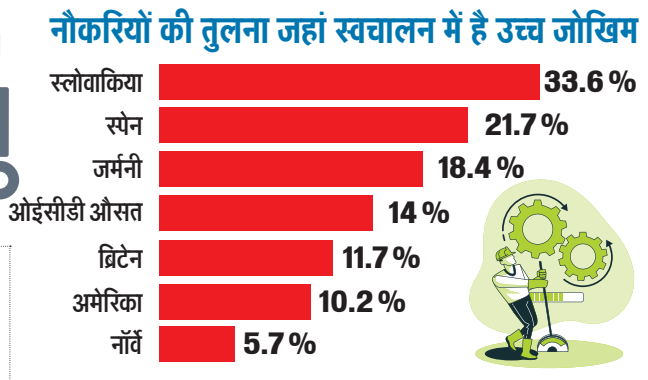

79% अधिकारी मानते हैं कि आकस्मिक और फ्रीलांस कर्मचारी अगले कुछ वर्षों में पूर्ण कालिक कर्मचारियों का स्थान लें लेंगे।

92% फ्रीलांसर कर्मचारियों का कहना है कि फ्रीलांस जीवनशैली अत्यंत (55%) या कुछ हद तक (37%) महत्वपूर्ण है।

एचडीएफसी बैंक का मुनाफा 33 फीसद बढ़ा

नई दिल्ली : निजी क्षेत्र के एचडीएफसी बैंक को चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में जबर्दस्त मुनाफा हुआ है। अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में बैंक को 7,416 .5 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ। पिछले वित्त वर्ष की समीक्षाधीन अवधि के मुकाबले मुनाफे में 32 .8 फीसद की वृद्धि हुई है। सालभर पहले कंपनी का मुनाफा 5,585 .9 करोड़ रुपये रहा था। बैंक ने बताया, 'बीती तिमाही में ब्याज से बैंक की शुद्ध आय सालभर पहले के 12,576 .8 करोड़ रुपये से बढ़कर 14,172 .9 करोड़ रुपये हो गई। (प्रेट्र)

अगले पांच वर्षों में पांच लाख करोड़ डॉलर की इकोनॉमी का लक्ष्य मुश्किल जरूर है, मगर असंभव कतई नहीं है।
— नितिन गडकरी
सड़क परिवहन मंत्री

इन्फ्रा-ऑटो को इन्सेंटिव, स्टील को टैक्स में राहत संभव

बजट से उम्मीदें

- रेलवे, सड़क, शिपिंग व हाउसिंग सेक्टर में स्फूर्ति पर टिकी है स्टील की मांग
- कोकिंग कोल के आयात पर सीमा शुल्क में कमी की है उम्मीद

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

अगले वित्त वर्ष के लिए पहली फरवरी को प्रस्तावित आम बजट से ऑटोमोबाइल सेक्टर और इन्फ्रास्ट्रक्चर के साथ-साथ स्टील सेक्टर को भी नई ऊर्जा मिल सकती है। पिछले पांच वर्षों से स्टील सेक्टर सुस्त विकास दर का सामना कर रहा है। इस सुस्ती को दूर करने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कोकिंग कोल और पेट कोल के आयात पर शुल्क दरों में कटौती का एलान कर सकती हैं।

स्टील सेक्टर बड़ी बेसब्री से पहली फरवरी का इंतजार कर रहा है। जब वित्त मंत्री सीतारमण संसद में वर्ष 2020-21 का बजट पेश करेंगी। स्टील सेक्टर को उम्मीद है कि वित्त मंत्री इन्फ्रास्ट्रक्चर और ऑटोमोबाइल सेक्टर में जान फूंकने के लिए कुछ बड़े कदमों का एलान करेंगी जिनसे अर्थव्यवस्था के साथ-साथ स्टील सेक्टर की सुस्ती दूर करने में भी सहायता मिलेगी।

स्टील कंपनियों के मुताबिक अक्टूबर, 2019 में स्टील की मांग न्यूनतम स्तर पर पहुंचने के बाद अभी कुछ सुधार अवश्य दिखाई दे रहा है। लेकिन यह स्थिति बरकरार रहेगी, इसमें संदेह है। इसलिए सरकार को ऑटोमोबाइल उद्योग को वित्तीय प्रोत्साहन देने के साथ इन्फ्रास्ट्रक्चर, खासकर रेल, सड़क, बिजली और हाउसिंग सेक्टर में निवेश बढ़ाने के उपाय करने होंगे। यह शुभ संकेत है कि सरकार रेलवे में नई लाइनों, दोहरीकरण, विद्युतीकरण, सिग्नलिंग के अलावा कोच एवं वैगन उत्पादन तथा स्टेशनों के विकास से जुड़ी परियोजनाओं पर निवेश बढ़ाने के लिए लगातार कदम उठा रही है। साथ ही सड़क निर्माण में भारतमाला जैसी महा-योजना पर तेजी से काम के लिए प्रयास हो रहे हैं। स्टील की मांग बढ़ाने में शिपिंग तथा राष्ट्रीय जलमार्ग सेक्टर की भी महत्वपूर्ण भूमिका है और सरकार इन क्षेत्रों का भी विस्तार कर रही है। इसके लिए सागरमाला और जलमार्ग विकास परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। बजट में इन सभी के लिए के लिए आबंटन बढ़ने तथा निजी और पीपीपी परियोजनाओं को प्रोत्साहन देने के उपाय संभावित हैं।

स्टील सेक्टर की एक बड़ी समस्या ईंधन व कच्चे माल की बढ़ती कीमतें हैं। इनका संबंध मुख्यतया अच्छी गुणवत्ता वाले कोयले से है, जिनका आयात करना पड़ता है। महंगे कोयले के आयात से निजात दिलाने के लिए सरकार ने हाल ही में कोयला क्षेत्र को निजी निवेश के लिए पूरी तरह खोलने फैसला किया है। लेकिन कोकिंग कोल के आयात पर निर्भरता जारी रहने की संभावना है। इसलिए उद्योग ने इस पर आयात शुल्क घटाए जाने की मांग की है। माना जाता है कि बजट में वित्त मंत्री इस पर अवश्य विचार करेंगी।

पिछले चार वर्षों से देश के रियल एस्टेट और ऑटो सेक्टर दोनो को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। वाहनों की बिक्री न्यूनतम स्तर पर पहुंच चुकी है और बिक्री में मामूली सुधार के अलावा इससे उबरने का कोई रास्ता नहीं दिखाई देता। स्टील उद्योग वाहनों की बिक्री बढ़ने का इंतजार कर रहा है। रियल्टी और हाउसिंग सेक्टर को उबारने के लिए सरकार ने कुछ समय पहले पैकेज का एलान किया था। लेकिन उसका सीमित लाभ हुआ है। इसलिए इस सेक्टर को भी बजट से कर राहत की उम्मीदें हैं। स्टील सेक्टर को बूस्टर खुराक मिलना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि भारत में प्रति व्यक्ति स्टील की खपत अब भी मात्र 65 किलोग्राम है। जबकि चीन में यह 400 किलोग्राम है।

स्टार्ट-अप की भरमार इन्हें फंड की दरकार

- राज्य सरकार को केंद्र से नहीं मिलता कोई फंड
- राज्य बजट से अभी तक 22 स्टार्ट-अप को ही सीड मनी
- झारखंड इनोवेशन लैब में उपकरण नहीं, सभी जिलों में लैब नहीं

राज्य ब्यूरो, रांची

झारखंड के युवाओं में आइडिया की कमी नहीं है। अपने आइडिया को धरातल पर उतारने के लिए युवा लगातार प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इसमें फंड की कमी बाधक बन रही है। कई स्टार्ट-अप पूंजी के अभाव में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। राज्य सरकार ने स्टार्ट-अप को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2016 में ही झारखंड स्टार्ट-अप पॉलिसी लागू की है। इस पॉलिसी के तहत चयनित स्टार्ट-अप को दस लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता राशि देने का प्रावधान है। लेकिन स्थिति यह है कि अभी तक महज 22 स्टार्ट-अप को ही प्रोटोटाइप फंडिंग हो सकी है। इन सभी को अभी तक महज 32.10 लाख रुपये ही उपलब्ध हो सके हैं। स्टार्ट-अप कल्चर को बढ़ावा देने के लिए राशि का प्रावधान राज्य बजट से किया जाता है, जो काफी कम होता है। दूसरी तरफ, राज्य स्तर पर स्थापित इनोवेशन लैब में आवश्यक उपकरण उपलब्ध नहीं हैं। सभी जिलों में लैब की सुविधा भी नहीं है। स्टार्ट-अप इंडिया कार्यक्रम की जिम्मेदारी संभाल रहे और राज्य सरकार के सूचना, तकनीक व ई-गवर्नेंस विभाग के पदाधिकारी डीएस वर्मा के अनुसार स्टार्ट-अप इंडिया कार्यक्रम के तहत राज्य को केंद्र से कोई अनुदान नहीं मिलता है। केंद्र से इसके लिए राशि मिलने से न केवल राज्य सरकार के बजट पर बोझ कम पड़ेगा, बल्कि स्टार्ट-अप इंडिया का उद्देश्य भी पूरा होगा। इसके लिए केंद्रीय बजट में राशि का प्रावधान किया जाना चाहिए।

आइआइएम, अहमदाबाद करता है स्क्रीनिंग

राज्य में स्टार्ट-अप की स्क्रीनिंग झारखंड इनोवेशन लैब करती है, जिसके संचालन की जिम्मेदारी आइआइएम, अहमदाबाद को दी गई है। झारखंड में स्टार्ट-अप के लिए कुल 317 आवेदन आए थे। आइआइएम, अहमदाबाद द्वारा इनमें से 95 की स्क्रीनिंग की गई, जिनका निबंधन हुआ। इनमें से 22 स्टार्टअप का चयन आर्थिक सहयोग देने के लिए हुआ। बताते चलें कि स्टार्टअप को आर्थिक सहयोग देने के लिए स्टेट इवेल्यूशन बोर्ड गठित है, जो आइआइएम, अहमदाबाद द्वारा चयनित स्टार्टअप का प्रजेंटेशन देकर आर्थिक सहयोग देने की अनुशंसा राज्य सरकार से करती है। चयनित स्टार्ट-अप को तीन चरणों में राशि देने का प्रावधान है, लेकिन चयनित 22 स्टार्ट-अप दूसरे फेज की राशि नहीं ले सके है। झारखंड स्टार्ट-अप पॉलिसी में स्टार्ट-अप की मार्केटिंग करने के लिए भी 10 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता के प्रावधान किए गए हैं, लेकिन किसी भी स्टार्ट-अप को यह राशि नहीं मिल पाई है। चयनित 22 में तीन स्टार्ट-अप ने अपनी अच्छी पहचान बनाई है।

झारखंड के शिल्प को बाजार उपलब्ध कराने वाले स्टार्ट अप 'शिल्पकारी' के लिए युवा अतुल को फंड की दरकार है। बताते हैं कि वे इसके लिए कई बार सरकार से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन उन्हें हर बार आश्वासन ही मिला है।

केंद्र सरकार स्टार्ट-अप को बढ़ावा देने के लिए कोई राशि नहीं देती। अलबत्ता जो स्टार्ट-अप सीधे केंद्र से रजिस्टर होते हैं, उन्हें फंड मिलता है। केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में इसके संचालन की जरूरत है, ताकि राज्य सरकार को 50-60 फीसद राशि मिल सके। इससे कई लैब भी स्थापित किए जा सकते हैं।
उमेश शाह, पूर्व निदेशक, सूचना तकनीक

झारखंड में प्रतिभा की कमी नहीं है। कई युवा अपने आइडिया को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन उन्हें आर्थिक सहायता उपलब्ध नहीं हो पाती। जागरूकता की भी कमी है। जरूरत बैंकों से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने तथा सिंगल विंडो सिस्टम लागू करने की है।
कुणाल अजमानी, प्रेसिडेंट, झारखंड चैंबर ऑफ कामर्स

तेल आयात पर रूस से बड़े समझौते की तैयारी

निगाहें ▶ बदले समीकरण में अन्य देशों से तेल खरीदने की रणनीति

अमेरिका की तरह रूस भी होगा भारत का बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

भारत अपनी जरूरत का तकरीबन 60 प्रतिशत तेल खाड़ी के देशों से आयात करता रहा है। लेकिन इस क्षेत्र के हालात रह-रह कर जिस तरह अनिश्चित हो जाते हैं, उसे देखते हुए भारत अब तेल के दूसरे विश्वसनीय स्रोतों की तलाश करने लगा है। बहुत संभव है कि जिस तरह से अमेरिका पिछले तीन वर्षों के भीतर भारत को क्रूड ऑयल (कच्चे तेल) की आपूर्ति करने वाला एक बड़ा देश बन गया है, उसी तरह से अगले दो-तीन वर्षों में रूस भी भारत के लिए एक विश्वसनीय तेल आपूर्तिकर्ता देश बन जाएगा। दोनो देशों के बीच इस बारे में बातचीत विशिष्ट दौर में पहुंच चुकी है। पिछले हफ्ते दोनो देशों के विदेश मंत्रियों के बीच हुई वार्ता में भी ऊर्जा सुरक्षा का मुद्दा बहुत अहम रहा। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने हाल ही में कहा भी था कि रूस भारत का एक बड़ा तेल साझेदार देश हो सकता है।

सूत्रों के मुताबिक भारत की फिलहाल सबसे बड़ी चिंता कच्चे तेल की आपूर्ति को सुरक्षित बनाने की है। जब से अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ा है तब से भारत को वैकल्पिक स्रोतों की जरूरत ज्यादा महसूस होने लगी है। यह भी महत्वपूर्ण तथ्य है कि रूस के पास कच्चे तेल का बड़ा भंडार है जिसके लिए उसे भारत जैसे बड़े खरीदार की जरूरत है। रूस व भारत के बीच क्रूड कारोबार को बढ़ाने को लेकर पिछले वर्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूस दौरे के दौरान भी चर्चा हुई थी। उस यात्रा के दौरान दोनो देशों के बीच एनर्जी सेक्टर को लेकर तीन बड़े समझौते हुए थे। इसमें दो समझौते गैस सेक्टर को लेकर थे, जबकि एक समझौता कोयला को लेकर था।

अभी भारत बहुत ही कम तेल का आयात रूस से करता है। जबकि रूस के सखालीन के एक तेल फील्ड में ओएनजीसी विदेश की हिस्सेदारी भी है। इसके पीछे बड़ी वजह रूस से कच्चे तेल के परिवहन की लागत है। इस लागत को कम करने के लिए ही रूस के शहर व्लादिवोस्तोक से भारत के चेन्नई पोर्ट तक समुद्री मार्ग विकसित करने पर बात हो रही है। इस मार्ग का इस्तेमाल क्रूड के साथ ही एलएनजी आयात के लिए भी हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक अगर दोनो देशों के बीच तेल कारोबार शुरू हो जाता है तो वर्ष 2025 तक 30 अरब डॉलर के द्विपक्षीय कारोबार के लक्ष्य को आसानी से पूरा किया जा सकेगा। अभी भारत व रूस में 11 अरब डॉलर का द्विपक्षीय कारोबार होता है।

भारत अभी अपनी जरूरत का 82-83 फीसद कच्चा तेल आयात करता है। भारत ईरान से तेल खरीदना पूरी तरह बंद कर चुका है जबकि ईरान तीसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता देश है। भारत अभी सबसे ज्यादा तेल इराक से खरीदता है, लेकिन वहां की स्थिति भी बहुत उत्साहजनक नहीं है। अगर अमेरिका इराक पर भी प्रतिबंध लगाता है भारत के लिए समस्या बढ़ जाएगी। इस नए माहौल में ही भारत ने अमेरिका से क्रूड खरीद काफी बढ़ा दी है।

यह सदी भारत की, आर्थिक महाशक्ति बनना तय

- गडकरी बोले - इकोनॉमी का नया लक्ष्य मुश्किल, लेकिन असंभव नहीं
- कहा - राष्ट्रीय राजमार्गों पर खोलेंगे एक हजार से ज्यादा पेट्रोल पंप

इंदौर, नईदुनिया

केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि 21वीं सदी भारत की है और हम आर्थिक महाशक्ति बनेंगे। हमारी अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है। गडकरी शनिवार को इंदौर मैनेजमेंट एसोसिएशन (आइएमए) द्वारा आयोजित कार्यक्रम में गडकरी का कहना था कि ग्लोबल इकानॉमी, मांग और आपूर्ति जैसी चुनौतियां आती रहेंगी। लेकिन भारत चुनौतियों और परेशानियों को मौकों में बदलने में माहिर है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि अगले पांच वर्षों में पांच लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य कठिन भले हो, लेकिन असंभव बिल्कुल नहीं है।

गडकरी ने कहा कि नेतृत्व में टीम वर्क होना चाहिए। योग्यता, गुणवत्ता पर एकाधिकार नहीं होता है। यदि विफल हो जाएं तो खुद पर नाराज नहीं होना चाहिए। विफलता से ही अनुभव मिलते हैं। ड्राइवरलेस कार के कयासों पर केंद्रीय मंत्री ने फिर कहा कि जब तक मैं मंत्री हूं, ड्रायवरलेस (चालक रहित) कार भारत में नहीं आएगी। मैं तकनीक का विरोधी नहीं हूं, लेकिन मेरे देश में 22 लाख ड्रायवरों के जरिये एक करोड़ लोगों को रोजगार मिलता है। रोजगार देना भी हमारी जिम्मेदारी है।

16 हजार करोड़ रुपये बचाए

गडकरी का कहना था कि सरकार ने

प्रतीकात्मक

दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में अलवर, सवाई माधोपुर, झाबुआ, रतलाम जैसे आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों को जोड़कर 16 हजार करोड़ रुपये भूमि अधिग्रहण में बचाए हैं। यह कॉरिडोर अहमदाबाद, सूरत जैसे क्षेत्रों से निकाले जाते, तो अधिग्रहण के लिए छह करोड़ रुपए प्रति हेक्टेयर खर्च होता, लेकिन हमने ऐसे क्षेत्र चुने जहां लागत 80 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर आ रही है। इस कॉरिडोर के बनने के बाद दिल्ली से मुंबई के बीच की दूरी 210 किलोमीटर कम हो जाएगी और 12 लेन होने के कारण समय भी कम लगेगा। एनएचएआइ अब जल्दी ही राष्ट्रीय राजमार्गों पर एक हजार से ज्यादा पेट्रोल पंप भी खोलेगा।

भूली-बिसरी 'जायद' फिर होगी जिंदा

नई पहल

- रबी और खरीफ के बीच भी लहलहाएगी जायद
- इस अवधि में सूखी पड़ी 70 फीसद खेतों के उपयोग की तैयारी

सुरेंद्र प्रसाद सिंह, नई दिल्ली

जायद क्या होती है, इसका जवाब बहुत थोड़े लोगों को पता होगा। सच्चाई तो यह है कि कृषि प्रधान देश होने के बावजूद यहां सरकारों ने भी सिर्फ रबी और खरीफ फसलों को याद रखा, जायद को भुला दिया। जायद यानी खरीफ और रबी सीजन के बीच की फसलें जो न तो अधिक पानी मांगती है न खाद, फिर भी लहलहाती हैं। अफसोस कि देश की लगभग 70 फीसद खेत इस दौरान खाली पड़े रहते हैं। बिहार और पश्चिम बंगाल में धान की खेती के बाद तकरीबन 10 लाख हेक्टेयर खेत परती पड़े रहते हैं। न तो किसान जागते हैं और न ही सरकार। किसानों और देश के लिए सुखद यह है कि अब सरकार भी जागी है और किसानों को जगाने का फैसला किया गया है।

पहली बार जायद सीजन की फसलों की तैयारी के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें सभी राज्यों के कृषि सचिवों और अन्य प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। किसानों को जानकारी से लेकर बीज तक उपलब्ध कराए जाएंगे। जाहिर तौर पर 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने में भी इसका बड़ा हाथ होगा।

जायद फसलों में तेज गरमी और शुष्क हवाओं को सहने की अच्छी क्षमता होती है। इसकी वजह यह है कि इस सीजन में बारिश की संभावना नहीं के बराबर रहती है, जबकि गरमी की शुरुआत हो जाती है। ऐसे मौसम में उत्तरी राज्यों में तरबूज, खरबूजा, खीरा, ककड़ी, तोरी, भिंडी, टिंडा और करेला की खेती होती है। इनके अलावा दलहन और तिलहन की फसलें भी होती हैं, जिनमें मूंग और उड़द के साथ तिलहनी सूरजमुखी प्रमुख हैं।

केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सम्मेलन के मौके पर सभी राज्यों के प्रतिनिधियों से इस अवसर का लाभ उठाने की अपील की। उन्होंने कहा कि कुपोषण दूर करने के लिए जायद की फसलें सबसे मुफीद साबित हो सकती हैं। इनमें सब्जियां और फल शामिल हैं। कृषि मंत्रालय की योजना के मुताबिक जायद की फसलों के लिए उपयुक्त बीजों की आपूर्ति सबसे बड़ी चुनौती है, जिससे निपटने की तैयारियां पहले से ही कर ली गई हैं। इच्छुक किसानों को राज्यों में सरकार बीजों के पैकेट प्रदान करेगी। केंद्र की राजग सरकार ने जायद सीजन की फसलों पर फोकस किया है। इसके लिए सीजन की फसलों के बीजों की आपूर्ति हर राज्य की जरूरत के हिसाब से की जाएगी, जिसकी जानकारी राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान प्राप्त की गई।पीएम-किसान योजना के तहत साल के तीनों सीजन से पहले दो-दो हजार रुपये की किस्तें किसानों के खाते में जमा कराती है। इस बार जायद सीजन के ठीक पहले योजना की किस्त किसानों के बैंक खाते में पहुंच जाएगी।

हरित क्रांति के बाद से स्थितियां बदलीं तो सारा ध्यान खाद्यान्न पर टिक गया। बाकी फसलें तिलहन, दलहन और बागवानी हाशिये पर चली गईं। इसी मौसमी असंतुलन के चलते कुपोषण की समस्या भी गंभीर हो गई, जिससे उबरने के लिए परंपरागत खेती को आगे बढ़ाने की कोशिशें की जा रही हैं।

रोजगार के अवसर बढ़ाने पर होगा बजट में खास जोर

बजट पूर्वावलोकन : 2020-21

- कृषि, एमएसएमई और इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रों को मिल सकती हैं सुविधाएं व रियायतें
- मनरेगा का विस्तार व देसी किराना स्टोरों व टेक्सटाइल उद्योगों को राहत संभव

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

आगामी बजट में सरकार का जोर आर्थिक सुस्ती दूर करने के साथ रोजगार के अवसर बढ़ाने पर रहेगा। इसके लिए वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण कृषि और बुनियादी ढांचा क्षेत्र के साथ सूक्ष्म एवं मध्यम उद्योग क्षेत्र के लिए विशिष्ट उपायों का एलान कर सकती हैं। आर्थिक सुस्ती के चलते रोजगार की स्थिति और बिगड़ गई है। स्किल इंडिया, स्टार्ट-अप, मेक इन इंडिया जैसे मिशनों ने कुछ हद तक रोजगार सृजन का काम किया है। लेकिन आर्थिक सुस्ती ने इन मिशनों के प्रभाव को सीमित कर दिया है। जबकि स्वरूप में बदलाव ने मनरेगा जैसी रोजगारमूलक स्कीम को संपत्ति सृजन वाली स्कीम बना दिया है। इसमें सुधार के लिए बजट में मनरेगा को लेकर कुछ एलान संभव हैं।

कृषि और कृषि से जुड़े उद्योगों में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए विशिष्ट उपायों की घोषणा भी की जा सकती है। पिछले पांच

प्रतीकात्मक

वर्षों में ग्रामीण मजदूरी की दर में 0.6 फीसद की औसत वृद्धि हुई है। ग्रामीण आमदनी में बढ़ोतरी से गांवों में औद्योगिक सामानों की खपत भी बढ़ेगी। जिससे घटती मांग का संकट दूर होगा और अर्थव्यस्था की हालत सुधरेगी। भारत नेट और मोबाइल नेटवर्क के विस्तार से डिजिटल ढांचे तथा पोस्ट पेमेंट बैंक ढांचे से वित्तीय गतिविधियों के विस्तार के चलते गांवों में रोजगार के नए अवसर सृजित होने की संभावना है। बजट में इन योजनाओं में तेजी लाने के कुछ नए उपाय घोषित किए जा सकते हैं।

शहरी क्षेत्रों में रोजगार बढ़ाने के लिए सरकार का फोकस सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों तथा सेवा क्षेत्र से जुड़ी गतिविधियों में जान फूंकने पर होगा। इसके लिए इस क्षेत्र को आसान कर्ज के साथ करों में और राहत की घोषणाएं हो सकती है। रिटेल क्षेत्र में विदेशी निवेश तथा ई-कॉमर्स वाले ऑनलाइन बिक्री चैनलों के कारण परंपरागत देसी किराना दुकानदारों को काफी नुकसान उठाना पड़ा है। इससे उबरने के लिए देश के सवा करोड़ देसी किराना स्टोर बजट से राहत की उम्मीद कर रहे हैं। इन्हें डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने तथा ऑनलाइन कंपनियों के साथ साझेदारी के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सरकार कोई बड़ी स्कीम ला सकती है। इससे शहरी युवाओं को रोजगार का नया और बड़ा प्लेटफॉर्म मिलने की आशा है। टेक्सटाइल तथा जेम्स व ज्वैलरी सेक्टर भी रोजगार के बड़े माध्यम हैं। इसमें अकेले टेक्सटाइल सेक्टर 10 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार देता है। परंतु वियतनाम व बांग्लादेश में सस्ते उत्पादन ने टेक्सटाइल निर्यात के लिए नई चुनौती खड़ी कर दी है। इस मुश्किल से बचाने के लिए सरकार टेक्सटाइल उत्पादकों को ड्यूटी में छूट दे सकती है।

भारत की जीडीपी में जेम्स एंड ज्वैलरी सेक्टर की सात फीसद हिस्सेदारी है। जबकि मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट में इस क्षेत्र का 15 फीसद योगदान है। इसलिए सरकार इन क्षेत्रों की मदद के लिए सोने पर आयात शुल्क घटाने के साथ-साथ नई स्वर्ण मौद्रीकरण योजना का एलान भी कर सकती है।

पढ़े-लिखे व दक्ष लोगों के साथ-साथ अकुशल और अर्द्धकुशल लोगों को रोजगार देने में इन्फ्रास्ट्रक्चर सेक्टर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए सरकार बजट के जरिये सड़कों, रेलवे लाइनों, छोटे हवाई अड्डों तथा बंदरगाहों के निर्माण में तेजी लाने का प्रयास भी करेगी। इसके लिए भारतमाला, सागरमाला परियोजनाओं का बजट बढ़ाने के साथ-साथ पूंजीगत सामानों के उत्पादन और आयात को आसान बनाने के उपक्रम होंगे। विद्युतीकरण और सिग्नल प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए रेलवे का बजट बढ़ना तय माना जा रहा है। रोजगार बढ़ाने के लिए श्रम कानूनों में संशोधन की प्रक्रिया जारी है।

भविष्य के बारे में सही अनुमान लगाना मुश्किल, मगर असंभव नहीं

कुछ समय पहले मुझे निवेश के बारे में दिलचस्प जानकारी मिली। यह एक स्पीच थी। यह स्पीच फंड मैनेजमेंट कंपनी के इन्वेस्टमेंट मैनेजर लगभग 40 साल पहले दी थी। अब यह स्पीच वेब और सोशल मीडिया पर काफी लोकप्रिय हो गई है। इस स्पीच में कुछ ऐसी बुनियादी बातें बताईं गई हैं जो निवेश के लिहाज से काफी फायदेमंद हो सकतीं हैं।

इस स्पीच का शीर्षक था 'ट्राइंग टू हार्ड' यानी अत्यधिक प्रयास करना। यह अपने आप में अजीब लगता है। वास्तव में ट्राइंग टू हार्ड यानी बहुत ज्यादा प्रयास करने जैसी कोई चीज नहीं होती है। आप गूगल सर्च करके यह स्पीच पा सकते हैं और पूरी बात पढ़ सकते हैं। इस स्पीच की सबसे दिलचस्प बात भौतिक विज्ञान और निवेश के तौर तरीकों में समानता है।

भौतिक विज्ञान इस सिद्धांत पर आधारित है कि सभी भौतिक घटनाएं भौतिक नियमों के अनुसार चलती हैं। यह ऐसे नियम हैं जिनको तर्कपूर्ण तरीके से समझ सकते हैं। और अगर हम इन नियमों को अच्छी तरह से जान लेते हैं तो हम ज्ञान को बढ़ाने के साथ अपने पर्यावरण को प्रभावित कर सकते हैं।

तमाम शेयरों के बारे में विश्लेषण, तकनीकी विश्लेषण, आर्थिक सिद्धांत और अनुमान के तरीके जो हमने और आपने सीखें है यह भी इसी सिद्धांत पर आधारित है। कुछ आर्थिक ताकते हैं जो तार्किक हैं और जिनका आसानी से अनुमान लगाया जा सकता है। और अगर हम पूरा प्रयास करें और कंपनी के बारे में हर जरूरी डिटेल जान लें। अनुमान लगाने के तौर- तरीकों के लिए सही घटकों का पता लगा लें। अगर हम पूरा प्रयास करें तो आय, कीमतें और ब्याज दरें तार्किक और अनुमानित तरीके से व्यवहार करेंगी।

हालांकि भौतिक विज्ञान की तरह ही निवेशक की वास्तविकता काफी हद तक क्वांटम मकैनिक्स की तरह है। यहां पर घटनाएं हमेशा तर्क और अनुमान के आधार पर नहीं चलती हैं। समय के साथ हमें पता चलता है कि वित्तीय और आर्थिक घटनाओं को संचालित करने वाले कारकों के बारे में हमारी जानकारी उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए।

धीरेंद्र कुमार, सीईओ
वैल्यू रिसर्च

बोनस

बहुत से निवेश सलाहकारों, विशेषज्ञों और निवेशकों को लगता है कि शेयरों के बारे में विश्लेषण, तकनीकी विश्लेषण, आर्थिक सिद्धांत और अनुमान के तरीके किसी न किसी सिद्धांत पर आधारित हैं। इन्हें तार्किक रूप से समझ लेने से भविष्य की कुछ घटनाओं का सही अनुमान लगाना आसान हो जाता है। निवेश करने के तौर-तरीकों में दो तरह का नजरिया दिखता है। बहुत ज्यादा प्रयास करके भविष्य के बारे में अनुमान लगाना उनमें से एक है। दूसरा तरीका यह है कि मौजूदा घटनाओं के कारणों का आकलन करें और पता करें कि कि वे कौन सी चीजें जो हुईं हैं और आगे भी बनी रहेंगी। इतना तय है कि बहुत ज्यादा प्रयास करने से भविष्य नहीं दिखता।

ज्यादातर इक्विटी निवेशक सोचते हैं कि अगर वे जरूरी जानकारी जुटाकर इस पर सही से अमल करें तो वे यह जान सकते हैं कि आने वाले दिनों में उनके निवेश का प्रदर्शन कैसा होगा। इन सब बातों का मतलब यह जानना है कि कल शेयर की कीमतें क्या होंगी और इस तरह से कुछ पैसे कमाए जा सकते हैं। हम मानते हैं कि कोई रिसर्च पेपर या किसी बिजनेस अखबार में छपा लेखा भविष्य का अनुमान लगा सकता है। लेकिन क्या वे सफलतापूर्वक ऐसा कर पाते हैं? यह इस बात पर निर्भर करता है कि भविष्य से आपका क्या मतलब है? क?या भविष्य से आपका मतलब निकट भविष्य मे आने वाले बड़ी कंपनियों के वित्तीय आंकड़ों से है या आपका मतलब कुछ बड़ा असर डालने वाले चीजों से है?

इस सवाल का जवाब पीछे मुड़कर देखने से साफ हो जाता है कि किस बात का अनुमान लगाया जा सकता था और किसका नहीं। आप याद करिए कि 20वीं शताब्दी के आखिरी 25 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या हुआ था? क्या इन घटनाओं का अनुमान पहले से लगाया जा सकता था। आपको लंबी अवधि के रुझानों के साथ छोटी अवधि के रुझानों पर भी गौर करना होगा। 1980 के अंत में क्या आप सॉफ्टवेयर सेवाओं के शानदार भविष्य का अनुमान लगा सकते थे? क्या शहरों में भारतीयों के जीवन-स्तर की गुणवत्ता में आए उछाल का किसी ने अनुमान लगाया था? क्या वर्ष 1995 में यह सोचा जा सकता था कि आने वाले समय में ब्याज दरों में गिरावट आएगी और अर्थव्यवस्था में आसानी से पैसा कमाया जा सकेगा? क्या हाउसिंग सेक्टर में आए उछाल का अंदाजा पहले से किसी को था?

वर्ष 1996 के आसपास जब एक सस्ते और बेसिक मोबाइल फोन की कीमत आज के 20,000 रुपये के बराबर थी तब क्या किसी ने इस बात का सटीक अनुमान लगाया था कि वर्ष 2008 में भारत में कितने मोबाइल कनेक्शन होंगे? इसी तरह से क्या किसी ने यह पूर्वानुमान जताया था कि 2008 में पूरा वैश्विक आर्थिक तंत्र बुरी तरह से चरमरा जाएगा? और जब 2009 में मनमोहन सिंह की प्रधानमंत्री के तौर पर वापसी को इक्विटी मार्केट ने सराहा था तो क्या किसी ने सोचा था कि अगले पांच साल में स्थितियां कितनी खराब होने जा रही हैं?

अब भी कई एक्सपर्ट दावा करेंगे कि उनको इन घटनाओं के बारे में पहले से संकेत मिल गए थे। वे कहते हैं कि अंग्रेजी बोलने वालों की बड़ी संख्या और टेक्निकल मैनपावर की वजह से आइटी और इससे जुड़े सेवाओं के निर्यात के क्षेत्र में भारत का सुपर पावर बनना तय था।

ऐसा भी नहीं है कि निवेशकों के पास भविष्य का आकलन करने का कोई जरिया नहीं है। निवेशक को किसी बिजनेस या कंपनी की गुणवत्ता को लंबी अवधि के ट्रैक रिकॉर्ड पर परखना चाहिए। इसके अलावा निवेशक का पोर्टफोलियो बड़ा और डायवर्सिफाइड होना चाहिए जिससे कंपनी और किसी खास सेक्टर में होने वाली नकारात्मक घटनाओं के असर को कम किया जा सके।

निवेश करने के तौर तरीकों में दो तरह का नजरिया दिखता है। एक है बहुत ज्यादा प्रयास करके भविष्य के बारे में अनुमान लगाना और एक है कि आज हो रही घटनाओं के कारणों को पहचानना और इस बात का आकलन करना कि वे कौन सी चीजें जो हुईं हैं और आगे भी बनी रहेंगी।

1949 के बाद चीन में जन्म-दर पिछले 70 वर्षों में सबसे कम हो गई है। चीन के नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अनुसार, 2019 में यह 10.48 प्रति एक हजार थी। इसकी बड़ी वजह 1979 में लागू एक बच्चा नीति को माना जा रहा है।

अमेरिकी जज ने दिया फेसबुक को झटका

- यूजर्स की गोपनीयता भंग करने वाले एप का डाटा सौंपने का निर्देश
- कंपनी ने माना था कि उसने अपनी वॉल से इन एप को हटा दिया था

प्रतीकात्मक।

न्यूयॉर्क, आइएएनएस : अमेरिका में फेसबुक को तगड़ा झटका लगा है। अमेरिकी अदालत के एक जज ने फेसबुक को निर्देश दिया है कि वह उन हजारों एप के डाटा पुलिस को सौंपे, जिनसे यूजर्स की गोपनीयता का उल्लंघन किया गया है। ताजा आदेश कैंब्रिज एनालिटिका डाटा घोटाले की जांच के संबंध में पूर्व में दिए फैसले के तहत जारी किया गया है। दिग्गज सोशल मीडिया कंपनी ने पिछले साल ही माना था कि गोपनीयता उल्लंघन के आरोपों के बाद उसने अपनी वॉल से इन एप को हटा दिया था।

वाशिंगटन पोस्ट में शुक्रवार को प्रकाशित खबर के मुताबिक, मैसाच्युसेट्स के जज ने कंपनी के उन प्रयासों को भी खारिज कर दिया, जिसमें उसने अहम दस्तावेज जांचकर्ताओं के पास जाने से रोकने की अपील की थी। फेसबुक के प्रवक्ता एंडी स्टोन ने कहा, 'हम इस बात से निराश हैं कि मैसाच्युसेट्स के अटार्नी जनरल और कोर्ट ने हमारी दलीलों पर विचार नहीं किया। हम इस आदेश के खिलाफ ऊंची अदालत में अपील सहित अन्य विकल्पों पर विचार कर रहे हैं।' मैसाच्युसेट्स के डेमोक्रेटिक अटॉर्नी जनरल मौरा हेले ने कहा, 'हम इस बात से खुश हैं कि कोर्ट ने फेसबुक को यह आदेश दिया है कि वह बताए कि कौन से अन्य एप डेवलपर कैंब्रिज एनालिटिका की तरह आचरण में लगे हैं।' कैंब्रिज एनालिटिका मामले को सामने लाने वाले व्हिसलब्लोअर ब्रिटनी कैसर इससे जुड़े कुछ नए तथ्य सामने लाए हैं। उन्होंने कहा कि डाटा चोरी का पता लगने के बाद 2015 में फेसबुक ने पॉलिटिकल कंसलटेंसी फर्म से केवल डाटा हटाने के लिए ई-मेल के जरिये अनुरोध किया था और लापरवाह तरीके से इस संबंध में पुष्टि करने के लिए कहा था।

क्या है कैंब्रिज एनालिटिका का मामला

मुद्दा फेसबुक से डाटा चोरी कर उसका गलत इस्तेमाल करने का है। मामला अमेरिका का है। इसकी शुरुआत साल 2013 में हुई। कैंब्रिज यूनिवर्सिटी के रिसर्चर एलेक्जेंडर कोगन ने एक पर्सनालिटी क्विज एप बनाया। फिर इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए अलग-अलग फेसबुक वॉल पर पोस्ट करवाया। जब लोगों ने उस एप को डाउनलोड करना चाहा तो यूजर्स को फेसबुक के जरिये लॉग-इन करना पड़ा था। ऐसा करते वक्त एप यूजर्स का डाटा एक्सेस करने की अनुमति मांगी जाती थी। इससे धीरे-धीरे एप के जरिये 8.7 करोड़ यूजर्स की फेसबुक प्रोफाइल की पूरी जानकारी कोगन तक पहुंच गई।

अमेरिका में फिर गोलीबारी, चार की मौत

लॉस एंजिलिस, एजेंसियां: अमेरिकी में फिर गोलीबारी की घटना हुई है। इस दफा उटाह प्रांत के एक घर में हुई गोलीबारी में चार लोगों की जहां मौत हो गई वही एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने संदिग्ध हमलावर को गिरफ्तार कर लिया है। राज्य की राजधानी साल्टलेक सिटी के बाहरी इलाके ग्रांटसविले में शुक्रवार रात इस वारदात को अंजाम दिया गया। यहां पर लगभग दस हजार लोग रहते हैं।

ग्रांटसविले की पुलिस अधिकारी रोहन्डा फील्ड्स ने बताया कि पांच लोगों को गोली मारी गई थी, जिसमें चार की मौत हो गई। मृतकों की शिनाख्त हो गई है, लेकिन घायल व्यक्ति के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल सकी है। घटना की सूचना देने के लिए पीड़ितों के रिश्तेदारों का पता लगाया जा रहा है। पुलिस ने पीड़ितों और संदिग्ध हमलावर के नाम की कोई जानकारी नहीं दी है। ग्रांटसविले के मेयर ब्रेंट मार्शल ने इस बात की पुष्टि की है कि पीड़ित और हमलावर एक ही परिवार से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कहा कि यह पता करने में समय लग सकता है कि आखिर यह घटना क्यों हुई। उटाह प्रांत के गवर्नर गैरी हर्बर्ट ने ट्वीट करके समूची घटना पर संवेदना व्यक्त की है।

पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट का परवेज मुशर्रफ की अर्जी पर सुनवाई से इन्कार

- शीर्ष अदालत ने कहा, पहले सरेंडर करें, फिर होगी अपील पर सुनवाई
- देशद्रोह मामले में विशेष अदालत के फैसले को दी थी चुनौती

परेवज मुशर्रफ (फाइल फोटो)। एपी

इस्लामाबाद, प्रेट्र : पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने देशद्रोह मामले में मौत की सजा को चुनौती देने वाली पूर्व सैन्य शासक परवेज मुशर्रफ की अर्जी पर सुनवाई करने से इन्कार कर दिया है। कोर्ट ने याचिका वापस करते हुए कहा कि जब तक वह सरेंडर नहीं करते हैं, तब तक उनको अपील करने की इजाजत नहीं होगी।

मुशर्रफ ने गत गुरुवार को शीर्ष कोर्ट में अर्जी दाखिल कर विशेष अदालत के फैसले को रद करने की अपील की थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गठित विशेष अदालत ने गत 17 दिसंबर को मुशर्रफ को देशद्रोह का दोषी करार देते हुए मौत की सजा सुनाई थी। वह 2016 से दुबई में रह रहे हैं।

एक्सप्रेस ट्रिब्यून अखबार के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार कार्यालय ने शुक्रवार को इस टिप्पणी के साथ पूर्व सैन्य शासक मुशर्रफ की अर्जी लौटा दी कि अपील से पहले दोषी आत्मसमर्पण करें। सर्वोच्च अदालत ने इस आपत्ति को दूर करने के लिए एक माह की मोहलत दी है। इसका मतलब यह हुआ कि मुशर्रफ को एक महीने के अंदर सरेंडर करना होगा। ऐसा नहीं करने पर वह अपील करने का अधिकार गंवा देंगे।

74 वर्षीय पूर्व सेना प्रमुख मुशर्रफ ने अपने वकील सलमान सफदर के जरिये गत गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में 90 पेज की अर्जी दाखिल की थी। इसमें बताया गया था कि विशेष अदालत में मुशर्रफ की अनुपस्थिति इरादतन नहीं थी। वह खराब सेहत के कारण अदालत में पेश नहीं हो पा रहे थे। मुशर्रफ को बीमार मानने के बावजूद विशेष अदालत ने उनकी अनुपस्थिति में फैसला सुना दिया। इसके पहले बीते सोमवार को लाहौर हाई कोर्ट ने मुशर्रफ की अपील पर विशेष अदालत के फैसले को असंवैधानिक करार दिया था।

इस मामले में हुई सजा

वर्ष 2007 में पाकिस्तान पर आपातकाल लागू करने, संविधान को निलंबित करने और जजों को हिरासत में रखने के आरोप में मुशर्रफ के खिलाफ 2013 में मुकदमा दर्ज किया गया था। यह मुकदमा तत्कालीन नवाज शरीफ सरकार की ओर से दर्ज कराया गया था। मामले में खुद को घिरते देख मुशर्रफ इलाज के बहाने 18 मार्च, 2016 को दुबई चले गए थे। तब से वह अपने मुल्क नहीं लौटे।

'पाकिस्तान ने कश्मीर पर कमजोरी दिखाई'

लाहौर, प्रेट्र : अपने बयानों के लिए अक्सर चर्चा में रहने वाले पाकिस्तान के रेल मंत्री शेख राशिद ने शनिवार को सरकार के उलट बयान दिया। कहा, पाकिस्तान ने कश्मीर मसले पर अपनी कमजोरी दिखाई। वह अपनी बात मजबूती से नहीं रख पाया। पाकिस्तान सरकार अभी तक दावा करती आई है कि जम्मू-कश्मीर मसले के अंतरराष्ट्रीयीकरण में वह सफल रही है।

रेल मंत्री ने बताया कि सत्तारूढ़ तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी की सरकार पांच फरवरी तक देश में जनसभाएं कर कश्मीर के लोगों के प्रति अपने समर्थन का इजहार करेगी। राशिद ने कहा, उनका मानना है कि कश्मीर मसले पर कमजोरी दिखाई गई। यह बात उन्होंने कैबिनेट की बैठकों में भी कही है। प्रधानमंत्री इमरान खान ने हाल में एक जर्मन अखबार से साक्षात्कार में कश्मीर मसले पर खुद के अकेले पड़ने की बात कही। इमरान ने ट्वीट कर कहा, जम्मू-कश्मीर विवाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के संकल्प के अनुसार सुलझना चाहिए। कश्मीरी लोगों की भावना का सम्मान होना चाहिए। इमरान ने कश्मीरी लोगों के आंदोलन को नैतिक, राजनीतिक और कूटनीतिक समर्थन का भी एलान किया है। कहा है कि सुरक्षा परिषद में मामले पर विचार होना साबित करता है कि कश्मीर मसले का अंतरराष्ट्रीयीकरण हो चुका है। सुरक्षा परिषद ने 1965 के बाद पहली बार मसले पर विचार किया। कई देशों के नेता और अखबार कश्मीर मसले पर बयान दे रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। यह पाकिस्तान सरकार के प्रयास से ही संभव हुआ है।

अमेरिका-तालिबान में इसी माह हो सकता है समझौता

संभावना ▶ आतंकी संगठन के प्रवक्ता ने जताई उम्मीद

अमेरिका और तालिबान के बीच दिसंबर 2018 से दोहा में वार्ता चल रही थी, कई बार आ चुका है उतार-चढ़ाव

काबुल, एएफपी : अफगानिस्तान में 19 साल से जारी खूनी संघर्ष के खत्म होने के आसार बढ़ गए हैं। तालिबान ने कहा कि अमेरिका के साथ जनवरी के आखिर तक समझौते पर हस्ताक्षर करने का लक्ष्य है। इसके लिए आतंकी गतिविधियों को कम किया जाएगा।

पाकिस्तानी अखबार डॉन ने तालिबान के प्रमुख प्रवक्ता सुहैल शाहीन के एक बयान के हवाले से यह खबर दी। इसके पहले इसी आतंकी संगठन के सूत्रों ने बताया था कि संक्षिप्त संघर्ष विराम का प्रस्ताव दिया गया है। इस प्रस्ताव के बाद कतर की राजधानी दोहा में अमेरिका और तालिबान के बीच वार्ता शुरू हुई है।

शाहीन ने कहा, 'अमेरिका के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर के लिए हम कुछ दिनों के लिए अपनी गतिविधियों में कमी लाने पर सहमत हुए हैं। तालिबान को इस माह के आखिर तक अमेरिका के साथ समझौते पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है।' अमेरिका शांति वार्ता बहाल करने के लिए तालिबान से हिंसा कम करने की मांग कर रहा था।

तालिबानी प्रवक्ता सुहैल शाहीन। फाइल

पोंपियो ने की शांति प्रयास की तारीफ

वाशिंगटन, आइएएनएस : पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने शुक्रवार को अमेरिकी समकक्ष माइक पोंपियो से मुलाकात की। पोंपियो ने अफगान संकट का शांतिपूर्ण हल निकालने के प्रयास में पाकिस्तान की कोशिश की तारीफ की। कुरैशी पश्चिम एशिया के संकट को दूर करने के प्रयास में ईरान और सऊदी अरब भी गए थे। उन्होंने इन देशों के नेताओं के साथ हुई चर्चा के बारे में पोंपियो को जानकारी दी।

वार्ता की उतार-चढ़ाव भरी राह

अमेरिका और तालिबान के बीच दिसंबर 2018 से दोहा में वार्ता चल रही थी। लेकिन इस वार्ता में कई बार उतार-चढ़ाव देखने को मिला। गत सितंबर में जब दोनों पक्ष समझौते के करीब पहुंच गए थे, तब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तालिबान के हमले में एक अमेरिकी सैनिक की मौत पर यह वार्ता रद कर दी थी। इसके बाद गत दिसंबर में वार्ता फिर पटरी पर लौटी। लेकिन अफगानिस्तान में एक अमेरिकी सैन्य अड्डे के पास आतंकी हमले के बाद वार्ता रुक गई थी। इस हमले के बाद से ही अमेरिका संघर्ष विराम की मांग कर रहा था।

ब्रिटेन में ब्रेक्जिट के लिए उलटी गिनती शुरू

लंदन, प्रेट्र : ब्रिटेन के यूरोपीय यूनियन (ईयू) से रिश्ता तोड़ने की तैयारियां अंतिम दौर में हैं। करीब चार साल के इंतजार के बाद 31 जनवरी को ब्रेक्जिट की प्रक्रिया पूरी कर ब्रिटेन यूरोपीय यूनियन से अलग हो जाएगा। लंदन में प्रधानमंत्री आधिकारिक आवास 10, डाउनिंग स्ट्रीट पर एक बड़ी घड़ी लगाकर उलटी गिनती शुरू कर दी गई है। 31 जनवरी को रात 11 बजे ब्रिटेन औपचारिक रूप से यूरोपीय यूनियन के 27 देशों से अलग हो जाएगा। इससे पहले प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन कैबिनेट की विशेष बैठक करेंगे और उसके बाद राष्ट्र को संबोधित करेंगे।

31 जनवरी को ब्रिटिश कैबिनेट की विशेष बैठक इंग्लैंड के उत्तरी इलाके के किसी शहर में करेंगे। इसका उद्देश्य पूरे यूनाइटेड किंगडम की एकजुटता दिखाना होगा। यह स्कॉटलैंड, उत्तरी आयरलैंड और वेल्स के साथ होने का संकेत होगा। शनिवार को प्रधानमंत्री कार्यालय ने बयान जारी कर कहा, 31 जनवरी इतिहास का महत्वपूर्ण दिन होगा। इस दिन यूनाइटेड किंगडम यूरोपीय यूनियन छोड़ेगा और दोबारा अपने स्वतंत्र स्वरूप में आएगा। सरकार इस मौके को नवनिर्माण के उत्सव के तौर पर मनाना चाहती है जिसमें समाज सभी वर्गों और समुदायों का योगदान होगा। प्रधानमंत्री आवास में इस सिलसिले में एक बड़ी घड़ी लगाई गई है जो 31 जनवरी को रात 11 बजे के समय से दूरी प्रदर्शित करने वाली है। जैसे ही 11 बजेंगे-पूरी डाउनिंग स्ट्रीट और प्रधानमंत्री आवास का व्हाइट हॉल रोशनी से जगमगाने लगेगा।

म्यांमार से करार कर चीन ने हिंद महासागर में बढ़ाया दखल

- म्यांमार के साथ 33 समझौतों पर चीन ने किए दस्तखत
- ओबीओआर परियोजना में शामिल हुआ पड़ोसी देश

नेपीता में शनिवार को द्विपक्षीय बैठक के दौरान चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग के साथ म्यांमार की स्टेट काउंसलर आंग सान सू की। एएफपी

नेपीता, प्रेट्र : रोहिंग्या मुस्लिमों पर अत्याचार से उपजे विवाद पर मिट्टी डालते हुए चीन और म्यांमार ने शनिवार को 33 बड़े समझौतों पर दस्तखत किए। इनमें ओबीओआर (वन बेल्ट-वन रोड) परियोजना में म्यांमार की भागीदारी भी शामिल है। इसी के साथ चीन को हिंद महासागर में लंगर डालने का नया ठिकाना मिल गया है। ओबीओआर आधारभूत ढांचे के विस्तार की चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग की महात्वाकांक्षी परियोजना है।

राष्ट्रपति शी चिनफिंग के दो दिवसीय म्यांमार दौरे के अंतिम दिन शनिवार को उनकी स्टेट काउंसलर आंग सान सू की के साथ लंबी वार्ता हुई। इस वार्ता के बाद ही इन समझौतों पर दस्तखत किए गए। ये समझौते राजनीति, व्यापार, निवेश, दोनों देशों के लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने और ओबीओआर (वन बेल्ट-वन रोड) को लेकर हैं। इस दौरान सू की ने रोहिंग्या मसले पर पश्चिमी देशों के रुख की निंदा की।

कई बार हमले झेल चुकी सेना ने दो साल पहले रोहिंग्या मुस्लिमों के खिलाफ कार्रवाई की थी जिसमें सैकड़ों मारे गए थे और साढ़े सात लाख रोहिंग्या भागकर बांग्लादेश चले गए थे। वे बांग्लादेश में अभी रह रहे हैं। इसके चलते म्यांमार अंतरराष्ट्रीय समुदाय के निशाने पर रहा है। म्यामांर की इस कार्रवाई को लेकर कई मानवाधिकार संगठन और देशों ने उसकी तीखी आलोचना की थी। संयुक्त राष्ट्र ने माना है कि म्यांमार में मानवाधिकारों के बड़े पैमाने पर उल्लंघन हुआ। इस पर सू की ने कहा, कुछ देश अन्य देशों के अंदरूनी मामलों में जबरन दखल को अपना अधिकार समझते हैं। इसके लिए वे मानवाधिकार, धार्मिक और मूलवासी होने जैसी बातों का सहारा लेते हैं। लेकिन म्यांमार इस तरह की बातों को लेकर किसी का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करेगा। चाइना डेली के मुताबिक सू की ने उम्मीद जताई कि चीन म्यांमार जैसे छोटे और मध्यम दर्जे के देशों के साथ न्याय और सहयोग की अपनी नीति जारी रखेगा। इस संदर्भ में दोनों देशों के बीच समझौते को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

सू की के बयान के जवाब में राष्ट्रपति चिनफिंग ने कहा, चीन म्यांमार का विश्वसनीय दोस्त है। वह हमेशा म्यांमार और अन्य देशों के विकास के रास्ते का सम्मान करता है और मानता है कि किसी भी देश को अन्य देश के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। चीन अंतरराष्ट्रीय मंचों पर म्यांमार के साथ न्याय होने के लिए हमेशा आवाज उठाएगा और उसके समर्थन में खड़ा रहेगा। म्यांमार चीन के साथ मिलकर इकोनोमिक कॉरीडोर बनाने पर सहमत है। इससे दोनों देशों के बीच यातायात, ऊर्जा, उत्पादन क्षमता और मानवीय व सांस्कृतिक बढ़ेगा। यह वैसा ही कॉरीडोर होगा, जैसा चीन पाकिस्तान के साथ मिलकर बना रहा है। इन नए कॉरीडोर से चीन अपने दक्षिण-पश्चिम इलाके को हिंद महासागर से जोड़ेगा।

हिटलर के मंत्री का हवाला देने पर ब्राजील के मंत्री बर्खास्त

ब्राजीलिया, आइएएनएस: एक विवादास्पद वीडियो सामने आने के बाद ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो ने अपने संस्कृति मंत्री रोबर्टो अल्विम को बर्खास्त कर दिया है। रोबर्टो अल्विम वीडियो में हिटलर के प्रचार मंत्री जोसेफ गोएबल्स का हवाला देते हुए ब्राजील की कला एवं संस्कृति पर भाषण देते दिखाई दे रहे हैं। बोल्सोनारो के हस्ताक्षर से जारी एक बयान में कहा गया, 'यह ठीक है कि रोबर्टो अल्विम ने माफी मांग ली है, लेकिन उनका बयान किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता है। उन्हें संस्कृति मंत्रालय से हटाने की घोषणा की जाती है।'

गुरुवार को आधिकारिक सोशल मीडिया चैनल पर साझा किए गए फुटेज में अल्विम राष्ट्रीय कला पुरस्कार का प्रचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इस दौरान वह जोसेफ गोएबल्स की कई बातों का उल्लेख करते हैं। उनका यह वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोग बिफर पड़े। कई यूजर ने कहा कि संस्कृति मंत्री अपने दायरे से बाहर जा चुके हैं और यह कतई अस्वीकार्य है। प्रेसिडेंट ऑफ द चैंबर्स ऑफ डिप्टीज रोड्रिगो मिया ने कहा कि ब्राजील सरकार को उन्हें तत्काल पद से हटा देना चाहिए। वर्कर्स पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा ने भी उनकी आलोचना की।

रोबर्टो अल्विम। फाइल

कौन था गोएबल्स : डॉ. जोसेफ गोएबल्स 1933 से 1945 तक नाजी जर्मनी का प्रचार मंत्री था। गोएबल्स का जन्म 1897 में हुआ था। गोएबल्स ने कहा था कि एक झूठ को अगर कई बार दोहराया जाए तो वह सच बन जाता है। गोएबल्स को उसकी जोशीली भाषणकला और यहूदी विरोध के लिए जाना जाता था।

फ्रांस में फायर फाइटरों ने किया प्रदर्शन

फ्रांस के स्ट्रासबर्ग शहर में सहयोगियों पर हमले के विरोध में फायर फाइटर्स ने विरोध प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि फायर फाइटर पर हमले की घटनाएं बढ़ रही हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि नववर्ष की पूर्व संध्या पर कुछ लोगों ने दमकल की गाड़ी पर पथराव किया था। इससे कर्मचारी घायल हो गए थे। पिछले सप्ताह एक रेस्क्यू अभियान के दौरान एक फायर फाइटर को चाकू मार दिया गया था। एएफपी

चीन में जानलेवा वायरल न्यूमोनिया की चपेट में चार और लोग

बीजिंग, प्रेट्र: चीन के शहर वुहान में चार और लोगों के जानलेवा वायरल न्यूमोनिया की चपेट में आने का पता चला है। वुहान हेल्थ कमीशन के मुताबिक, ताजा मामलों को जोड़कर अब तक 45 लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं। दो लोगों की जहां मौत हो चुकी है, वहीं पांच की हालत गंभीर है। 15 को छुट्टी दी जा चुकी है जबकि अन्य की हालत स्थिर है। न्यूमोनिया की वजह एक नए प्रकार के कोरोना वायरस को माना जा रहा है। बता दें कि इसी तरह के एक वायरस से 2002 में सार्स (एसएआरएस) संबंधी बीमारी फैली थी। चीन के दक्षिणी इलाके से शुरू हुई इस बीमारी की चपेट में आकर दो दर्जन देशों के 800 लोगों की मौत हुई थी।

वायरल न्यूमोनिया से डरे अमेरिका ने वुहान से आने वाले यात्रियों की एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग शुरू कर दी है। उसने इस काम के लिए लॉस एंजिलिस, सैन फ्रांसिस्को और न्यूयॉर्क के केनेडी एयरपोर्ट पर 100 कर्मचारियों को तैनात किया है। यहां पर वुहान से आने वाले यात्रियों से ना केवल उनके लक्षणों के बारे में पूछा जाएगा बल्कि उनका तापमान भी लिया जाएगा। एशिया के कम से कम छह अन्य देशों ने भी मध्य चीन से आने वाले हवाई यात्रियों की स्क्रीनिंग शुरू कर दी है। इसमें थाइलैंड और जापान भी शामिल हैं। लंदन के इंपीरियल कॉलेज एमआरसी सेंटर फॉर ग्लोबल इंफेक्शियस डिजीज एनालिसिस के वैज्ञानिकों ने प्रभावित लोगों की संख्या एक हजार से अधिक होने का दावा किया है। इन वैज्ञानिकों का अनुमान है कि 12 जनवरी तक कुल 1,723 लोग इसकी चपेट में आए हैं।

क्या है कोरोना वायरस : डब्ल्यूएचओ के मुताबिक, कोरोना वायरस सी-फूड से जुड़ा है। कोरोना वायरस विषाणुओं के परिवार का है। यह वायरस ऊंट, बिल्ली तथा चमगादड़ सहित कई पशुओं में भी प्रवेश कर रहा है। इसके मरीजों में जुखाम, खांसी, गले में दर्द, सांस लेने में दिक्कत जैसे लक्षण देखे जाते हैं।

ट्रंप ने बयां की सुलेमानी को मारे जाने की दास्तां

पाम बीच, रायटर : अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तीन जनवरी को बगदाद में मारे गए ईरानी मेजर जनरल कासिम सुलेमानी पर ड्रोन हमले के अंतिम समय का घटनाक्रम बयां किया है। उन्होंने यह घटनाक्रम अपने चुनाव के लिए चंदा 10 मिलियन डॉलर (करीब 70 करोड़ रुपये) जुटाने के लिए आयोजित डिनर में बयां किया।

इस डिनर में मीडिया को आमंत्रित नहीं किया गया था लेकिन ट्रंप के अंदाज-ए-बयां ऑडियो क्लिप सीएनएन के हाथ लग गई है। इसमें ट्रंप अपने निर्देशन में सुलेमानी को मारे जाने के ऑपरेशन के बारे में शब्दशः बता रहे हैं। ट्रंप के अनुसार यह ऑपरेशन दो मिनट 11 सेकेंड का था जिसकी उन्हें व्हाइट हाउस स्थित वॉल रूम में लाइव रिपोर्टिंग की जा रही थी। ट्रंप ने बताया, सेना के अधिकारी ने उन्हें बताया- वे (सुलेमानी और इराकी शिया मिलिशिया के उप प्रमुख) साथ हैं, सर। सर, उनके पास अब दो मिनट और 11 सेकेंड हैं। भावनाओं के लिए कोई जगह नहीं। उनके पास जिंदा रहने के लए अब दो मिनट 11 सेकेंड ही हैं, सर। अब वे लोग कार में हैं, यह एक आर्मर्ड वेहिकिल (बख्तरबंद वाहन) है। सर, अब उनका जीवन एक मिनट बचा है। अब उनके पास 30 सेकेंड बचे हैं... अब 10, 9, 8....इसी के बाद एक जोर की आवाज आती है। वे जा चुके हैं, सर।

कासिम सुलेमानी। फाइल

सैन्य कार्रवाई को इस तरह से अमेरिका के किसी राष्ट्रपति ने पहली बार सार्वजनिक किया है। इसके लिए उनकी निंदा भी हो रही है। ट्रंप ने इस पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की है।

इराक में सरकार विरोधी प्रदर्शन में दो की जान गई

बगदाद, एपी: इराक की राजधानी बगदाद में सरकार के विरोध में सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़प में दो प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई और कई घायल हो गए। कई सप्ताह तक प्रदर्शन बंद रहने के बाद विरोध की यह ताजा घटना है।

कार्यकर्ताओं और अधिकारियों ने बताया कि दंगा रोधी बल ने प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे और तेज आवाज पैदा करने वाला बम फेंका। उनका कहना था कि प्रदर्शनकारी सिनाक पुल पर थे और वे सीमेंट की दीवार को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। इस सीमेंट वाली दीवार को सुरक्षाबलों ने बनाया था। उन्हें रोकने के लिए सुरक्षाबलों की तरफ से कार्रवाई की गई, जिसमें कई के घायल होने की बात कही जा रही है। तीन कार्यकर्ताओं और एक सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि प्रदर्शन के दौरान दो लोगों की मौत हो गई और कम से कम 20 घायल हो गए। अधिकारी ने नाम न जाहिर करने की शर्त पर बताया कि प्रदर्शनकारी बड़े बदलाव, नया नेतृत्व और समय से पूर्व चुनाव कराने की मांग कर रहे हैं। गौरतलब है कि बगदाद हवाई अड्डे के बाहर अमेरिकी ड्रोन हमले में ईरान के शीर्ष जनरल सुलेमानी की मौत के बाद ईरान और अमेरिका के बीच तनाव काफी बढ़ गया था जिसके बाद ये प्रदर्शन रुक गए थे, लेकिन कुछ समय की शांति के बाद प्रदर्शन फिर से शुरू हो गया।

गिराए गए यात्री विमान का ब्लैक बॉक्स यूक्रेन भेजेगा ईरान

दुबई, रायटर : अंतरराष्ट्रीय दबाव के बाद ईरान ने कहा है कि मिसाइल प्रहार से मार गिराए गए यात्री विमान का ब्लैक बॉक्स जांच के लिए यूक्रेन भेजा जाएगा। यात्री विमान यूक्रेन का था और आठ जनवरी को उड़ान के कुछ समय बाद मार गिराए गए इसमें कुल 176 यात्री थे। कोई भी यात्री जिंदा नहीं बचा है। यह विमान तब गिराया गया था जब अमेरिकी हमले की आशंका से ईरान हाई अलर्ट पर था। ईरान में विरोध प्रदर्शनों और अंतरराष्ट्रीय दबाव के बाद ईरानी सेना ने माना कि गलती से दागी गई मिसाइल से विमान गिरा। रडार पर अमेरिकी मिसाइल होने की आशंका में ईरान सेना ने मिसाइल दागी थी। जिस समय यह दुर्घटना हुई उससे कुछ ही देर पहले विमान तेहरान हवाई अड्डे से उड़ा था और यूक्रेन जा रहा था। इसमें सर्वाधिक यात्री ईरान के थे जबकि 57 कनाडा के थे। विमान का ब्लैक बॉक्स यूक्रेन भेजा जाएगा।

बराबरी का मुकाबला

ये भी जानिए
एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में वनडे में एक टीम का सर्वाधिक स्कोर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ही बना है। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ छह विकेट पर 383 रनों का बड़ा स्कोर खड़ा किया था।

ओपनरों की 'उपस्थिति' तय करेगी सीरीज

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा और आखिरी वनडे आज मैच से पहले होगा शिखर और रोहित के खेलने पर फैसला

बेंगलुरु, प्रेट्र : पिछले साल घर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पांच वनडे की सीरीज 2-3 से हारने वाली भारतीय टीम जब वर्तमान सीरीज का पहला मुकाबला पुणे में 10 विकेट से हारी तो लगा कि इस बार भी रिजल्ट कुछ वैसा ही होने वाला है लेकिन राजकोट में हुए दूसरे वनडे में ओपनर रोहित शर्मा (42) और शिखर धवन (96) ने पहले विकेट के लिए 81 रनों की साझेदारी कर टीम इंडिया के मजबूत स्कोर की नींव रखी। भारत ने मेहमानों को 341 रनों का लक्ष्य दिया और 36 रनों से जीत हासिल की लेकिन इस जीत से पहले ही भारत के दोनों ओपनर चोटिल हो गए। शिखर की पसलियों में बल्लेबाजी के समय ही पैट कमिंस की गेंद लगी थी जबकि रोहित क्षेत्ररक्षण करते समय अपना कंधा चोटिल कर बैठे थे। इस सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला रविवार को बेंगलुरु में है और भारत को इस 1-1 पर चल रही सीरीज को जीतने के लिए यह मैच जीतना होगा। इस मैच को जीतने के लिए भारत के दोनों ओपनरों का खेलना जरूरी है लेकिन इन पर अंतिम फैसला मुकाबले से ठीक पहले लिया जाएगा।

बीसीसीआइ की तरफ से बताया गया है कि दोनों की चोट में सुधार हो रहा है लेकिन इनके खेलने पर फैसला मैच से पहले ही लिया जाएगा। इस सीरीज के शुरू से ही रोमांचक होने की संभावना थी लेकिन जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया ने पहले मैच में एकतरफा जीत दर्ज की उससे एकबारगी लगने लगा था कि वह भारत में लगातार दूसरी सीरीज जीतने में कामयाब रहेगा। भारत ने राजकोट में हर विभाग में बेहतरीन प्रदर्शन करके शानदार वापसी की और साबित कर दिया।

राहुल पर बढ़ा भार

भारत दूसरे वनडे में अपने बल्लेबाजी संयोजन को ढर्रे पर ले आया तथा केएल राहुल ने भी पांचवें नंबर पर मिले मौके का पूरा फायदा उठाया। रोहित शर्मा और शिखर धवन ने पारी का आगाज किया जबकि कप्तान विराट कोहली अपने पसंदीदा तीसरे नंबर पर उतरे और श्रेयस अय्यर चौथे नंबर पर आए। अगर शिखर और रोहित फिट हो जाते हैं तो रविवार को भी यही बल्लेबाजी क्रम बरकरार रहने की संभावना है। दोनों के स्वास्थ्य पर कड़ी निगाह रखी जा रही है। अगर ये दोनों नहीं खेलते हैं या इनमें से कोई एक नहीं खेलता है तो कप्तान विराट कोहली की मुश्किल बढ़ना लाजमी है।

पांडे पर दवाव

चोटिल रिषभ पंत की जगह मनीष पांडे को दूसरे वनडे में खेलने का मौका मिला लेकिन वह सफल नहीं हो सके। उनके लिए बेंगलुरु में एक और मौका होगा। राजकोट में भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण पंत की जगह विकेटकीपर करने वाले राहुल की पारी रही जो उन्होंने नंबर पांचवें नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए खेली। इससे नई संभावनाएं पैदा हो गईं जिससे टीम संतुलन को सुधारने में मदद मिल सकती है। विशेषज्ञ सलामी बल्लेबाज राहुल ने 150 से अधिक स्ट्राइक रेट से रन बनाए। वह पहले मैच में नंबर तीन पर खेले थे। कोहली ने इसे राहुल की सर्वश्रेष्ठ पारी तक करार दे दिया। पंत की अनुपस्थिति में उन्होंने विकेटकीपिंग की जिम्मेदारी भी संभाली और आरोन फिंच को बड़ी चपलता से स्टंप आउट करने के अलावा दो कैच भी लिए।

गेंदबाजी में बदलाव की उम्मीद नहीं

गेंदबाजी में किसी तरह के बदलाव की संभावना नहीं है और टीम तीन तेज गेंदबाजों और दो स्पिनरों के साथ ही उतर सकती है। कुलदीप यादव पिछले साल अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं कर पाए थे लेकिन पिछले मैच में उन्होंने एक ओवर में एलेक्स कैरी और स्टीव स्मिथ के विकेट लेकर मैच का पासा पलटा और खुद को उपयोगी साबित किया। कलाई के दूसरे स्पिनर युजवेंद्रा सिंह चहल को कुलदीप के साथ खेलने का मौका मिल सकता है क्योंकि चिन्नास्वामी आइपीएल में उनका घरेलू मैदान है।

फिट बुमराह भारत के लिए फायदेमंद

चोट से उबरकर वापसी करने वाले जसप्रीत बुमराह की कसी हुई गेंदबाजी भारत के लिए एक और सकारात्मक पहलू रहा। उन्होंने एक छोर से दबाव बनाया और दूसरे छोर से विकेट मिलते रहे। मुहम्मद शमी और नवदीप सैनी ने भी अंतिम ओवरों में अच्छी गेंदबाजी की। ऑस्ट्रेलिया भी हार के बाद बहुत ज्यादा बदलाव करेगा ऐसी संभावना नहीं है। कुलदीप के ओवर में दो विकेट गंवाने से पहले वह लक्ष्य हासिल करने की स्थिति में बना हुआ था।

लाबुशाने ने दिखाई फॉर्म

बेहतरीन फॉर्म में चल रहे मार्नस लाबुशाने ने अपनी पहली वनडे पारी में प्रभाव छोड़ा। यही नहीं स्टीव स्मिथ ने एक समय मैच ऑस्ट्रेलिया के पक्ष में मैच मोड़ ही दिया था लेकिन कुलदीप ने उन्हें शतक और जीत से महरूम कर दिया। मिशेल स्टार्क ने पिछले मैच में 10 ओवर में 78 रन लुटाए लेकिन वह वापसी के लिए प्रतिबद्ध होंगे। उनके साथ नई गेंद संभालने वाले पैट कमिंस की गेंदों पर रन बनाना फिर से आसान नहीं होगा जबकि एडम जांपा फिर से कोहली को आउट करने का प्रयास करेंगे। वह सीमित ओवरों के क्रिकेट में अब तक सात बी कोहली को आउट कर चुके हैं। बायें हाथ के स्पिनर एश्टन एगर हालांकि प्रभाव नहीं छोड़ पाए। उन्हें निर्णायक मैच में बेहतर खेल दिखाना होगा।

टीमें इस प्रकार है

भारत : विराट कोहली (कप्तान), रोहित शर्मा, शिखर धवन, के एल राहुल, श्रेयस अय्यर, मनीष पांडे, केदार जाधव, शिवम दुबे, रवींद्र जडेजा, युजवेंद्रा सिंह चहल, कुलदीप यादव, नवदीप सैनी, जसप्रीत बुमराह, शार्दुल ठाकुर और मुहम्मद शमी।

ऑस्ट्रेलिया : आरोन फिंच (कप्तान), एलेक्स कैरी, पैट कमिंस, एश्टन एगर, पीटर हैंड्सकोंब, जोश हेजलवुड, मार्नस लाबुशाने, केन रिचर्डसन, डी आर्ची शॉर्ट, स्टीव स्मिथ, मिशेल स्टार्क, एश्टन टर्नर, डेविड वार्नर, एडम जांपा।

2 पिछले वनडे जो बेंगलुरु में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुए, उनमें कुल मिलाकर 709 और 647 रन बने थे

100 वनडे विकेट पूरे करने के लिए ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज पैट कमिंस को दो विकेट की दरकार है। अगर वह रविवार को ऐसा करते हैं तो 100 विकेट सबसे तेज पूरे करने वाले ऑस्ट्रेलिया के छठे गेंदबाज बनेंगे। कमिंस ने फिलहाल 60 वनडे खेले हैं

3 पिछली वनडे पारियों में रोहित शर्मा ने बेंगलुरु में 318 रन बनाए थे, जिसमें एक दोहरा शतक भी शामिल है। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 122 का रहा। इस मैदान पर उनसे ज्यादा रन सिर्फ वीरेंद्र सहवाग और सचिन तेंदुलकर ने ही बनाए हैं

राजकोट में शुक्रवार को दूसरे वनडे के दौरान पैट कमिंस की गेंद लगने के बाद गिर पड़े थे शिखर धवन ● फाइल फोटो, एपी

क्षेत्ररक्षण के दौरान बायें कंधे में चोट लगने के बाद मैदान में लेट गए थे रोहित शर्मा ● फाइल फोटो, एएफपी

स्मिथ, केन के वीडियो देख तैयारी की : केएल राहुल

राजकोट, प्रेट्र : सलामी बल्लेबाज के रूप में बल्लेबाजी करते हुए सबसे अधिक सहज महसूस करने वाले केएल राहुल ने मध्य क्रम में सफल होने के लिए वर्तमान समय के दिग्गज विराट कोहली से लगातार बातचीत करने के अलावा स्टीव स्मिथ और केन विलियमसन के वीडियो देखकर खुद को चुनौती के लिए तैयार किया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शुक्रवार को दूसरे वनडे में राहुल ने पांचवें नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए 52 गेंदों पर 80 रन की पारी खेली।

वीडियो देखकर संवारी पारी : राहुल ने पहले वनडे में कप्तान कोहली की जगह नंबर तीन पर बल्लेबाजी की थी तथा 61 गेंदों पर 47 रन बनाए थे। राहुल ने दूसरे वनडे के बाद कहा कि मुझे नहीं लगता है कि तकनीकि तौर पर मैंने अलग तरह से अभ्यास किया। मैंने केवल मध्य क्रम के बल्लेबाजों से बहुत अधिक बातचीत की तथा ढेर सारे वीडियो देखे। मैंने विराट से काफी बात की तथा डिविलियर्स और स्टीव स्मिथ के कई वीडियो देखे कि कैसे वे अपनी पारी संवारते हैं। उन्होंने कहा कि मैंने केन विलियमसन का अनुसरण करने की कोशिश की और उनके कुछ वीडियो देखे और यह समझने की कोशिश की कि वह अपनी पारी को कैसे आगे बढ़ाते हैं और कुछ विशेष परिस्थितियों में कैसे खेलते हैं। मैं इस चीज को समझने की कोशिश कर रहा हूं कि मैं कुछ विशेष परिस्थितियों में कैसे बेहतर खेल सकता हूं।

समझ हुई है बेहतर: इस 27 वर्षीय बल्लेबाज ने कहा कि बल्लेबाजी क्रम में विभिन्न स्थानों पर खेलने से खेल की उनकी समझ बेहतर हो गई है। वह अब तक 17 बार सलामी बल्लेबाज, तीन बार तीसरे नंबर, चार बार चौथे नंबर, दो बार पांचवें और एक बार छठे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए उतरे हैं। इससे पहले पिछली बार वह अगस्त 2017 में श्रीलंका के खिलाफ नंबर पांच पर उतरे थे और तब उन्होंने सात रन बनाए थे। राहुल ने कहा कि यह बड़ी चुनौती है। मैं अच्छी फार्म में हूं और अपने कौशल पर मुझे पूरा विश्वास है इसलिए हर मैच में नई जिम्मेदारी और नई भूमिका भी किसी वरदान से कम नहीं है, बहुत कम बल्लेबाजों को ऐसा मौका मिलता है। मैं इसे इसी तरह से देखता हूं।

ओपनिंग में सबसे ज्यादा सहज : उन्होंने कहा कि मैं हमेशा बल्लेबाजी का आगाज करता रहा हूं तो उस स्थिति में खुद को सबसे अधिक सहज महसूस करता हूं। मैं जानता हूं कि पारी को कैसे आगे बढ़ाना है लेकिन जब मुझे तीन, चार या पांच नंबर पर उतरना पड़ता है तो मुझे स्वयं के बारे में, अपनी बल्लेबाजी और एक कला के रूप में बल्लेबाजी के बारे में काफी कुछ सीखने को मिलता है। इस बीच राहुल को पिछले दो वनडे में विकेटकीपर की भूमिका भी निभानी पड़ी। राहुल अंडर-19 विश्व कप में विकेटकीपिंग कर चुके हैं।

लोकेश राहुल ● फाइल फोटो, प्रेट्र

एक नजर में

सिंधू और ताई होंगी पीबीएल-5 की स्टार आकर्षण

चेन्नई : भारत की शीर्ष बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधू और बी साई प्रणीत के अलावा पूर्व महिला नंबर एक ताई जु यिंग सोमवार से यहां शुरू होने वाली प्रीमियर बैडमिंटन लीग के पांचवें चरण में आकर्षण का केंद्र होंगे। सात टीमें लीग में खिताब हासिल करने की कोशिश करेंगी जिसकी कुल इनामी राशि छह करोड़ रुपये की है। विश्व चैंपियन सिंधू के अलावा भाग लेने वाले बड़े खिलाड़ी चीनी ताइपे की ताई जु यिंग, ओलंपिक रजत पदकधारी क्रिस्टिना पेडरसन (महिला डबल्स), दुनिया की पूर्व नंबर नौ तानोनगसाक साएनसोमबूनसुक के अलावा भारतीय स्टार शटलर साई प्रणीत, पी कश्यप, लक्ष्य सेन और सत्विकसाईराज रेंकी रेड्डी हैं। चेन्नई के अलावा मैच लखनऊ और हैदराबाद में आयोजित किए जायेंगे। फाइनल नौ फरवरी को हैदराबाद में होगा। (प्रेट्र)

आनंद ने खेला ड्रॉ

विच्क आन जी (नीदरलैंड्स) : पांच बार के विश्व चैंपियन विश्वनाथन आनंद ने टाटा स्टील मास्टर्स में शनिवार को यहां छठे दौर में नीदरलैंड्स के जोर्डन वान फोरीस्ट से ड्रॉ खेला। काले मोहरों से खेलते हुए आनंद से सफेद मोहरों से खेल रहे जोर्डन को 34 चाल के बाद ड्रॉ पर रोका। इस ड्रॉ मुकाबले से आनंद छह मुकाबलों में तीन अंक के साथ संयुक्त रूप से छठे स्थान पर बरकरार हैं। अभी सात दौर का खेल बाकी है और अगर आनंद को शीर्ष पर पहुंचना है जो उन्हें दमदार वापसी करनी होगी। सातवें दौर में इस भारतीय खिलाड़ी का सामना मैगनस कार्लसन से होगा। चैलेंजर वर्ग में भारत के सूर्यशेखर गांगुली स्थानीय ग्रैंडमास्टर जान स्मीट्स से ड्रॉ खेलकर संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर खिसक गए। (प्रेट्र)

रिकी ने होंडा को विजेता बनाया

रियाद : अमेरिकी राइडर रिकी ब्राबेक ने डकार रैली 2020 के 12वें चरण के बाद ओवरऑल रैंकिंग में शीर्ष पर रहते हुए होंडा को 31 साल के बाद चैंपियन बनाने में अहम भूमिका निभाई। मोंस्टर ईनर्जी होंडा टीम फैक्ट्री के इस चालक ने सीआरएफ450 रैली बाइक से यह जीत दर्ज की। पहली बार इस टीम से जुड़े 28 साल के ब्राबेक के लिए यह पांचवीं डकार रैली थी। उन्होंने तीसरे चरण में जीत दर्ज करने के बाद आखिर तक अपनी ओवरआल बढ़त बरकरार रखी। उनके टीम के जोश इगनासिओ चौथे और युआन बार्रेडा सातवें स्थान पर रहे। (आइएएनएस)

राशिद सातवें स्थान पर

सिंगापुर : भारतीय गोल्फर राशिद खान सिंगापुर ओपन गोल्फ टूर्नामेंट में शनिवार को तीसरे दौर में यहां दो अंडर-69 का कार्ड खेलकर संयुक्त रूप से सातवें स्थान पर हैं। एशियाई टूर पर दो खिताब जीतने वाले दिल्ली के 28 साल के इस गोल्फर ने तीसरे दौर में चार बोगी और छह बर्डी लगाई जिससे उनका कुल स्कोर आठ अंडर 205 हो गया। (प्रेट्र)

बीसीसीआइ ने राष्ट्रीय चयनकर्ताओं के लिए मांगे आवेदन

नई दिल्ली, जेएनएन: बीसीसीआइ ने जूनियर पुरुष टीम और सीनियर महिला टीम की चयनकर्ताओं के लिए नए आवेदन मांगे हैं। पुरुषों की सीनियर और जूनियर चयन समिति के लिए दो-दो पद और महिलाओं की समिति के लिए पांच पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। बता दें कि सीनियर चयन समिति के प्रमुख चयनकर्ता एमएसके प्रसाद (दक्षिण) और उनके साथी गगन खोड़ा (पश्चिम) ने अपना चार वर्ष का कार्यकाल पूरा कर लिया है जबकि शरणदीप सिंह (उत्तर), देवांग गांधी (पूर्व) और जतिन परांजपे (मध्य) का कार्यकाल अभी एक वर्ष बचा है। जो भी नया चयनकर्ता बनेगा उनमें से एक चयन समिति का नेतृत्व करेगा। इस चयन समिति पर भारतीय टीम, भारत-ए, दलीप ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, चैलेंजर ट्रॉफी और ईरानी कप के लिए शेष भारत की टीमों के चयन की जिम्मेदारी होती है। आवेदक वही हो सकते हैं जिन्होंने खेल से कम से कम पांच साल पहले ही संन्यास लिया हो।

अभी यह साफ नहीं है कि क्रिकेट सलाहकार समिति (सीएसी) के प्रस्तावित सदस्य मदन लाल, गौतम गंभीर और सुलक्षणा नायक आवेदकों के साक्षात्कार लेंगे या नहीं। राष्ट्रीय चयनकर्ता बनने के लिए आवेदक की उम्र 60 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। हाल ही में दिलीप वेंगसरकर का नाम चयनकर्ता के लिए उभरा था, लेकिन वह 64 वर्षीय हैं।

हार्दिक की फिटनेस जांचने के बाद होगा टीम का चयन

बेंगलुरु, प्रेट्र : हार्दिक पांड्या की फिटनेस जांचने के बाद ही राष्ट्रीय चयनकर्ता कुछ दिन बाद न्यूजीलैंड दौरे के लिए वनडे और टेस्ट टीम का चयन करेंगे। पहले चयन बैठक रविवार को आयोजित होनी थी। बीसीसीआइ अधिकारी ने कहा कि इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमारे लिए फिट हार्दिक ज्यादा जरूरी हैं। जब राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी की ओर से हमें हार्दिक की फिटनेस पर जवाब मिल जाएगा तो वह अपने आप ही पहली पसंद बन जाएंगे। ऐसे में चयनकर्ता कुछ दिन के लिए इंतजार करना चाहते हैं। अगर हार्दिक फिट नहीं हो पाते हैं तो चयनकर्ताओं के पास सूर्यकुमार को वनडे टीम में चुन सकते हैं, जो पहले से ही भारतीय ए टीम के साथ न्यूजीलैंड में मौजूद हैं।

चयनकर्ताओं की निगाहें केएल राहुल की टेस्ट टीम में वापसी कराने पर भी होंगी, क्योंकि सीमित ओवर क्रिकेट में राहुल ने शानदार प्रदर्शन किया है। विराट कोहली भी कह चुके हैं कि राहुल जैसे खिलाड़ी को किसी भी टीम से निकालना मुश्किल होगा। वह पृथ्वी शॉ या युवा शुभमन गिल से ज्यादा बेहतर साबित हो सकते हैं। जो न्यूजीलैंड दौरे पर तीसरे ओपनर हो सकते हैं। एक बदलाव जो टेस्ट टीम में देखने को मिल सकता है वह स्पिनर कुलदीप यादव की जगह एक अतिरिक्त तेज गेंदबाज नवदीप सैनी हो सकते हैं। न्यूजीलैंड की तेज पिचों पर जब रविचंद्रन अश्विन और रवींद्र जडेजा अंतिम-11 में होंगे तो कुलदीप का टीम में जगह बनाना मुश्किल होगा। वहीं वनडे टीम में केदार जाधव की जगह अजिंक्य रहाणे की वापसी हो सकती है। बीसीसीआइ से जुड़े सूत्रों ने कहा कि केदार 2023 विश्व कप नहीं खेलने जा रहे हैं और वह अब गेंदबाजी भी नहीं करते हैं। वह टी-20 टीम में नहीं है।

पहली बार टीम बैठक में शामिल होंगे चयनकर्ता

नई दिल्ली : बीसीसीआइ ने शनिवार को एक जरूरी बदलाव करते हुए नए राष्ट्रीय चयनकर्ताओं को अधिकारिक टीम बैठक में शामिल होने के लिए कहा है। हालांकि यह अभी तय नहीं है कि अंतिम-11 चुनने के लिए चयनकर्ता अपना वोट दे सकेंगे या नहीं। यह भी तय नहीं है कि नए चयनकर्ताओं में से कौन चयन समिति का नेतृत्व करेगा, क्योंकि मौजूदा तीन चयनकर्ताओं में कोई उसके काबिल नहीं है। बीसीसीआइ अधिकारी ने कहा कि आमतौर पर किसी दौरे पर चयनकर्ता कोच या कप्तान के साथ अभ्यास सत्र में रणनीति के बारे में चर्चा करते हैं, लेकिन अब इसमें बदलाव किया गया है। यह अच्छा होगा अगर किसी दौरे पर चयनकर्ता टीम बैठक का हिस्सा बन सकेंगे।

अंडर-19 विश्व कप

जीत से आगाज करना चाहेगा भारत

ब्लूमफोनटेन (दक्षिण अफ्रीका), एएफपी : मौजूदा विजेता भारतीय टीम आइसीसी अंडर-19 विश्व कप में अपने खिताब बचाने के अभियान की शुरुआत रविवार को श्रीलंका के खिलाफ होने वाले मैच से करेगी। प्रियम गर्ग की कप्तानी वाली टीम काफी पहले दक्षिण अफ्रीका पहुंच चुकी थी और वहां उसने परिस्थितियों के साथ तालमेल बैठाने के लिए सीरीज भी खेल ली हैं। उसने विश्व कप से पहले मेजबान दक्षिण अफ्रीका को तीन मैचों की वनडे सीरीज में 2-1 से हराकर अपनी तैयारियों का परिचय दे दिया था।

भारतीय टीम की बल्लेबाजी में अगर बड़े नामों का जिक्र करें तो यशस्वी जायसवाल वह चेहरा है जो घरेलू क्रिकेट में भी दमदार प्रदर्शन कर चुका है। वह अंडर-19 टीम के लिए कई बेहतरीन पारियां खेलते आए हैं। यशस्वी टीम की बल्लेबाजी की धुरी हैं और उनसे इस विश्व कप में असरदार प्रदर्शन की उम्मीद होगी। साथ ही में वह गेंद से भी योगदान दे सकते हैं। बल्लेबाजी में उनका साथ देने के लिए कप्तान प्रियम, तिलक वर्मा, ध्रुव चंद जुरेल हैं। दिव्यांश सक्सेना ने भी बीते मैचों में अपनी बल्लेबाजी से प्रभावित किया है। भारत को पहले एक झटका लग चुका है क्योंकि हरफनमौला खिलाड़ी दिव्यांश जोशी वनडे सीरीज में चोटिल होने के काराण विश्व कप से बाहर हो गए थे और उनके स्थान पर सिद्देश वीर को मौका मिला है।

बजरंग पूनिया ने बनाई फाइनल में जगह

रोम, प्रेट्र : भारत के स्टार पहलवान बजरंग पूनिया ने शनिवार को यहां रैंकिंग सीरीज प्रतियोगिता के 65 किग्रा के फाइनल में पहुंचकर कम से कम रजत पदक पक्का कर लिया।

बजरंग को पहले दौर में अमेरिका के जैन एलेन रदरफोर्ड के खिलाफ पसीना बहाना पड़ा। हालांकि वह 5-4 से जीत दर्ज करने में सफल रहे। क्वार्टर फाइनल में भारतीय पहलवान ने अमेरिका के जोसफ क्रिस्टोफर मैक केना को 4-2 से शिकस्त दी और फिर सेमीफाइनल में यूक्रेन के वासिल शुपतार का सफर 6-4 से समाप्त किया। बजरंग का सामना अब फाइनल में अमेरिका के पहलवान जॉर्डन माइकल ओलिवर से होगा। हालांकि जितेंदर का 74 किग्रा में और विश्व चैंपियनशिप के रजत पदकधारी दीपक पूनिया का 86 किग्रा वर्ग में अभियान समाप्त हो गया। जितेंदर ने पहले दौर में यूक्रेन के डेनिस पावलोव को 10-1 से हराया था लेकिन वह क्वार्टर फाइनल में तुर्की के सोनेर देमिरतास से 0-4 से हार गए। उन्हें रेपेचेज में खेलने का मौका मिला क्योंकि देमिरतास फाइनल में पहुंच गए थे। पर यह भारतीय इस मौके का फायदा नहीं उठा सका और कजाखिस्तान के दानियार काईसानोव से 2-9 से पराजित हो गया। वहीं, दीपक को शुरुआती दौर में पुअर्तो रिको के इथान एड्रियन रामो से 1-11 से शिकस्त का सामना करना पड़ा। रवि कुमार दहिया 57 किग्रा के बजाय 61 किग्रा में भाग ले रहे हैं, उन्होंने दोनों दौर जीत लिए हैं। उन्होंने पहले मोलदोवा के एलेक्सांद्रू चिरतोआका और कजाखिस्तान के नूरीस्लाम सानायेव को मात दी।

रैंकिंग सीरीज के सेमीफाइनल में पूनिया ने वासिल को हराया पहलवान जितेंदर और दीपक हारकर हुए बाहर

ओलंपिक वर्ष में तैयारियां सही दिशा में : विनेश

रोम, प्रेट्र : भारतीय पहलवान विनेश फोगाट ने सत्र के शुरुआती रैंकिंग सीरीज टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक अपने नाम करने के बाद कहा कि इससे दिखता है कि ओलंपिक वर्ष में उनकी तैयारियां सही दिशा में आगे बढ़ रही हैं। विनेश ने 53 किग्रा में स्वर्ण पदक जीतने के दौरान चीन की दो कड़ी प्रतिद्वंद्वियों को मात दी और फाइनल में इक्वाडोर की लुईसा एलिजाबेथ वालवरडे को पराजित किया। ओलंपिक में भारत के लिए पदक की प्रबल दावेदार विनेश ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में भाग लेने से हमारी ट्रेनिंग की परीक्षा होती है। इससे हमें पता चलता है कि हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं या नहीं?

अर्जुन मुंडा बने भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली : केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा शनिवार को तीन पर्यवेक्षकों की निगरानी में कराए गए चुनाव में निलंबित भारतीय तीरंदाजी संघ (एएआइ) के अध्यक्ष चुने गए।

एएआइ के पूर्व अध्यक्ष विजय कुमार मल्होत्रा के समर्थन से झारखंड तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष मुंडा ने असम तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष और सेवानिवृत आइएएस अधिकारी बीवीपी राव को 34-18 के अंतर से हराया। मुंडा के पूरे पैनल ने जीत दर्ज की जिसका कार्यकाल चार साल का होगा। महाराष्ट्र के प्रमोद चंदुरकर ने सचिव पद के चुनाव में चंडीगढ़ के महासिंह को 31-21 से हराया जबकि वरिष्ठ उपाध्यक्ष के चुनाव में हरियाणा के पूर्व मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने मणिपुर के जीए इबोपिशाक को 32-20 से शिकस्त दी। कोषाध्यक्ष पद के चुनाव में उत्तराखंड के राजेंद्र सिंह तोमर ने ओडिशा के समिख्या नंदा दास को 34-18 से मात दी। 31 राज्य संघ एएआइ का हिस्सा हैं, लेकिन 26 राज्यों को मतदान में हिस्सा लेने का मौका मिला जहां प्रत्येक राज्य के दो-दो मत थे। उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और जम्मू-कश्मीर निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं हैं। इस तरह कुल 52 मतों से अध्यक्ष, महासचिव, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, आठ उपाध्यक्ष, सात संयुक्त सचिव और एक कोषाध्यक्ष सहित 19 सदस्यीय कार्यकारी समिति का चयन हुआ।

टेनिस डायरी भाग्य के सहारे भारतीय खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन के मुख्य ड्रॉ में जगह बनाई

जोकोविक से भिड़ सकते हैं प्रजनेश

मेलबर्न, एएफपी: भारतीय टेनिस खिलाड़ी प्रजनेश गुणेश्वरन ने शनिवार को अपने भाग्य के सहारे ऑस्ट्रेलियन ओपन के पुरुष सिंगल्स के मुख्य ड्रॉ में जगह बनाई और अगर वह पहली बाधा पार करने में सफल रहते हैं तो दूसरे दौर में उनका मुकाबला विश्व के नंबर दो सर्बिया के दिग्गज खिलाड़ी नोवाक जोकोविक से हो सकता है। साल के पहले ग्रैंडस्लैम की शुरुआत सोमवार से हो रही है। प्रजनेश क्वालीफाइंग दौर के अपने अंतिम मैच में लाटविया के अर्नेस्ट गुलबिस से सीधे सेटों में हार गए थे, लेकिन भाग्य के सहारे वह मुख्य ड्रॉ में जगह बनाने में सफल रहे क्योंकि एलेक्स डि मिनॉर और कामिल माजचरजक के चोटिल होने तथा निकोलस के डोपिंग के कारण टूर्नामेंट से बाहर होने के बाद प्रजनेश को मुख्य ड्रॉ में पहुंचने का मौका मिल गया।

प्रजनेश को अच्छा ड्रॉ : बायें हाथ से खेलने वाले प्रजनेश लगातार पांचवीं बार किसी ग्रैंडस्लैम के मुख्य ड्रॉ में खेलेंगे। चेन्नई के इस खिलाड़ी ने पिछले साल क्वालीफायर के जरिये ऑस्ट्रेलियन ओपन में जगह बनाई थी लेकिन विंबलडन, फ्रेंच ओपन और अमेरिकी ओपन में बेहतर रैंकिंग के आधार पर उन्होंने मुख्य ड्रॉ में स्थान पाया था। प्रजनेश को शुरू में अच्छा ड्रॉ मिला है। उनका पहला मुकाबला सोमवार को जापान के तात्सुमो इटो से होगा जो भारतीय खिलाड़ी से 22 पायदान नीचे 144वीं रैंकिंग पर काबिज हैं। उन्हें ग्रैंडस्लैम के मुख्य ड्रॉ में पहला मैच जीतने का मौका मिला है।

फेडरर से भिड़े थे नागल : पिछले साल अमेरिकी ओपन में सुमित नागल ने दिग्गज रोजर फेडरर के खिलाफ प्रभावशाली प्रदर्शन करके सभी का ध्यान अपनी तरफ खींचा था। नागल और रामकुमार रामनाथन मुख्य ड्रॉ में जगह नहीं बना पाए। ये दोनों क्वालीफायर्स में हार गए थे।

जोकोविक और ओसाका से आस : गत विजेता जोकोविक और जापान की नाओमी ओसाका के लिए अपने खिताब को बचाना आसान नहीं रहेगा। दोनों खिलाड़ियों से अच्छे प्रदर्शन की आस है। सर्बियाई खिलाड़ी की टूर्नामेंट में राह 20 बार के ग्रैंडस्लैम विजेता रोजर फेडरर और विश्व के नंबर एक राफेल नडाल मुश्किल पैदा कर सकते हैं। वहीं, अमेरिकी दिग्गज सेरेना ओसाका को लगातार दूसरी बार यह खिताब जीतने से रोकना चाहेंगी।

आयोजकों पर बरसे फेडरर : फेडरर ने शनिवार को ऑस्ट्रेलियन ओपन में वायु गुणवत्ता को लेकर बेहतर संवाद की मांग की क्योंकि यहां जंगलों में लगी आग के कारण फैले धुएं से इस टूर्नामेंट की तैयारियों पर असर पड़ा और आयोजकों को प्रदूषण को लेकर नए दिशानिर्देश जारी करने पड़े। फेडरर ने कहा, 'मेरा मानना है कि टूर्नामेंट के आयोजकों का लोगों, मीडिया, प्रशंसकों, खिलाड़ियों से संवाद बेहद जरूरी है क्योंकि आप सुन रहे हैं कि बाहर निकलना सुरक्षित नहीं है, अपने पालतू पशुओं को अंदर रखे और खिड़कियां बंद रखें।' वहीं, विश्व के छठे नंबर के खिलाड़ी स्टेफानोस सितसिपास ने कहा, 'मैं लगातार खांस रहा था। मुझे दो घंटे तक सांस लेने में परेशानी हुई।'

प्रजनेश गुणेश्वरन ● ट्विटर

22 साल की जापानी खिलाड़ी नाओमी ओसाका पिछले साल ऑस्ट्रेलियन ओपन में महिला सिंगल्स की विजेता रही थीं

2019 में सर्बिया के नोवाक जोकोविक ने ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जीता था। उन्होंने सबसे ज्यादा बार इस टूर्नामेंट का सिंगल्स खिताब अपने नाम किया है। वह सात बार इस ट्रॉफी को जीत चुके हैं

11 बार ऑस्ट्रेलिया की दिग्गज मागरेट कोर्ट ने ऑस्ट्रेलियन ओपन में महिला सिंगल्स की विजेता ट्रॉफी जीती है। वह इस टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स में सबसे ज्यादा बार खिताब जीतने वाली खिलाड़ी हैं

बार्टी ने घरेलू सरजमीं पर पहला खिताब जीता

एडिलेड : ऑस्ट्रेलिया की महिला टेनिस खिलाड़ी एश्ले बार्टी ने एटीपी-डब्ल्यूटीए एडिलेड अंतराष्ट्रीय टूर्नामेंट के फाइनल में 19 साल की डायना यास्त्रेमस्का को हराकर करियर में पहली बार घरेलू सरजमीं पर खिताब अपने नाम किया। नंबर एक खिलाड़ी बार्टी ने यूक्रेन की 24वीं रैंकिंग वाली खिलाड़ी के खिलाफ मुकाबले को 6-2, 7-5 से जीता। बार्टी ने इसके साथ ही सोमवार से शुरू हो रहे ऑस्ट्रेलियन ओपन के खिताब के लिए अपनी दावेदारी मजबूत की।

सानिया की खिताबी जीत के साथ वापसी

होबार्ट, प्रेट्र : सानिया मिर्जा ने दो साल के विश्राम के बाद वापसी पर शानदार शुरुआत करते हुए शनिवार को यहां नादिया किचनोक के साथ मिलकर डब्ल्यूटीए होबार्ट अंतरराष्ट्रीय का महिला डबल्स खिताब जीता। भारत और यूक्रेन की गैरवरीयता प्राप्त जोड़ी ने शुहाई पेंग और शुहाई झांग की दूसरी वरीयता प्राप्त चीनी जोड़ी को एक घंटे 21 मिनट तक चले मैच में 6-4, 6-4 से हराया। सानिया बेटे इजहान के जन्म के बाद पहली बार किसी टूर्नामेंट में खेल रही थीं। इस 33 वर्षीय खिलाड़ी ने इस तरह से ओलंपिक वर्ष में शानदार शुरुआत की और ऑस्ट्रेलियन ओपन के लिए भी पुख्ता तैयारियों का सबूत पेश किया। सनिया बेटे के जन्म के कारण 2018 और 2019 के सत्र में डब्ल्यूटीए सर्किट में नहीं खेली थीं। सानिया ने कहा कि होबार्ट में सप्ताह शानदार रहा है। मैं दो साल बाद वापसी कर रही हूं और अब खिताब जीतने से अच्छा लग रहा है। सानिया और नादि

25 जनवरी को होगी देहरादून के आसन वेटलैंड में प्रवासी परिंदों की गणना। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट के निदेशक डॉ. धनंजय मोहन की देख-रेख में विशेषज्ञ इस कार्य को अंजाम देंगे।

बना लें प्लान, ग्लेशियरों से दिल्लगी का मिलेगा भरपूर मौका

रविवार विशेष

ओपी अवस्थी, पिथौरागढ़

बर्फ ही बर्फ...

- पर्यटकों को लुभाएंगे उच्च हिमालय के अल्पाइन ग्लेशियर
- मौसम की जोरदार बर्फबारी ने दिए संकेत उच्च हिमालयी क्षेत्र ग्लेशियरों से होगा गुलजार
- भारी हिमपात ने छोटी नदियों और नालों को दे दिया ग्लेशियर का रूप
- शीतकाल लंबा होने से सीजनल ग्लेशियरों की बढ़ेगी उम्र, पर्यटक मई तक कर सकेंगे दीदार
- कुछ स्थानों पर साल भर सीजनल ग्लेशियर बने रहने की संभावना

उत्तराखंड में पिथौरागढ़ के छिरकानी के निकट सीजनल ग्लेशियर (फाइल फोटो)। जागरण

पिथौरागढ़ के मिलम मार्ग में सीजनल ग्लेशियर के नीचे से हो रही आवाजाही (फाइल फोटो)। जागरण

इस बार प्रकृति हिमालय आने वाले पर्यटकों पर मेहरबान है। मौसम की जोरदार बर्फबारी ने स्पष्ट संकेत दे दिए हैं कि आने वाले दिनों में उच्च हिमालयी क्षेत्र ग्लेशियरों से गुलजार रहेगा। नदी-नाले जमने लग गए हैं और सीजनल ग्लेशियरों का बनना शुरू हो गया है। मई तक पर्यटकों को इनके दीदार का भरपूर मौका मिलेगा।

प्रतिवर्ष शीतकाल में बर्फबारी के बाद उच्च हिमालय में सीजनल ग्लेशियर बनते हैं। उच्च हिमालय के सभी नाले, गधेरे यानी छोटी नदी विभिन्न आकार के ग्लेशियरों में तब्दील हो जाते हैं। इसके अलावा सारे बुग्याल (घास के मैदान) भी ग्लेशियर के रूप में नजर आते हैं। पिछले कई वर्षों से हिमपात कम होने या फिर फरवरी-मार्च में हिमपात होने से सीजनल ग्लेशियरों की उम्र कम हो गई थी। देरी से गिरने वाली यह बर्फ हल्की गर्मी पड़ते ही पिघलने लगती थी। इससे ग्लेशियर आकार ही नहीं ले पाते थे या फिर जब तक पर्यटक उच्च हिमालय में पहुंचते थे, तब तक अधिकांश ग्लेशियर पिघल जाते थे। ग्लेशियरों के कुछ खंड ही मार्गों के आसपास नजर आते थे।

इस वर्ष लंबे अंतराल के बाद दिसंबर से ही भारी बर्फबारी के कारण शीतकाल की अवधि बढ़ी है। ऐसे में भारी हिमपात से ग्लेशियरों की संख्या ही नहीं बल्कि उनकी उम्र भी बढ़नी तय है। उच्च हिमालय में बनने वाले सीजनल यानी अल्पाइन ग्लेशियरों का आकार अलग-अलग होता है। छोटे ग्लेशियर सौ से डेढ़ सौ मीटर तो बड़े ग्लेशियर पांच सौ मीटर या इससे अधिक आकार के होते हैं। बीते वर्ष मिलम मार्ग के छिरकानी में पांच सौ मीटर का ग्लेशियर बना था। मई की गर्मी में भी लोग इस ग्लेशियर से ही चल कर आगे जा रहे थे। यह ग्लेशियर अक्टूबर में पिघला था। इस वर्ष की बंपर बर्फबारी से कुछ स्थानों पर साल भर सीजनल ग्लेशियर रहने की संभावना जानकार जता रहे हैं।

शीतकाल में बनने वाले सीजनल ग्लेशियर जल के बड़े स्रोत माने जाते हैं। गर्मी बढ़ते ही ये पिघलने लगते हैं। जिससे हिमानी नाले ऊफान पर आ जाते हैं और नदियों का जलस्तर बढ़ जाता है।

दारमा घाटी मुफीद: उच्च हिमालय में जाने वाले पर्यटकों की जिज्ञासा ग्लेशियर देखने में अधिक होती है। इस बार दारमा घाटी सीजनल ग्लेशियरों के लिहाज से पर्यटकों के लिए मुफीद साबित होने वाली है। तीन उच्च हिमालयी घाटियों दारमा, मिलम व व्यास में से दारमा घाटी ही मोटर मार्ग से जुड़ी है। जहां पहुंच पाना सरल होगा। यहां आना पर्यटकों के लिए निश्चिततौर से एक अलग ही तरह का अनुभव होगा।

> आल्प्स पर्वत की तर्ज पर बनने वाले इन सीजनल ग्लेशियरों को अल्पाइन ग्लेशियर कहा जाता है। इस वर्ष की भारी बर्फबारी से इनका आकार काफी बढ़ा और आकर्षक होने की पूरी स्थिति बन चुकी है। पूरी गर्मी तक ये रहेंगे और पर्यटक इनका दीदार कर सकेंगे।
> **-पीएस धर्मशक्तू, पर्वतारोही एवं पर्यावरण के जानकार**

> गत वर्षों की तुलना में इस बार जमकर बर्फबारी हुई है। अकसर फरवरी में होती थी, इस साल दिसंबर से हो रही है। लिहाजा मौसम की मेहरबानी से इस वर्ष सीजनल ग्लेशियरों की भरमार होने वाली है, जो लंबे समय तक टिके रहेंगे। इससे पर्यटन और ट्रेकिंग को लाभ होगा।
> **-सुरेंद्र पवार, ट्रेकर एवं उच्च हिमालय के जानकार**

जागरण विशेष की अन्य खबरें पढ़ें
www.jagran.com/topics/jagran-special

कुंभ के लिए पीएम से मांगे 1000 करोड़

राज्य ब्यूरो, देहरादून: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर हरिद्वार में 2021 में होने वाले महाकुंभ की तैयारियों के संबंध में जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री से महाकुंभ के सफल संचालन के लिए एक हजार करोड़ से अधिक के कार्यों के लिए आर्थिक सहायता देने का भी अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को प्रदेश में चारधाम देवस्थानम बोर्ड कानून के संबंध में भी जानकारी दी। उन्होंने प्रधानमंत्री को अप्रैल में होने वाली वेलनेस समिट के शुभारंभ और देश के सबसे बड़े मोटर केबल पुल डोबरा चांटी के लोकार्पण के लिए भी आमंत्रित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्य को मिशन मोड पर करने की बात कही। साथ ही प्रदेश में वित्तीय संसाधनों को बढ़ाने के लिए जीएसटी कलेक्शन में विशेष प्रयास करने को कहा।

शनिवार को नई दिल्ली में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2010 में हरिद्वार में आयोजित कुंभ मेले में देश-विदेश से आठ करोड़ श्रद्धालु आए थे। 2021 में होने वाले कुंभ मेले में 15 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को केदारनाथ में किए जा रहे पुनर्निर्माण कार्यों के संबंध में भी जानकारी दी।

मजाक उड़ाने वालों को आईना दिखातीं मीना और रीना

केएस मोबिन, रोहतक

चल पड़ी गाड़ी...

- हेवी लाइसेंस लेकर बस चला रहीं दो सगी बहनें, परिवार की गाड़ी पटरी पर लौटाई
- बस चलाने के साथ ही बच्चों को पढ़ाती भी हैं, कर रहीं स्नातक की पढ़ाई
- सामाजिक संस्था ने दी ड्राइवर की नौकरी, झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए रोजाना बस में लाना और छोड़ना इनके जिम्मे

हरियाणा के रोहतक की इन दो बहनों के जज्बे की मिसाल आज हर कोई देता है। बस ड्राइवर बन ये बेटियां पुरुषों के एकाधिकार वाले इस पेशे में चुनौती पेश कर रही हैं। दोनों ने तंगहाली में गुजर कर रहे परिवार की गाड़ी को पटरी पर ला दिया है। यही नहीं, स्नात्कोत्तर की पढ़ाई भी कर रही हैं।

नारी सशक्तीकरण

रोहतक शहर की एकता कालोनी निवासी दो सगी बहनें रीना हुड्डा और मीना हुड्डा बेटियों के लिए प्रेरणास्रोत हैं। मेक द फ्यूचर ऑफ कंट्री (एमटीएफसी) संस्था से जुड़ी दोनों बहनें हेवी वाहन चालन के लिए लाइसेंस ले चुकी हैं और संस्था के लिए बस चलाती हैं। झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए रोजाना बस में लाना और छोड़ना इनके जिम्मे है। बस चलाने के साथ ही ये बच्चों को पढ़ाती भी हैं। दोनों फिलहाल इग्नू से मास्टर इन सोशल वर्क की पढ़ाई भी कर रही हैं।

बचपन में ही पिता का साया सिर से उठने के कारण परिवार का सारा बोझ मां इंद्रावती पर आ गया। इंद्रावती ने बड़ी मुश्किल से अपनी दो बेटियों और बेटों को पाला। आर्थिक तंगी के कारण भाइयों को बहुत कम उम्र से ही घर की जिम्मेदार उठानी पड़ी, लेकिन जरूरतों के आगे वह कमाई बौनी पड़ रही थी। फिर मां भी बेटियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना चाहती थीं, ताकि वे किसी की मदद को मोहताज न रहें। तंगी में गुजर कर रही मां ने बेटियों का एमटीएफसी संस्था में दाखिला कराया। यह फैसला दोनों के लिए टर्निंग प्वाइंट साबित हुआ है।

यहां से स्कूल की पढ़ाई करने के साथ ही बेटियों ने स्कूटी, बाइक और कार चलाना भी सीखा। संस्था के संचालकों और अध्यापकों के प्रेरित करने पर छोटी बहन मीना ने हरियाणा रोडवेज के रोहतक प्रशिक्षण केंद्र पर हैवी व्हीकल लाइसेंस के लिए आवेदन किया। करीब एक महीने के सफलतापूर्वक प्रशिक्षण के बाद अप्रैल 2018 में लाइसेंस प्राप्त किया। ऐसा करने वाली वह रोहतक की पहली महिला भी हैं। इससे उत्साहित बड़ी बहन रीना ने भी बहादुरगढ़ के प्रशिक्षण केंद्र से हैवी लाइसेंस प्राप्त किया और वह वहां से हैवी लाइसेंस लेने वाली पहली महिला बनीं। रीना और मीना की मां कहती है उन्हें गर्व है कि उनकी ऐसी बेटियां हैं।

रीना और मीना का कहना है कि मां और दोनों भाइयों ने हमेशा उनका साथ दिया। बस चलाने की इच्छा जब जाहिर की तो भाइयों ने समर्थन किया। परिवार के हौसला बढ़ाने पर झिझक कम हुई। खुद की कामयाबी के लिए दो बहनें एमटीएफसी के संचालक नरेश ढल, तस्वीर हुड्डा, मनीषा अग्रवाल को धन्यवाद देती हैं।

बस चालक बनीं रोहतक की रीना। जागरण

100 लड़कों के बैच में थी...

बस चालन प्रशिक्षण बैच में करीब 100 लड़कों में वह अकेली लड़की थी रीना। लड़के अकसर मजाक उड़ाया करते थे। हालांकि प्रशिक्षण के बाद होने वाले जरूरी ट्रायल में पहली ही बार में रीना पास हो गई। उन्होंने बताया कि झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए ऑटो रिक्शा से लाना और वापस छोड़ना पड़ता था। संस्था को बस मिली तो ड्राइवरों की जरूरत भी पड़ी, जिसके लिए बहनें आगे आईं।

बस चालक बनीं रोहतक की मीना। जागरण

सरोकार की अन्य खबरें पढ़ें
www.jagran.com/topics/positive-news

रॉयल लुक देती है मेवाड़ की अनूठी ठीकरी कला

आकर्षक ▶ देश-विदेश में बढ़ रही मांग, कांच के टुकड़ों से बनाई जाती हैं सुंदर कलाकृतियां

उदयपुर में दो सौ से अधिक कलाकार पा रहे रोजी, अब दुनिया के विभिन्न देशों में मांग

सुभाष शर्मा, उदयपुर

मेवाड़ की ठीकरी कला यानी कांच के टुकड़ों से सजी सुंदर कलाकारी। कभी राजस्थान में राजसी ठाठ-बाठ में चार चांद लगाने वाली इस कला की मांग अब देश में ही नहीं, बल्कि विदेश में भी बढ़ रही है। पहले जहां राजा-महाराजाओं के महलों और अमीरों की हवेलियों में ही ठीकरी कलाकृतियां पाई जाती थीं, वहीं अब फाइव स्टार होटलों और घरों में भी सजावट के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाने लगा है।

उदयपुर में दो सौ से अधिक कलाकार इसी कला से जुड़े हुए हैं। ठीकरी कला की मांग अब फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान सहित यूरोप और एशिया के विभिन्न देशों में बढ़ी है। ठीकरी कला का उपयोग छोटे से लेकर समूचे भवन पर किया जा सकता है। विभिन्न प्रकार के दर्पणों, गुलदस्तों से लेकर दीवार पर बनाए जाने वाली हाथी-घोड़े, मोर सहित विभिन्न सुंदर आकृतियां कांच के टुकड़ों से गढ़ी जाती हैं।

छोटी कलाकृतियों को विदेशी पर्यटक, व्यवसायी उदयपुर से खरीदकर ले जाते हैं। वहीं विभिन्न होटल समूह, बड़े घराने अपने संस्थान और मकानों पर ठीकरी कला का काम कराने के लिए उदयपुर से कलाकारों को बुलाते हैं। ठीकरी कला से जुड़े प्रशांत जोशी बताते हैं कि दशक भर पहले तक जहां इसकी मांग कम थी, वहीं अब हैरिटेज लुक का काम बढ़ने से इसकी मांग बेहद बढ़ गई है।

इस कलाकृति में भावनाएं जुड़ी होती हैं। असल में यह कला मेवाड़ से जुड़ी हुई है और इसका अपना समृद्ध इतिहास है। मेवाड़ में सैकड़ों साल से ठीकरी कला का काम चलता आ रहा है। इसमें कांच को काटने से लेकर चिपकाने तक का काम हाथों से किया जाता है। प्रशांत ने बताया कि अब तो देश में भी विभिन्न संस्थानों के दफ्तर और म्यूजियम आदि भी ठीकरी कला का काम कराने लगे हैं। इसमें रंग-बिरंगे कानवेक्स ग्लास का इस्तेमाल होता है।

एक अन्य कारोबारी अरविंद कुमार बताते हैं कि पीओपी बेस पर रंग-बिरंगे कांच के टुकड़ों को चिपकाकर कलाकृतियां बनाई जाती हैं। एक फ्रेम तैयार करने में कई बार महीनों भी लग जाते हैं। यह कलाकृतियां आसान नहीं, इसके लिए काफी मेहनत की जरूरत होती है। छोटी सी गलती भी किए कराए काम को बिगाड़ सकती है।

ठीकरी कला पर आधारित कलाकृतियां हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। जागरण

अपना देस खुशबू माटी की

फिर चलन में राजसी ठाठ...

कोठियों, दफ्तरों, होटलों, फार्महाउस में, अब तेजी से रॉयल लुक वाला इंटीरियर चलन में आ रहा है। ठीकरी कला इसमें चार चांद लगा रही है। कई इंटीरियर डिजाइनर इस थीम को अपना रहे हैं। पांच सितारा होटलों के स्वागत कक्षों में ठीकरी आर्ट नजर आने लगा है। ठीकरी कला में दक्ष कलाकारों की मांग बढ़ रही है। पैसे के साथ उसे मेवाड़ी कला को देश-विदेश में फैलाने का अवसर मिलता है।

राष्ट्रपति के हाथों पुरस्कार प्राप्त करेगी उत्तराखंड की बहादुर बिटिया राखी

जागरण संवाददाता, देहरादून: छोटे भाई की जान बचाने को अदम्य साहस का परिचय देते हुए गुलदार से भिड़ने वाली 11 साल की राखी को राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार मिलेगा। छोटे भाई को बचाने में राखी को गुलदार ने गंभीर घायल कर दिया था। इसके बाद लंबे समय तक राखी का दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में उपचार चला।

पौड़ी गढ़वाल की चौबट्टाखाल तहसील की सैंधार पट्टी के देवकुंडई गांव में बीते चार अक्टूबर को गुलदार ने खेत में अपनी मां के साथ गए चार साल के राघव पर हमला कर दिया था। साथ में मौजूद 11 वर्षीय बहन राखी भाई को बचाने के लिए उसके ऊपर लेट गई और गुलदार को राघव तक नहीं पहुंचने दिया।

इस पर गुलदार ने राखी पर हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। तभी कुछ दूरी पर घास काट रही उनकी मां ने यह सब देखा तो गुलदार की ओर शोर मचाते हुए दौड़ीं और उस पर पत्थर से वार करने लगीं। शोर सुनकर आसपास के ग्रामीण भी मौके पर पहुंच गए और गुलदार को वहां से भगा दिया। घायल राखी को तत्काल पोखड़ा स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। वहां उसे प्राथमिक उपचार देकर हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। इसके बाद राखी को संयुक्त चिकित्सालय कोटद्वार पहुंचाया गया। एक दिन बाद ही राखी को दिल्ली स्थित सफदरजंग अस्पताल भेज दिया गया। वहां उसका लंबे समय तक उपचार चला, जबकि आंशिक रूप से घायल राघव को कोटद्वार अस्पताल से उपचार देकर घर भेज दिया गया था।

राखी के साहस को देखते हुए क्षेत्रवासियों ने जिलाधिकारी को पत्र लिख कर राखी का नाम राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार के लिए भेजने की मांग की थी। राखी के पिता दलबीर सिंह ने फोन पर बताया कि वे पुरस्कार ग्रहण करने दिल्ली पहुंच चुके हैं।

खिलौनों से रोजी-रोटी नहीं, परंपरा बचाने की जुगत

संडे बॉक्स जरा हटके...

73 वर्षीय भोला सिंह वर्षों से बना रहे लकड़ी के पारंपरिक खिलौने

▶ इनसे खेल जवां हुई बीती पीढ़ियां, शहरीकरण के साथ बीत गया जमाना

सुभाष चंद्र, बठिंडा

बठिंडा, पंजाब निवासी 73 वर्षीय भोला सिंह लकड़ी के खिलौने बनाने के कार्य में आज भी पूरी तल्लीनता से लगे रहते हैं। यह जुगत वह रोजी-रोटी के लिए नहीं, बल्कि पारंपरिक खिलौनों को बचाने के लिए है। कहते हैं, आज भी जब मैं वह गाना सुनता हूं- लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा..., तो सोच में पड़ जाता हूं कि समय कितना कुछ बदल देता है, पीछे रह जाती हैं तो बस यादें।

अमरपुरा बस्ती में भोला की छोटी सी दुकान है, जहां वे लकड़ी के खिलौने बनाते दिख जाएंगे- पूरी लगन और तन्मयता के साथ। कहते हैं, दो दशक पहले तक भी लकड़ी के खिलौने चलन में थे, सस्ते, टिकाऊ और हानिरहित। लेकिन आज प्लास्टिक के आधुनिक खिलौनों के आगे लकड़ी के ये खिलौने फीके पड़ गए हैं। मैं चाहता हूं कि आज के बच्चे देश की संस्कृति से जुड़े इन पारंपरिक खिलौनों को देख सकें, इसलिए इन्हें बनाता हूं। संतोष इस बात का है कि इन खिलौने के चंद कद्रदान आज भी मेरी दुकान पर पहुंच जाते हैं। भोला सिंह अपनी इस छोटी से दुकान में बैठकर लकड़ी के अनेक खिलौने गढ़ते हैं। ट्रैक्टर-ट्रालियां, बैलगाड़ियां, रथ, गाड़ी, गाय, भेड़, बकरी, शेर, हिरण, गड़ारी..., उनकी दुकान में वे सारे खिलौने मिल जाएंगे, जो पुराने दौर की याद दिलाते हैं। आज बेशक छोटे बच्चों को चलना सिखाने के लिए वाकर ने जगह ले ली है, लेकिन भोला सिंह आज भी पुराने जमाने में चलन में रही गड़ारी बनाते हैं। भोला सिंह का कहना है कि वाकर में वो बात कहां जो लकड़ी की इस गड़ारी में है। वास्तव में छोटे बच्चे गड़ारी से ही सही ढंग से चलना सीखते हैं। यह बच्चों को खड़े होना भी सिखाता है। इससे उनका संतुलन बेहतर बनता है। ग्राहकों के बारे में कहते हैं, शहरी तो नहीं, लेकिन ग्रामीण महिलाएं आज भी अपने बच्चों के लिए इसे खरीदकर ले जाती हैं। रोज कोई न कोई ये खिलौने खरीदने के लिए आ ही जाता है। ये खिलौने बेचकर मैं रोजाना तीन-चार सौ रुपये की कमाई कर लेता हूं। इस शौक के बारे में उन्होंने बताया कि बरसों पहले जब मैं अपने गांव मैहणा में रहा करता था तो खिलौनों के साथ-साथ खेती से संबंधित औजार और घर की रसोई में काम आने वाली वस्तुएं खुद बना लिया करता था। फिर परिवार के बच्चों के लिए बनाने लगा। इस काम में मुझे सुकून मिलता।

अमरपुरा बस्ती स्थित अपनी दुकान पर लकड़ी का खिलौना बनाते भोला सिंह। जागरण

याद आ जाता है बचपन...

भोला सिंह कहते हैं मैं यह काम रोजी-रोटी के लिए नहीं, शौकिया तौर पर कर रहा हूं। मेरे तीन बेटे हैं, जो अपना-अपना काम करके अच्छी कमाई कर रहे हैं। बच्चों के खिलौने बनाने में मुझे बेहद आनंद आता है। बचपन की यादें भी ताजा हो जाती हैं। चाहता हूं कि नई पीढ़ी भी इन्हें जाने, समझे और अपनाए।

राष्ट्रपति करेंगे सूरजकुंड मेले का शुभारंभ

जासं, फरीदाबाद: 34वें सूरजकुंड हस्तशिल्प मेले का उद्घाटन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद करेंगे। मेला एक से 16 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा। यह ऐसा तीसरा अवसर होगा, जब राष्ट्रपति मेले का शुभारंभ करेंगे। इससे पहले 2009 में तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल और 2013 में तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी मेले का उद्घाटन कर चुके हैं। हरियाणा पर्यटन विभाग के महाप्रबंधक राजेश जून ने बताया कि हरियाणा सरकार की ओर से राष्ट्रपति को पत्र भेज कर उद्घाटन के बारे में आग्रह किया गया था।

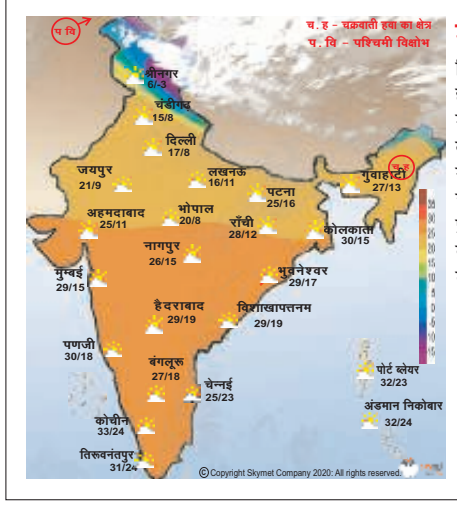

मौसम विशेष

दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सुबह में अधिकांश भागों में घना कोहरा छाया रहेगा। अधिकांश स्थानों का मौसम शुष्क रहेगा। जम्मू-कश्मीर, लद्दाख व हिमाचल प्रदेश में एक-दो स्थानों पर हल्की वर्षा व बर्फबारी जारी रहेगी रात के तापमान में गिरावट आएगी।

भारत के मुख्य शहरों का तापमान:

शहर		शहर	
मुम्बई	30/17/आंबा	अहमदाबाद	29/13/आंबा
कोलकाता	30/14/आंबा	हवाई	31/13/सा
चेन्नई	30/24/आंबा	नागपुर	27/15/आंबा
हैदराबाद	30/20/आंबा	इन्दौर	26/11/आंबा
बंगलूरू	28/18/ग	रांची	28/14/आंबा
त्रिवेन्द्रम	32/25/सा	पटना	24/08/आंबा
गुवाहाटी	24/13/आंबा	जमशेदपुर	30/16/सा
गंगटोक	02/-14/आंबा	पुणे	34/19/आंबा

साप्ताहिक राशिफल

रविवार 19 जनवरी, 2020 से शनिवार 25 जनवरी, 2020 तक

पं. बी. बी. शास्त्री 'देवेश'

मेष (चू,चे,चो,ला,ली,लू,ले,लो,आ)
व्यापार, नौकरी, उद्योग के कार्य में प्रगति, धनागम अच्छा, नए स्थानों पर संपर्क, प्रतिस्पर्धा का योग, समाज में अपयश, मन में अशांति, चयन में सफलता, शत्रुपक्ष परास्त, प्रणय में सुख, राज्य पक्ष से सावधान, अपने लक्ष्य का ध्यान रखें, आय से प्रति, शुभ अंक 5 ।

वृष (इ,ऊ,ए,ओ,पा,वी,वू,वे,वो)
धनागम में प्रयास, वर्तमान परिस्थिति के साथ कार्य करें, विदेश व्यापार में सफलता, चिंता का समाधान, वाहन योग, संतान के लिए योजना, अध्ययन में एकाग्रता, यथार्थ को स्वीकार करें, प्रणय में अनबन, रक्षासाधन कार्य में सफलता, राज्य पक्ष से सहयोग, व्यय अधिक, शुभ अंक 6।

मिथुन (का,की,कू,घ,ड,छ,के,को,हा)
अर्थसाधन में प्रयास करें, परिश्रम एवं सलाह से कार्य योजना बनाएं, साझेदारी में सावधानी, विदेश व्यापार में प्रयास सफल, चिंता की समाप्ति, वाहन योग, संतान की प्रगति, चयन में सफलता, ईर्ष्या से बचें, जीवन साथी का मिलन, अधिकारी से सहयोग, व्यय अधिक, शुभ अंक 7।

कर्क (ही,हू,हे,हो,डा,डी,डू,डे,डो)
अर्थसाधन अच्छा, पूंजी निवेश में सावधानी, साझेदारी में तनाव, पारिवारिक जनों की चिंता, निर्माण कार्य में अवरोध, मित्रों से सावधानी, अतिविश्वास से बचें, जीवन साथी से अनबन, यात्रा में सावधानी, अधिकारी से अनबन, यंत्र विस्तार योजना, शुभ अंक 8 ।

सिंह (मा,मी,मू,मे,मो,टा,टी,टू,टे)
नौकरी, उद्योग, व्यापार के कार्य में सफलता, धनागम अच्छा, सामाजिक कार्य में यश, विदेश व्यापार में सफलता, वाहन योग, भूमि-भवन कार्य में प्रगति, अध्ययन में एकाग्रता, वर्तमान अवसर का लाभ उठाएं, राज्य पक्ष से सावधानी, धर्म में रुचि, शुभ अंक 9।

कन्या (टो,पा,पी,पू,ष,ण,ठ,पे,पो)
अर्थसाधन में प्रगति, धन के आवागमन में सावधानी, प्रतिस्पर्धा से परेशानी, साझेदारी में सावधानी, चिंता की समाप्ति, वाहन निर्माण कार्य में प्रगति, संतान की प्रगति, चयन में सफलता, मित्रों से सावधान, दांपत्य में सुख, धर्म में रुचि, अधिकारी से सहयोग, आय में सुधार, शुभ अंक 11।

तुला (रा,री,रू,रे,रो,ता,ती,तू,ते)
धनागम में प्रगति, कार्य करने वालों से सहयोग, सामाजिक अपयश, भौतिक साधनों की पूर्ति, अध्ययन में एकाग्रता, चयन में सफलता, प्रणय में सुख, दृढ़ निश्चयता के साथ कार्य करें, संपूर्ति का अनुबंध, रक्षा साधन कार्य में प्रगति, शुभ अंक 11।

वृश्चिक (तो,ना,नी,नू,ने,नो,या,यी,यू)
व्यापार, नौकरी, उद्योग के कार्य में श्रम से सफलता, धनागम में देरी, विदेश कार्य में अवरोध, सामाजिक कार्य में अपयश, चिंता की समाप्ति, संतान से चिंतित, मित्रों से सावधान, ससुराल से सहयोग, धर्म में रुचि, अधिकारी से सहयोग, एकाएक कार्य संपन्न, आय में सुधार, शुभ अंक 11 ।

धनु (ये,यो,भा,भी,भू,धा,फा,ढा,भे)
अर्थ साधन ठीक, नए क्षेत्र में कार्य योग, विदेश कार्य में प्रयास सफल, मन में चिंता, संतान के लिए योजना, अध्ययन में अवरोध, शत्रु पत्र प्रभावी, रक्षा साधन कार्य में प्रगति, राज्य कर्मचारी को अपयश, रुके कार्य संपन्न, विशेष घटनाक्रम से चिंतित, शुभ अंक 1।

मकर (भो,जा,ज,खी,खू,खे,खो,गा,गी)
व्यापार, नौकरी, उद्योग के कार्य में सफलता, धनागम में प्रयास, दूसरों के साथ सामंजस्य बनाएं, निर्णय सोचकर करें, अपने लक्ष्य का ध्यान रखें, विदेश व्यापार में सफलता, चिंता की समाप्ति, वाहन-भूमि कार्य में सफलता, अध्ययन में एकाग्रता, धर्म में रुचि, व्यय से बचें, शुभ अंक 2।

कुम्भ (गू,गे,गो,सा,सी,सू,से,सा,दा)
नौकरी, व्यापार, उद्योग के कार्य में प्रगति, अर्थ साधन ठीक, सामाजिक कार्य का योग, निर्णय सलाह से करें, पारिवारिक चिंता, भौतिक साधनों की पूर्ति, संतान से चिंतित, चयन में सफलता, मित्रों से सावधान, भ्रमण के अवसर, राजनीतिक प्रयास सार्थक, शुभ अंक 3।

मीन (दी,दू,थ,झ,ञ,दे,दो,चा,ची)
व्यापार, नौकरी, उद्योग के कार्य में प्रयास से सफलता, धनागम में प्रयास करें, अति विश्वास न करें, सलाह से कार्य करें, पिता से तनाव, वाहन योग, संतान की प्रगति, शत्रु पक्ष परास्त, प्रणय में सुख, राज्य पक्ष से सावधान, अनुबंध की प्राप्ति, आय में सुधार, शुभ अंक 4।

राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
आजकल
रविवार 19 जनवरी 2020
www.jagran.com

पहली बार विद्युत प्रकाश प्रणाली अस्तित्व में आई

आज ही के दिन 1883 में पहली बार न्यूजर्सी के रोसले में थॉमस एडिसन द्वारा तैयार विद्युत प्रकाश प्रणाली का इस्तेमाल हुआ। दरअसल एडिसन साबित करना चाहते थे कि पूरा समाज एक केंद्रीय जनरेटिंग स्टेशन से प्रकाशित हो सकता है।

पहला पर्सनल कंप्यूटर वायरस ब्रेन आया सामने

1986 में आज ही पर्सनल कंप्यूटर वायरस ब्रेन दुनिया के सामने आया था। फ्लॉपी डिस्क से इसका प्रसार हुआ। यह फ्लॉपी के बूट सेक्टर को प्रभावित करता था। इसे पाकिस्तान के दो भाईयों ने लिखा था। हालांकि यह वास्तव में कॉपी प्रोटेक्शन के लिए था।

अभिनय को जी रहे हैं बहुमुखी प्रतिभा के धनी सौमित्र चटर्जी

आज ही के दिन 1935 में फिल्म एवं थिएटर अभिनेता सौमित्र चटर्जी का जन्म ब्रिटिश भारत के दौरान बंगाल के कृष्णा नगर में हुआ। वे कवि और लेखक भी हैं। शुरुआती जीवन में ही उन्होंने स्कूली नाटकों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। 1959 में उनकी पहली बंगाली फिल्म अपूर संसार आई, जिसे सत्यजीत रे ने निर्देशित किया। रे के साथ 14 फिल्मों में अभिनय किया। छह दशक के उनके फिल्मी जीवन में 250 से ज्यादा फिल्में हैं। राष्ट्रीय फिल्म, दादा साहेब फाल्के, संगीत नाटक अकादमी और कई बार फिल्मफेयर से सम्मानित हैं। वे अभी सक्रिय हैं।

इधर-उधर की

खरगोश ने बिजनेस क्लास में किया सफर

न्यूयॉर्क, एजेंसी : अपने पालतुओं से प्यार करने वाले अक्सर उनके लिए कुछ भी कर जाते हैं। एक महिला ने अपने खरगोश को विमान यात्रा कराई। इस यात्रा के दौरान खरगोश को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया। 11 घंटे लंबी यह यात्रा सैन फ्रैंसिस्को से जापान तक की थी। इस खरगोश का नाम कोको है। यह शानदार जीवन जीता है, जो दूसरों के लिए महज एक सपना ही होता है। कोको आठ साल का है। इसे विमान में अलग से सीट दी गई और उसने विमान यात्रियों का काफी ध्यान खींचा। कोको की उम्र ज्यादा होने से उसकी मालकिन टकाको ने सौ डॉलर में भावनात्मक समर्थन जानवर के रूप में उसका पंजीकरण कराया। इसके बाद वह उनके साथ केबिन में आ सका और अपने मालिक की तरह ही उसे सारी सुविधाएं प्रदान की गई। यह कोको की पहली विमान यात्रा नहीं है। तीन साल पहले वह जापान से कैलिफोर्निया आया था।

सड़कें और भवन खुद होंगे दुरुस्त

मिली सफलता ▶ वैज्ञानिकों ने बैक्टीरिया युक्त कंक्रीट बनाया, दरार को खुद से करेगा ठीक

हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को सोख भी सकेंगे नए कंक्रीट से बने भवन

वाशिंगटन, प्रेट्र : वैज्ञानिकों ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए बैक्टीरिया युक्त कंक्रीट का निर्माण किया है। यह कंक्रीट जीवित अवस्था में रहेगा। यह एक ऐसी खोज है जिसके माध्यम से निर्माण उद्योग के कारण पर्यावरण पर पड़ रहे दुष्प्रभाव को कम किया जा सकता है। नए कंक्रीट से बनी ईंट हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को सोख भी सकेगी और खुद ही अपनी दरार को भी समाप्त कर सकती है। शोधकर्ताओं का कहना है कि निकट भविष्य में इस कंक्रीट का इस्तेमाल व्यापक तौर पर शुरू हो सकता है। अभी इसमें और शोध की जरूरत है।

'मैटर' जर्नल में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार, कंक्रीट की नई सामग्री में साइनोबैक्टीरिया (नील हरित शैवाल) का इस्तेमाल किया गया है। यह एक प्रकार के सूक्ष्म जीव हैं जो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा ग्रहण करते हैं। अमेरिका के बोल्डर में कोलोराडो यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर विल स्रुबेर ने बताया कि वर्तमान में भी हम अपने घरों या बिल्डिंग में जैविक उत्पादों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन, यह उत्पाद ज्यादा दिनों तक टिकने वाले नहीं होते हैं। शोधकर्ताओं ने कहा उनके नए प्रयोग में बैक्टीरिया को इतने समय तक जीवित रखने से पता चलता है कि भविष्य में जीवित सड़कें और जीवित इमारतें बहुत दूर की बात नहीं है। उन्होंने कहा कि इस तरह की संरचनाएं एक दिन अपनी दरारों को खुद समाप्त करने लगेंगी। हवा से विषाक्त पदार्थों को चूस सकती हैं या अपने आप में चमक भी ला सकती है। विल ने कहा कि वर्तमान में अंधाधुंध बिल्डिंगें बन रही हैं। इनका निर्माण कार्य मंहगा भी है और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाला भी है।

उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार है निर्माण उद्योग : शोधकर्ताओं के अनुसार, सड़कों, पुलों, गगनचुंबी इमारतों और अन्य संरचनाओं के लिए आवश्यक सीमेंट और कंक्रीट को बनाने से दुनिया में छह फीसद ग्रीनहाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है।

खुद ही सही हो जाएंगी दरारें : शोधकर्ताओं ने बताया कि इस कंक्रीट से बने भवन या सड़कें दरार पड़ने की स्थिति में खुद से ही सही हो जाएंगी। बैक्टीरिया प्रजनन करके वापस से पुरानी स्थिति को हासिल कर लेगा। शोधकर्ताओं ने बताया कि इस कंक्रीट से बनी ईंट को आधा काट दें तो यह फिर से पूरी हो जाएगी।

कुछ समस्याएं भी : शोधकर्ताओं के अनुसार, साइनोबैक्टीरिया को जीवित रहने के लिए ह्यूमिडिटी (आर्द्र स्थितियों) की आवश्यकता होती है। इस वजह से यह प्रयोग दुनिया के शुष्क देशों में सफल नहीं है।

प्रतीकात्मक

इस तरह किया प्रयोग

शोधकर्ताओं ने साइनोबैक्टीरिया पर प्रयोग करना शुरू किया। सही परिस्थितियों में ये हरे जीवाणु कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अवशोषित करने में मदद करते हैं। ताकि उन्हें बढ़ने और कैल्शियम कार्बोनेट बनाने में मदद मिल सके। कैल्शियम कार्बोनेट ही चूना पत्थर और सीमेंट का मुख्य घटक होता है। निर्माण प्रक्रिया शुरू करने के लिए रेत और जिलेटिन के मिश्रण में साइनोबैक्टीरिया की कॉलोनियों को बसाया गया। थोड़ी देर में बैक्टीरिया द्वारा जिलेटिन के इस्तेमाल से कैल्शियम कार्बोनेट का उत्पादन किया जाता है जो ईंट और रेत को आपस में जोड़ने का काम करता है। शोधकर्ताओं ने कहा कि ऐसी ईंटें हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को हटा देंगी। नमी की स्थिति में इस कंक्रीट की मजबूती उतनी ही होती है जितनी वर्तमान में प्रयोग हो रहे सीमेंट के कंक्रीट की।

फोटो न्यूज

25 मीटर ऊंचे ड्रम में बिताए 67 दिन

कुछ अलग करने और रिकॉर्ड बनाने के लिए कुछ लोग अजीबो-गरीब काम करते हैं। दक्षिण अफ्रीका के 52 वर्षीय वर्नोन क्रूगर ने डलस्टूम शहर में जमीन से 25 मीटर ऊंचे पोल पर एक ड्रम में 67 दिन बिताने का अपना ही रिकॉर्ड तोड़कर नया विश्व रिकॉर्ड बना डाला। वर्ष 1997 में क्रूगर ने 54 दिन ड्रम में बिताए थे। एएफपी

मंगल पर दस लाख लोगों को बसाना चाहते हैं स्पेसएक्स के सीईओ मस्क

▶ कहा, 2050 तक इन लोगों को लाल ग्रह पर भेजने का लक्ष्य

सैन फ्रांसिस्को, आइएएनएस : स्पेसएक्स के सीईओ एलन मस्क ने महत्वाकांक्षी मंगल ग्रह मिशन का एलान किया है। उन्होंने वर्ष 2050 तक इस लाल ग्रह पर दस लाख लोगों को भेजने का लक्ष्य निर्धारित किया है। उन्होंने इस बात से भी पर्दा उठाया कि वह मंगल ग्रह पर बस्ती बसाने और इंसानों को दूसरे ग्रहों पर रहने लायक बनाने के चुनौतीपूर्ण लक्ष्य को किस तरह हासिल करने जा रहे हैं।

अमेरिकी निजी अंतरिक्ष कंपनी के सीईओ मस्क ने एक के बाद एक ट्वीट के जरिये अपनी योजना की जानकारी दी। उन्होंने अपने अंतरिक्षयान स्टारशिप प्रोग्राम के बारे में जानकारी देते हुए बताया, 'रॉकेट के जरिये हर साल मेगाटन कार्गो मंगल ग्रह पर पहुंचाया जाएगा। इससे इस ग्रह को 2050 तक इंसानों के रहने योग्य बनाया जाएगा।' मस्क ने एक ट्वीट में अपने तीन करोड़ से ज्यादा फॉलोवर्स से कहा, 'स्टारशिप की डिजाइन इस तरह तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे रोजाना इसकी तीन उड़ानें हो सके। इस तरह एक साल में इसकी एक हजार से ज्यादा उड़ानें होंगी। हर उड़ान में सौ टन सामान भेजा जाएगा।' 48 वर्षीय मस्क ने बताया, 'स्पेसएक्स का लक्ष्य 2050 तक दस लाख लोगों को मंगल पर भेजने का है।'

लैंडिंग साइट पर मांगी जानकारी : गत वर्ष सितंबर में स्पेसएक्स ने अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा से लाल ग्रह पर ऐसे संभावित लैंडिंग साइट के बारे में जानकारी मांगी थी, जहां अंतरिक्षयान को उतारा जा सकता है।

अंतरिक्षयान पर चल रहा काम : स्पेसएक्स में ऐसे स्टारशिप का निर्माण किया जा रहा है, जिनका दोबारा इस्तेमाल हो सके। इस तरह के अंतरिक्षयान से इंसानों और सामान को मंगल ग्रह पर पहुंचाया जा सकता है। फिलहाल 'एसएन1' नामक स्टारशिप प्रोटोटाइप का निर्माण स्पेसएक्स के टेक्सास संयंत्र में चल रहा है।

भारी-भरकम खर्च का अनुमान

मस्क ने लाल ग्रह पर रहने योग्य माहौल बनाने की लागत का अनुमान लगाया है। उनका आकलन है कि मंगल मिशन पर 700 लाख करोड़ रुपये तक का खर्च आ सकता है।

एलन मस्क। फाइल

मिल्की वे के केंद्र में मिलीं रहस्यमय गैसीय वस्तुएं

▶ जर्नल नेचर में छपा है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के शोधकर्ताओं का शोध

▶ यह खोज ब्रह्मांड और खगोलीय पिंडों के बारे में बढ़ाएगी हमारी समझ

लॉस एंजिलिस, प्रेट्र : खगोलविदों ने हमारी आकाशगंगा 'मिल्की वे' के केंद्र में एक बड़े ब्लैक होल के करीब अजीब गैस जैसी वस्तुओं को देखा है। यह एक ऐसी खोज है जो ब्रह्मांड में तारों और अन्य खगोलीय पिंडों को बनाने वाली शक्तियों के प्रति हमारी समझ को और विस्तार दे सकती है।

अमेरिका में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, लॉस एंजिलिस की एंड्रिया गेज ने कहा, 'ये वस्तुएं दिखने में तो गैसीय लगती हैं, पर व्यवहार से ये तारों जैसी हैं। जर्नल नेचर में छपे अध्ययन के मुताबिक, नई वस्तुएं ज्यादातर समय समूह में दिखती हैं और जब उनकी कक्षा उन्हें घने ब्लैक होल के सबसे करीब लाती है, तो उन्हें बाहर की ओर खींचती प्रतीत होती है। ये वस्तुएं साजिटेरियस ए नामक ब्लैक होल के चारों ओर अपनी परिक्रमा पूरी करने में लगभग 100 से 1,000 वर्ष तक का समय लेती हैं।

होता है विशेष प्रकार की सिग्नेचर : पिछले शोध में खगोलविदों ने मिल्की वे के केंद्र में दो असामान्य वस्तुओं की पहचान की, जिसे उन्होंने जी 1 और जी 2 नाम दिया और सामूहिक रूप से इसे जी ऑब्जेक्ट का नाम दिया गया था। उनका मानना है कि जी 2 दो तारे हो सकते हैं जो अग्रानुक्रम में ब्लैक होल की परिक्रमा कर रहे थे और एक बड़े तारे में इनका विलय हो गया था, जो मोटी गैस और धूल में लिप्त थे। जी 2 की लगातार निगरानी करने पर खगोलविदों ने पाया कि इसका एक विशेष प्रकार का सिग्नेचर भी होता है, जिससे इसकी पहचान आसान हो जाती है।

गेज ने कहा, हम पहले भी इसे देख चुके थे, लेकिन तब बहुत अजीब नहीं लग रहा था। जब यह ब्लैक होल के करीब पहुंचा तो यह लंबा हो गया और इसकी गैस का रिसाव हो गया और ब्लैक होल में समा गया, लेकिन अब यह ब्लैक होल से दूर हुआ तो यह पुनः अपनी पूर्वावस्था में आ गया।

मोटापा के साथ ही दिमाग पर भी असर डाल सकता है सोयाबीन का तेल

शोध अनुसंधान

सोयाबीन तेल का खाने में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है। एक भारतवंशी समेत शोधकर्ताओं के दल ने अध्ययन में पाया है कि इस तेल का दिमाग पर भी असर पड़ सकता है। सोयाबीन तेल के सेवन से ना सिर्फ मोटापा और डायबिटीज बल्कि ऑटिज्म, अल्जाइमर और डिप्रेशन जैसी समस्याओं का खतरा पहले ही पाया जा चुका है।

अमेरिका की कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं के अनुसार, चूहों पर किए गए एक अध्ययन में मस्तिष्क के हाइपोथेलेमस हिस्से पर सोयाबीन तेल का स्पष्ट प्रभाव पाया गया है। मस्तिष्क के इसी हिस्से में हार्मोन के स्राव समेत कई अहम प्रक्रियाएं होती हैं। शोधकर्ताओं ने सोयाबीन तेल से करीब 100 जीन को प्रभावित पाया। शोधकर्ता पूनमजोत देओल ने कहा, 'अध्ययन के इस नतीजे से सेहतमंद तेल बनाने में मदद मिल सकती है। मैं लोगों को सोयाबीन तेल का कम इस्तेमाल करने की सलाह देती हूं।' -आइएएनएस

शराब से मस्तिष्क की संरचना में हो सकता बदलाव

शराब से होने वाले नुकसान से हर कोई अवगत है। इसके सेवन से कई तरह की स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। अब एक नए अध्ययन के अनुसार, बहुत ज्यादा शराब पीने से मस्तिष्क की संरचना या कार्यक्षमता में बदलाव हो सकता है।

शोधकर्ताओं के अनुसार, शराब पर बढ़ती निर्भरता के लिए नया उपचार तैयार करने के इरादे से दिमाग के ऐसे कई हिस्सों पर गौर किया गया, जिन पर पहले ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया था। अमेरिका के यूसी सैन डिएगो स्कूल ऑफ मेडिसिन के एसोसिएट प्रोफेसर ओलिवियर जॉर्ज ने कहा, 'नशे की लत के संबंध में न्यूरोसाइंस में उल्लेखनीय प्रगति हुई है, लेकिन ब्रेन सर्किट्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के बारे में समझ सीमित रही। हमारे नतीजों से इसकी पुष्टि हुई कि लत के संबंध में मस्तिष्क के ये भाग काफी अहम हैं।' -एएनआइ

फिल्म रिव्यू

हंसा पाने में नाकामयाब

जय मम्मी दी

प्रमुख कलाकार : सनी सिंह, सोनाली सहगल, सुप्रिया पाठक, पूनम ढिल्लो
निर्देशक : नवजोत गुलाटी
अवधि : एक घंटा 45 मिनट

'जय मम्मी दी' की कहानी दो मम्मियों लाली खन्ना (सुप्रिया पाठक कपूर) और पिंकी भल्ला (पूनम ढिल्लो) की आपसी लड़ाई पर केंद्रित है। कॉलेज के दिनों में दोनों दोस्त हुआ करती थीं, लेकिन किसी बात पर अनबन होने की वजह से दोनों की दोस्ती दुश्मनी में बदल जाती है और दोनों अपने ही बच्चों की लवस्टोरी में विलेन बन जाती हैं।

दरअसल, लाली का बेटा पुनीत (सनी सिंह) और पिंकी की बेटी सांझ (सोनाली सहगल) एक दूसरे से प्यार करते हैं। वे अपनी मम्मियों को गब्बर और मोगैंबो संबोधित करते हैं। मम्मी के सामने अपने प्यार का इजहार करने से डरते हैं। दोनों की शादी अलग-अलग पर एक ही दिन तय होती है। इन्हीं तानों-बानों से हास्य पैदा करने की नाकाम कोशिश की गई है।

फिल्म की पटकथा लचर है। स्क्रीनप्ले और किरदारों को विकसित करने पर लेखक का ध्यान नहीं है। दोनों मम्मी के झगड़े की वजह को अंत में बहुत सतही तरीके से निपटा दिया गया है। गानों की भरमार है। फिल्म देखते समय कहानी में लॉजिक ढूंढ़ने की गलती कदापि न करें।

'प्यार का पंचनामा' 1 व 2 और 'सोनू के टीटू की स्वीटी' के निर्देशक लव रंजन इसके सहनिर्माता हैं। उनकी फिल्मों में स्त्री के प्रति द्वेष उठाने वाले मुद्दे इस फिल्म से नदारद हैं। यहां कहीं-कहीं पर नारीवाद का समर्थन करने का प्रयास हुआ है।

मसलन एक जगह सांझ कहती है कि शादी के बाद लड़की ही क्यों अपना घर छोड़कर आए। बहरहाल, सनी सिंह और सोनाली सहगल लव रंजन की फिल्मों का हिस्सा रहे हैं। फिल्म 'उजड़ा चमन' में नजर आए सनी सिंह लगातार कॉमेडी फिल्म कर रहे हैं। सोनाली स्टाइलिश और ग्लैमरस लगी हैं। लेकिन भावनात्मक दृश्यों में दोनों कमजोर नजर आते हैं। फिल्म में बीच-बीच में वनलाइनर हैं जो बमुश्किल हंसा पाते हैं। सुप्रिया पाठक और पूनम ढिल्लो की प्रतिभा का निर्देशक समुचित उपयोग नहीं कर पाए हैं। आलोक नाथ को फिल्म में शामिल करने की वजह समझ में नहीं आती। निर्देशक नवजोत गुलाटी इससे पहले तापसी पन्नू अभिनीत 'रनिंग शादी' की कहानी लिख चुके हैं। उसकी कहानी की तरह 'जय मम्मी दी' में भी वह चूक गए हैं।

स्मिता श्रीवास्तव

★★★★★ उत्कृष्ट ★★★★ बहुत अच्छी ★★★ अच्छी ★★ औसत ★ औसत से कम

स्क्रीन शॉट

'शकीला' अटकी नहीं, पोस्ट प्रोडक्शन में है : रिचा चड्ढा

अभिनेत्री रिचा चड्ढा साल की शुरुआत फिल्म 'पंगा' से कर रही हैं। उसमें वह कबड्डी खिलाड़ी की भूमिका में नजर आएंगी। उसके अलावा उनकी फिल्म 'अभी तो पार्टी शुरू हुई है' और 'शकीला' भी रिलीज होने की कतार में हैं। 'शकीला' साउथ की एडल्ट स्टार शकीला की जिंदगी पर आधारित है। फिल्म को बीते साल रिलीज करने की खबरें आई थीं। इस बारे में रिचा चड्ढा का कहना है, 'ऐसा गलतफहमी के कारण हुआ। जब फिल्म की शूटिंग हो रही थी, उस दौरान उसका कैलेंडर वितरित कर दिया गया था। लोगों को लगा कि फिल्म आ रही है। दरअसल, अंदर के पन्नों को पूरा किए बिना ही फ्रंट पेज छाप दिया गया। 'शकीला' अभी पोस्ट प्रोडक्शन में है। उसकी शूटिंग पूरी हो चुकी है। एडीटिंग भी हो गई है।'

कभी हकलाते थे शरद केलकर

'तान्हाजी : द अनसंग वॉरियर' में छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमिका में नजर आए शरद केलकर अपनी दमदार आवाज के लिए भी जाने जाते हैं। वह कई हॉलीवुड फिल्मों की हिंदी में डबिंग कर चुके हैं। 'बाहुबली' में प्रभास के किरदार की डबिंग उन्होंने ही की थी। हालांकि एक वक्त ऐसा भी था, जब शरद हकलाते थे। शरद बताते हैं, 'वर्ष 2003 में मैं रेडियो स्टेशन में ऑडिशन देने गया था, जिसमें मुझे रिजेक्ट कर दिया गया था। टीवी पर काम करता था तब दोस्त कहते थे कि आवाज इतनी अच्छी है, तुम सही ढंग से क्यों नहीं बोलते हो? तुम बहुत जल्दी में कह जाते हो। तब लगा कि एक्टर बनने के लिए हकलाने की समस्या दूर करनी होगी। मैंने उस पर काम शुरू किया। अमिताभ बच्चन सर ने एक इंटरव्यू में कहा था कि एक एक्टर अपनी डबिंग से अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर कर सकता है और खराब भी। डबिंग एक्टिंग का बहुत अहम हिस्सा है। अगर आप उसे सीख जाएं तो अपनी परफॉर्मेंस को ऊपर ला सकते हैं। यह बात जेहन में थी। मुंबई में एक स्टूडियो में डबिंग की। वहां पैसे कम थे, मगर सीखने के लिए किया। तीन-चार फिल्मों में डबिंग की, तब आवाज में निखार आया। 'गोलियों की रासलीला-रामलीला' में लोगों ने आवाज की तारीफ की। मगर हां, कई बार जहां पर किरदार में दमदार आवाज की जरूरत नहीं होती, वे रोल हाथ से निकल भी जाते हैं। मगर ज्यादातर यह आपके लिए फायदेमंद होता है।'

गाने में ज्यादा सुकून लाने के लिए बदली धुन

इन दिनों फिल्म 'मलंग' का गाना 'चल घर चलें' संगीत प्रेमियों को बहुत रास आ रहा है। इस गाने को यूट्यूब पर अब तक ढाई करोड़ से भी ज्यादा बार देखा जा चुका है। इस गाने के संगीतकार मिठुन गाने के संबंध में बताते हैं, 'फिल्म के निर्देशक मोहित सूरी फिल्म में कोई ऐसा गाना शामिल करना चाहते थे, जिसमें घर की बात हो। हिंदुस्तान के प्यार की तारीफ की जाती हो। हम गाने में इसी हिंदुस्तानियत को दिखाना चाहते थे। घर से ज्यादा सुकून कहीं और नहीं मिल सकता। हम सभी के अंदर अपने घर जाने का एक अनोखा उत्साह होता है और हम गाने के जरिए उसी उत्साह को दिखाना चाहते थे। गाने के बोल तय होने के बाद, जब मैंने पहली बार मोहित को धुन सुनाई तो उन्हें ज्यादा बेकरारी महसूस हुई, जबकि वह गाने में बेकरारी की जगह सुकून चाहते थे। फिर मैंने एक दूसरी धुन बनाई, जो उन्हें अच्छी लगी।

सनी कौशल से पहले कास्ट किया गया उनके पापा को

हिंदी सिनेमा में कई स्टार किड्स हैं, जिनके माता-पिता भी उनके साथ फिल्मों में सक्रिय हैं। उनकी पहचान उनके बच्चों से बड़ी हैं, चाहे वे स्क्रीन पर नजर आ रहे हों या पर्दे के पीछे सिनेमा से जुड़े दूसरे कामों में व्यस्त हों। सनी कौशल के पिता तो वेब शो 'द फॉरगॉटन आर्मी- आजादी के लिए' से डिजिटल डेब्यू भी कर रहे हैं। कबीर खान निर्देशित इस सीरीज में पहली बार सनी ने अपने पिता शाम कौशल के साथ काम किया है। शाम कौशल वर्षों से हिंदी सिनेमा में एक्शन डायरेक्टर हैं। इस सीरीज के लिए सनी से पहले उनके पिता को साइन कर लिया गया था। सनी ने बताया कि 'द फॉरगॉटन आर्मी' के ऑडिशन पर जाने से पहले उन्होंने अपने पिता को इसके बारे में बताया था। पिता ने कहा था कि ऑडिशन देने जरूर जाओ। वैसे वह बतौर एक्शन डायरेक्टर काम कर रहे हैं। यह पहली बार है, जब सनी अपने पिता के साथ किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। सीरीज का पूरा एक्शन शाम कौशल ने ही डिजाइन किया है। यह सीरीज सुभाष चंद्र बोस द्वारा गठित आजाद हिंद फौज पर आधारित है। 24 जनवरी से यह सीरीज अमेजॉन प्राइम वीडियो पर शुरू होगी।

अब अक्टूबर में रिलीज होगी आरआरआर

निर्देशक राजामौली अपनी फिल्म 'आरआरआर' की शूटिंग में व्यस्त हैं। फिल्म में रामचरण, आलिया भट्ट जैसे कलाकार हैं। अजय देवगन उसमें कैमियो कर रहे हैं। फिल्म को जुलाई में रिलीज करने की बात कही गई थी, लेकिन अब इसकी तारीख आगे खिसका दी गई है। फिल्म टीम के करीबी सूत्रों के अनुसार, फिल्म को अक्टूबर में रिलीज करने की संभावना हैं। हाल ही में रे स्टीवेंसन, ओलिविया मॉरिस और एलिसन डूडी जैसे मशहूर कलाकार 'आरआरआर' से जुड़े हैं। 70 प्रतिशत हिस्सा पहले ही शूट किया जा चुका है। यह फिल्म 10 भाषाओं में रिलीज करने की तैयारी है।

मेघना अगले साल शूट करेंगी सैम मानेकशॉ की बायोपिक

'तलवार', 'राजी' और 'छपाक' जैसी लगातार वास्तविक घटनाओं और लोगों से प्रेरित फिल्में बना रहीं मेघना गुलजार की आगामी फिल्म भी वास्तविक घटना से प्रेरित होगी। इसकी घोषणा वह पहले ही कर चुकी हैं। यह फिल्म सैम मॉनेकशॉ पर आधारित होगी। वर्ष 1971 में हुए भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान सैम मानेकशॉ भारतीय सेना के प्रमुख थे। युद्ध में ऐतिहासिक जीत के बाद भारत एक शक्तिशाली देश बनकर विश्व के सामने उभरा था। इसी के साथ विश्व मानचित्र पर एक नए देश के रूप में बांग्लादेश का जन्म हुआ। मेघना का कहना है कि वास्तविक घटनाओं पर फिल्में बनाना एक जिम्मेदारी का काम होता है। उनका कहना है, 'फिल्म मेकिंग अपने आप में जिम्मेदारी का काम है। जब असल जीवन पर फिल्में बनती हैं तो यह जिम्मेदारी दोगुनी हो जाती है, क्योंकि उसमें विश्वसनीयता बहुत जरूरी हो जाती है। जब ऐसी फिल्मों में वास्तविक लोग जुड़े होते हैं, फिर भले ही वे लोग जीवित हो या न हों, पर यह कोशिश करनी होती है कि कहीं पर भी किसी की भावना को ठेस न पहुंचे। फिल्ममेकर को यह जिम्मेदारी लेकर चलना चाहिए।' मेघना का कहना है कि मॉनेकशॉ पर फिल्म सिर्फ देशभक्ति और 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध पर ही आधारित नहीं है। यह उनकी जिंदगी के कई पहलुओं को दर्शाएगी। उनकी देशभक्ति, उनकी सोच और उनके डायलॉग्स में यह बात दिखेगी। अगर वह अपने प्रधानमंत्री से टक्कर लेते हैं, तो वह रूप भी नजर आएगा। फिल्म की शूटिंग 2021 की शुरुआत से आरंभ होगी। उसमें विक्की कौशल प्रमुख भूमिका में होंगे।

याद आए बाबूजी...

सोशल मीडिया पर सक्रिय अमिताभ बच्चन अक्सर अपने परिवार की तस्वीरें या अपनी पुरानी यादों को ताजा करते रहते हैं। इस बार उन्होंने दो लोगों को याद करते हुए श्रद्धांजलि दी है। 14 जनवरी को उनकी समधिन रितु नंदा का निधन हुआ था। रितु उनकी बेटी श्वेता नंदा की सास थीं। अमिताभ बच्चन ने रितु नंदा की तस्वीर साझा करते हुए लिखा, 'आज समाप्त हुआ परिवार के एक आदर्शपूर्ण समधी का चौथा। बस कुछ ही क्षणों में पूज्य बाबूजी (हरिवंश राय बच्चन) की पुण्यतिथि... जीवन है चलायमान...बहती नदी के समान...'। दरअसल, शनिवार को हिंदी के मशहूर कवि हरिवंश राय बच्चन की 17वीं पुण्यतिथि भी थी। इस मौके पर ऑल इंडिया रेडियो ने भी हरिवंश राय बच्चन की कविता और तस्वीर साझा करते हुए लिखा, 'जीवन में एक सितारा था, माना वह बेहद प्यारा था। छायावादी कवि डॉ. हरिवंशराय बच्चन की मधुबाला, निशा निमंत्रण, सतरंगिनी, मिलन यामिनी जैसी कई कालजयी कृतियां मन मोह लेती हैं। उनकी रचनाओं में सहज शैली से व्यक्तित्व और जीवन की सच्चाई झलकती है। पीढ़ी दर पीढ़ी चहेते पाठकों में 'मधुशाला' की खुमारी कायम है। पुण्यतिथि पर नमन।'

फास्फोरस के अणुओं से आया पृथ्वी पर जीवन

लंदन, प्रेट्र : शोधकर्ताओं ने दावा किया है कि पृथ्वी तक जीवन की उत्पत्ति के लिए प्रमुख अणु कैसे पहुंचे। उन्होंने बताया है कि सेल मेटाबोलिज्म के लिए जरूरी फॉस्फोरस के अणु अंतरिक्ष से पृथ्वी पहुंचे हैं। शोधकर्ताओं ने रोसेटा स्पेसक्राफ्ट में लगे रोसिना उपकरण से मिले डाटा का अध्ययन किया। इसमें उत्तरी चिली के अटाकामा रेगिस्तान में 66 रेडियो दूरबीनों के नेटवर्क द्वारा जुटाए डेटा का प्रयोग किया गया। शोधकर्ताओं ने तारों के निर्माण होने वाले ब्रह्मांडीय क्षेत्र एएफजीएल-5142 में यह पता किया कि वहां फॉस्फोरस के अणु कहां बनते हैं। उन्होंने पाया कि तारे बनने की प्रक्रिया में फॉस्फोरस के अणु बनते हैं। इनमें फास्फोरस मोनोऑक्साइड अधिक होता है। यह अंतरिक्ष में जमकर धूमकेतु, उल्का पिंड बन जाते हैं, जो ग्रहों पर गिरते हैं।